



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274151
CG-DL-E-04072026-274151

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948

No. 183]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 25 जून, 2026

मामला सं. एडी(ओआई)-23/2025

विषय: कुवैत राज्य, मलेशिया, ओमान सल्तनत, कतर राज्य, सऊदी अरब साम्राज्य और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लीनियर लो-डेंसिटी पॉलीएथिलीन" (एलएलडीपीई) के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच।

फा. सं. 6/26/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और उसके तहत बनाए गए सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995, जैसा कि समय-समय पर संशोधित (इसके बाद "एडी नियमावली, 1995" के रूप में संदर्भित) को ध्यान में रखते हुए:

मामले की पृष्ठभूमि

1. केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (सीपीएमए) (इसके बाद "आवेदक संघ" के रूप में संदर्भित) ने भारतीय एलएलडीपीई निर्माताओं की ओर से, सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 और एडी नियमावली, 1995 के अनुसार, कुवैत राज्य ("कुवैत"), मलेशिया, ओमान सल्तनत ("ओमान"), कतर राज्य ("कतर"), सऊदी अरब साम्राज्य ("सऊदी अरब") और संयुक्त अरब अमीरात ("यूएई") के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "रैखिक निम्न-घनत्व पॉलीएथिलीन" (इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' या 'संबद्ध वस्तुएँ' या 'एलएलडीपीई' के रूप में भी संदर्भित) के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच शुरू करने के लिए प्राधिकारी (इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में भी संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "संबद्ध देश" कहा गया है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (इसके बाद "एचपीएल") और एचपीसीएल-मितल एनर्जी लिमिटेड (इसके बाद "एचएमईएल"), जिन्हें सामूहिक रूप से "घरेलू उद्योग" कहा गया है, ने क्षति की जानकारी प्रदान की और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक समर्थन पत्र दायर किया।
2. और जबकि, आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के मद्देनजर, प्राधिकारी ने 30 जून 2025 की अधिसूचना संख्या 6/26/2025-डीजीटीआर द्वारा, भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें पाटन रोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात में पाटन रोधी जांच शुरू की गई ताकि कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश की जा सके, जो यदि लगाया जाए, तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

क. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क.1 जांच की शुरुआत

- i. प्राधिकारी ने एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए आगे बढ़ने से पहले संबद्ध देशों के दूतावासों को भारत में वर्तमान पाटन रोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

- ii. इसके अलावा, भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अनुच्छेद 7.2 के पैरा 3 के तहत संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा जांच शुरू करने से पूर्व परामर्श के अनुरोध के अनुसरण में, 29.06.2025 को यूएई सरकार के साथ परामर्श किया गया।
- iii. क्षति अवधि के साथ-साथ जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देन-वार विवरण प्रदान करने के लिए डीजीसीआईएंडएस और डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने लेन-देन की उचित जांच के बाद आयातों की मात्रा के निर्धारण और आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- iv. नियम 6 के अनुसार, आवेदन की जांच करने और पाटन, क्षति, संभावना और कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए जाने पर, प्राधिकारी ने 30 जून 2025 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई, जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच शुरू की गई।
- v. एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की सरकारों को, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, जांच शुरू करने की सूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार ज्ञात कराने का अनुरोध किया।

क.2 जांच अवधि

- vi. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच अवधि (पीओआई) 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 (12 महीने) है। क्षति जांच अवधि [आईआईपी] वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और जांच अवधि की अवधि को शामिल करती है।

क.3 आवेदन के अगोपनीय संस्करण का परिचालन

- vii. एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसरण में, प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय संस्करण की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देशों की सरकारों को, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से प्रदान की।
- viii. नियम 6(4) के अनुसरण में, भारत में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली जारी की गई, जिसमें सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत का विवरण शामिल था। जहाँ भी अनुरोध किया गया, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन के अगोपनीय संस्करण की एक प्रति प्रदान की गई।

क.4 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भागीदारी

- ix. संबद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली प्रतिक्रियाएँ दाखिल करके उत्तर दिया है:

देश	उत्पादक/निर्यातक का नाम
कुवैत	इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी ("इक्वेट")
मलेशिया	मलेशिया से कोई उत्पादक भाग नहीं लिया है
ओमान	मेसर्स ओक्यू पॉलिमर एल.एल.सी. ("ओक्यू पॉलिमर")
	ओक्यू मार्केटिंग एल.एल.सी. ("ओक्यू मार्केटिंग")
कतर	कतोफिन कंपनी लिमिटेड क्यू.पी.जे.एस.सी ("कतोफिन")
कतर	कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंतजात) क्यू पी जे एस सी ("मुंतजात")
	कतर एनर्जी मार्केटिंग ("क्यूईएम")
	टोटलएनर्जीज पेट्रोकेमिकल्स फ्रांस - कतर शाखा कार्यालय ("टोटल एनर्जीज")

सऊदी अरब	अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या")
सऊदी अरब	अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी ("पेट्रोकेम्या")
सऊदी अरब	ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी ("शर्क")
सऊदी अरब	जुबैल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी ("यूनाइटेड")
सऊदी अरब	राबिघ रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कंपनी ("आरआरपीसी")
सऊदी अरब	सदारा केमिकल कंपनी ("सदारा")
सऊदी अरब	यान्बू राष्ट्रीय पेट्रोकेमिकल कंपनी ("यानसाब")
सऊदी अरब	सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ("सैबिक")
सऊदी अरब	सैबिक एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड ("एसएपीपीएल")
सऊदी अरब	एसपीडीसी
सऊदी अरब	एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड
सऊदी अरब	डाउ सऊदी अरब प्रोडक्ट मार्केटिंग बी.वी. ("डीएसए")
सऊदी अरब	डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड ("डीसीपी (एस)")
सऊदी अरब	डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, दुबई शाखा ("डीसीपी (डी)")
सऊदी अरब	डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड दुबई शाखा ("डीसीआईपीएल")
संयुक्त अरब अमीरात	अबू धाबी पॉलिमर्स कंपनी लिमिटेड ("एडीपीसीएल")
संयुक्त अरब अमीरात	बोरौज पीटीई लिमिटेड
संयुक्त अरब अमीरात	एसआरजे ग्लोबल एफ.जेड.ई.

- x. निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने प्रश्नावली प्रतिक्रियाएँ दाखिल करके उत्तर दिया है:
- i. सैबिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ("एसआरटीपीएल")
 - ii. एक्सॉनमोबिल कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("ईएमसीआईपीएल")
- xi. जांच शुरू करने की सूचना के जवाब में, किसी भी संघ ने भाग नहीं लिया है या वर्तमान जांच में प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है। अखिल भारतीय एचडीपीई/पीपी बुने कपड़े निर्माता संघ ने कानूनी अनुरोधों की हैं जिन पर प्राधिकारी ने विचार किया है।
- xii. निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान कार्यवाहियों में अपनी सभी अनुरोधों का अगोपनीय संस्करण अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया था।
- xiii. सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली प्रशासनिक लाइन मंत्रालय को भी साझा की गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली केवल घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई थी।
- xiv. विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, या इस जांच के लिए प्रासंगिक सूचना प्रदान नहीं की है, असहयोगी माना गया है।

क.5 आगे की प्रक्रिया

- xv. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल अनुरोधों के अगोपनीय संस्करण सभी भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी जिसमें उन सभी से अपनी अनुरोधों का अगोपनीय संस्करण अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करने का अनुरोध किया गया था।
- xvi. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 15 अप्रैल 2026 को आयोजित एक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षों को मौखिक

- रूप से व्यक्त विचारों की लिखित अनुरोधयाँ देने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोधयाँ दी गईं।
- xvii. नियम 6(8) के अनुसार, जहाँ भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने पहुँच से इनकार किया है या वर्तमान कार्यवाहियों के दौरान अन्यथा समयबद्ध तरीके से आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा डाली है, ऐसे पक्षों को असहयोगी माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए गए हैं।
- xviii. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की ऐसे गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, गोपनीयता दावों को जहाँ भी उचित था स्वीकार कर लिया गया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दाखिल सूचना का पर्याप्त अगोपनीय संस्करण प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
- xix. नियम 8 के अनुसार, जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना और आंकड़ों की सटीकता का, जहाँ तक प्रासंगिक, व्यावहारिक और आवश्यक समझा गया, सत्यापन किया गया। प्रस्तुत आंकड़ों और दस्तावेजों का सत्यापन अंतिम निष्कर्ष का आधार बनता है और प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाहियों में अपने विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- xx. प्राधिकारी ने 30 जून 2025 की जांच शुरू करने की सूचना के पैरा 5 के माध्यम से जांच शुरू होने के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर टिप्पणियाँ मांगी थीं। हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति पर 20 जुलाई 2025 तक टिप्पणियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था। प्राधिकारी ने, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करने के बाद, 22 अगस्त 2025 की अधिसूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के अंतिम कार्यक्षेत्र को अधिसूचित किया। सभी हितबद्ध पक्षकारों को पीसीएन पद्धति की अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर, अंतिम रूप दिए गए विचाराधीन उत्पाद के अनुसार प्रश्नावली प्रतिक्रियाएँ दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। कुछ हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, समय सीमा को आगे बढ़ाकर 12 सितंबर 2025 कर दिया गया।

- xxi. क्षति रहित कीमत की गणना, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमों के अनुबंध III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री की इष्टतम लागत और लागत के आधार पर की गई है।
- xxii. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई अनुरोधयाँ, जहाँ तक साक्ष्य से समर्थित और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक मानी गई, प्राधिकारी द्वारा इस प्रकटीकरण विवरण में उचित रूप से विचार किया गया है।
- xxiii. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्क और प्रदान की गई सूचना, जहाँ तक वही साक्ष्य से समर्थित है और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक मानी गई है, पर विचार किया गया है।
- xxiv. इस दस्तावेज में '***' एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और एडी नियमावली, 1995 के तहत प्राधिकारी द्वारा ऐसा माना गया है।
- xxv. इस जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 84.58 है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ख.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- एलएलडीपीई मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, इसके बहुलकीकरण के दौरान उपयोग किए जाने वाले सहबहुलक के आधार पर, यथा सी-4 (ब्यूटीन आधारित), सी-6 (हेक्सीन आधारित) और सी-8 (ऑक्टीन आधारित)। आवेदक सी-8 आधारित एलएलडीपीई का निर्माण नहीं करते हैं और मौखिक सुनवाई के दौरान इसे स्वीकार किया था। उत्पाद कार्यक्षेत्र में वे उत्पाद शामिल नहीं हो सकते जो वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादित और बेचे नहीं जाते।
 - सी-8 आधारित एलएलडीपीई में मानक एलएलडीपीई की तुलना में उन्नत गुण होते हैं और यह आधार श्रेणियों पर एक महत्वपूर्ण मूल्य प्रीमियम प्राप्त करता है।

- iii. चूंकि सी-8 आधारित एलएलडीपीई भारत को निर्यात नहीं किया गया है, इस पर पाटन रोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता। तदनुसार, सभी सी-8 आधारित एलएलडीपीई को उत्पाद कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- iv. चूंकि आवेदकों द्वारा उत्पादित सी-4 और सी-6 एलएलडीपीई व्यक्तिगत रूप से सीधे सी-8 आधारित एलएलडीपीई को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते और केवल दोनों का संयोजन सी-8 आधारित एलएलडीपीई को प्रतिस्थापित कर सकता है, यह नहीं कहा जा सकता कि सी-4 और सी-6 एलएलडीपीई के भौतिक और रासायनिक गुण सी-8 आधारित एलएलडीपीई के समान हैं।
- v. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा सी-8 एलएलडीपीई का उत्पादन, जो घरेलू उद्योग का घटक नहीं है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में एलएलडीपीई को शामिल करने का आधार प्रदान नहीं कर सकता। यदि केवल जांच के समर्थक सी-8 आधारित एलएलडीपीई का निर्माण कर रहे हों तो यह पर्याप्त नहीं है। समर्थकों को संपूर्णता में जांच का हिस्सा होना चाहिए।
- vi. अन्य उत्पादकों द्वारा भागीदारी के अभाव में, प्राधिकारी यह सत्यापित नहीं कर सकता कि अन्य उत्पादक सी-8 आधारित एलएलडीपीई का निर्माण कर रहे हैं या नहीं।
- vii. आवेदक एलएलडीपीई के चूर्ण रूप का निर्माण नहीं करते हैं और तदनुसार, इसे बाहर रखा जाना चाहिए। एचएमईएल के श्रेणियाँ एम2024एल और एम5026एल में उच्च प्रवाह सूचकांक है, तथापि, ऐसी श्रेणियों का रूप और उपयोग भिन्न है। इस प्रकार, एमजी200024 और एमजी500026 (यौगिकीकरण के लिए चूर्ण रूप) को विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- viii. आवेदकों का यह दावा कि छर्ी और चूर्ण रूप विनिमेय हैं, इस तथ्य को संबोधित नहीं करता कि उत्तरदाताओं द्वारा उत्पादित श्रेणियों का रूप और उपयोग भिन्न है और तदनुसार, इसे विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- ix. सैबिक की श्रेणियाँ 6821एनजे और 6318बी जो सी-6 आधारित एलएलडीपीई हैं, को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उनमें उच्चतर विदारण और तनन सामर्थ्य है, जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता।
- x. घरेलू उद्योग ने इस तर्क का खंडन नहीं किया है कि भारत में सी-6 एलएलडीपीई के लिए पर्याप्त मांग-आपूर्ति अंतराल मौजूद है। उसने न तो श्रेणी-वार उत्पादन या मांग आंकड़े प्रदान किए हैं।

- xi. गैर-धातुसीन श्रेणियों एन0118एल/एन0120एल और धातुसीन श्रेणियों (जैसे एफ0120एलएम/एफ0118एलएम/एन0118एलएम/एन0120एलएम) के बीच महत्वपूर्ण मूल्य अंतर है। एचएमईएल मूल्य परिपत्र के आधार पर यह मूल्य अंतर 15% तक है।
- xii. सदारा मुख्यतः उच्च एल्फा ओलेफिन एलएलडीपीई ("एचएओ एलएलडीपीई") के निर्यात में संलग्न है, जबकि एचएमईएल और एचपीएल मुख्यतः सी4 एलएलडीपीई का उत्पादन करते हैं। सी4 आधारित एलएलडीपीई का उपयोग प्लास्टिक बैग, किराना बैग, द्वितीयक बैग आदि में अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जबकि सी6 और सी8 आधारित एलएलडीपीई का उपयोग मुख्यतः उच्च-निष्पादन अनुप्रयोगों में किया जाता है क्योंकि इसमें काफी अधिक कठोरता, उच्चतर प्रभाव प्रतिरोध और बेहतर ऊष्मा सील गुण होते हैं, जैसे स्टैंडअप पाउच (एसयूपी), भारी शुल्क शिपिंग बोरे (एचडीएसएस), चूर्ण/तरल पाकिट, पिलो पाउच, डायपर/स्त्री स्वच्छता के लिए पश्च फलक फिल्म आदि।
- xiii. एचएओ एलएलडीपीई एक प्रीमियम उत्पाद है, जो उन्नत निष्पादन प्रदान करता है और उच्च कीमतें प्राप्त करता है। साथ ही, भारत में एचएओ एलएलडीपीई के लिए पर्याप्त मांग और आपूर्ति अंतराल है।
- xiv. बोरस्टार® एलएलडीपीई श्रेणियाँ "जिनका एमएफआई/एमएफआर 0.25 ग्राम/10मिनट या उससे कम है (एफबी2230, एफबी1200 और एफबी1350) स्वामित्व बोरस्टार® द्विबहुलकीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादित की जाती हैं। इनमें द्विबहुलकीय आणविक भार वितरण और निम्न गलन प्रवाह अनुपात के साथ उच्च आणविक भार होता है। ये भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं की जाती हैं।
- xv. इन श्रेणियों में उच्चतर यांत्रिक गुण होते हैं जो एक मैट फिनिश भी प्रदान करते हैं। यह अधिक मोटी फिल्म शीट, यानी 2 मिमी तक मोटाई के उत्पादन की भी अनुमति देता है। यह सब पारंपरिक एलएलडीपीई के उपयोग से संभव नहीं है। इसके अलावा, बोरस्टार® एलएलडीपीई श्रेणियाँ उत्कृष्ट मुद्रण पंजीकरण और स्पष्टता के साथ आसान लेखन की अनुमति देती हैं। यह आवश्यकता घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पारंपरिक एलएलडीपीई से पूरी नहीं होती।
- xvi. एलडीपीई जांच के विपरीत, अधिकतम घनत्व निर्धारित नहीं किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में शामिल एलएलडीपीई के अधिकतम घनत्व को स्पष्ट करना चाहिए।

ख.2 घरेलू उद्योग के विचार

5. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. किसी भी आयातक या उपयोगकर्ता ने उत्पाद बहिष्करण के संबंध में एक भी अनुरोध नहीं की है या यह आरोप नहीं लगाया है कि आवेदकों सहित घरेलू उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की गई श्रेणियाँ तुलनीय नहीं हैं या तकनीकी/वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।
- ii. हाल के मध्य पूर्व संकट के बाद से, भारतीय उत्पादक उपयोगकर्ता उद्योग के अनन्य आपूर्तिकर्ता रहे हैं और सभी श्रेणियों की भारतीय मांग को पूरा कर रहे हैं। इन तथ्यों में, कोई बहिष्करण उचित नहीं है।
- iii. सी-8 आधारित एलएलडीपीई और उच्च एल्फा ओलेफिन (एचएओ) आधारित एलएलडीपीई का बहिष्करण उचित नहीं है क्योंकि आवेदक उत्पादक सी4 और सी6 धातुसीन श्रेणियाँ निर्मित करते हैं, जो आनुपातिक रूप से मिश्रित होने पर, सी8 आधारित एलएलडीपीई से सीधे प्रतिस्पर्धा करती हैं।
- iv. स्टैंडअप पाउच, भारी शुल्क शिपिंग बोरे, तरल पाकिट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एलएलडीपीई किसी एकल एकलक आधारित एलएलडीपीई का उपयोग करके निर्मित नहीं किए जाते हैं। बल्कि, ब्यूटीन और अन्य श्रेणियों का संयोजन ऐसे उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है।
- v. भारतीय उद्योग भारत में आयात किए जा रहे सी6, सी8 एलएलडीपीई और उन्नत एलएलडीपीई के समरूप या उनसे सीधे प्रतिस्पर्धा करने वाली श्रेणियाँ निर्मित करता है। एचएमईएल ने सी6 आधारित एलएलडीपीई से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सी8 आधारित एलएलडीपीई का उत्पादन करता है।
- vi. एचपीएल विचाराधीन उत्पाद का यौगिकीकृत रूप में निर्माण करता है।
- vii. आवेदकों ने न केवल एलएलडीपीई का चूर्ण रूप निर्मित किया है बल्कि एलएलडीपीई का छर्चा रूप भी निर्मित किया है और जो सैबिक द्वारा निर्यात एलएलडीपीई के चूर्ण रूप से सीधे प्रतिस्पर्धा करता है।
- viii. सैबिक श्रेणियों एमजी200024 और एमजी500026 के बहिष्करण के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूर्ण रूप मास्टरबैच निर्माताओं द्वारा उपयोग किया जाता है, जो या तो चूर्ण रूप आयात करना और स्वयं योजक जोड़ना चुन सकते हैं या सीधे

- एलएलडीपीई के छर्चा रूप का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार, आवेदकों द्वारा बेचा गया एलएलडीपीई का छर्चा रूप सैबिक द्वारा निर्यात एलएलडीपीई के चूर्ण रूप से सीधे प्रतिस्पर्धा करता है।
- ix. सैबिक श्रेणियाँ 6821एनजे और 6318बीजे भारत में आयात नहीं की गई हैं और इसलिए, ऐसी श्रेणियों के बहिष्करण का प्रश्न ही नहीं उठता। इस तथ्य के बावजूद, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एचएमईएल समान और तुलनीय श्रेणियाँ उत्पादित करता है।
- x. एचएमईएल समान गुणों वाली समान श्रेणियाँ, 6821एनजे और 6318बी, विशेष रूप से तनन सामर्थ्य, जो सामान्यतः निर्धारक कारक है, उत्पादित करता है। इस प्रकार, यदि ये श्रेणियाँ आयात की जानी थीं, तो वे एचएमईएल द्वारा निर्मित की जा रही श्रेणियों से सीधे प्रतिस्पर्धा करेंगी।
- xi. जबकि एडीपीसीएल और बोरौज ने उत्पादों के बीच मामूली तकनीकी अंतर बताए हैं, यह स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि घरेलू रूप से उपलब्ध तुलनीय श्रेणियाँ वाणिज्यिक रूप से गैर-प्रतिस्थापनीय हैं।
- xii. अंतिम उत्पाद (फिल्म) की मैट या ग्लास फिनिश संबद्ध वस्तुओं का अंतर्निहित गुण नहीं है, बल्कि यह प्रसंस्कर्ता द्वारा वांछित फिनिश पर निर्भर करता है, और आवेदकों या अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग मैट-आधारित फिल्म बनाने के लिए भी किया जाता है।
- xiii. गलन प्रवाह सूचकांक ग्राहकों के संबद्ध वस्तुओं के उपयोग के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि आवेदक कंपनियों ने अपनी संबद्ध वस्तुएँ उन्हीं ग्राहकों को बेची हैं, जो आयातित और घरेलू उत्पादों का विनिमेय रूप से उपयोग करते हैं।
- xiv. स्वामित्व प्रौद्योगिकी बहिष्करण का आधार नहीं हो सकती जब भारतीय एलएलडीपीई उत्पादकों और बोरौज द्वारा निर्मित उत्पाद विनिमेय रूप से उपयोग किए जा रहे हों और एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हों।
- xv. धातुसीन और अन्य उच्च-निष्पादन-आधारित श्रेणियाँ वाणिज्यिक रूप से धातुसीन श्रेणियाँ कहलाती हैं, ऐसी श्रेणियों का तकनीकी नाम भिन्न हो सकता है क्योंकि "धातुसीन" एक्सॉन द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक अनन्य व्यापार चिह्न है।
- xvi. धातुसीन एलएलडीपीई या उच्च-निष्पादन एलएलडीपीई या तो धातुसीन उत्प्रेरकों या अन्य धातुसीन परिवार उत्प्रेरकों के माध्यम से निर्मित होते हैं और इसलिए, उन्हें धातुसीन श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

- xvii. अबू धाबी पॉलिमर्स कंपनी लिमिटेड और बोरौज द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धातुसीन श्रेणियाँ "एंटियो" नाम से व्यापारित होती हैं। इसी प्रकार, सदारा केमिकल्स ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति डॉवलेक्स 5400 जी जैसे नामों से करती है और उन्हें उच्च-निष्पादन एलएलडीपीई के रूप में वर्गीकृत करती है, जबकि सैबिक उन्हें सुपीर नाम से आपूर्ति करता है और उन्हें धातुसीन के रूप में उल्लेखित करता है।
- xviii. घरेलू उद्योग ने निष्पादन उन्नत श्रेणियों को धातुसीन श्रेणियों के साथ क्लब करने का अनुरोध किया था और किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की है।
- xix. प्राधिकारी को सत्यापित करना चाहिए कि क्या निर्यातकों ने अपने उत्पाद को उपयुक्त पीसीएन श्रेणी में सही ढंग से वर्गीकृत किया है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्च-निष्पादन या धातुसीन श्रेणियाँ धातुसीन श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत हों।
- xx. मांग मुख्यतः सी4 आधारित एलएलडीपीई की है जो कुल मांग और आयातों का 80-90% है। सी6 और सी8 आधारित एलएलडीपीई के गुण आवेदकों द्वारा निर्मित उत्पाद के समान ही हैं, विशिष्ट तकनीकी गुण सी4 आधारित एलएलडीपीई को उपयुक्त अनुपात में धातुसीन श्रेणियों के साथ संयोजित करके प्राप्त किए जा सकते हैं।
- xxi. घरेलू उद्योग, यद्यपि सी8-आधारित एलएलडीपीई का निर्माण नहीं करता, सी4 और सी6 धातुसीन श्रेणियाँ उत्पादित करता है, जो आनुपातिक रूप से संयोजित होने पर सी8 आधारित एलएलडीपीई के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अन्य घरेलू उत्पादक, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल है, जो भारतीय उद्योग का हिस्सा है और जांच में एक समर्थक है, वाणिज्यिक मात्रा में सी8-आधारित एलएलडीपीई का निर्माण और बिक्री करता है। एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार, घरेलू उद्योग में समान वस्तु के सभी घरेलू उत्पादक शामिल हैं, न कि केवल डीजीटीआर के समक्ष आवेदक। चूंकि पाटन रोधी शुल्कों का उद्देश्य संपूर्ण घरेलू उद्योग की रक्षा करना है, सी8-आधारित एलएलडीपीई को उत्पाद कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता।
- xxii. एलएलडीपीई का चूर्ण रूप एक मध्यवर्ती उत्पाद है जिसमें छर्रे बनाने के लिए योजक और वर्णक मिलाए जाते हैं। घरेलू उद्योग छर्रे के रूप में तुलनीय श्रेणियाँ निर्मित करता है, जो सैबिक द्वारा निर्यात चूर्ण रूप से सीधे प्रतिस्पर्धा करती हैं, क्योंकि मास्टरबैच निर्माता किसी भी रूप का उपयोग कर सकते हैं।

- xxiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि आवेदकों द्वारा निर्मित उत्पाद उच्च-निष्पादन अनुप्रयोग के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते। उक्त कथन अनिवार्य है। ऐसे अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले एलएलडीपीई एक एकल एकलक से नहीं बल्कि सी4 आधारित एलएलडीपीई और अन्य श्रेणियों जैसे आवेदकों द्वारा उत्पादित सी6 धातुसीन श्रेणी या अन्य भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्मित सी8 आधारित एलएलडीपीई के संयोजन से निर्मित होते हैं। इसलिए, आवेदकों द्वारा निर्मित वस्तुएँ अन्य उत्पादकों द्वारा निर्यात उत्पादों के साथ प्रतिस्थापनीय हैं।
- xxiv. कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि तुलनीय घरेलू श्रेणियाँ वाणिज्यिक रूप से गैर-प्रतिस्थापनीय हैं या मूल्य या लागत में भिन्न हैं। "समान वस्तु" की परिभाषा के अनुसार, वस्तुओं का समरूप होना आवश्यक नहीं है बल्कि समान विशेषताएँ होनी आवश्यक हैं। बोरौज की स्वामित्व प्रौद्योगिकी से निम्न गलन प्रवाह सूचकांक पर आधारित दावे अप्रासंगिक हैं, क्योंकि ऐसे उत्पाद और घरेलू वस्तुएँ एक ही ग्राहकों द्वारा विनिमेय रूप से उपयोग की जाती हैं।
- xxv. घरेलू उद्योग भारतीय मानक सीमा 908.4 से 940.4 किग्रा/घन मीटर के भीतर किसी भी घनत्व का एलएलडीपीई उत्पादित कर सकता है, जांच अवधि के दौरान आवेदकों ने 938 किग्रा/घन मीटर तक उत्पादन किया है और बिना किसी अतिरिक्त मशीनरी परिवर्तन के 940.4 किग्रा/घन मीटर तक पहुँचने में सक्षम हैं।
- xxvi. धातुसीन और गैर-धातुसीन श्रेणियों के बीच महत्वपूर्ण मूल्य अंतर मौजूद हैं। दोनों श्रेणियों को प्रारंभ में संबद्ध देशों से धातुसीन श्रेणियों के नगण्य आयातों के कारण पृथक नहीं किया गया था।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. 22 अगस्त 2025 की विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन पद्धति अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट किया गया विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में संदर्भित) रैखिक निम्न-घनत्व पॉलीएथिलीन है, जिसका घनत्व 908.4 से 940.4 किग्रा/घन मीटर है (इसके बाद "संबद्ध वस्तुएँ" भी कहा जाएगा)।

एलएलडीपीई एथिलीन और अन्य एल्कीनों जैसे ब्यूटीन, हेक्सीन या ऑक्टीन का एक सहबहुलक है। इसके परिणामस्वरूप एक अनिवार्यतः रेखिक श्रृंखला व्यवस्था होती है, जिसमें सहबहुलक (यानी ब्यूटीन, हेक्सीन या ऑक्टीन) मुख्य कार्बन रीढ़ पर छोटी, नियमित श्रृंखलाएँ बनाते हैं। यह एक रंगहीन, गैर-ज्वलनशील, गैर-अभिक्रियाशील ठोस है जिसमें कोई गंध नहीं होती। यह मुख्यतः प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जैसे पैकेजिंग फिल्म, प्रोफाइल, तार और केबल, बहिर्वेधन लेपन, घूर्णी ढाला उत्पाद, इंजेक्शन ढलाई के लिए उच्च-निम्न श्रेणियाँ, मास्टर बैच आदि।"

7. विचाराधीन उत्पाद अध्याय 39 "प्लास्टिक और इसके वस्तुएँ" के तहत एचएस कोड 3901 40 10 और 3901 10 10 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
8. इसके अतिरिक्त, धातुसीन और गैर-धातुसीन श्रेणियों के बीच मूल्य अंतर को संबोधित करने के लिए, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर निम्नलिखित पीसीएन अपनाए गए:

- क. **धातुसीन श्रेणियाँ:** धातुसीन उत्प्रेरक का उपयोग करके उत्पादित एलएलडीपीई श्रेणियाँ।
- ख. **गैर-धातुसीन श्रेणियाँ:** धातुसीन के अतिरिक्त अन्य उत्प्रेरकों का उपयोग करके उत्पादित पारंपरिक एलएलडीपीई श्रेणियाँ।

क्र.सं.	विवरण	श्रेणियाँ	कोड
1.	उत्प्रेरक के रूप में धातुसीन का उपयोग करके उत्पादित एलएलडीपीई श्रेणियाँ	धातुसीन श्रेणियाँ	एमपीजी
2.	धातुसीन के अतिरिक्त अन्य उत्प्रेरक का उपयोग करके उत्पादित पारंपरिक एलएलडीपीई श्रेणियाँ	गैर-धातुसीन श्रेणियाँ	एनएमजी

9. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति पर किए गए तर्कों की सावधानीपूर्वक जांच की गई। यह ध्यान दिया जाता है कि दावे मुख्यतः कुछ श्रेणियों के बहिष्करण के लिए इस आधार पर किए गए हैं कि घरेलू उद्योग कथित रूप से उनका

निर्माण नहीं कर रहा है या आवेदकों द्वारा उत्पादित श्रेणियाँ तकनीकी या वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने अनुरोधों का खंडन किया है और दावा किया है कि उनके द्वारा निर्मित उत्पाद उन्हीं अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। उन्होंने दावा किया है कि विभिन्न एकलकों के एलएलडीपीई को वांछित विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए आयातित उत्पादों के रूप में एक साथ संयोजित किया जा सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने प्रपत्र और तकनीकी आंकड़ा पत्रक प्रदान करके भारतीय बाजार में उनके द्वारा उत्पादित और बेची जा रही तुलनीय श्रेणियों का साक्ष्य प्रदान किया है।

10. **एलएलडीपीई के चूर्ण रूप का बहिष्करण:** चूर्ण श्रेणी एलएलडीपीई के बहिष्करण से संबंधित सैबिक की अनुरोधों के संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग भी एलएलडीपीई का चूर्ण रूप निर्मित करता है। घरेलू उद्योग ने एलएलडीपीई के चूर्ण रूप के बिक्री प्रपत्रों के रूप में साक्ष्य प्रदान किया है। आगे यह नोट किया जाता है कि एलएलडीपीई का चूर्ण रूप मुख्यतः यौगिकीकरण प्रक्रियाओं के लिए मास्टरबैच निर्माताओं द्वारा उपयोग किया जाता है जिसमें योजक और रंग वर्णक पिघलाए जाते हैं और फिर एलएलडीपीई में मिलाए जाते हैं, और बाद में एलएलडीपीई छर्ने निर्मित किए जाते हैं। इस प्रकार, एक उपयोगकर्ता के पास या तो यौगिकीकरण प्रक्रिया स्वयं करने का विकल्प होता है या वही एलएलडीपीई निर्माताओं द्वारा किया जा सकता है जो ऐसे उपयोगकर्ता के लिए सीधे एलएलडीपीई छर्ने निर्मित करते हैं। तदनुसार, चूंकि घरेलू उद्योग एलएलडीपीई का चूर्ण रूप निर्मित कर रहा है और चूंकि एलएलडीपीई का छर्ना और चूर्ण रूप केवल एलएलडीपीई के दो रूप हैं, प्राधिकारी उत्पाद कार्यक्षेत्र से एलएलडीपीई के चूर्ण रूप के बहिष्करण की अनुमति न देने का निर्णय करते हैं।
11. **उच्च एल्फा ओलेफिन ("एचएओ") आधारित एलएलडीपीई का बहिष्करण:** सैबिक समूह और सदारा के उच्च एल्फा ओलेफिन, अर्थात् सी6 और सी8 आधारित एलएलडीपीई के बहिष्करण के अनुरोध के संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग वास्तव में सी6 आधारित एलएलडीपीई का निर्माण कर रहा है। सी8 आधारित एलएलडीपीई के संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यद्यपि वह सी8 आधारित एलएलडीपीई का निर्माण नहीं करता, इसका उपयोग अन्य एलएलडीपीई एकलकों जैसे सी4 या सी6 के साथ संयोजन में किया जाता है और सी8 आधारित एलएलडीपीई द्वारा प्रदर्शित गुण सी4 और सी6 धातुसीन श्रेणियों के संयोजन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह ध्यान दिया जाता है कि किसी भी व्यक्तिगत उपयोगकर्ता ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और उपयोगकर्ता संघ, अखिल

भारतीय एचडीपीई/पीपी बुने कपड़े निर्माता संघ ने घरेलू उद्योग के इस दावे पर आपत्ति नहीं की है। आगे यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने भी घरेलू उद्योग के इस दावे का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है।

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सैबिक समूह ने सी8 आधारित एलएलडीपीई के बहिष्करण का अनुरोध इस आधार पर भी किया है कि घरेलू उद्योग ऐसी श्रेणियों का वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन और बिक्री नहीं कर रहा है। जबकि घरेलू उद्योग सी8 आधारित एलएलडीपीई का निर्माण नहीं करता, वह सी4 और सी6 श्रेणियाँ निर्मित करता है जिनके बारे में उसने दावा किया है कि कुछ अनुपातों में संयोजित होने पर वे आयातित सी8 आधारित एलएलडीपीई के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उक्त दावे का अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा खंडन नहीं किया गया है। आवेदक संघ ने सी8 आधारित एलएलडीपीई के लिए प्रपत्र भी प्रस्तुत किए हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वर्तमान जांच के समर्थक, द्वारा निर्मित और बेचा जा रहा है। समर्थक द्वारा सी8 आधारित एलएलडीपीई के उत्पादन के बावजूद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सी8 आधारित एलएलडीपीई के गुण सी4 और सी6 धातुसीन श्रेणियों के संयोजन से प्राप्त किए जा सकते हैं, और तदनुसार, उत्पाद कार्यक्षेत्र से सी8 आधारित एलएलडीपीई के बहिष्करण की अनुमति न देने का निर्णय करते हैं।
13. सदारा के इस तर्क के संबंध में कि भारत में सी6 आधारित एलएलडीपीई के लिए महत्वपूर्ण मांग आपूर्ति अंतराल मौजूद है और घरेलू उद्योग ने इस तर्क का खंडन नहीं किया है या श्रेणी वार उत्पादन या मांग आंकड़े प्रदान नहीं किए हैं, यह ध्यान दिया जाता है कि उत्पाद कार्यक्षेत्र से बहिष्करण का प्रश्न भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसका निर्णय इस आधार पर किया जाता है कि क्या घरेलू उद्योग भारत में आयात की जा रही वस्तुओं के समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री कर रहा है।
14. **6821एनजे और 6318बीजे श्रेणियों का बहिष्करण:** सैबिक समूह के श्रेणियों 6821एनजे और 6318बीजे के बहिष्करण अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्वीकार्य रूप से ये श्रेणियाँ भारत को निर्यात नहीं की गई हैं। आगे यह नोट किया जाता है कि सैबिक समूह ने मुख्य रूप से इस आधार पर इन वस्तुओं के बहिष्करण का अनुरोध किया है कि सैबिक श्रेणियों में उच्चतर विदारण सामर्थ्य है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने उनके द्वारा बेची गई

तुलनीय श्रेणियों का साक्ष्य प्रदान किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) को याद करते हैं जो कहता है:

“समान वस्तु” से तात्पर्य ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटित की जाने की जांचाधीन वस्तु के सभी पहलुओं में समरूप या समान है या ऐसी वस्तु की अनुपस्थिति में, कोई अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी पहलुओं में समान नहीं है, फिर भी जांचाधीन वस्तुओं से मिलती-जुलती विशेषताएँ रखती है”

15. उपरोक्त परिभाषा से यह नोट किया जाता है कि दो उत्पादों को एक-दूसरे के समान वस्तु तब माना जा सकता है, न केवल जब वे सभी पहलुओं में समरूप या समान हों बल्कि तब भी जब ऐसी वस्तुओं में मिलती-जुलती विशेषताएँ हों। वर्तमान मामले में, सैबिक श्रेणियों और घरेलू रूप से उत्पादित तुलनीय श्रेणियों दोनों में उच्च विदारण सामर्थ्य है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि इन श्रेणियों का विदारण सामर्थ्य भिन्न है, ऐसा अंतर अपने आप में उत्पादों को एक-दूसरे के समान वस्तु नहीं बनाता। आगे यह नोट किया जाता है कि विदारण सामर्थ्य फिल्म की मोटाई पर भी निर्भर करता है। आगे यह नोट किया जाता है कि ये श्रेणियाँ भारत में आयात नहीं की गई हैं क्योंकि भारत में इन उत्पादों की मांग मौजूद नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी सैबिक श्रेणियों 6821एनजे और 6318बीजे को बाहर न करने का निर्णय करते हैं।
16. बोरस्टार श्रेणियों का बहिष्करण: द्विबहुलकीय बोरस्टार प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्मित बोरस्टार श्रेणियों (एफबी2230, एफबी1200 और एफबी1350) के बहिष्करण के संबंध में, एडीपीसीएल ने तर्क दिया है कि इन श्रेणियों में उच्च आणविक भार और निम्न गलन प्रवाह दर (0.25 ग्राम/10 मिनट से कम या बराबर) है और घरेलू उद्योग 1 ग्राम/10 मिनट से कम गलन प्रवाह दर वाली संबद्ध वस्तुओं का निर्माण नहीं करता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह आवश्यक नहीं है कि दो उत्पाद सभी पहलुओं में समान हों। निम्न गलन प्रवाह सूचकांक के अलावा, एडीपीसीएल द्वारा निर्यात की गई संबद्ध वस्तुएँ और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएँ मिलती-जुलती विशेषताएँ रखती हैं। तदनुसार, निम्न गलन प्रवाह सूचकांक को बहिष्करण का आधार नहीं माना जा सकता। आगे यह नोट किया जाता है कि प्रत्येक उत्पादक के पास ऐसी प्रौद्योगिकी के लाइसेंस पर निर्भर करते हुए उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली भिन्न उत्पादन प्रौद्योगिकी हो सकती है। तथापि, जब तक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया विशिष्ट भौतिक/रासायनिक विशेषताओं की ओर ले जाने वाला कोई गुण

प्रदान नहीं करती, उत्पादन प्रक्रिया में अंतर अपने आप में किसी उत्पाद के बहिष्करण का आधार नहीं बन सकता। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एडीपीसीएल ने यह स्थापित करने वाला कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि एडीपीसीएल द्वारा उत्पादित एलएलडीपीई और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एलएलडीपीई वाणिज्यिक या तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।

17. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि एडीपीसीएल ने अपने इस दावे को प्रमाणित करने के लिए कुछ घरेलू उपयोगकर्ताओं से पत्र प्रस्तुत किए हैं कि बोरस्टार श्रेणियों का एक विशिष्ट अंतिम उपयोग अनुप्रयोग है और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुएँ तकनीकी रूप से उसका प्रतिस्थापन नहीं कर सकतीं। यह ध्यान दिया जाता है कि इनमें से किसी भी उपयोगकर्ता ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। उनके द्वारा प्रदान किए गए पत्रों में सामान्य सूचना और समान वाक्य और शब्दावली है। आगे यह नोट किया जाता है कि ये सभी पत्र विशेष रूप से पारंपरिक सी4 आधारित एलएलडीपीई के साथ तुलना पर भरोसा करते हैं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए अन्य एलएलडीपीई की गुणवत्ता या विशेषताओं को संबोधित नहीं करते। जबकि, एडीपीसीएल द्वारा अपनी अनुरोधों के भाग के रूप में प्रदान किया गया प्रदर्श 3 धातुसीन और गैर-धातुसीन आधारित एलएलडीपीई दोनों के लिए ऐसी विशेषताओं का उल्लेख करता है न कि केवल पारंपरिक एलएलडीपीई के लिए। तदनुसार, प्राधिकारी एडीपीसीएल के दावे से असहमत हैं और बोरस्टार श्रेणियों को बाहर न करने का निर्णय करते हैं।
18. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएँ भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन, वस्तुओं के वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि भारत में आयात की जा रही संबद्ध वस्तुएँ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समरूप हैं। पाटित किए गए आयातों और आवेदकों द्वारा निर्मित वस्तुओं की तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, कार्यों या अंतिम-उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएँ और आयातित वस्तुएँ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और तदनुसार, प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के तहत इन उत्पादों को 'समान वस्तु' मानने का विचार करते हैं।

ग. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और स्थिति

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. याचिका में नियम 2(ख) और एडी समझौते के अनुच्छेद 5.2 के तहत अपेक्षित जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए क्षति का अपर्याप्त साक्ष्य है और तदनुसार इसे शुरू नहीं किया जाना चाहिए था।
- ii. आवेदक ने कुल घरेलू उत्पादन के लिए वास्तविक आंकड़ों पर नहीं बल्कि अनुमानित आंकड़ों पर भरोसा किया है। यदि वास्तविक आंकड़ों पर विचार किया जाए, तो आवेदक स्थिति आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है।
- iii. ओपीएएल पेट्रो एडिशनल्स लिमिटेड ("ओपीएएल") को जांच अवधि के दौरान एक विशेष आर्थिक क्षेत्र ("एसईजेड") इकाई होने के आधार पर बाहर रखने के कारण आवेदक की स्थिति दूषित है। एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) या नियम 5 में केवल एसईजेड इकाई होने के आधार पर किसी उत्पादक को बाहर रखना अनिवार्य नहीं है। यदि ओपीएएल को एक पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में शामिल किया जाता है, तो एचपीएल और एचएमईएल नियम 5(3) की आवश्यकता को पूरा नहीं करेंगे।
- iv. ओपीएएल का कुल घरेलू उत्पादन से बहिष्करण पर्याप्त औचित्य के बिना है क्योंकि यह 08 मार्च, 2025 को एसईजेड से बाहर हो गया था, और आवेदक द्वारा आवेदन दाखिल करने के समय घरेलू शुल्क क्षेत्र का हिस्सा था।
- v. चाहे ओपीएएल एसईजेड में कार्य कर रहा था या नहीं, इसके उत्पादन को कुल घरेलू उत्पादन में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह भारत में स्थापित है और जांच अवधि के दौरान इसने अपना लगभग 85-90% एलएलडीपीई भारतीय घरेलू बाजार में बेचा।
- vi. ओपीएएल का बहिष्करण कृत्रिम रूप से कुल पात्र उत्पादन को कम करता है और इस प्रकार, कुल घरेलू उत्पादन में एचपीएल और एचएमईएल के हिस्से को बढ़ाता है।
- vii. ओपीएएल की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान की गई सूचना के आधार पर, यदि ओपीएएल का उत्पादन शामिल किया जाता है, तो एचपीएल और एचएमईएल का हिस्सा एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के तहत निर्धारित 25% की सीमा से नीचे गिर जाएगा। तदनुसार, एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) की पूर्ति के संबंध में

- किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, प्राधिकारी को सभी प्रासंगिक घरेलू उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री की मात्रा का सत्यापन करना चाहिए।
- viii. ओपीएल को उसकी एसईजेड स्थिति के आधार पर बाहर करने का प्रयास करके, आवेदक प्रभावी रूप से इस आर्थिक वास्तविकता की अवहेलना करता है कि ओपीएल भारत में स्थापित एक उत्पादक है जो घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पर्याप्त उत्पादन और बिक्री करता है।
- ix. प्राधिकारी ने पिछली जांचों (विद्युत इन्सुलेटर और सौर सेल) में एसईजेड इकाइयों को घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने के योग्य माना है।
- x. यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय प्रथा के भी अनुरूप है। यूएसआईटीसी ने बड़े आवासीय वाशर में क्षति निर्धारण के संदर्भ में विदेशी व्यापार क्षेत्रों में उत्पादन को घरेलू उत्पादन माना। इसी प्रकार, यूएसआईटीसी ने जापान से माइक्रोवेव ओवन में मुक्त व्यापार क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुएँ माना। जबकि ये निष्कर्ष क्षति विश्लेषण के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे न कि स्थिति के, अंतर्निहित सिद्धांत समान बने रहते हैं।
- xi. यूरोपीय आयोग सामान्यतः स्थिति के निर्धारण और घरेलू उद्योग की परिभाषा के लिए मुक्त क्षेत्रों में कार्यरत उत्पादकों को घरेलू उत्पादक मानता है। मुक्त क्षेत्र संघ सीमा शुल्क संहिता के अनुच्छेद 243(1) के अनुसरण में यूरोपीय संघ के राज्यक्षेत्र का भाग हैं।
- xii. एसईजेड ढांचा घरेलू शुल्क क्षेत्र बिक्री पर रोक नहीं लगाता। एसईजेड में कार्यरत इकाइयों को लागू शर्तों, जिनमें शुल्क और समग्र निवल विदेशी मुद्रा ("एनएफई") आवश्यकताएँ शामिल हैं, के अधीन घरेलू बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति करने की अनुमति है। महत्वपूर्ण रूप से, सकारात्मक एनएफई बनाए रखने की आवश्यकता इकाई के समग्र परिचालन निष्पादन से संबंधित है और घरेलू बिक्री के तथ्य को नकारती या प्रतिबंधित नहीं करती। तदनुसार, केवल यह तथ्य कि कोई उत्पादक एसईजेड के भीतर कार्य करता है, उसे घरेलू उद्योग से बाहर करने का आधार नहीं हो सकता जहाँ वह घरेलू बाजार में पर्याप्त बिक्री करता है।
- xiii. चूंकि एचपीएल और एचएमईएल घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि नहीं हैं और कुल भारतीय उत्पादन का 25% भी नहीं हैं (यदि ओपीएल उत्पादन शामिल किया जाए), प्राधिकारी को याचिका अस्वीकार कर देनी चाहिए थी।

- xiv. एचपीएल और एचएमईएल का घरेलू बिक्री (ओपीएल को छोड़कर) में 26.33% हिस्सा है, जबकि स्वयं ओपीएल की महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमता है, जो इंगित करता है कि इसका समावेश स्थिति विश्लेषण को भौतिक रूप से बदल देगा।
- xv. भारतीय एलएलडीपीई उद्योग खंडित नहीं है और इसलिए, 25-35% का हिस्सा प्रमुख अनुपात माने जाने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसा अनुपात स्वतः प्रमुख अनुपात की आवश्यकता को संतुष्ट नहीं करता। अधिक जानकारी प्राप्त करने में कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं है, और इसलिए, आवेदन को अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- xvi. एचपीएल और एचएमईएल की स्थिति अपीलीय निकाय द्वारा ईसी - फास्टनर में निर्धारित मानक से काफी नीचे आती है, विशेष रूप से जब ओपीएल के साथ-साथ अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन को ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा, यदि अन्य भारतीय उत्पादकों के आंकड़ों पर विचार किया जाए, तो क्षति मापदंडों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा।
- xvii. यदि प्राधिकारी घरेलू उद्योग की प्रस्तावित परिभाषा को उत्पादकों के सीमित उपसमुच्चय के रूप में स्वीकार करता है, तो वह प्रासंगिक भारतीय उद्योग के 20% से कम के एक अल्प और स्व-चयनित अनुपात के विरुद्ध क्षति का आकलन करेगा, जिससे विरूपण का भौतिक जोखिम उत्पन्न होगा और क्षति विश्लेषण तिरछा हो जाएगा, विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के अन्य प्रमुख उत्पादकों के पास उत्पादन के बहुत बड़े हिस्से को देखते हुए।
- xviii. घरेलू उद्योग के उत्पादन का हिस्सा "कुल घरेलू उत्पादन का पर्याप्त प्रतिबिंब" होना चाहिए ताकि "घरेलू उद्योग" की परिभाषा क्षति निर्धारण को तिरछा या विकृत न करे।
- xix. पाटन रोधी शुल्क का उद्देश्य और लक्ष्य समग्र रूप से घरेलू उद्योग या उन उत्पादकों की रक्षा करना है जो भारतीय उत्पादन में अपने पर्याप्त/प्रमुख हिस्से के कारण घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि हैं। पाटन रोधी शुल्क चुनिंदा कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए नहीं लगाया जा सकता।
- xx. प्राधिकारी ने उचित रूप से यह निर्धारित करने में विफल रहा है कि आवेदन एडी नियमों के नियम 5(3) के तहत अपेक्षित "घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से" दायर किया गया है।
- xxi. ईसी - फास्टनर में अपीलीय निकाय ने इस बात पर जोर दिया कि "एक प्रमुख अनुपात" को समग्र रूप से सभी उत्पादकों के प्रकाश में मूल्यांकित कुल घरेलू

- उत्पादन के अपेक्षाकृत उच्च और वास्तविक रूप से प्रतिनिधि हिस्से का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इसने ईयू के 27% और यहाँ तक कि 36% जैसे निम्न हिस्सों पर भरोसा करने को अस्वीकार कर दिया, यह निर्णय देते हुए कि ऐसे स्तर (विशेष रूप से जब स्व-चयनित या गैर-प्रतिनिधि नमूने से प्राप्त हों) मानक को पूरा नहीं करते और क्षति विश्लेषण को विकृत करते हैं।
- xxii. आवेदक एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के तहत प्रमुख अनुपात की पृथक आवश्यकता को संतुष्ट नहीं करते। एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के तहत आवेदन करने के लिए न्यूनतम सीमा को नियम 2(ख) तक विस्तारित नहीं किया जा सकता।
- xxiii. नियम 2(ख) में "प्रमुख अनुपात" की आवश्यकता नियम 5(3) के तहत 25% की सीमा से भिन्न और अतिरिक्त है। यदि प्रत्येक मामले में 25-30% के न्यूनतम हिस्से को पर्याप्त मान लिया जाए, तो नियम 2(ख) में पृथक आवश्यकता निरर्थक हो जाती है।
- xxiv. संचालन प्रथाओं की नियमावली का पैरा 4.9.11(iii) एक पूर्ण नियम नहीं बनाता कि प्रत्येक उत्पादक या उत्पादकों का समूह जो केवल 25% की न्यूनतम सीमा को पार करता है, उसे कुल घरेलू उत्पादन का "प्रमुख अनुपात" माना जाना चाहिए।
- xxv. ईसी - फास्टनर में विश्व व्यापार संगठन अपीलीय निकाय ने एडी समझौते के अनुच्छेद 5.4 के तहत स्थिति का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए 25% की सीमा आवश्यकता को "प्रमुख अनुपात" की आवश्यकता के साथ समान करने को अस्वीकार कर दिया और इसे एडी समझौते के अनुच्छेद 4.1 के तहत "घरेलू उद्योग" का पता लगाने के लिए अप्रासंगिक माना।
- xxvi. अपीलीय निकाय ने समझाया कि "एक प्रमुख अनुपात" को समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों के कुल उत्पादन के संदर्भ में परिभाषित अनुपात के रूप में समझा जाना चाहिए। ऐसे कुल उत्पादन का "एक प्रमुख अनुपात" मानक रूप से कुल घरेलू उत्पादन का पर्याप्त प्रतिबिंब होगा।
- xxvii. वास्तव में, अनुपात जितना कम होगा, एक जांच प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए उतना ही अधिक संवेदनशील होना होगा कि उपयोग किया गया अनुपात समग्र रूप से उत्पादकों के कुल उत्पादन को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करता है।
- xxviii. जबकि "प्रमुख अनुपात" क्या है इसके लिए कोई कठोर संख्यात्मक सीमा नहीं है, इस वाक्यांश को कुल घरेलू उत्पादन के "महत्वपूर्ण, गंभीर या सार्थक" अनुपात को इंगित करने के लिए समझा गया है। इस प्रकार, कुल उत्पादन का हिस्सा "कुल घरेलू

- उत्पादन का पर्याप्त प्रतिबिंब" होना चाहिए ताकि "घरेलू उद्योग" की परिभाषा क्षति निर्धारण को तिरछा या विकृत न करे।
- xxix. ईसी - फास्टनर (चीन) (अनुच्छेद 21.5) में अपीलीय निकाय ने निर्णय दिया कि कुल घरेलू उत्पादन का 36% का अनुपात भी, खंडित फास्टनर उद्योग के संदर्भ में, निम्न बना रहता है।
- xxx. प्राधिकारी को आगे बढ़ने से पहले जांच अवधि के लिए सभी प्रमुख घरेलू उत्पादकों से पूर्ण और सत्यापित आंकड़े मंगाने चाहिए। आवेदक का दावा उद्योग के एक सीमित खंड पर आधारित है, जबकि भारत की कुल क्षमता के पर्याप्त हिस्से वाले उत्पादकों ने क्षति के किसी आरोप का समर्थन नहीं किया है।
- xxxi. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई सूचना अपर्याप्त है क्योंकि यह 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना संख्या 05/2021 में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती।
- xxxii. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी स्थापित क्षमता, घरेलू और निर्यात बिक्री के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा है और तदनुसार, इसका सत्यापन नहीं किया जा सकता। भले ही बाद में साक्ष्य प्रदान किया गया हो, जांच शुरू करने के चरण में सूचना अपर्याप्त बनी रहती है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- xxxiii. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आंकड़ा अपर्याप्त और डुप्लिकेट प्रविष्टियों के साथ असंगत है, जो इसे अविश्वसनीय बनाता है।
- xxxiv. अद्यतन समर्थन पत्र का बाद में दाखिल किया जाना मूलभूत दोष को ठीक नहीं कर सकता। आवेदक ने परिवर्तनों का पारदर्शी रूप से खुलासा नहीं किया।
- xxxv. आवेदक ने अपने आवरण पत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समर्थन पत्र में किए गए परिवर्तनों की स्पष्ट रूप से पहचान नहीं की।
- xxxvi. याचिका में दावा किया गया है कि एलएलडीपीई के अन्य भारतीय उत्पादकों ने आवेदन का समर्थन किया है, तथापि, इनमें से किसी भी उत्पादक ने व्यापार सूचना 05/2021 के अनुसार समर्थन पत्र दाखिल नहीं किया है।
- xxxvii. प्राधिकारी को याचिका में उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद के अन्य स्थापित भारतीय उत्पादकों, अर्थात् रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईओसीएल, गेल, बीसीपीएल और ओपीएएल से क्षति और लागत आंकड़े मंगाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी क्षति आकलन समग्र रूप से घरेलू उद्योग का प्रतिनिधि हो और इस मामले में केवल एचएमईएल जैसे कुछ उत्पादकों को शामिल करने से तिरछा न हो।

- xxxviii. अन्य स्थापित खिलाड़ियों की भागीदारी के अभाव में, प्राधिकारी यह आकलन नहीं कर सकता कि ऐसे खिलाड़ी लाभ कमा रहे हैं या हानि उठा रहे हैं। प्राधिकारी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से कम से कम उनकी लाभप्रदता के आंकड़े प्रदान करने के लिए कहना चाहिए।
- xxxix. प्राधिकारी ने पिछली जांचों जैसे 6मिमी और उससे अधिक मोटाई वाले सादे मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड (एमडीएफ) में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित किसी अन्य उत्पादक से क्षति और लागत संबंधी आंकड़े मंगाए थे।
- xi. भारत के सबसे बड़े उत्पादकों से किसी भी सूचना की अनुपस्थिति का केवल यही अर्थ लगाया जा सकता है कि वे संबद्ध आयातों के कारण किसी क्षति का सामना नहीं कर रहे हैं, और उनकी गैर-भागीदारी का तात्पर्य है कि वे क्षति नहीं झेल रहे हैं।
- xli. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आईओसीएल व्यापार उपचारात्मक उपायों के नियमित उपयोगकर्ता हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईओसीएल, गेल, बीसीपीएल और ओपीएल के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी को यह मानना चाहिए कि एलएलडीपीई के ये घरेलू उत्पादक पाटन रोधी उपाय लगाए जाने के विरोधी हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

20. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- वर्तमान जांच के लिए क्षति की जानकारी एचपीएल और एचएमईएल द्वारा प्रदान की गई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सह-आवेदकों के अलावा, एलएलडीपीई के 5 अन्य उत्पादक हैं, यथा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड और ओएनजीसी-पेट्रो एडिशनस लिमिटेड। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जांच अवधि और क्षति अवधि के दौरान, ओएनजीसी-पेट्रो एडिशनस लिमिटेड एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई के रूप में कार्यरत था और इसलिए इसे घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता था।
 - डीजीटीआर की संचालन प्रथाओं की नियमावली के पैरा 4.19.21 और 4.19.23, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं कि एसईजेड में स्थित इकाइयों को "घरेलू उद्योग नहीं माना जाएगा" और "देश के कुल उत्पादन का अनुमान लगाते समय एसईजेड के उत्पादन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए"।

- iii. प्राधिकारी ने कई हाल के मामलों जैसे सौर सेल, औद्योगिक लेजर मशीनों में एसईजेड आधारित इकाइयों को अपात्र घरेलू उत्पादक माना है और एसईजेड आधारित उत्पादकों की बिक्री को भारत में आयात माना है।
- iv. एचपीएल और एचएमईएल का भारत में कुल एलएलडीपीई उत्पादन का लगभग 25%-35% हिस्सा है। इस प्रकार, एचपीएल और एचएमईएल का उत्पादन एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार भारत में कुल घरेलू उत्पादन का "प्रमुख अनुपात" है। आवेदक प्रस्तुत करते हैं कि कुल पात्र घरेलू उत्पादन के 25% से अधिक उत्पादन को "प्रमुख अनुपात" मानना प्राधिकारी की प्रथा है। इस संबंध में, आवेदक प्रमुख अनुपात के परीक्षण से संबंधित डीजीटीआर की मानक संचालन प्रथाओं की नियमावली के पैरा 4.9.11 (iii) में दी गई व्याख्या पर भरोसा करते हैं।
- v. जैसा कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया गया, ओपीएएल 08 मार्च, 2025 को, जांच अवधि की समाप्ति के 2 महीने बाद, एसईजेड से बाहर हुआ। इस प्रकार, ओपीएएल का घरेलू शुल्क क्षेत्र में प्रवेश जांच अवधि के पश्चात पूर्ण हुआ।
- vi. यह प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा है कि जांच अवधि के दौरान किए गए उत्पादन के आधार पर कुल पात्र घरेलू उत्पादन का आकलन किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे पाटन और क्षति जांच अवधि पश्चात के तथ्य पर आधारित नहीं होते।
- vii. ईसी - फास्टनर में, यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ में लगभग 318 ज्ञात उत्पादकों को प्रश्नावली जारी की थी, जिनमें से केवल 70 उत्पादकों ने उत्तर दिया। इन 70 उत्पादकों में से, आयोग ने 25 उत्पादकों की प्रतिक्रियाओं को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वे पर्याप्त सूचना प्रदान करने में विफल रहे थे।
- viii. इसलिए, आयोग ने अंततः शेष 45 उत्पादकों के आधार पर परिभाषित किया, जिससे घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र केवल उन उत्पादकों तक सीमित हो गया जो नमूने में शामिल होने के इच्छुक थे और कुछ ऐसे उत्पादकों को बाहर कर दिया जिन्होंने अन्यथा प्रासंगिक सूचना प्रदान की थी, इस प्रकार क्षति विश्लेषण में भौतिक विरूपण का जोखिम उत्पन्न हुआ।
- ix. इसके अलावा, यूरोपीय आयोग ने संबद्ध वस्तुओं के कुल संघ उत्पादन के केवल 17.6% का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 घरेलू उत्पादकों का एक नमूना चुना। इससे क्षति विश्लेषण के लिए उपलब्ध आंकड़ा कवरेज काफी सीमित हो गया।
- x. इस प्रकार, ईसी - फास्टनर का निर्णय ऐसी स्थिति में दिया गया जहाँ प्रासंगिक उत्पादकों को पद्धतिगत रूप से बाहर रखा गया था और नमूना कुल उत्पादन के केवल सीमित अनुपात का प्रतिनिधित्व करता था।

- xi. ईसी - फास्टनर में अपीलीय निकाय ने न्यूनतम सीमा प्रदान करने से परहेज किया लेकिन मुख्य रूप से इस आधार पर आगे बढ़ा कि जांच प्राधिकारियों को स्व-चयन प्रक्रिया के माध्यम से घरेलू उत्पादकों को बाहर नहीं करना चाहिए, जिससे आंकड़ा कवरेज कम होगा और जिससे क्षति विश्लेषण में विरूपण का भौतिक जोखिम उत्पन्न होगा।
- xii. यह प्रस्तुत किया जाता है कि न तो विश्व व्यापार संगठन का पाटन रोधी समझौता और न ही भारतीय नगरपालिका कानून "प्रमुख अनुपात" निर्धारित करने के लिए कोई सीमा प्रदान करते हैं।
- xiii. ईसी-फास्टनर के तथ्यों के विपरीत, जहाँ नमूना चयनित घरेलू उत्पादक कुल घरेलू उत्पादन का केवल 17.6% थे, वर्तमान जांच में, एचपीएल और एचएमईएल का भारत में कुल एलएलडीपीई उत्पादन का लगभग 25-35% हिस्सा है।
- xiv. प्राधिकारी ने प्रथा के रूप में, जैसा कि डीजीटीआर की मानक संचालन प्रथाओं की नियमावली के पैरा 4.9.11 (iii) में समझाया गया है, एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार 25% से अधिक उत्पादन को "प्रमुख अनुपात" माना है।
- xv. एलएलडीपीई के 3 सबसे बड़े उत्पादक, जो भारतीय एलएलडीपीई उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा रखते हैं, ने भाग लिया है और समष्टि आर्थिक और मूल्य आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।
- xvi. आवेदकों ने अन्य भारतीय उत्पादकों के लिए अनुमानित बिक्री और मात्रात्मक मापदंड भी प्रदान किए हैं। तदनुसार, वर्तमान जांच में "क्षति निर्धारण को विकृत करने का भौतिक जोखिम उत्पन्न करने" का प्रश्न नहीं उठता।
- xvii. आवेदन को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आगे समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसने लागू व्यापार सूचनाओं के तहत आवश्यक समर्थक आंकड़े प्रदान किए हैं।
- xviii. सीईएसटीएटी ने लुब्रिजोल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्राधिकारी 2005 (7) टीएमआई 132 में, "प्रमुख अनुपात" शब्द की व्याख्या करते हुए कुल घरेलू उत्पादन के 31% के उत्पादन को प्रमुख अनुपात माना। इसने आगे कहा कि "कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख अनुपात" को तुलनात्मक माप या संपूर्ण के विभिन्न भागों के आकार को शामिल करने वाले गणितीय योग को हल करने के कोण से नहीं देखा जा सकता"।
- xix. प्राधिकारी ने अपने कई पिछले निष्कर्षों (13.08.2025 दिनांकित मिश्रधातु या गैर-मिश्रधातु इस्पात के तप्त वेल्लित फ्लैट उत्पाद) में "प्रमुख अनुपात" की व्याख्या कुल

- घरेलू उत्पादन के 50% से अधिक उत्पादन के रूप में करने से इनकार किया है और इसे महत्वपूर्ण अनुपात के रूप में अर्थ लगाया है।
- xx. प्राधिकारी ने कई जांचों में कुल घरेलू उत्पादन के 25-35% प्रतिशत वाले घरेलू उत्पादकों को एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग माना है। पीवीसी निलंबन श्रेणी रेजिन (सूर्यास्त समीक्षा) में, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन का 30% रखने वाले उत्पादकों को प्रमुख अनुपात माना था।
- xxi. घरेलू उद्योग प्रस्तुत करता है कि उसे अन्य घरेलू उत्पादकों से आंकड़े मंगाने पर कोई आपत्ति या हिचक नहीं है। तथापि, ऐसे उत्पादकों की वर्तमान जांच में गैर-भागीदारी प्राधिकारी के समक्ष घरेलू उद्योग को राहत देने से इनकार करने का आधार नहीं बननी चाहिए।
- xxii. प्राधिकारी जांच प्रक्रिया के भाग के रूप में सभी उत्पादकों से आंकड़े मंगाने हैं। तथापि, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को छोड़कर किसी अन्य घरेलू उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया है।
- xxiii. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समर्थन पत्र का गोपनीय संस्करण जांच शुरू करने के चरण से पहले आवेदन के साथ अभिलेख पर दाखिल किया गया था जिसमें माप की सभी इकाइयाँ और बिक्री का विवरण लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे पत्र में स्पष्ट रूप से पहचाना गया था।
- xxiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आग्रह किए गए तथ्यों के विपरीत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गोपनीय समर्थन पत्र में कोई अद्यतन नहीं किया गया है।
- xxv. घरेलू उद्योग एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार प्रमुख अनुपात का गठन करता है और इसलिए, अन्य घरेलू उत्पादकों की गैर-भागीदारी प्राधिकारी को अपने समक्ष घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच करने से नहीं रोकती।
- xxvi. आवेदन सीपीएमए द्वारा भारतीय एलएलडीपीई उत्पादकों की ओर से दायर किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहले ही प्राधिकारी के पास अपना समर्थन पत्र दाखिल कर चुका है। इसके अलावा, सीपीएमए के अन्य सदस्यों, आईओसीएल और गेल ने भी संबद्ध देशों के विरुद्ध उपयुक्त व्यापार उपचारात्मक कार्यवाहियाँ चलाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रकार, भारतीय एलएलडीपीई उत्पादकों ने क्षति के आरोप का समर्थन किया है। इसके अलावा, जांच शुरू होने के बाद किसी भी घरेलू उत्पादक की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. एडी नियमावली, 1995 का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को नीचे बताए अनुसार परिभाषित करता है:

'घरेलू उद्योग' से तात्पर्य समान वस्तु के निर्माण और उससे जुड़ी किसी गतिविधि में लगे समय रूप से घरेलू उत्पादक या वे जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात है, सिवाय इसके जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित की गई वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों के रूप में लगाया जा सकता है।

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन सीपीएमए द्वारा भारतीय एलएलडीपीई उद्योग की ओर से दायर किया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित चिंताएँ उठाई हैं:

- क. ओपीएएल को कुल पात्र घरेलू उत्पादन के कार्यक्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए था
- ख. हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड घरेलू उद्योग के प्रमुख अनुपात का प्रतिनिधित्व नहीं करते

क. ओपीएएल को कुल पात्र घरेलू उत्पादन के कार्यक्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए था

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि ओपीएएल, एसईजेड इकाई होने के बावजूद, भारत में स्थित एक एलएलडीपीई उत्पादक है और तदनुसार, घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में ओपीएएल को कुल पात्र घरेलू उत्पादन की गणना से गलत तरीके से बाहर रखा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अन्य अधिकारिताएँ मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थित उत्पादकों को कुल पात्र घरेलू उत्पादन के कार्यक्षेत्र में मानती हैं। इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि यदि ओपीएएल को कुल पात्र घरेलू उत्पादन के कार्यक्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो एचपीएल और एचएमईएल का उत्पादन एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के तहत आवेदक के रूप में योग्य होने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

24. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसईजेड अधिनियम, 2005 की योजना स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि एसईजेड इकाइयाँ प्राधिकृत प्रचालनों के लिए भारत के सीमा शुल्क राज्यक्षेत्र के बाहर के राज्यक्षेत्र मानी जाती हैं और मूलतः निर्यात-उन्मुख संस्थाएँ हैं। प्राधिकारी पहले ही पूर्व कार्यवाहियों में इस मुद्दे की विस्तार से जांच कर चुके हैं और यह मान्यता दी है कि एसईजेड इकाइयाँ घरेलू शुल्क क्षेत्र ("डीटीए") में कार्यरत उत्पादकों की तुलना में एक भिन्न कानूनी और आर्थिक आधार पर खड़ी हैं।
25. इसके अलावा, प्राधिकारी एसईजेड अधिनियम की धारा 53 को याद करते हैं जो स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि किसी एसईजेड को प्राधिकृत प्रचालन करने के प्रयोजनों के लिए भारत के सीमा शुल्क राज्यक्षेत्र के बाहर का राज्यक्षेत्र माना जाएगा। इसके अलावा, एसईजेड अधिनियम की धारा 2(i) एसईजेड क्षेत्रों को "घरेलू शुल्क क्षेत्र" की परिभाषा से बाहर करती है। डीटीए इकाइयों से एसईजेड इकाइयों को आपूर्ति "निर्यात" मानी जाती है, और एसईजेड इकाइयों से डीटीए इकाइयों को वस्तुओं की आपूर्ति पर एसईजेड अधिनियम की धारा 30 के तहत सीमा शुल्क, जिसमें पाटन रोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क शामिल हैं, लगते हैं। इसलिए कानूनी ढांचा जानबूझकर एसईजेड इकाइयों और डीटीए उत्पादकों के बीच एक आर्थिक और सीमा शुल्क भेद उत्पन्न करता है।
26. यह भी उल्लेखनीय है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 53 के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत के सीमा-शुल्क क्षेत्र से बाहर है, यद्यपि वह भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित है। उपर्युक्त के आलोक में, बिना इसे स्वीकार किए, केवल तर्कार्थ यह मान भी लिया जाए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित उत्पादन इकाई ओपीएएल के उत्पादन को कुल भारतीय उत्पादन की गणना में शामिल किया जाना चाहिए, तब भी आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का संयुक्त उत्पादन, आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का ***% है। इसके अतिरिक्त, किसी भी घरेलू उत्पादक ने आवेदन का विरोध नहीं किया है।
27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग की परिभाषा की व्याख्या एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड प्रचालनों को शासित करने वाले सीमा शुल्क ढांचे के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए। केवल इसलिए कि कोई संस्था भारत में निगमित है या भारत में भौतिक रूप से वस्तुओं का निर्माण करती

है, वह व्यापार उपचारात्मक प्रयोजनों के लिए स्वतः घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं बन जाती जहाँ शासी कानूनी व्यवस्था स्वयं ऐसी संस्था को भारत के सीमा शुल्क राज्यक्षेत्र के बाहर कार्यरत मानती है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने अपनी सभी हाल की जांचों में एसईजेड इकाइयों को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा है। तदनुसार, प्राधिकारी कुल पात्र घरेलू उत्पादन की गणना से ओपीएएल को बाहर रखते हैं।

28. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि चूंकि ओपीएएल 08 मार्च, 2025 को, अर्थात् जांच अवधि के बाद, एसईजेड से बाहर हो गया था, और आवेदन दाखिल करने के समय डीटीए का हिस्सा था, इसे कुल पात्र घरेलू उत्पादन का हिस्सा माना जाना चाहिए था। प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस अनुरोध से असहमत हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच की जांच अवधि सीवाई 2024 है। पाटन और क्षति से संबंधित सभी निर्धारण जांच अवधि से संबंधित सूचना पर आधारित होने चाहिए। जांच अवधि के दौरान, ओपीएएल एसईजेड का हिस्सा बना रहा और डीटीए इकाई नहीं था। तदनुसार, एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के तहत कुल पात्र घरेलू उत्पादन की गणना के लिए, ओपीएएल द्वारा किए गए उत्पादन को कुल पात्र घरेलू उत्पादन का हिस्सा नहीं माना जा सकता।

ख. हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड घरेलू उद्योग के प्रमुख अनुपात का प्रतिनिधित्व नहीं करते

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि एचपीएल और एचएमईएल का भारत में कुल उत्पादन का केवल 25%-30% हिस्सा है और इस प्रकार ये कुल पात्र घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस संबंध में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ईसी - फास्टनर में अपीलीय निकाय के निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें अपीलीय निकाय ने निर्णय दिया था कि कुल घरेलू उत्पादन का 27% रखने वाले घरेलू उत्पादक पाटन रोधी पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुच्छेद 4.1 के अनुसार "प्रमुख अनुपात" नहीं बनते थे।
30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि फास्टनर जांच में, यूरोपीय आयोग ने, फास्टनर मूल जांच में घरेलू उद्योग को परिभाषित करते हुए, घरेलू उद्योग की परिभाषा को केवल ऐसे उत्पादकों तक सीमित कर दिया था जो नमूने में शामिल होने के इच्छुक थे। जांच शुरू होने के बाद, आयोग को 318 ज्ञात उत्पादकों में से 70 उत्पादकों से सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद, आयोग

ने इन 70 उत्पादकों में से 25 को घरेलू उद्योग की परिभाषा के दायरे से बाहर कर दिया, इस आधार पर कि ऐसे उत्पादकों ने नमूने का हिस्सा बनने की अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी, जिससे, जानबूझकर अभिलेख पर प्रासंगिक सूचना की अवहेलना की गई, और इस प्रकार, क्षति जांच में विरूपण का भौतिक जोखिम उत्पन्न हुआ। इस संबंध में, प्राधिकारी ईसी - फास्टनर में अपीलीय निकाय की टिप्पणियों को स्मरण करते हैं

"429. यूरोपीय संघ के स्पष्टीकरण के अनुसार, आयोग ने विभिन्न कारणों से इन 70 उत्पादकों में से 25 को घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा, जिनमें से एक उत्पादकों की नमूने का हिस्सा बनने की व्यक्त अनिच्छा थी।⁵⁷⁷ तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, घरेलू उत्पादकों का नमूना घरेलू उद्योग से छोटा समूह है, और नमूने का हिस्सा बनने की अनिच्छा इस बात को प्रभावित नहीं करनी चाहिए कि किसी उत्पादक को घरेलू उद्योग का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। इसकी पुष्टि फास्टनर जांच के प्रासंगिक तथ्यों से होती है। विशेष रूप से, आयोग ने नमूने के हिस्से के रूप में छह उत्पादकों का चयन किया, उनसे प्रासंगिक सूचना प्राप्त की, और उनके परिसरों पर सूचना का सत्यापन किया। आयोग ने तब नमूना चयनित उत्पादकों से प्राप्त सूचना का उपयोग "सूक्ष्म आर्थिक" क्षति कारकों के अपने विश्लेषण के लिए किया, लेकिन "समष्टि आर्थिक" क्षति कारकों का अपना विश्लेषण घरेलू उद्योग की परिभाषा में शामिल सभी 45 उत्पादकों से प्राप्त सूचना के आधार पर किया। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की परिभाषा में केवल उन लोगों को शामिल करके जो नमूने का हिस्सा बनने के इच्छुक थे, आयोग के दृष्टिकोण ने उन उत्पादकों के समूह को सीमित कर दिया जिनके आंकड़ों का उपयोग क्षति निर्धारण के भाग के लिए किया जा सकता था। यद्यपि, फास्टनर उद्योग की खंडित प्रकृति के कारण, सूचना प्राप्त करने पर व्यावहारिक बाधाएं घरेलू उद्योग की परिभाषा में घरेलू उत्पादन के छोटे अनुपात को शामिल करने को उचित ठहरा सकती हैं, आयोग का उन लोगों को बाहर करने का दृष्टिकोण जिन्होंने प्रासंगिक सूचना प्रदान की लेकिन नमूने का हिस्सा बनने के इच्छुक नहीं थे, ऐसी व्यावहारिक बाधाओं से असंबंधित था, और उनके द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सकता।"

31. जैसा कि अपीलीय निकाय की टिप्पणियों से देखा जा सकता है, यूरोपीय आयोग ने घरेलू उद्योग की परिभाषा को केवल ऐसे उत्पादकों तक सीमित कर दिया जो नमूने में शामिल होने के इच्छुक थे। घरेलू उद्योग के कवरेज को केवल ऐसे उत्पादकों तक सीमित करके आयोग ने "उन उत्पादकों के समूह को सीमित कर दिया जिनके आंकड़ों का उपयोग क्षति निर्धारण के भाग के लिए किया जा सकता था" क्योंकि इसने उन उत्पादकों को बाहर कर

दिया "जिन्होंने प्रासंगिक सूचना प्रदान की लेकिन नमूने का हिस्सा बनने के इच्छुक नहीं थे"।

32. उपरोक्त तथ्यों के विपरीत, वर्तमान जांच हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए क्षति सूचना आंकड़ों के आधार पर शुरू की गई थी जिनका कुल भारतीय उत्पादन में ***% से अधिक हिस्सा है। जांच शुरू करने के चरण से पहले, आवेदन को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा समर्थन प्राप्त था, जिसने क्षति अवधि के लिए स्थापित क्षमता, उत्पादन, घरेलू और निर्यात बिक्री के मूल्य और मात्रा से संबंधित सूचना प्रदान की थी। जांच शुरू होने के बाद, प्राधिकारी ने 08.07.2025 के ईमेल के माध्यम से अन्य घरेलू उत्पादकों, अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ब्रह्मपुत्र क्रैकर पॉलीमर लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से पूर्ण क्षति सूचना प्रदान करने के लिए सूचना मंगाई। तथापि, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अलावा, जिसने लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार जांच के समर्थक के रूप में सूचना प्रदान की, किसी अन्य उत्पादक ने इसका उत्तर नहीं दिया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा भाग न लेना विरूपण का भौतिक जोखिम उत्पन्न नहीं करता। इस संबंध में, प्राधिकारी चीन - ऑटोज (यूएस) में पैनल की टिप्पणी को स्मरण करते हैं जिसमें निम्नलिखित कहा गया था:

"7.214. हम अमेरिका के इस तर्क को अविश्वसनीय पाते हैं कि एमओएफसीओएम की पंजीकरण आवश्यकता ने विरूपण का एक भौतिक जोखिम उत्पन्न किया, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो घरेलू उद्योग की परिभाषा में घरेलू उत्पादकों के बीच स्व-चयन की ओर ले जाने में सक्षम है। हम ध्यान देते हैं कि एडी और सीवीडी जांचों में कई कदम उठाए जाने चाहिए, और जांच प्राधिकारी इस संबंध में संभार-तंत्र संबंधी बाधाओं का सामना करते हैं। पिछले मामलों में, पैनलों और अपीलीय निकाय ने निष्कर्ष निकाला है कि एक जांच प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने में कुछ लचीलापन दिया जाना चाहिए कि वह अपनी जांचों का व्यवस्थित संचालन कैसे सुनिश्चित करता है, उदाहरण के लिए हितबद्ध पक्षकारों के लिए घरेलू उद्योग में शामिल होने पर विचार किए जाने हेतु आगे आने की समय-सीमाएं स्थापित करके।³³⁶ हम मानते हैं कि लचीलेपन की वही आवश्यकता पंजीकरण प्रक्रिया के उपयोग को उचित ठहराती है, जो अनिवार्य रूप से हितबद्ध पक्षकारों से एक समय-सीमा तक आगे आने और स्वयं को जांच प्राधिकारी को जात कराने की अपेक्षा करती

हैं ताकि उन्हें घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जा सके। केवल यह तथ्य कि कुछ उत्पादक ऐसा न करना चुन सकते हैं, अर्थात्, आगे आने से 'स्व-चयन' करके बाहर हो जाना, अमेरिकी शब्दावली का उपयोग करें तो, हमारे विचार में, घरेलू उद्योग को परिभाषित करने की जांच प्राधिकारी की प्रक्रिया में विरूपण का कोई भौतिक जोखिम उत्पन्न नहीं करता। हमारे विचार में, केवल यह कि घरेलू उत्पादक भाग न लेना चुन सकते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि पंजीकरण आवश्यकता अनुच्छेद 4.1 और 16.1 के साथ असंगत घरेलू उद्योग की परिभाषा की ओर ले जाती है। बशर्ते कोई पंजीकरण जांच में भाग लेने के हितबद्ध पक्षकारों के अधिकारों और प्रशासनिक दक्षता के बीच एक उपयुक्त संतुलन बनाए, हम प्रासंगिक प्रावधानों में ऐसा कुछ भी नहीं देखते जो इसे रोके।"

33. वर्तमान जांच में, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के सभी घरेलू उत्पादकों से सूचना मंगाई थी, तथापि, ऐसी सूचना प्रदान नहीं की गई। यूरोपीय आयोग के विपरीत, प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध किसी भी सूचना की अवहेलना नहीं की है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि आवेदकों को कुल भारतीय उत्पादन का कम से कम 50% होना चाहिए। जैसा कि अर्जेटीना - ब्राजील से पोल्ट्री पर निश्चित पाटन रोधी शुल्क में पैनल द्वारा नोट किया गया, "प्रमुख अनुपात का संदर्भ बताता है कि 'घरेलू उद्योग' को परिभाषित करने के प्रयोजन के लिए एक से अधिक 'प्रमुख अनुपात' हो सकते हैं।"

34. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि प्रमुख अनुपात गणितीय गणना के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में, प्राधिकारी माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के लुब्रिजोल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्राधिकारी [2005 (187) ई.एल.टी. 402 (ट्राई. - देल.)] में की गई टिप्पणियों को स्मरण करते हैं, जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि प्रमुख अनुपात बनाने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि प्राधिकारी के समक्ष घरेलू उद्योग का उत्पादन देश के कुल उत्पादन के 50% से अधिक हो।

"15.1 हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि 'घरेलू उद्योग' को परिभाषित करने वाले नियम 2(ख) में शब्द 'कुल उत्पादन का प्रमुख अनुपात' की व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती है कि इसका अर्थ कुल उत्पादन का महत्वपूर्ण अनुपात या महत्वपूर्ण भाग है जो आवश्यक रूप से 50% से अधिक न हो। 'प्रमुख' शब्द, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, 'महत्वपूर्ण, गंभीर या सार्थक' का अर्थ देता है।"

'अनुपात' शब्द, इस संदर्भ में, हिस्से का अर्थ देगा। इसलिए, 'प्रमुख अनुपात' अभिव्यक्ति, घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन के संदर्भ में, महत्वपूर्ण या सार्थक हिस्से का अर्थ देगी। ऐसी व्याख्या स्पष्ट रूप से अनुज्ञेय है और इसके अनुसार, कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक का हिस्सा, 31% से अधिक होना, निस्संदेह एक महत्वपूर्ण या सार्थक हिस्सा अर्थात् उसका एक प्रमुख अनुपात था। 'कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख अनुपात' शब्दों को तुलनात्मक माप या संपूर्ण के विभिन्न भागों के आकार को शामिल करने वाले गणितीय योग को हल करने के कोण से नहीं देखा जा सकता। इस वाक्यांश का उपयोग घरेलू उत्पादकों के उत्पादन उत्पाद के संदर्भ में किया गया है और यह एक व्यापक व्याख्या की अनुमति देता है ताकि अपने दायरे में उन उत्पादकों के सामूहिक उत्पाद को ले सके जो निर्माण में लगे हैं या ऐसे वस्तु के निर्माण से जुड़ी किसी गतिविधि में लगे हैं, जैसा कि नियम 2(ख) द्वारा परिकल्पित है, उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक महत्वपूर्ण या सार्थक हिस्सा बनता है..."

35. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि ईसी - फास्टनर में अपीलीय निकाय की टिप्पणियाँ केवल ऐसी परिस्थितियों तक सीमित हैं जिनमें प्राधिकारी घरेलू उत्पादकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से भौतिक विरूपण का जोखिम उत्पन्न करता है। इस संबंध में, प्राधिकारी चीन - ऑटोज (यूएस) में पैनल के निष्कर्षों को स्मरण करते हैं:

"7.220. ... इसके अलावा, अपीलीय निकाय ने नोट किया कि जांच प्राधिकारी ने, वास्तव में, अंततः घरेलू उद्योग में शामिल किए गए 45 से अधिक उत्पादकों की पहचान की थी और उनसे सूचना प्राप्त की थी। अपीलीय निकाय ने निष्कर्ष निकाला कि घरेलू उद्योग में केवल उन उत्पादकों को शामिल करके जो नमूने में शामिल होने के इच्छुक थे, जांच प्राधिकारी के दृष्टिकोण ने उन उत्पादकों के समूह को सीमित कर दिया जिनके आंकड़ों का उपयोग क्षति निर्धारण करने में किया जा सकता था।"

36. वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने जांच शुरू करने पर सभी घरेलू उत्पादकों से सूचना मंगाई थी। इसके अलावा, यह प्रश्न कि क्या एचपीएल और एचएमईएल एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार "प्रमुख अनुपात" को संतुष्ट करते हैं, एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) से स्वतंत्र रूप से भी आंका गया है। तदनुसार, ईसी - फास्टनर में अपीलीय निकाय की टिप्पणियाँ वर्तमान मामले पर लागू नहीं होतीं।

37. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर के घरेलू उत्पादकों से संबंधित सूचना घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक कारकों का मूल्यांकन करने के लिए प्रासंगिक नहीं है। इस संबंध में, प्राधिकारी ईसी - बेड लिनेन में पैनल की टिप्पणियों को स्मरण करते हैं, जिसमें निम्नलिखित कहा गया था:

"6.182 तथापि, भारत के दावे के दूसरे पहलू के संबंध में हमारा निष्कर्ष भिन्न है। जैसा कि हमने नोट किया है, क्षति का निर्धारण जांच प्राधिकारियों द्वारा परिभाषित घरेलू उद्योग के लिए किया जाना चाहिए, इस मामले में यूरोपीय समुदायों द्वारा परिभाषित 'समुदाय उद्योग' को शामिल करने वाले 35 उत्पादक। हमारे विचार में, घरेलू उद्योग के भीतर नहीं आने वाली कंपनियों से संबंधित सूचना अनुच्छेद 3.4 के तहत अपेक्षित 'उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों' के मूल्यांकन के लिए अप्रासंगिक है। यह सत्य है भले ही वे कंपनियाँ वर्तमान में उत्पादित कर रही हों, या अतीत में उत्पादित कर चुकी हों, समान उत्पाद, बेड लिनेन। घरेलू उद्योग से बाहर की कंपनियों के लिए अनुच्छेद 3.4 के कारकों से संबंधित सूचना स्वयं घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव के बारे में निष्कर्षों के लिए कोई आधार प्रदान नहीं करती। यदि अन्य वर्तमान या पूर्व बेड लिनेन उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना गया होता, तो यह तथ्य कि उनमें से कुछ व्यवसाय से बाहर हो गए, घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक होता। लेकिन यह देखते हुए कि यूरोपीय समुदायों ने घरेलू उद्योग को 35 बेड लिनेन उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया, अन्य कंपनियों से संबंधित सूचना एडी समझौते के अनुच्छेद 3.4 के तहत 'उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारकों और सूचकांकों' के मूल्यांकन को सूचित नहीं करती, और इस प्रकार पाटित किए गए आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव के संबंध में निष्कर्षों का आधार नहीं बन सकती।"

38. इस प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा रही है कि प्रमुख अनुपात को महत्वपूर्ण अनुपात माना जाए न कि केवल कुल घरेलू उत्पादन के 50% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पादक।
39. आवेदन में प्रदान की गई सूचना के आधार पर, निम्नलिखित तालिका भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल पात्र घरेलू उत्पादन को दर्शाती है:

भारतीय उत्पादन (मी.ट.)

उत्पादक का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आवेदक)	***	***	***	***
एचपीसीएल-मितल एनर्जी लिमिटेड (आवेदक)	***	***	***	***
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (समर्थक)	***	***	***	***
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	***	***	***	***
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	***	***	***	***
ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	***	***	***	***
कुल उत्पादन	16,69,245	16,90,915	18,44,069	22,25,014
कुल उत्पादन में एचपीएल और एचएमईएल का हिस्सा	***	***	***	***
सीमा	0-10	0-10	20-30	25-35
आवेदक + समर्थक	***	***	***	***
सीमा	40-50%	60-70%	60-70%	70-80%

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य भारतीय हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए कुल भारतीय उत्पादन अनुमान का विरोध किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी ने जांच अवधि सहित क्षति अवधि के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर कुल पात्र भारतीय उत्पादन की पुनर्गणना की है। प्राधिकारी ने वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए रिपोर्ट में रिपोर्ट किए गए कुल उत्पादन पर विचार किया है। इसके अलावा, यह देखते हुए कि जांच अवधि¹ कोई वित्तीय वर्ष नहीं है, प्राधिकारी ने जनवरी'24 - मार्च'24 और अप्रैल'24 - दिसंबर'24 के लिए उत्पादन का अनुमान वित्त वर्ष

¹ <https://chemindia.chemicals.gov.in/Publicationspdf/Statistics-at-a-Glance-2024.pdf>

2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों को आनुपातिक रूप से विभाजित करके लगाया। प्राधिकारी ने उपरोक्त अवधियों के लिए ओपीएएल की वार्षिक रिपोर्टों का भी संदर्भ लिया और इसकी बिक्री की गणना के लिए वही पद्धति लागू की। इसके अलावा, ओपीएएल के उत्पादन आंकड़ों पर पहुँचने के लिए मालसूची से आवर्त अनुपात लागू किया गया। इस प्रकार आकलित उत्पादन नीचे दिया गया है:

भारतीय उत्पादन (मी.ट.)

उत्पादक का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आवेदक)	***	***	***	***
एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (आवेदक)	***	***	***	***
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (समर्थक)	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादक	***	***	***	***
ओपीएएल	***	***	***	***
कुल उत्पादन*	29,14,100	24,24,400	27,50,000	28,42,700
कुल पात्र उत्पादन (कुल उत्पादन ओपीएएल को छोड़कर)	22,81,600	17,91,900	22,32,500	22,30,325
कुल उत्पादन में एचपीएल और एचएमईएल का हिस्सा	***	***	***	***
सीमा	0-10	0-10	20-30	25-35
आवेदक + समर्थक	***	***	***	***
सीमा	40-50%	60-70%	60-70%	70-80%

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किया गया कुल उत्पादन अनुमान और प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि के लिए रिपोर्ट के आधार पर अनुमानित उत्पादन समान

सीमा में हैं। इस निर्धारण के लिए कि क्या घरेलू उद्योग कुल पात्र घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात बनाता है, प्राधिकारी ने रिपोर्ट के आधार पर उत्पादन आंकड़ों पर भरोसा किया है। इसी के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुल पात्र उत्पादन में एचएमईएल और एचपीएल के उत्पादन का हिस्सा ***% है, जो घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए हिस्से की ही सीमा में है।

42. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि एचएमईएल और एचपीएल भारत में एलएलडीपीई के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े पात्र उत्पादक (ओपीएल को छोड़कर) हैं और कुल भारतीय उत्पादन का 25%-30% रखते हैं। इसके अलावा, समर्थक के साथ, एचपीएल और एचएमईएल कुल भारतीय उत्पादन का ***% रखते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और एचपीसीएल-मितल एनर्जी लिमिटेड एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार 'प्रमुख अनुपात' बनाते हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य उत्पादकों से संबंधित समष्टि आर्थिक आंकड़ों पर विचार किया है।
43. जहाँ तक अन्य घरेलू उत्पादकों से संबंधित आंकड़ों का प्रश्न है, प्राधिकारी ने अपने 08.07.2025 के ईमेल के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं के सभी घरेलू उत्पादकों से निर्धारित प्रारूप के अनुसार पूर्ण क्षति सूचना मंगाई थी। मंगाई गई सूचना में बिक्री, उत्पादन लागत और घरेलू उत्पादकों की लाभप्रदता से संबंधित सूचना शामिल थी। तथापि, किसी भी अन्य घरेलू उत्पादक ने प्राधिकारी को ऐसी सूचना प्रदान नहीं की। प्राधिकारी को केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से एक समर्थन पत्र प्राप्त हुआ जो जांच शुरू होने से पहले ही प्राधिकारी के पास दाखिल किया जा चुका था। यह भी ध्यान दिया जाता है कि न तो प्राधिकारी और न ही घरेलू उद्योग किसी भी घरेलू उत्पादक को क्षति मापदंडों से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकता है।
44. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि आवेदकों ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदक संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातक से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा, आवेदकों का उत्पादन कुल पात्र घरेलू उत्पादन का एक महत्वपूर्ण और सार्थक अनुपात दर्शाता है और इस प्रकार कुल पात्र घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात है। इस प्रकार, आवेदक एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग बनाते हैं, और आवेदन एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की आवश्यकता को संतुष्ट करता है।

45. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दाखिल समर्थन पत्र के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू करने के चरण में दाखिल पत्र और आवेदन के अद्यतन अगोपनीय संस्करण के साथ परिचालित पत्र में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग ने आवेदन के अद्यतन अगोपनीय संस्करण में केवल अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के आधार पर माप की इकाई का उचित रूप से उल्लेख किया है। तदनुसार, प्राधिकारी समर्थन पत्र में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं।

घ. गोपनीयता

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियाँ

46. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
 - ख. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन के विवरण पर गोपनीयता का दावा किया है।
 - ग. घरेलू उद्योग ने आवेदन का अद्यतन अगोपनीय संस्करण विलंब से परिचालित किया है।

घ.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियाँ

47. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार आंकड़े प्रदान किए हैं।
 - ख. अन्य हितबद्ध पक्षकार कुछ ऐसी सूचना दाखिल करने का अनुरोध कर रहे हैं, जो अब आवेदन प्रारूप का हिस्सा नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, एडी नियमावली, 1995 का नियम 7 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

'गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उप-नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ, या जांच के दौरान किसी पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्राधिकारी को प्रदान की गई कोई अन्य सूचना, प्राधिकारी के उसकी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट हो जाने पर, उसके द्वारा ऐसी मानी जाएगी और ऐसी कोई सूचना ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकारी के बिना किसी अन्य पक्ष को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों से अपेक्षा कर सकता है कि वे इसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करें और यदि, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्ष की राय में, ऐसी सूचना सारांश के योग्य नहीं है, तो ऐसा पक्ष प्राधिकारी को इस बात के कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश बनाना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या सूचना प्रदान करने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने के लिए अनिच्छुक है या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकता है।'

49. इक्वेट और आरआरपीसी ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने आवेदन में कुल भारतीय उत्पादन आंकड़ों पर गोपनीयता का दावा किया है। इसका प्रकटीकरण प्राधिकारी द्वारा ऊपर कर दिया गया है।
50. देश-वार मूल्य और मात्रा आंकड़ों के प्रकटीकरण के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसका प्रकटीकरण घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन के अद्यतन अगोपनीय संस्करण में किया जा चुका है।
51. इक्वेट और कतोफिन ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने आवेदन का अद्यतन अगोपनीय संस्करण विलंब से परिचालित किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा 11.04.2026 को आवेदन का एक अद्यतन अगोपनीय संस्करण परिचालित किया गया था, इसके बाद कि इक्वेट और कतोफिन ने 09.04.2026 को पहली बार घरेलू उद्योग को गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियाँ परिचालित की थीं। अद्यतन याचिका मुख्य रूप से उक्त निर्यातकों द्वारा दाखिल गोपनीयता पर टिप्पणियों को संबोधित करती है। यह ध्यान दिया जाता है कि अनुरोधों के अगोपनीय संस्करणों का परिचालन स्वयं हितबद्ध पक्षकारों का

दायित्व है। 09.04.2026 को टिप्पणियों के परिचालन के बाद, घरेलू उद्योग ने इक्वेट और कतोफिन सहित हितबद्ध पक्षकारों को अगोपनीय आवेदन का अद्यतन संस्करण परिचालित किया। इस प्रकार, चूंकि गोपनीयता पर टिप्पणियाँ इक्वेट और कतोफिन द्वारा विलंब से परिचालित की गई थीं, जिस पर घरेलू उद्योग ने 11.04.2026 को उत्तर दिया, तदनुसार, यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग ने विलंबित उत्तर परिचालित किया है।

52. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने आवेदन के अगोपनीय संस्करण के संबंध में व्यापार सूचना संख्या 10/2018 का अनुपालन नहीं किया है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियाँ घरेलू उद्योग को परिचालित की गई थीं, जिसके बाद घरेलू उद्योग ने देश-वार आयात आंकड़े (मात्रा और मूल्य), आवश्यक प्रारूप में क्षमता उपयोग, अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन की समग्र मात्रा, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत में किए गए समायोजन प्रदान किए हैं। घरेलू उद्योग ने आगे प्रस्तुत किया है कि हितबद्ध पक्षकारों की अन्य टिप्पणियाँ अब गोपनीयता से संबंधित आवेदन प्रारूप का हिस्सा नहीं हैं।
53. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ भी उचित था, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दाखिल सूचना का पर्याप्त अगोपनीय संस्करण प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
54. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी जिसमें उन सभी से अपनी अनुरोधों का अगोपनीय संस्करण अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करने का अनुरोध किया गया था।

ड. विविध अनुरोध

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियाँ

55. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. जांच शुरू करना भारत-यूई सीईपीए की भावना के विरुद्ध है क्योंकि जांच अवधि के दौरान यूई से आयात प्रदर्शनीय रूप से गिरे हैं।
- ख. याचिका में असंगत आंकड़े हैं और इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

ड.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियाँ

56. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि अखिल भारतीय एचडीपीई निर्माता संघ द्वारा की गई सभी कानूनी और तथ्यात्मक अनुरोधों की अवहेलना करें और प्राधिकारी से अनुरोध करता है क्योंकि इसने न तो कोई प्रश्नावली प्रतिक्रिया दाखिल की है, और न ही अपना स्थान स्थापित करने के लिए कोई अन्य अनुरोध/दस्तावेज दाखिल किया है।
- ख. संघ ने अपने सदस्यों की पूर्ण सूची, अपने उप-नियम, बैठक के कार्यवृत्त यह प्रदर्शित करने के लिए प्रदान नहीं किए हैं कि किन सदस्यों ने उसे वर्तमान कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए प्राधिकृत किया है। इसके अभाव में, संघ द्वारा की गई अनुरोधों पर कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार उपचारात्मक जांचें एडी नियमावली, 1995 के तहत अपेक्षित पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर शुरू की जाती हैं। आगे यह नोट किया जाता है कि आयातों में गिरावट जांच शुरू न करने का कारण नहीं बन सकती यदि आवेदन में साक्ष्य में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित सूचना शामिल थी। प्राधिकारी ने, भारत-यूई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत निर्धारित अनुसार, यूई सरकार के प्रतिनिधियों के साथ जांच-पूर्व परामर्श किया और उन्हें तर्क प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जिन पर प्राधिकारी ने इस अंतिम जाँच परिणाम में विचार किया है।
58. आवेदन में शामिल आंकड़ों में असंगति के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत और अंतिम जाँच परिणाम उन आंकड़ों पर आधारित है, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के लेखा अभिलेखों से विधिवत सत्यापित किया गया था।
59. अखिल भारतीय एचडीपीई/पीपी बुने कपड़े निर्माता संघ द्वारा उपयोगकर्ता प्रश्नावली दाखिल न करने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अपनी सुसंगत प्रथा के अनुरूप और यह ध्यान में रखते हुए कि किसी अन्य भारतीय उपयोगकर्ता ने जांच में भाग नहीं लिया है, इसने संघ से कानूनी अनुरोधों की अनुमति दी है और उन पर विचार किया

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियाँ

60. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. याचिका में कतर और कुवैत के विरुद्ध जांच शुरू करने को उचित ठहराने के लिए पाटन का पर्याप्त साक्ष्य नहीं था।
- ii. आवेदक यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि उसने अपने इस दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई विश्वसनीय प्रयास किए कि कतर राज्य, कुवैत और अन्य संबद्ध देशों में प्रचलित कीमतों; या तीसरे देशों को निर्यातों पर विश्वसनीय सूचना अनुपलब्ध थी।
- iii. एलएलडीपीई मूल्य सूचकांक और बाजार आकलन व्यापक रूप से प्रकाशित होते हैं। वास्तव में आवेदक को ज्ञात था कि प्राधिकारी ने कतर राज्य से एलडीपीई से संबंधित पिछली जांच में घरेलू बिक्री मूल्यों को प्रतिनिधि पाया था।
- iv. प्राधिकारी को पाना चाहिए कि याचिका में पाटन का सटीक और पर्याप्त साक्ष्य नहीं था। तदनुसार, जांच समाप्त की जानी चाहिए।
- v. जहाँ घरेलू कीमतें उपलब्ध नहीं हैं, आवेदक को या तो निर्यात कीमतों या उत्पत्ति देश में उत्पादन लागत पर भरोसा करना आवश्यक है। भारतीय उत्पादकों की लागतों के आधार पर सामान्य मूल्य का अनुमान लगाने का कोई आधार नहीं था।
- vi. एडी समझौते का अनुच्छेद 5.2 पाटन मार्जिन की गणना के लिए उपयोग किए गए सामान्य मूल्य के लिए मानक के प्रकटीकरण की आवश्यकता रखता है। प्राधिकारी को याचिका को अस्वीकार कर देना चाहिए था क्योंकि सामान्य मूल्य किसी भी विधि पर आधारित नहीं था।
- vii. आवेदक ने उत्पत्ति देश में उपलब्ध उत्पादन लागत पर विचार न करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया है और यह भी नहीं समझाया है कि भारतीय घरेलू उत्पादकों की लागतें सऊदी अरब, कतर और ओमान राज्य में लागतों को क्यों प्रतिबिंबित करती हैं।
- viii. संबंधित-पक्ष आपूर्ति का संदर्भ वास्तविक अंतरण कीमतों की अवहेलना करने को उचित नहीं ठहराता बिना यह प्रदर्शित किए कि ऐसे लेन-देन बाजार-आधारित नहीं हैं या वे बाजार मूल्य को युक्तियुक्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते।

- ix. सऊदी अरब से राबिघ समूह, केम्या समूह और सदारा समूह के लिए उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के आधार पर पृथक पाटन और क्षति अंतर की गणना की जानी चाहिए।
- x. यूई से समान उत्पादों (एलडीपीई) पर पाटन की अनुपस्थिति पिछली जांच में स्थापित की जा चुकी है।
- xi. सऊदी अरब, कतर और कुवैत में कोई विशेष बाजार स्थिति (पीएमएस) नहीं है। सामान्य दावे के अलावा इसके अस्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है।
- xii. प्राधिकारी ने हाल ही में कुवैत, सऊदी अरब और सिंगापुर से मोनोएथिलीन ग्लाइकोल में, यह पाया कि जांच अवधि के दौरान कुवैत में पीएमएस का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था।
- xiii. प्राधिकारी ने सऊदी अरब के विरुद्ध पिछली जांच में यह मानने से इनकार कर दिया है कि पीएमएस मूल्य तुलनीयता को प्रभावित करता है।
- xiv. प्राधिकारी ने एलडीपीई जांच में निर्धारित किया था कि यूई में कोई कच्चा माल/उपयोगिता मूल्य विकृति नहीं थी।
- xv. आवेदक ने एक व्यापक और अप्रमाणित आरोप लगाया है कि जीसीसी कुछ इनपुट सामग्रियों और उपयोगिताओं के मूल्य निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप के कारण पीएमएस से प्रभावित है, बिना कोई आधार प्रदान किए।
- xvi. प्राधिकारी ने पिछली जांचों जैसे ईरान और कतर से रैखिक एल्किल बेंजीन (एलएबी) और कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका से निम्न-घनत्व पॉलीएथिलीन (एलडीपीई) में ऐसे अनुपयुक्त दावों को अस्वीकार कर दिया है। तदनुसार, पीएमएस के अस्तित्व के ऐसे सामान्य और निराधार दावों को खारिज किया जाना चाहिए।
- xvii. ऑस्ट्रेलिया - ए4 कॉपी पेपर में पैनल के निर्णय के अनुसार आवेदक को पीएमएस के अतिरिक्त, घरेलू और निर्यात बिक्री के बीच उचित तुलना को रोकने वाली ऐसी स्थिति स्थापित करनी आवश्यक है।
- xviii. आरआरपीसी को सैबिक समूह के लिए निर्धारित भारित औसत दर प्रदान की जानी चाहिए।
- xix. आरआरपीसी पहले सऊदी अरामको और सुमितोमो केमिकल के पास 37.5% प्रत्येक के साथ, शेष 25% सार्वजनिक शेयरधारकों के पास था। अरामको ने अक्टूबर 2025

- में सुमितोमो से आरआरपीसी में 22.5% अतिरिक्त हिस्सेदारी अधिग्रहीत की। आरआरपीसी और सैबिक सैबिक के सामान्य नियंत्रण में हैं।
- xx. प्राधिकारी ने हाल ही में संपन्न एमईजी जांच में आरआरपीसी को सैबिक समूह पर लागू शुल्क प्रदान किया था।
- xxi. किसी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक की प्रतिक्रिया को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई अन्य संस्था जिसने उत्पादक के उत्पाद का एक छोटा भाग निर्यात किया है, ने प्रश्नावली प्रतिक्रिया दाखिल नहीं की है।
- xxii. आरआरपीसी द्वारा अधिकांश निर्यात मात्रा सैबिक के माध्यम से निर्यात की गई थी और कुछ मात्रा सुमितोमो के माध्यम से निर्यात की गई थी। अरामको द्वारा आरआरपीसी में सुमितोमो की 37.5% हिस्सेदारी में से 22.7% हिस्सा अधिग्रहीत करने की घोषणा के साथ, सुमितोमो की भूमिका सीमित हो गई।
- xxiii. भले ही प्राधिकारी यह मानता है कि सुमितोमो की गैर-भागीदारी के कारण आरआरपीसी की निर्यात श्रृंखला पूरी तरह से अभिलेख पर नहीं है, उसे फिर भी सहयोगी उत्पादक और सहयोगी संबंधित संस्था द्वारा अभिलेख पर रखी गई सूचना का उपयोग उस सीमा तक करना चाहिए जहाँ तक ऐसी सूचना अनुबंध ॥ की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है।
- xxiv. आरआरपीसी ने सत्यापन दस्तावेजों के भाग के रूप में सुमितोमो की पुनर्विक्रय मूल्य सूचना और लाभप्रदता विवरण भी प्रस्तुत किया है। तदनुसार, सुमितोमो की गैर-भागीदारी को आरआरपीसी की संपूर्ण प्रश्नावली प्रतिक्रिया को अस्वीकार करने के आधार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
- xxv. प्राधिकारी ने पॉलिस्टायरीन और एसीटोन निष्कर्षों में केवल असहयोगी बिक्री चैनल की सीमा तक उपलब्ध तथ्य लागू किए।
- xxvi. मलेशिया से संबंधित उत्पादक प्रीफकेम की गैर-भागीदारी सऊदी अरब में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन रोधी शुल्कों के निर्धारण के लिए अप्रासंगिक है।
- xxvii. प्राधिकारी ने पीवीसी सस्पेंशन रेजिन, हैलोब्यूटाइल-रबर और आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रिन रबर में सहयोगी निर्यातकों को व्यक्तिगत शुल्क दर प्रदान की तब भी जब गैर-संबद्ध देशों से संबंधित उत्पादकों ने जांच में सहयोग नहीं किया।
- xxviii. शर्क सैबिक और एसपीडीसी का 50-50 का संयुक्त उपक्रम है। मित्सुबिशी कॉरपोरेशन सैबिक समूह का सहबद्ध नहीं है, बल्कि मित्सुबिशी कॉरपोरेशन एसपीडीसी का एक शेयरधारक है। व्यापार सूचना संख्या 09/2018 के तहत यह नहीं कहा जा सकता कि मित्सुबिशी शर्क या सैबिक से संबंधित है।

- xxix. दो पक्षों के बीच मात्र संबंध नियंत्रण स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्राधिकारी ने सौर पैनलों/मॉड्यूलों के लिए एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम फ्रेम में निर्णय दिया है कि जांच को इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि क्या एक संस्था "कानूनी या प्रचालनात्मक रूप से दूसरे पर संयम या निर्देशन का प्रयोग करने की स्थिति में है"।
- xxx. मित्सुबिशी के पास एसपीडीसी के शेयरों का केवल 33.34% है, जबकि एसपीडीसी के पास शर्क के शेयरों का 50% है। न तो शर्क और न ही मित्सुबिशी के पास शर्क में 5% से अधिक है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि मित्सुबिशी और शर्क संबंधित संस्थाएँ हैं।
- xxxi. शर्क सैबिक और एसपीडीसी के बीच 50:50 का संयुक्त उपक्रम है और उनमें से कोई भी कानूनी या प्रचालनात्मक रूप से शर्क पर संयम या निर्देशन का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है और इस प्रकार, वे स्वतंत्र रूप से शर्क पर नियंत्रण का प्रयोग नहीं कर सकते।
- xxxii. जबकि सैबिक और एसपीडीसी एक साथ शर्क को नियंत्रित कर सकते हैं, मित्सुबिशी एसपीडीसी में केवल एक अल्पांश शेयरधारक है और इसलिए कानूनी या प्रचालनात्मक रूप से एसपीडीसी पर संयम का प्रयोग नहीं कर सकता।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

61. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए कि क्या संबद्ध देशों से भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा पूर्ण घरेलू और निर्यात बिक्री चैनल रिपोर्ट किया गया है।
 - एसएपीपीएल की प्रश्नावली प्रतिक्रिया के अगोपनीय संस्करण में इस तथ्य का कोई संदर्भ नहीं है कि इसने प्रीफकेम द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं की भारत को आपूर्ति की है।
 - यह अस्पष्ट है कि एसएपीपीएल द्वारा भारत को आपूर्ति की गई प्रीफकेम वस्तुएँ वास्तव में मलेशिया से उत्पन्न वस्तुएँ हैं या सऊदी अरब से उत्पन्न वस्तुएँ जिन्हें बाद में प्रीफकेम और एसएपीपीएल के माध्यम से व्यापारित किया गया और इसलिए, भारत को निर्यात किया गया।

- iv. जैसा कि एसएपीपीएल की प्रश्नावली से स्पष्ट है, एसएपीपीएल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने केवल केएसए में उत्पादकों द्वारा निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति की है।
- v. सैबिक की प्रतिक्रिया में भी यह उल्लेख नहीं है कि उसने अन्य संबद्ध देशों में निर्मित संबद्ध वस्तुओं की भारत को आपूर्ति की है।
- vi. एसएपीपीएल और सैबिक की प्रतिक्रिया से निकलने वाला एकमात्र तार्किक निष्कर्ष यह है कि प्रीफकेम, मलेशिया से निर्यात की गई वस्तुएँ वास्तव में सऊदी अरब से उत्पन्न वस्तुएँ हैं जिन्हें प्रीफकेम और एसएपीपीएल के माध्यम से व्यापारित और निर्यात किया गया।
- vii. सैबिक समूह के संबंधित उत्पादक, मलेशिया में प्रीफकेम, शर्क के संबंधित निर्यातक, मित्सुबिशी कॉरपोरेशन और पेट्रो राबिघ के संबंधित निर्यातक सुमितोमो केमिकल एशिया पीटीई लिमिटेड ने जांच में भाग नहीं लिया है।
- viii. संचालन प्रथाओं की नियमावली का पैरा 12.20 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि उत्तरदाता उत्पादक को सहयोगी माने जाने और व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्राप्त करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों में शामिल सभी संबंधित संस्थाओं के संबंध में पूर्ण प्रतिक्रिया दाखिल करनी होगी।
- ix. अपूर्ण बिक्री चैनल को देखते हुए, प्राधिकारी को सदारा और केम्या सहित सैबिक समूह की संपूर्ण प्रतिक्रिया को अस्वीकार कर देना चाहिए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

62. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

'i) उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित, निर्यातक देश या राज्यक्षेत्र में उपभोग के लिए अभिप्रेत होने पर, समान वस्तु के लिए, व्यापार के सामान्य क्रम में, तुलनीय कीमत, या

ii) जब निर्यातक देश या राज्यक्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य क्रम में समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं होती, या जब विशेष बाजार स्थिति या निर्यातक देश या राज्यक्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती, सामान्य मूल्य या तो होगा:

(क) उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित, निर्यातक देश या राज्यक्षेत्र या उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किए जाने पर समान वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य; या उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित, प्रशासनिक, विक्रय और सामान्य लागतों और लाभों के लिए युक्तियुक्त जोड़ के साथ उत्पत्ति देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) परंतु उत्पत्ति देश से भिन्न किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में और जहाँ वस्तु को केवल निर्यात के देश से पारगमित किया गया हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं होती या निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, सामान्य मूल्य उत्पत्ति के देश में इसकी कीमत के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।'

63. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के साथ-साथ उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रश्नावली भेजी जिसमें उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और रीति में सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई।
64. निम्नलिखित उत्पादकों ने जांच में भाग लिया है:

देश	उत्पादक/निर्यातक का नाम	उत्पादक-निर्यातक / निर्यातक
कुवैत	इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी ("इक्वेट")	उत्पादक-निर्यातक
मलेशिया	मलेशिया से कोई उत्पादक भाग नहीं लिया है	-
ओमान	मेसर्स ओक्यू पॉलिमर एल.एल.सी. ("ओक्यू")	उत्पादक-निर्यातक
	ओक्यू मार्केटिंग एल.एल.सी. ("ओक्यूएम")	निर्यातक
कतर	कतोफिन कंपनी लिमिटेड क्यू.पी.जे.एस.सी ("कतोफिन")	उत्पादक-निर्यातक
	कतर रासायनिक और पेट्रोरासायनिक विपणन और वितरण कंपनी (मुंतजात) क्यू.पी.जे.एस.सी ("मुंतजात")	निर्यातक
	कतरएनर्जी मार्केटिंग ("क्यूईएम")	निर्यातक
	टोटलएनर्जीज पेट्रोकेमिकल्स फ्रांस - कतर शाखा कार्यालय ("टोटलएनर्जीज")	निर्यातक

सऊदी अरब	अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या")	उत्पादक-निर्यातक
	अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी ("पेट्रोकेम्या")	उत्पादक-निर्यातक
	ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी ("शर्क")	उत्पादक-निर्यातक
	जुबैल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी ("यूनाइटेड")	उत्पादक-निर्यातक
	राबिघ रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कंपनी ("आरआरपीसी")	उत्पादक-निर्यातक
	सदारा केमिकल कंपनी ("सदारा")	उत्पादक-निर्यातक
	यान्बू राष्ट्रीय पेट्रोकेमिकल कंपनी ("यानसाब")	उत्पादक-निर्यातक
	सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ("सैबिक")	निर्यातक
	सैबिक एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड ("एसएपीपीएल")	निर्यातक
	एसपीडीसी	निर्यातक
	एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड ("ईएमएपीपीएल")	निर्यातक
	डाउ सऊदी अरब उत्पाद विपणन बी.वी. ("डीएसए")	निर्यातक
	डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड ("डीसीपी (एस)")	निर्यातक
	डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, दुबई शाखा ("डीसीपी (एस) (डी)")	निर्यातक
डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड दुबई शाखा ("डीसीआईपीएल")	निर्यातक	
संयुक्त अरब अमीरात	अबू धाबी पॉलिमर्स कंपनी लिमिटेड ("एडीपीसीएल")	उत्पादक-निर्यातक
	बोरौज पीटीई लिमिटेड ("बोरौज")	निर्यातक
	एसआरजे ग्लोबल एफ.जेड.ई.	निर्यातक

65. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने संबद्ध देशों के विरुद्ध विशेष बाजार स्थिति के आरोप का विरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य नहीं रखा है। तदनुसार, प्राधिकारी ने आरोप की जांच नहीं की है, और विशेष बाजार स्थिति

के कारण उत्पादन लागत या सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

66. जहाँ किसी निर्यातक उत्पादक ने अनेक बिक्री चैनलों (नीचे गणित) के माध्यम से निर्यात किया है, प्राधिकारी ने भारत औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए उस निर्यातक के भारत औसत निर्यात कीमत से तुलना की है। इसके अलावा, जहाँ किसी निर्यातक ने एक से अधिक पीसीएन निर्यात किया है, पाटन और क्षति अंतर पीसीएन वार निर्धारित किया गया है, और समग्र रूप से उत्पादक के लिए भारत औसत पाटन और क्षति अंतर भी निर्धारित किया गया है।
67. प्राधिकारी यह भी ध्यान देते हैं कि कई संबंधित उत्पादकों ने भी जांच में भाग लिया है। प्राधिकारी ने ऐसे उत्पादकों के लिए व्यक्तिगत पाटन और क्षति अंतर निर्धारित किए हैं और समूह के लिए भारत औसत पाटन और क्षति अंतर भी निर्धारित किया है। सभी संबंधित उत्पादकों के लिए अंतिम शुल्क अनुशंसा, यदि कोई हो, समूह के लिए भारत औसत पाटन या क्षति अंतर में से जो भी कम हो पर आधारित होगी। निम्नलिखित तालिका वर्तमान जांच में भाग लेने वाले उत्पादकों के बिक्री चैनल को दर्शाती है:

बिक्री चैनल	उत्पादक	निर्यातक 1*	निर्यातक 2*	निर्यातक 3*	टिप्पणी
घरेलू	इक्वेट	-	-	-	असंबंधित ग्राहक
निर्यात	इक्वेट	-	-	-	असंबंधित ग्राहक
घरेलू	ओक्यू पॉलिमर	ओक्यू मार्केटिंग	-	-	असंबंधित ग्राहक
निर्यात	ओक्यू पॉलिमर	ओक्यू मार्केटिंग	-	-	असंबंधित ग्राहक
घरेलू	कतोफिन	मुंतजात	-	-	असंबंधित ग्राहक

घरेलू	कतोफिन	क्यूईएम	-	-	असंबंधित ग्राहक
निर्यात	कतोफिन	मुंतजात	-	-	असंबंधित ग्राहक
	कतोफिन	क्यूईएम	-	-	असंबंधित ग्राहक
	कतोफिन	मुंतजात	टोटल एनर्जीज	-	असंबंधित ग्राहक
घरेलू	पेट्रोकेम्या	सैबिक	-	-	असंबंधित ग्राहक
निर्यात	पेट्रोकेम्या	सैबिक	एसएपीपीएल	-	असंबंधित ग्राहक
घरेलू	शर्क	सैबिक	-	-	असंबंधित ग्राहक
निर्यात	शर्क	सैबिक	एसएपीपीएल	-	असंबंधित ग्राहक
	शर्क	एसपीडीसी	मित्सुबिशी	-	असंबंधित ग्राहक
घरेलू	यूनाइटेड	सैबिक	-	-	असंबंधित ग्राहक
निर्यात	यूनाइटेड	सैबिक	एसएपीपीएल	-	असंबंधित ग्राहक
घरेलू	यानसाब	सैबिक	-	-	असंबंधित ग्राहक
निर्यात	यानसाब	सैबिक	एसएपीपीएल	-	असंबंधित ग्राहक

घरेलू	केम्प्या	सैबिक	-	-	-
निर्यात	केम्प्या	सैबिक	एसएपीपीएल	-	असंबंधित ग्राहक
	केम्प्या	ईएमसीएपी	-	-	असंबंधित ग्राहक
घरेलू	आरआरपीसी	सैबिक	-	-	असंबंधित ग्राहक
	आरआरपीसी	सुमितोमो	-	-	असंबंधित ग्राहक
	आरआरपीसी	-	-	-	असंबंधित ग्राहक
निर्यात	आरआरपीसी	सैबिक	एसएपीपीएल	-	असंबंधित ग्राहक
	आरआरपीसी	सुमितोमो	-	-	असंबंधित ग्राहक
घरेलू निर्यात	सदारा	सैबिक	-	-	असंबंधित ग्राहक
	सदारा	डीएमएस	-	-	असंबंधित ग्राहक
	सदारा	सैबिक	एसएपीपीएल	-	असंबंधित ग्राहक
	सदारा	डीएसए	डीसीपी (एस)	-	असंबंधित ग्राहक
	सदारा	डीएसए	डीसीपी (एस)	डीसीआईपीएल	असंबंधित ग्राहक

	सदारा	डीएसए	डीसीआईपीएल	-	असंबंधित ग्राहक
	सदारा	डीएसए	डीसीपी(एस) (डी)	असंबंधित निर्यातक	असंबंधित ग्राहक
घरेलू	एडीपीसीएल	बोरौज	-	-	असंबंधित ग्राहक
निर्यात	एडीपीसीएल	बोरौज	-	-	असंबंधित ग्राहक
	एडीपीसीएल	बोरौज	एसआरजे (असंबंधित निर्यातक)	-	असंबंधित ग्राहक

**सभी निर्यातक संबंधित हैं जब तक विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो कि वे असंबंधित हैं (असंबंधित निर्यातक)।*

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कई उत्पादक-निर्यातकों, संबंधित और असंबंधित निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है। इन उत्पादक-निर्यातकों ने संबद्ध वस्तुओं को अपने घरेलू बाजार में बेचा है और संबंधित पक्ष बिक्री चैनलों के माध्यम से भारत को निर्यात किया है। जांच के दौरान, प्राधिकारी ने पाया कि कुछ मामलों में उत्पादक अपने संबंधित निर्यातकों को उच्च कीमतों पर बेच रहे थे और बाद में ये संबंधित निर्यातक भारत को पाटित कीमतों पर वस्तुओं का निर्यात कर रहे थे। तदनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(क) के तहत अधिदेशित अनुसार, प्राधिकारी ने उत्पादक स्तर पर एक्स-फैक्ट्री मूल्य निर्धारित करने के लिए संबंधित निर्यातकों के एसजीए व्यय और लाभ और उत्पादकों के एसजीए व्यय को घटाने के बाद स्वतंत्र ग्राहकों को पहली पुनर्विक्रय के बिंदु से सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों निर्धारित किए हैं।
69. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सऊदी अरब के सभी उत्पादक अर्थात्, केम्या, पेट्रोकेम्या, शर्क, यूनाइटेड, आरआरपीसी, सदारा और यानसाब, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

रूप से सैबिक या सऊदी अरामको, सैबिक के बहुसंख्य शेयरधारक (70%), द्वारा नियंत्रित हैं और इस प्रकार, संबंधित पक्ष माने गए हैं। शेयरधारिता प्रतिरूप निम्नानुसार हैं:

उत्पादक	शेयरधारिता	प्रत्यक्ष शेयरधारक	शेयरधारिता	प्रत्यक्ष शेयरधारक का शेयरधारक
केम्या	***	सैबिक	***	सऊदी अरामको
	***	एक्सॉन केमिकल अरेबिया इंक.	***	
पेट्रोकेम्या	***	सैबिक	***	सऊदी अरामको
आरआरपीसी	***	सऊदी अरामको	***	
	***	सुमितोमो केमिकल कंपनी	***	
	***	सार्वजनिक शेयरधारिता	***	
शर्क	***	सैबिक	***	सऊदी अरामको
	***	एसपीडीसी	***	मित्सुबिशी कॉरपोरेशन
यूनाइटेड	***	सैबिक	***	सऊदी अरामको
	***	सामाजिक बीमा के लिए सामान्य संगठन	***	
यानसाब	***	सैबिक	***	
	***	सार्वजनिक	***	

उत्पादक	शेयरधारिता	प्रत्यक्ष शेयरधारक	शेयरधारिता	प्रत्यक्ष शेयरधारक का शेयरधारक
एसएपीपीएल	***	सऊदी अरामको	***	सऊदी अरामको
सदारा	***	एक्सीलेंट परफॉर्मेंस केमिकल्स कंपनी	***	सऊदी अरामको
	***	डाउ सऊदी अरब होल्डिंग बी.वी.	***	

70. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकारी ने केम्या, पेट्रोकेम्या, शर्क, यूनाइटेड, आरआरपीसी, सदारा और यानसाब को संबंधित उत्पादक माना है और ये एक ही समूह, सऊदी अरामको - सैबिक समूह, का हिस्सा हैं।
71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सैबिक समूह के दो उत्पादकों, अर्थात् शर्क और आरआरपीसी, का बिक्री चैनल संबंधित निर्यातकों की गैर-भागीदारी के कारण अपूर्ण है। शर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शर्क ने अपनी संबंधित संस्था एसपीडीसी के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है जिसने बदले में उन्हें अपनी संबंधित संस्था मित्सुबिशी कॉरपोरेशन ("मित्सुबिशी") को पुनर्विक्रय किया, जिसने आगे भारत को निर्यात किया है। मित्सुबिशी ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। शर्क के अपूर्ण बिक्री चैनल को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि शर्क की प्रश्नावली प्रतिक्रिया को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रश्नावली प्रतिक्रिया के भाग के रूप में, भाग लेने वाले निर्यातकों को निर्यात और घरेलू बिक्री चैनलों से संबंधित सूचना प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें यह तथ्य शामिल है कि क्या कोई संबंधित या असंबंधित निर्यातक ऐसे बिक्री चैनलों का हिस्सा थे। इसके अलावा, प्रश्नावली में विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों में शामिल गैर-उत्पादक संबंधित संस्थाओं को अनुबंध-5 के साथ भाग I, भाग II प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, अनुबंध 3क में, प्राधिकारी विशेष रूप से भाग लेने वाले निर्यातक से निर्यातक और ग्राहक के बीच संबंध की पहचान करने की अपेक्षा करता है, अर्थात्, वे संबंधित हैं या नहीं,

और संबंध की प्रकृति। यह सूचना निवल निर्यात कीमत के सटीक निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए मांगी जाती है, क्योंकि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिनमें निर्यातक का संबंधित या असंबंधित निर्यातक पाटन कर रहा हो। सभी निर्यात बिक्री चैनलों से संबंधित सटीक सूचना के अभाव में, प्राधिकारी न तो उस कीमत का निर्धारण कर पाएगा जिस पर वस्तुएँ अंततः भारत को निर्यात की गईं और न ही भारत में ऐसी वस्तुओं की पहुँच कीमत का।

73. वर्तमान जांच में, शर्क और एसपीडीसी ने 12 सितंबर, 2025 को दाखिल अपनी मूल प्रश्नावली प्रतिक्रिया में अपने बिक्री चैनल का पूर्ण और सटीक प्रकटीकरण प्रदान नहीं किया। विशेष रूप से, एसपीडीसी ने अपनी विवरणात्मक प्रश्नावली प्रतिक्रिया में यह प्रकट करना भी छोड़ दिया कि उसने अपने संबंधित पक्ष मित्सुबिशी के माध्यम से भारत को बिक्री की थी। इसके अलावा, एसपीडीसी ने न केवल दो स्तंभों अर्थात्, "यदि संबंधित" (निर्यातक और ग्राहक के बीच संबंध) और "क्या संबंध" (संबंध की प्रकृति) से संबंधित सूचना प्रदान करना छोड़ दिया, बल्कि वास्तव में अनुबंध 3क से इन स्तंभों को पूरी तरह से हटा दिया। एसपीडीसी को छोड़कर, सैबिक समूह की अन्य संस्थाओं ने इन स्तंभों को सटीक रूप से रिपोर्ट किया था।
74. चूंकि प्रश्नावली में व्यापक सूचना दाखिल करना शामिल है, कभी-कभी, अनजाने में चूक हो सकती है। ऐसी चूकों को सुधारने के लिए, 12 अक्टूबर, 2025 के ईमेल के माध्यम से, प्राधिकारी ने सभी निर्यातकों को दूसरा अवसर प्रदान किया और विशेष रूप से निर्यातकों से अनुरोध किया कि वे अपनी प्रतिक्रिया (सामान्य प्रश्नों के प्रश्न (ज)) में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री या उत्पादन में संलग्न सभी संबंधित उत्पादकों, निर्यातकों और निर्यातकों के नाम स्पष्ट करें। शर्क और एसपीडीसी को भी अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था। तथापि, अपनी प्रतिक्रिया में एसपीडीसी ने प्राधिकारी को यह सूचित नहीं किया कि मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन के माध्यम से भारत को इसके निर्यात संबंधित बिक्री थे। प्राधिकारी द्वारा उठाए गए एक विशिष्ट प्रश्न के बावजूद, एसपीडीसी, अपने संशोधित अनुबंधों में, एक बार फिर एसपीडीसी और मित्सुबिशी के बीच निर्यात बिक्री को संबंधित पक्ष बिक्री के रूप में रिपोर्ट करने या मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन को संबंधित पक्ष के रूप में पहचानने में विफल रहा। एसपीडीसी ने अपनी प्रश्नावली में फिर से अपने ग्राहक (मित्सुबिशी) के साथ संबंध से संबंधित स्तंभों को हटा दिया। इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि एसपीडीसी ने जानबूझकर मित्सुबिशी के साथ अपने संबंध से संबंधित सूचना को छोड़ा।

75. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि शर्क ने तर्क दिया है कि मित्सुबिशी शर्क का सहबद्ध नहीं है और मित्सुबिशी शर्क को नियंत्रित नहीं करता। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मित्सुबिशी और शर्क के बीच संबंध की जांच करने से पहले, प्राधिकारी को मित्सुबिशी और एसपीडीसी के बीच संबंध की जांच करनी चाहिए। मित्सुबिशी के पास एसपीडीसी में 33.34% हिस्सा है, और इस प्रकार सीधे एसपीडीसी में 5% से अधिक शेयर रखता है और अप्रत्यक्ष रूप से शर्क में 5% से अधिक हिस्सा रखता है। प्राधिकारी आगे मोनो एथिलीन ग्लाइकोल के आयातों से संबंधित अपनी हाल ही में संपन्न जांच को स्मरण करते हैं, जिसमें उसने एसपीडीसी और मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन को संबंधित माना था, जिस पर न तो शर्क या एसपीडीसी या मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन ने विवाद किया था। प्राधिकारी ने उस मामले में मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन द्वारा दाखिल प्रश्नावली प्रतिक्रिया का भी अवलोकन किया है और पाया कि मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन ने एसपीडीसी से खरीद को संबंधित पक्ष खरीद के रूप में रिपोर्ट किया था। इन तथ्यों के मद्देनजर, प्राधिकारी एसपीडीसी और मित्सुबिशी को एक-दूसरे से संबंधित पाते हैं और शर्क को अप्रत्यक्ष रूप से मित्सुबिशी से संबंधित पाते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार शर्क द्वारा की गई बिक्री के निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना का प्रयोग किया है।
76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सैबिक समूह ने एक अन्य संबंधित उत्पादक, अर्थात् मलेशिया से प्रीफकेम, की गैर-भागीदारी का प्रकटीकरण नहीं किया है। जबकि एसएपीपीएल और सैबिक के अनुबंध 3क/अनुबंध 3ख में निर्यात लेन-देन प्रीफकेम द्वारा निर्यात सूचीबद्ध करते हैं, पूरक प्रश्नावली प्रतिक्रिया में प्रश्नों के उत्तर में, उनमें से किसी ने भी प्रीफकेम (50% सऊदी अरामको और 50% पेट्रोनास के स्वामित्व वाली) की गैर-भागीदारी को स्पष्ट नहीं किया। प्रीफकेम की गैर-भागीदारी के कारण, प्राधिकारी ने एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर मलेशिया के लिए पाटन और क्षति अंतर निर्धारित किया है।
77. यह भी ध्यान दिया जाता है कि आरआरपीसी का निर्यात बिक्री चैनल इसके संबंधित निर्यातक सुमितोमो की गैर-भागीदारी के कारण अपूर्ण है। आरआरपीसी ने यह दावा करने के लिए पॉलिस्टायरीन में इस प्राधिकारी के निष्कर्षों पर भरोसा किया है कि इसकी प्रतिक्रिया को केवल इसके संबंधित निर्यातक द्वारा गैर-भागीदारी की सीमा तक, अस्वीकार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पॉलिस्टायरीन में, निर्यातक (तख्त-ए-जमशीद पार्स

अस्सलौयेह पेट्रोकेमिकल कंपनी) के सभी संबंधित निर्यातकों ने सहयोग किया था, और प्राधिकारी ने एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार असंबंधित निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित किया था। आरआरपीसी ने एसीटोन में प्राधिकारी के निर्धारण पर भी भरोसा किया है, जिसमें उसने असहयोगी बिक्री चैनल के लिए सर्वोत्तम सूचना लागू की थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसीटोन में भी, असहयोगी बिक्री चैनल केवल असंबंधित निर्यातकों से संबंधित था। उस मामले के तथ्यों के विपरीत, वर्तमान जांच में, आरआरपीसी के भारत को निर्यात केवल संबंधित पक्षों, अर्थात् सैबिक और सुमितोमो के माध्यम से किए जाते हैं। तदनुसार, उपर्युक्त में से कोई भी निष्कर्ष आरआरपीसी की प्रतिक्रिया पर आंशिक विचार के तर्क को कोई समर्थन नहीं देता।

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आरआरपीसी ने अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया की धारा ई में यह स्वीकार करते हुए कि उसने सुमितोमो और सैबिक दोनों के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया था, उसने सुमितोमो के लिए प्रश्नावली प्रतिक्रिया दाखिल नहीं की, न ही उसकी गैर-भागीदारी का कोई कारण निर्दिष्ट किया। 12 अक्टूबर, 2025² के ईमेल के माध्यम से, प्राधिकारी ने आरआरपीसी के बिक्री चैनलों के बारे में पूछताछ की। आरआरपीसी ने अपनी प्रतिक्रिया में समझाया कि 2024 में सऊदी अरामको और सुमितोमो ने सऊदी अरामको द्वारा आरआरपीसी में सुमितोमो की 22.5% शेयर पूंजी के अधिग्रहण की घोषणा की थी। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिग्रहण अंततः अक्टूबर 2025 में पूरा हुआ, अर्थात् जांच अवधि के बाहर। इसके अलावा, अधिग्रहण के बाद भी, सुमितोमो के पास आरआरपीसी में 5% से अधिक हिस्सा बना हुआ है और इसलिए दिनांकित व्यापार सूचना 9/2018 के अनुसार संबंधित बना रहता है।
79. आरआरपीसी ने यह भी समझाया कि सुमितोमो अब व्यवसाय में रुचि नहीं रखता था और यह आरआरपीसी की समझ थी कि सुमितोमो पॉलिमर व्यवसाय से बाहर निकलने का इरादा रखता था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सुमितोमो के पास जांच अवधि के दौरान आरआरपीसी में महत्वपूर्ण शेयरधारिता थी और इस प्रकार एक संबंधित पक्ष बना रहा। चूंकि सुमितोमो ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आरआरपीसी का बिक्री चैनल अपूर्ण बना हुआ है। जहाँ प्राधिकारी असंबंधित निर्यातकों के मामले में विवेक का प्रयोग करते हैं, वहीं संबंधित निर्यातकों की संलिप्तता के मामले में, वही छूट नहीं दी जा सकती

² <https://www.aramco.com/en/news-media/news/2025/aramco-completes-acquisition-of-additional-stake-in-petro-rabigh>

क्योंकि यह निम्न निर्यात कीमतों वाले संबंधित निर्यातकों द्वारा गैर-भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी और इस प्रकार, प्राधिकारी को पाटन के सटीक निर्धारण से रोकेगी। तदनुसार, प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार आरआरपीसी के निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य का निर्धारित किया है।

च.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

क) कुवैत से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी ("इक्वेट") के लिए सामान्य मूल्य

80. इक्वेट ने जांच अवधि में ***मीट्रिक टन की घरेलू बिक्री रिपोर्ट की है। उत्पादक ने दावा किया है कि सभी घरेलू बिक्री असंबंधित पक्षों को है। उत्पादक ने बीमा, आंतरिक परिवहन, उधार लागत और किसी अन्य कटौती के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक इक्वेट द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। इक्वेट द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत, जहाँ तक उसी का सत्यापन किया जा सकता था और इक्वेट द्वारा कानूनी रूप से प्रमाणित की जा सकती थी, प्राधिकारी द्वारा विचार की गई है। यह ध्यान दिया गया है कि 80% से अधिक घरेलू बिक्री लाभदायक पाई गई, तदनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी बिक्री पर विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

81. कुवैत से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ख) कुवैत से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

इक्वेट के मामले में निर्यात कीमत

82. इक्वेट ने जांच अवधि के दौरान एनएमजी पीसीएन के *** मीट्रिक टन निर्यात रिपोर्ट किए हैं। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने एक असंबंधित निर्यातक के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं के प्रत्यक्ष और साथ ही अप्रत्यक्ष निर्यात किए हैं। असंबंधित निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है। यह ध्यान दिया जाता है कि असंबंधित निर्यातक के माध्यम से की गई निर्यात बिक्री नगण्य है। उत्पादक ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, आंतरिक परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, उधार लागत और किसी अन्य कटौती के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक इक्वेट द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, निर्यात कीमत में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। प्राधिकारी ने उपयुक्त अनुबंधों में रिपोर्ट की गई मात्रा और मूल्य के आधार पर भारतीय ग्राहकों को की गई प्रत्यक्ष बिक्री को ध्यान में रखा है, और उन चैनलों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत पर भी विचार किया है जिनके लिए भारत को निर्यात कीमत उपलब्ध नहीं था क्योंकि असंबंधित निर्यातकों ने इस जांच में सहयोग नहीं किया। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत।

83. कुवैत से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

मलेशिया से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य।

84. मलेशिया से किसी उत्पादक-निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, मलेशिया से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत।

85. मलेशिया से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ओमान से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

ओक्यू पॉलिमर्स एलएलसी के लिए सामान्य मूल्य

86. ओक्यू पॉलिमर्स एलएलसी ने अपने घरेलू बाजार में *** मीट्रिक टन की घरेलू बिक्री रिपोर्ट की है। ये बिक्री इसके संबंधित निर्यातक ओक्यू मार्केटिंग एलएलसी के माध्यम से की गई है। ओक्यू पॉलिमर्स एलएलसी ने आंतरिक परिवहन के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक ओक्यू पॉलिमर्स द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। ओक्यू पॉलिमर्स द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत, जहाँ तक उसी का सत्यापन किया जा सकता था और ओक्यू पॉलिमर्स द्वारा कानूनी रूप से प्रमाणित की जा सकती थी, प्राधिकारी द्वारा विचार की गई है। यह ध्यान दिया गया है कि केवल ***% घरेलू बिक्री लाभदायक पाई गई, तदनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक बिक्री पर विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य।

87. ओमान से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ओक्यू पॉलिमर्स एलएलसी के लिए निर्यात कीमत

88. ओक्यू पॉलिमर्स एलएलसी ने जांच अवधि के दौरान एनएमजी पीसीएन के *** मीट्रिक टन निर्यात की बिक्री रिपोर्ट की है। ओक्यू पॉलिमर्स एलएलसी ने दावा किया है कि उसने केवल अपने संबंधित निर्यातक, ओक्यू मार्केटिंग एलएलसी के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष निर्यात किए हैं। ओक्यू पॉलिमर्स एलएलसी ने जहाजरानी लागत के कारण निर्यात कीमत में

समायोजनों का दावा किया है। ओक्यू मार्केटिंग एलएलसी ने उधार लागत के लिए समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक ओक्यू समूह द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, निर्यात कीमत में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत।

89. ओमान से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

कतर से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

कतोफिन कंपनी लिमिटेड क्यू.पी.जे.एस.सी ("कतोफिन") के लिए सामान्य मूल्य

90. कतोफिन ने अपने घरेलू बाजार में *** मीट्रिक टन की घरेलू बिक्री रिपोर्ट की है। ये बिक्री इसके संबंधित निर्यातक कतर रासायनिक और पेट्रोरासायनिक विपणन और वितरण कंपनी (मुंतजात) क्यू.पी.जे.एस.सी ("मुंतजात") के माध्यम से की गई है। कतोफिन ने विपणन शुल्क के कारण समायोजनों का दावा किया है। इसके अलावा, इसके संबंधित निर्यातक, मुंतजात ने बीमा, आंतरिक परिवहन, उधार लागत, एलसी प्रभार, बैंक प्रभार, उधार बीमा और दस्तावेजीकरण प्रभारों के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक कतोफिन और इसके संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। कतोफिन द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत, जहाँ तक उसी का सत्यापन किया जा सकता था और कतोफिन द्वारा कानूनी रूप से प्रमाणित की जा सकती थी, प्राधिकारी द्वारा विचार की गई है। यह ध्यान दिया गया है कि 80% से अधिक घरेलू बिक्री लाभदायक पाई गई, तदनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी बिक्री पर विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य।

91. कतर से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

कतोफिन के लिए निर्यात कीमत

92. कतोफिन ने जांच अवधि के दौरान एनएमजी पीसीएन के *** मीट्रिक टन निर्यात की बिक्री रिपोर्ट की है। कतोफिन ने दावा किया है कि उसने केवल अपने संबंधित निर्यातकों, मुंतजात, कतरएनर्जी मार्केटिंग और टोटल पेट्रोकेमिकल्स फ्रांस - कतर शाखा कार्यालय के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष निर्यात किए हैं। कतोफिन ने आंतरिक परिवहन के कारण निर्यात कीमत में समायोजनों का दावा किया है। टोटल पेट्रोकेमिकल्स फ्रांस - कतर शाखा कार्यालय ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, उधार लागत, बिल ऑफ लेडिंग शुल्क, लिफ्ट ऑन लिफ्ट ऑफ प्रभार, सीमा शुल्क प्रभार, एलसी प्रभार, उधार बीमा और दस्तावेजीकरण प्रभारों का दावा किया है। कतर एनर्जी मार्केटिंग ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, उधार लागत, एलसी प्रभार, बैंक प्रभार, उधार बीमा और दस्तावेजीकरण प्रभारों के कारण समायोजनों का दावा किया है। मुंतजात ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, उधार लागत, बिल ऑफ लेडिंग, लिफ्ट ऑन लिफ्ट ऑफ, सीमा शुल्क प्रभार, एलसी प्रभार, सीमा शुल्क प्रभार, बैंक प्रभार, उधार बीमा और दस्तावेजीकरण प्रभारों पर समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक कतोफिन और इसके संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, निर्यात कीमत में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत।

93. कतर से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

सऊदी अरब से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

केम्या के लिए सामान्य मूल्य

94. केम्या ने जांच अवधि में एनएमजी पीसीएन की *** मीट्रिक टन घरेलू बिक्री रिपोर्ट की है। सभी घरेलू बिक्री संबंधित निर्यातक सैबिक के माध्यम से की गई है। उत्पादक ने कोई समायोजन दावा नहीं किया है। सैबिक ने हैंडलिंग और पैकेजिंग, दस्तावेजीकरण, भंडारण, स्थल परिवहन और उधार बीमा के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक केम्या द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है।
95. प्राधिकारी ने पाया कि केम्या को छोड़कर सऊदी अरब में अन्य सभी उत्पादक जो केम्या से संबंधित हैं और एक ही बिक्री चैनल (सैबिक के माध्यम से) का उपयोग कर रहे हैं, ने विक्रय और वितरण व्यय का दावा किया है। केम्या ने बाद में अपनी पूरक प्रश्नावली प्रतिक्रिया में भी कोई समायोजन दावा न करना जारी रखा। यह सत्यापित करने के लिए कि क्या ऐसी लागतें इसके संबंधित निर्यातक द्वारा वहन की गई थीं, प्राधिकारी ने अन्य उत्पादकों के लिए सैबिक द्वारा दावा किए गए प्रति इकाई समायोजनों की जाँच की और पाया कि केम्या के लिए सैबिक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रति इकाई व्यय अन्य उत्पादकों की ही सीमा में थे। प्राधिकारी ने यह भी ध्यान दिया कि सैबिक को की गई बिक्री एक्स-फैक्ट्री नहीं बल्कि एफओबी लेन-देन थी। प्राधिकारी ने यह भी ध्यान दिया कि केम्या अपने संबंधित उत्पादकों के समान भौगोलिक क्षेत्र में स्थित था और इसलिए, विक्रय और वितरण व्यय के लिए समायोजन रिपोर्ट न करने का कोई कारण नहीं था। चूंकि अन्य सभी उत्पादक विक्रय और वितरण व्यय वहन कर रहे थे जिसके अतिरिक्त सैबिक भी ऐसी वस्तुओं को बेचने में व्यय वहन कर रहा था, प्राधिकारी ने एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार इसके संबंधित उत्पादकों के अनुबंध 4क में रिपोर्ट की गई प्रति इकाई दर लागू करके केम्या के विक्रय मूल्य को भी समायोजित किया। इसके अलावा, केम्या द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत, जहाँ तक उसी का सत्यापन किया जा सकता था और केम्या द्वारा कानूनी रूप से प्रमाणित की जा सकती थी, प्राधिकारी द्वारा विचार की गई है। यह ध्यान दिया गया है कि केवल ***% घरेलू बिक्री लाभदायक पाई गई, तदनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक बिक्री पर विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

पेट्रोकेम्या के लिए सामान्य मूल्य

96. पेट्रोकेम्या ने जांच अवधि में एनएमजी पीसीएन की ***मीट्रिक टन घरेलू बिक्री रिपोर्ट की है। सभी घरेलू बिक्री संबंधित निर्यातक सैबिक के माध्यम से की गई है। पेट्रोकेम्या ने विक्रय और वितरण व्यय के कारण समायोजनों का दावा किया है। सैबिक ने हैंडलिंग और पैकेजिंग, दस्तावेजीकरण, भंडारण, स्थल परिवहन और उधार बीमा के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक पेट्रोकेम्या द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। पेट्रोकेम्या द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत, जहाँ तक उसी का सत्यापन किया जा सकता था और पेट्रोकेम्या द्वारा कानूनी रूप से प्रमाणित की जा सकती थी, प्राधिकारी द्वारा विचार की गई है। प्राधिकारी ने व्यापार के सामान्य क्रम का परीक्षण करने के लिए ऐसी लागत का उपयोग किया। यह ध्यान दिया गया है कि 80% से अधिक घरेलू बिक्री लाभदायक पाई गई, तदनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी बिक्री पर विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

शर्क के लिए सामान्य मूल्य

97. शर्क ने जांच अवधि में एनएमजी पीसीएन की ***मीट्रिक टन घरेलू बिक्री रिपोर्ट की है। ऊपर उल्लिखित कारणों से, शर्क का सामान्य मूल्य एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार निर्धारित किया गया है। प्राधिकारी ने सऊदी अरब से सहयोगी उत्पादकों के उच्चतम सामान्य मूल्य को शर्क के सामान्य मूल्य के रूप में विचार किया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

यूनाइटेड के लिए सामान्य मूल्य

98. यूनाइटेड ने जांच अवधि में एनएमजी पीसीएन की ***मीट्रिक टन घरेलू बिक्री रिपोर्ट की है। सभी घरेलू बिक्री संबंधित निर्यातक सैबिक के माध्यम से की गई है। यूनाइटेड ने आंतरिक परिवहन के कारण समायोजनों का दावा किया है। सैबिक ने हैंडलिंग और पैकेजिंग,

दस्तावेजीकरण, भंडारण, स्थल परिवहन और उधार बीमा के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक यूनाइटेड द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। यूनाइटेड द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत, जहाँ तक उसी का सत्यापन किया जा सकता था और यूनाइटेड द्वारा कानूनी रूप से प्रमाणित की जा सकती थी, प्राधिकारी द्वारा विचार की गई है। प्राधिकारी ने व्यापार के सामान्य क्रम का परीक्षण करने के लिए ऐसी लागत का उपयोग किया। यह ध्यान दिया गया है कि 80% से अधिक घरेलू बिक्री लाभदायक पाई गई, और तदनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी बिक्री पर विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

राबिघ रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कंपनी के लिए सामान्य मूल्य

99. आरआरपीसी ने जांच अवधि में एनएमजी पीसीएन की *** मीट्रिक टन घरेलू बिक्री रिपोर्ट की है। ऊपर उल्लिखित कारणों से, आरआरपीसी का सामान्य मूल्य एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार निर्धारित किया गया है। प्राधिकारी ने सऊदी अरब से सहयोगी उत्पादकों के उच्चतम सामान्य मूल्य को आरआरपीसी के सामान्य मूल्य के रूप में विचार किया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

सदारा केमिकल कंपनी के लिए सामान्य मूल्य

100. सदारा केमिकल कंपनी ने अपने घरेलू बाजार में *** मीट्रिक टन की घरेलू बिक्री रिपोर्ट की है। ये बिक्री इसकी संबंधित संस्थाओं डाउ मटेरियल साइंसेज कंपनी और सैबिक के माध्यम से की गई है। सदारा ने आंतरिक परिवहन, उधार लागत, पैकिंग लागत और विपणन शुल्क के कारण समायोजनों का दावा किया है। डाउ मटेरियल साइंसेज कंपनी ने आंतरिक परिवहन, उधार लागत, पैकिंग लागत और किसी अन्य कटौती के कारण समायोजनों का दावा किया है। सैबिक ने हैंडलिंग और पैकिंग, दस्तावेजीकरण, भंडारण, स्थल परिवहन और उधार बीमा के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक सदारा द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। सदारा द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत, जहाँ तक उसी

का सत्यापन किया जा सकता था और सदारा द्वारा कानूनी रूप से प्रमाणित की जा सकती थी, प्राधिकारी द्वारा विचार की गई है। प्राधिकारी ने व्यापार के सामान्य क्रम का परीक्षण करने के लिए ऐसी लागत का उपयोग किया। यह ध्यान दिया गया है कि सभी बिक्री हानिकारक पाई गई।

101. चूंकि सदारा की सभी घरेलू बिक्री हानिकारक पाई गई, और चूंकि सऊदी अरब में अन्य उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध था, प्राधिकारी ने सदारा के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सऊदी अरब में अन्य सहयोगी उत्पादकों के आंकड़ों पर भरोसा किया। प्राधिकारी ने सऊदी अरब में मात्रा के संदर्भ में उच्चतम घरेलू बिक्री वाले पूर्णतः सहयोगी उत्पादकों के एनएमजी पीसीएन के सामान्य मूल्य पर विचार किया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

यानसाब के लिए सामान्य मूल्य

102. यानसाब ने अपने घरेलू बाजार में *** मीट्रिक टन की घरेलू बिक्री रिपोर्ट की है। ये बिक्री इसकी संबंधित संस्था सैबिक के माध्यम से हुई है। यानसाब ने भंडारण और परिवहन लागतों के कारण समायोजनों का दावा किया है। सैबिक ने हैंडलिंग और पैकेजिंग, दस्तावेजीकरण, भंडारण, स्थल परिवहन और उधार बीमा के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक यानसाब द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। यानसाब द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत, जहाँ तक उसी का सत्यापन किया जा सकता था और यानसाब द्वारा कानूनी रूप से प्रमाणित की जा सकती थी, प्राधिकारी द्वारा विचार की गई है। प्राधिकारी ने व्यापार के सामान्य क्रम का परीक्षण करने के लिए ऐसी लागत का उपयोग किया। यह ध्यान दिया गया है कि 80% से अधिक घरेलू बिक्री लाभदायक पाई गई, तदनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी बिक्री पर विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य।

103. सऊदी अरब से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

सऊदी अरब से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

केम्या के लिए निर्यात कीमत

104. केम्या ने जांच अवधि के दौरान एनएमजी पीसीएन के *** मीट्रिक टन निर्यात रिपोर्ट किए हैं। केम्या ने दावा किया है कि उसने केवल अपने संबंधित निर्यातकों, अर्थात् सैबिक-एसएपीपीएल और ईएमसीएपी के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष निर्यात किए हैं। केम्या ने अपनी प्रतिक्रिया में कोई समायोजन दावा नहीं किया है। सामान्य मूल्य के समान, प्राधिकारी ने पाया कि केम्या को छोड़कर सऊदी अरब में अन्य सभी उत्पादक जो केम्या से संबंधित हैं और एक ही बिक्री चैनल (सैबिक के माध्यम से) का उपयोग कर रहे हैं, ने विक्रय और वितरण व्यय का दावा किया है। केम्या ने बाद में अपनी पूरक प्रश्नावली प्रतिक्रिया में यह भी कहा कि उसने निर्यातों के संबंध में कोई व्यय वहन नहीं किया। यह सत्यापित करने के लिए कि क्या ऐसी लागतें इसके संबंधित निर्यातकों द्वारा वहन की गई थीं, प्राधिकारी ने अन्य उत्पादकों के लिए सैबिक द्वारा दावा किए गए प्रति इकाई समायोजनों की जाँच की और पाया कि केम्या के लिए सैबिक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रति इकाई व्यय अन्य उत्पादकों की ही सीमा में थे। प्राधिकारी ने यह भी ध्यान दिया कि सैबिक को की गई बिक्री एक्स-फैक्ट्री नहीं बल्कि एफओबी लेन-देन थी। प्राधिकारी ने यह भी ध्यान दिया कि केम्या अपने संबंधित उत्पादकों के समान भौगोलिक क्षेत्र में स्थित था और इसलिए, विक्रय और वितरण व्यय के लिए समायोजन रिपोर्ट न करने का कोई कारण नहीं था। चूंकि अन्य सभी उत्पादक विक्रय और वितरण व्यय वहन कर रहे थे जिसके अतिरिक्त सैबिक भी ऐसी वस्तुओं को बेचने में व्यय वहन कर रहा था, प्राधिकारी ने इसके संबंधित उत्पादकों के अनुबंध 3क में रिपोर्ट की गई प्रति इकाई दर लागू करके केम्या के विक्रय मूल्य को भी समायोजित किया।
105. सैबिक ने छूटों, पत्तन प्रभारों, समुद्री माल भाड़ा, हैंडलिंग और पैकिंग, दस्तावेजीकरण, अतिरिक्त पत्तन, अन्य व्यय, भंडारण, गोदाम में लेना, बैंक प्रभार, सीमा शुल्क निकासी, विलंब शुल्क, बीमा, युद्ध जोखिम, स्थल परिवहन, चढ़ाने/उतारने और उधार बीमा के कारण

समायोजनों का दावा किया है। एसएपीपीएल ने एलसी बीमा प्रीमियम, उधार बीमा, बाह्यस्रोत के शुल्क, बैंक प्रभार और कमीशन के कारण समायोजनों का दावा किया है। ईएमसीएपी ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, पतन और अन्य संबंधित व्यय, बट्टा, उधार लागत और प्रचार कमीशन के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, निर्यात कीमत में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

पेट्रोकेम्या के लिए निर्यात कीमत

106. पेट्रोकेम्या ने जांच अवधि के दौरान एनएमजी पीसीएन के *** मीट्रिक टन निर्यात रिपोर्ट किए हैं। पेट्रोकेम्या ने दावा किया है कि उसने केवल अपने संबंधित निर्यातकों, अर्थात् सैबिक-एसएपीपीएल के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष निर्यात किए हैं। पेट्रोकेम्या ने विक्रय और वितरण व्यय के कारण समायोजनों का दावा किया है। सैबिक ने छूटों, पतन प्रभारों, समुद्री माल भाड़ा, हैंडलिंग और पैकिंग, दस्तावेजीकरण, अतिरिक्त पतन, अन्य व्यय, भंडारण, गोदाम में लेना, बैंक प्रभार, सीमा शुल्क निकासी, विलंब शुल्क, बीमा, युद्ध जोखिम, स्थल परिवहन, चढ़ाने/उतारने और उधार बीमा के कारण समायोजनों का दावा किया है। एसएपीपीएल ने एलसी बीमा प्रीमियम, उधार बीमा, बाह्यस्रोतन शुल्क, बैंक प्रभार और कमीशन के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, निर्यात कीमत में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

शर्क के लिए निर्यात कीमत

107. शर्क ने जांच अवधि के दौरान एनएमजी पीसीएन के *** मीट्रिक टन निर्यात रिपोर्ट किए हैं। शर्क ने दावा किया है कि उसने केवल अपने संबंधित निर्यातकों, अर्थात् सैबिक-एसएपीपीएल और एसपीडीसी-मित्सुबिशी के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष निर्यात किए हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मित्सुबिशी कॉरपोरेशन, शर्क के संबंधित पक्ष ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, शर्क का बिक्री चैनल अपूर्ण बना हुआ है और इसलिए, प्राधिकारी ने एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर शर्क के लिए निर्यात कीमत निर्धारित किया है और सऊदी अरब से सहयोगी उत्पादकों के न्यूनतम

निर्यात कीमत पर विचार किया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

यूनाइटेड के लिए निर्यात कीमत

108. यूनाइटेड ने जांच अवधि के दौरान एनएमजी पीसीएन के *** मीट्रिक टन निर्यात रिपोर्ट किए हैं। यूनाइटेड ने दावा किया है कि उसने केवल अपने संबंधित निर्यातकों, अर्थात् सैबिक-एसएपीपीएल के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष निर्यात किए हैं। यूनाइटेड ने आंतरिक परिवहन के कारण निर्यात कीमत में समायोजनों का दावा किया है। सैबिक ने छूटों, पत्तन प्रभारों, समुद्री माल भाड़ा, हैंडलिंग और पैकिंग, दस्तावेजीकरण, अतिरिक्त पत्तन, अन्य व्यय, भंडारण, गोदाम में लेना, बैंक प्रभार, सीमा शुल्क निकासी, विलंब शुल्क, बीमा, युद्ध जोखिम, स्थल परिवहन, चढ़ाने/उतारने और उधार बीमा के कारण समायोजनों का दावा किया है। एसएपीपीएल ने एलसी बीमा प्रीमियम, उधार बीमा, बाह्यस्रोतन शुल्क, बैंक प्रभार और कमीशन के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, निर्यात कीमत में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

राबिघ रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कंपनी के लिए निर्यात कीमत

109. आरआरपीसी ने जांच अवधि के दौरान एनएमजी पीसीएन के *** मीट्रिक टन निर्यात रिपोर्ट किए हैं। आरआरपीसी ने दावा किया है कि उसने केवल अपने संबंधित निर्यातकों, अर्थात् सैबिक-एसएपीपीएल और सुमितोमो केमिकल एशिया पीटीई लिमिटेड के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष निर्यात किए हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सुमितोमो केमिकल एशिया पीटीई लिमिटेड, आरआरपीसी के संबंधित पक्ष ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, आरआरपीसी का बिक्री चैनल अपूर्ण बना हुआ है और इसलिए, प्राधिकारी ने एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरआरपीसी के लिए निर्यात कीमत निर्धारित किया है और सऊदी अरब से सहयोगी उत्पादकों के न्यूनतम निर्यात कीमत पर विचार किया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

सदारा केमिकल कंपनी के लिए निर्यात कीमत

110. एससीसी ने जांच अवधि के दौरान एनएमजी पीसीएन के *** मीट्रिक टन निर्यात की बिक्री रिपोर्ट की है। एससीसी ने दावा किया है कि उसने केवल अपने संबंधित निर्यातकों, अर्थात् सैबिक-एसएपीपीएल, डाउ सऊदी अरब मार्केटिंग बी.वी., डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड - दुबई शाखा और डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड दुबई शाखा के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष निर्यात किए हैं। एससीसी ने आंतरिक परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, पैकिंग लागत, उधार लागत और विपणन शुल्क के कारण समायोजनों का दावा किया है। डाउ सऊदी मार्केटिंग बी.वी. ने सदारा से डाउ गोदाम तक माल भाड़ा, बीमा, गोदाम लागत के कारण समायोजनों का दावा किया है, डाउ पैसिफिक सिंगापुर ने सऊदी अरब से डाउ गोदाम तक माल भाड़ा, बीमा, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय के कारण समायोजनों का दावा किया है। डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड - दुबई शाखा ने बीमा और उधार लागत के कारण समायोजनों का दावा किया है। डीसीआईपीएल ने ऋण लागत के मद में समायोजन का दावा किया है।
111. सैबिक ने छूटों, पत्तन प्रभारों, समुद्री माल भाड़ा, हैंडलिंग और पैकिंग, दस्तावेजीकरण, अतिरिक्त पत्तन, अन्य व्यय, भंडारण, गोदाम में लेना, बैंक प्रभार, सीमा शुल्क निकासी, विलंब शुल्क, बीमा, युद्ध जोखिम, स्थल परिवहन, चढ़ाने/उतारने और उधार बीमा के कारण समायोजनों का दावा किया है। एसएपीपीएल ने एलसी बीमा प्रीमियम, उधार बीमा, बाह्यस्रोतन शुल्क, बैंक प्रभार और कमीशन के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, निर्यात कीमत में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

यानसाब के लिए निर्यात कीमत

112. यानसाब ने जांच अवधि के दौरान एनएमजी पीसीएन के *** मीट्रिक टन निर्यात की बिक्री रिपोर्ट की है। यानसाब ने दावा किया है कि उसने केवल अपने संबंधित निर्यातकों, अर्थात् सैबिक-एसएपीपीएल के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष निर्यात किए हैं। यानसाब ने आंतरिक परिवहन के कारण निर्यात कीमत में समायोजनों का दावा किया है। सैबिक ने छूटों, पत्तन प्रभारों, समुद्री माल भाड़ा, हैंडलिंग और पैकिंग, दस्तावेजीकरण, अतिरिक्त पत्तन, अन्य व्यय,

भंडारण, गोदाम में लेना, बैंक प्रभार, सीमा शुल्क निकासी, विलंब शुल्क, बीमा, युद्ध जोखिम, स्थल परिवहन, चढ़ाने/उतारने और उधार बीमा के कारण समायोजनों का दावा किया है। एसएपीपीएल ने एलसी बीमा प्रीमियम, उधार बीमा, बाह्यस्रोतन शुल्क, बैंक प्रभार और कमीशन के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, निर्यात कीमत में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत।

113. सऊदी अरब से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

यूई से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

अबू धाबी पॉलिमर्स कंपनी लिमिटेड ("एडीपीसीएल") के लिए सामान्य मूल्य

114. एडीपीसीएल ने अपने घरेलू बाजार में *** मीट्रिक टन की घरेलू बिक्री रिपोर्ट की है। एडीपीसीएल ने घरेलू बाजार में एनएमजी और एमजी दोनों पीसीएन बेचे हैं। ये बिक्री इसकी संबंधित संस्था बोरौज पीटीई लिमिटेड के माध्यम से हुई है। एडीपीसीएल ने स्थल परिवहन, गोदाम और हैंडलिंग लागत, उधार लागत, पैकिंग लागत के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त, इसके संबंधित निर्यातक, बोरौज ने उधार लागत और ग्राहकों को दी गई छूटों के कारण समायोजनों का दावा किया है। एडीपीसीएल द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत, जहाँ तक उसी का सत्यापन किया जा सकता था और एडीपीसीएल द्वारा कानूनी रूप से प्रमाणित की जा सकती थी, प्राधिकारी द्वारा विचार की गई है। प्राधिकारी ने व्यापार के सामान्य क्रम का परीक्षण करने के लिए ऐसी लागत का उपयोग किया। यह ध्यान दिया गया है कि 80% से अधिक घरेलू बिक्री लाभदायक पाई गई, तदनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी बिक्री पर विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य।

115. यूएई से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

एडीपीसीएल के लिए निर्यात कीमत

116. एडीपीसीएल ने जांच अवधि के दौरान एनएमजी और एमपीजी पीसीएन के *** मीट्रिक टन निर्यात की बिक्री रिपोर्ट की है। एडीपीसीएल ने दावा किया है कि उसने केवल अपने संबंधित निर्यातक बोरौज पीटीई लिमिटेड और असंबंधित निर्यातक, एसआरजे ग्लोबल एफजेडई के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष निर्यात किए हैं। एडीपीसीएल ने समुद्री माल भाड़ा और बीमा, आंतरिक परिवहन, पत्तन गोदाम और अन्य व्यय, उधार लागत और पैकिंग लागत के कारण निर्यात कीमत में समायोजनों का दावा किया है। बोरौज पीटीई लिमिटेड ने उधार लागत, भारत कार्यालय की नियत लागत और छूटों के कारण समायोजनों का दावा किया है। एसआरजे ग्लोबल एफजेडई ने कोई समायोजन दावा नहीं किया है। प्राधिकारी ने जहाँ तक दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापन किया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजनों को स्वीकार किया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत।

117. यूएई से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन

118. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच में कई सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक-दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। पाटन/क्षति अंतर के निर्धारण के लिए संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों को एकल संस्था मानना और इस प्रकार

उनके लिए एकल पाटन/क्षति अंतर निर्धारित करना प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा रही है। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि व्यक्तिगत पाटन/क्षति अंतरों की गणना करना संबंधित निर्यातक उत्पादकों को न्यूनतम व्यक्तिगत पाटन/क्षति अंतर वाली कंपनी के माध्यम से भारत को अपने निर्यात प्रेषित करने में सक्षम बनाकर पाटन रोधी उपायों के परिवर्तन को प्रोत्साहित कर सकता है, इस प्रकार उन्हें अप्रभावी बना सकता है।

119. उपरोक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एकल संस्था माना गया है और सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के पाटन/क्षति अंतरों के भारत औसत के आधार पर परिकल्पित एकल पाटन/क्षति अंतर आरोपित किया गया है।

च.3.2 पाटन मार्जिन

120. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	पीसीएन	सामान्य मूल्य (\$/मी.टन)	निर्यात कीमत (\$/मी.टन)	पाटन मार्जिन (\$/मी.टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (सीमा)
कुवैत						
इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी	एनएमजी	***	***	***	***	10-20
अन्य	सभी	***	***	***	***	20-30
सऊदी अरब						
अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या")	एनएमजी	***	***	***	***	0-10

उत्पादक	पीसीएन	सामान्य मूल्य (\$/मी.टन)	निर्यात कीमत (\$/मी.टन)	पाटन मार्जिन (\$/मी.टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (सीमा)
अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी ("पेट्रोकेम्या")	एनएमजी	***	***	***	***	0-10
ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी ("शर्क")	एनएमजी	***	***	***	***	20-30
जुबैल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी ("यूनाइटेड")	एनएमजी	***	***	***	***	0-10
राबिघ रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कंपनी	एनएमजी	***	***	***	***	20-30
सदारा केमिकल कंपनी	एनएमजी	***	***	***	***	0-10
यान्बू राष्ट्रीय पेट्रोकेमिकल कंपनी ("यानसाब")	एनएमजी	***	***	***	***	0-10
सऊदी अरामको - सैबिक समूह	एनएमजी	***	***	***	***	10-20
अन्य	सभी	***	***	***	***	20-30
कतर						

उत्पादक	पीसीएन	सामान्य मूल्य (\$/मी.टन)	निर्यात कीमत (\$/मी.टन)	पाटन मार्जिन (\$/मी.टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (सीमा)
कतोफिन कंपनी लिमिटेड क्यू.पी.जे.एस.सी	एनएमजी	***	***	***	***	(10)-0
ओमान						
ओक्यू पॉलिमर्स एल.एल.सी.	एनएमजी	***	***	***	***	0-10
अन्य	सभी	***	***	***	***	10-20
यूएई						
अबू धाबी पॉलिमर्स कंपनी लिमिटेड	एनएमजी	***	***	***	***	0-10
अबू धाबी पॉलिमर्स कंपनी लिमिटेड	एमजी	***	***	***	***	(10)-0
अबू धाबी पॉलिमर्स कंपनी लिमिटेड	भारित औसत	***	***	***	***	0-10
अन्य	सभी	***	***	***	***	0-10
मलेशिया						
कोई भी	सभी	***	***	***	***	40-50

छ. क्षति का आकलन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

121. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. मांग-आपूर्ति अंतराल का अस्तित्व या अनुपस्थिति क्षति का निर्धारक नहीं है, और आवेदक की भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता, आवेदक को प्रतिकूल मात्रा और मूल्य प्रभावों को प्रदर्शित करने के दायित्व से मुक्त नहीं करती।
 - ii. प्राधिकारी ने सीमलेस ट्यूब और पाइप में जांच समाप्त कर दी थी जब प्रमुख उत्पादक, महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, सूचना प्रदान करने में विफल रहा।
 - iii. कतर राज्य से आयात 2021-22 की तुलना में गिर गए हैं और लगभग 65% कम हो गए हैं। इतनी नाटकीय गिरावट कतर राज्य से कथित पाटित किए गए आयातों से क्षति के किसी भी दावे को खारिज करती है। वास्तव में, कतर राज्य से आयात एचएमईएल के उत्पादन शुरू होने से पहले ही घटने लगे थे।
 - iv. जबकि कतर राज्य से आयात तेजी से गिरा, घरेलू उत्पादन 100 से 826 सूचकांक अंकों तक भारी रूप से बढ़ा, जबकि मांग 100 से 119 सूचकांक अंकों तक बढ़ी, इस प्रकार स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कतर राज्य से आयातों का घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।
 - v. जबकि कुवैत से आयात जांच अवधि में 153 सूचकांक अंकों से बढ़ा, घरेलू उद्योग की बिक्री और उत्पादन 826 और 798 सूचकांक अंकों से बढ़े। यह प्रदर्शित करता है कि कुवैत से आयातों ने घरेलू उद्योग के घरेलू उत्पादन और बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।
 - vi. जबकि क्षति अवधि के दौरान ओमान से आयातों की मात्रा स्थिर रही, घरेलू उद्योग की बिक्री और उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। ओमान से आयात पर्याप्त रूप से संकुचित हुए हैं जबकि घरेलू उद्योग का हिस्सा काफी बढ़ा है।
 - vii. यूएई का कुल मांग में हिस्सा जांच अवधि में गिरा है और यूएई से आयातों की मात्रा में कोई प्रभावी वृद्धि नहीं हुई है।
 - viii. याचिका में संबद्ध आयातों की मात्रा में या तो निरपेक्ष रूप में या भारत में उत्पादन या उपभोग के सापेक्ष वृद्धि का कोई साक्ष्य नहीं है।
 - ix. याचिका में ओमान से आयातों की बढ़ी हुई मात्रा दिखाई देती है जबकि निर्यातक द्वारा आपूर्ति किए गए वास्तविक आंकड़े और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध संगत

- तृतीय-पक्ष आंकड़े इसके विपरीत हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि क्षति विश्लेषण करने से पूर्व इसकी जांच करें।
- x. आवेदक ने मध्यवर्ती रुझानों की जांच किए बिना अंतिम बिंदु तुलनाओं पर भरोसा किया है। जैसा कि रूस - हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर पाटन रोधी शुल्क में मान्यता दी गई, अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु की तुलना मध्यवर्ती घटनाक्रमों को छिपा सकती है और रुझानों की विकृत तस्वीर उत्पन्न कर सकती है।
 - xi. इसके अलावा यूरोपीय समुदायों - ब्राजील से तन्य ढलवाँ लोहे की ट्यूब या पाइप फिटिंग पर पाटन रोधी शुल्क के अनुसार, जांच को केवल अंतिम बिंदुओं की तुलना के बजाय प्रत्येक क्षति कारकों और सूचकांकों में वास्तविक मध्यवर्ती रुझानों को ध्यान में रखना चाहिए।
 - xii. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा ने निरंतर वृद्धि का प्रवृत्ति नहीं दिखाया है बल्कि 2022-23 में 5,28,590 मीट्रिक टन से गिरकर 2023-24 में 4,85,524 मीट्रिक टन और पुनः जांच अवधि में 4,15,013 मीट्रिक टन हो गई, जो 2022-23 से मात्रा में 21 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है।
 - xiii. याचिका यह स्पष्ट नहीं करती कि गिरते आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति कैसे पहुँचाई।
 - xiv. आवेदक ही बड़ी हुई भारतीय मांग के एकमात्र लाभार्थी रहे हैं। आयातों का गिरता हिस्सा दर्शाता है कि ऐसे आयातों ने आवेदकों और समग्र रूप से भारतीय उद्योग की बिक्री पर प्रभाव नहीं डाला है।
 - xv. आयात मात्राओं में गिरावट का आयात मात्रा में वृद्धि के साथ संपाती होना स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि कोई सतत चोटिल आयात दबाव नहीं है।
 - xvi. आवेदकों की बिक्री में वृद्धि भारतीय मांग में वृद्धि से अधिक है। यदि एचएमईएल के उत्पादन के कारण आयात गिरे हैं, तो यह दर्शाता है कि एचएमईएल संबद्ध देशों से आयातों को प्रतिस्थापित करने में सक्षम रहा है।
 - xvii. आवेदकों की बिक्री जांच अवधि में 698% बढ़ी है। संबद्ध देशों से संबद्ध आयात घरेलू आपूर्ति के अनुसार समायोजित हो गए हैं।
 - xviii. कीमत प्रभाव और लाभप्रदता से संबंधित मुद्दे मात्रा प्रभाव से पृथक और असंबंधित हैं। मात्रा क्षति का अभाव आवेदकों की बिक्री और उनकी बाजार हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि के साथ-साथ वित्त वर्ष 2022-23 के बाद संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट के तथ्य से स्पष्ट है।

- xix. आयात केवल 2021-22 और 2022-23 के बीच बढ़े और उसके बाद गिर गए हैं। संबद्ध देशों से आयात पिछले वर्ष की तुलना में 32 सूचकांक अंकों से काफी गिर गए हैं।
- xx. जांच अवधि में संबद्ध आयातों का कुल हिस्सा मात्र 15% था, जबकि आवेदक की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष में 3% से बढ़कर जांच अवधि में 22% हो गई है।
- xxi. आयात मात्राओं में वृद्धि का आरोप लगाने के लिए चुनिंदा आंकड़ों पर भरोसा अनुपयुक्त है और प्रतिकूल मात्रा प्रभावों को स्थापित नहीं करता।
- xxii. आवेदक अन्य भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी में सामान्य गिरावट पर भरोसा करके स्वयं को क्षति का दावा नहीं कर सकता क्योंकि अन्य घरेलू उत्पादकों ने आंकड़े प्रदान नहीं किए हैं।
- xxiii. चीन - जीओईएस में अपीलीय निकाय के निर्णय के अनुसार, प्राधिकारी को कीमतों में प्रासंगिक रुझानों की पहचान करने से परे जाना चाहिए और प्रदर्शित करना चाहिए कि संबद्ध आयातों में ऐसे रुझानों की घटना के लिए "व्याख्यात्मक बल" है। वर्तमान जांच पर इस मानक का अनुप्रयोग आयातों की पहुँच कीमत और आवेदक के विक्रय मूल्य के बीच सहसंबंध का अभाव प्रदर्शित करता है।
- xxiv. ईसी - बेड लिनेन और थाईलैंड एच-बीम्स में अपीलीय निकाय के निर्णय के अनुसार, जांच प्राधिकारी को सभी प्रासंगिक कारकों की जांच करना आवश्यक है और प्रमुख मापदंडों में सकारात्मक घटनाक्रमों की अवहेलना नहीं की जा सकती।
- xxv. याचिका में शामिल आंकड़े दर्शाते हैं कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग का निष्पादन स्थिर रहा है या सुधरा है।
- xxvi. मात्रात्मक मापदंडों में सुधारों की अवहेलना करने का यह प्रयास कि पूर्व के आंकड़े केवल एचपीएल से संबंधित हैं, अनुपयुक्त है।
- xxvii. घरेलू उद्योग ने कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि आयातों ने घरेलू उत्पादन को विस्थापित किया है या उपलब्ध क्षमता के उपयोग को रोका है, तदनुसार घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है।
- xxviii. एचएमईएल आधार वर्ष में अस्तित्व में नहीं था और इसलिए जांच अवधि में घरेलू उद्योग के क्षति मापदंडों की आधार वर्ष से तुलना करना आर्थिक और तार्किक रूप से दोषपूर्ण है।
- xxix. स्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री क्षति अवधि और जांच अवधि में तेजी से बढ़े हैं।

- xxx. घरेलू उद्योग ने क्षमता का 200% से अधिक विस्तार किया, उत्पादन 726% बढ़ाया, घरेलू बिक्री लगभग 698% बढ़ाई और अपने कार्यबल, मजदूरी और उत्पादकता का व्यापक विस्तार किया।
- xxxi. सुविधानुसार आयात रुझानों की व्याख्या करने के लिए एचएमईएल की नई क्षमता के चालू होने पर भरोसा करने के बाद, आवेदक कंपनियाँ वित्तीय क्षति का दावा करने के प्रयोजन से उसी प्रवृत्ति को चुनिंदा रूप से पाटित किए गए आयातों पर आरोपित नहीं कर सकतीं।
- xxxii. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में अपनी बिक्री 300% बढ़ाई है। यह वृद्धि इंगित करती है कि विचाराधीन उत्पाद में घरेलू उत्पादकों का वित्तीय स्वास्थ्य अच्छा रहा है, अन्यथा एचएमईएल ने विचाराधीन उत्पाद बाजार में निवेश करने का निर्णय नहीं लिया होता।
- xxxiii. उत्पादकता, मजदूरी और रोजगार में लगातार सुधार हुआ है, जो तेजी से बढ़ती औद्योगिक गतिविधि और बेहतर प्रचालन दक्षता को इंगित करता है।
- xxxiv. मात्रात्मक मापदंडों में सुधारों की अवहेलना करने का यह प्रयास कि पूर्व के आंकड़े केवल एचपीएल से संबंधित हैं, अनुपयुक्त है।
- xxxv. आवेदक ने 2023-24 में आयात मात्राओं में गिरावट को स्वीकार किया है, जो एचएमईएल के उत्पादन शुरू होने के साथ संपाती है, यह प्रदर्शित करता है कि आयात बढ़ी हुई घरेलू आपूर्ति के अनुक्रिया में समायोजित हो गए हैं।
- xxxvi. घरेलू उद्योग ने समग्र देश-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है और उत्तरदाताओं के निर्यातक-विशिष्ट मामले का खंडन नहीं करता कि सदारा समूह के भारत को निर्यात आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में गिर गए।
- xxxvii. देश-स्तरीय आंकड़ों के आधार पर सदारा समूह को कोई प्रतिकूल मात्रा प्रभाव आरोपित नहीं किया जा सकता।
- xxxviii. ऐसी स्थिति जहाँ घरेलू उद्योग क्षमता का विस्तार करता है, अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखता है या सुधारता है, और घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण मात्राएँ बेचना जारी रखता है, मात्रात्मक क्षति गठित करना नहीं कहा जा सकता।
- xxxix. याचिका में घरेलू उद्योग पर कीमतों के प्रभाव पर पर्याप्त और सटीक साक्ष्य नहीं है।
- xl. आवेदक संपूर्ण क्षति अवधि के लिए कीमत कटौती आंकड़े प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। जांच अवधि में मामूली कीमत कटौती था।
- xli. कीमत कटौती ने आवेदक को अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने से नहीं रोका है।

- xlii. सदारा का निर्यात कीमत याचिका में इंगित कीमतों से 20-30% अधिक है। इसलिए सदारा घरेलू उद्योग की कीमतों को न्यून नहीं कर रहा है और घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल रहा है।
- xliii. यूएई की पहुँच कीमत संबद्ध देशों में सर्वोच्च है और इसलिए, यूएई से आयातों को कोई क्षति आरोप्य नहीं है। यूएई से कीमत कटौती अत्यंत कम और नगण्य है।
- xliv. संबद्ध देशों की पहुँच कीमत क्षति अवधि के दौरान कमोबेश स्थिर रही है, केवल जांच अवधि में गिरावट दर्ज की गई, जो घरेलू उद्योग के आक्रामक मूल्य निर्धारण के कारण थी।
- xliv. एचपीएल और एचएमईएल घरेलू उत्पादकों को बिक्री-पश्चात प्रोत्साहन प्रदान करते हैं और कथित कीमत कटौती की गणना करते समय ऐसी बिक्री पश्चात छूटों को हटाया जाना चाहिए।
- xlvi. कीमत कटौती की मात्रा का पता केवल तभी लगाया जा सकता है जब बिक्री पश्चात छूटों सहित पूर्ण सूचना प्राधिकारी को प्रदान की जाए।
- xlvii. डीजीटीआर को विशेष रूप से एचएमईएल द्वारा विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन शुरू करने के बाद मासिक मूल्य भिन्नताओं की जांच करनी चाहिए।
- xlvi. आवेदक अपने विक्रय मूल्य को बिक्री लागत में वृद्धि/कमी के अनुरूप बढ़ाने/घटाने में सक्षम रहे हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों ने न तो आवेदकों की कीमतों को अवसादित किया है और न ही दबाया है। कीमत हास/न्यूनीकरण, यदि कोई है, आवेदकों द्वारा आक्रामक मूल्य निर्धारण के कारण है।
- xlix. आवेदक ने वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू विक्रय मूल्य घटाए जबकि आयात कीमतें स्थिर रहीं, और जांच अवधि में आयात कीमतों में कमी आवेदक की पूर्व मूल्य कटौती का अनुसरण करती थी।
- i. आवेदक की यह अनुरोध कि वह हानि पर बेच रहा था, कीमत कटौती स्थापित करने के लिए प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि ऐसी हानियाँ उसकी अपनी लागत गति और वाणिज्यिक रणनीति के कारण हैं।
 - ii. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में अपनी कीमतें बढ़ाईं, भले ही संबद्ध आयातों की पहुँच कीमतें जांच अवधि में गिरीं।
 - iii. आवेदकों ने वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2023-24 में अपने विक्रय मूल्य 19% घटाए जबकि आयातों की पहुँच कीमत समान स्तर पर रही। इस प्रकार, आवेदकों द्वारा अपमार्जक और आक्रामक मूल्य निर्धारण के कारण निर्यातक अपनी कीमतें घटाने के लिए बाध्य हुए।

- liii. मूल्य दमन और अवसाद की गतियाँ अन्य समष्टि आर्थिक, उद्योग-कारकों और एचएमईएल के नव चालू संयंत्र के चालू होने के कारण हैं, न कि आयातों के कारण।
- liv. आवेदकों के विक्रय मूल्य उनकी अपनी बिक्री लागत के अनुरूप गतिमान हुए हैं न कि आयातों की पहुँच कीमत के अनुरूप।
- lv. जांच अवधि में आवेदकों के विक्रय मूल्यों में मामूली गिरावट 2021-22 में एक असाधारण मूल्य वृद्धि के पश्चात आती है और कीमत में गिरावट आयातों से गिरावट के दबाव के बजाय बाजार सुधार का परिणाम है।
- lvi. जबकि 2022-23 में पहुँच कीमत 1% गिरी, घरेलू उद्योग ने अपना विक्रय मूल्य 11% बढ़ाया। वित्त वर्ष 2023-24 में पहुँच कीमत में कोई बदलाव न होने के बावजूद, आवेदकों ने अपना विक्रय मूल्य 19% घटाया। इसके अलावा, भले ही जांच अवधि में पहुँच कीमत गिरी, आवेदक अपनी कीमतें 11% बढ़ाने में सक्षम रहा।
- lvii. एचपीएल ने वित्त वर्ष 24-25 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि उसने एलएलडीपीई में 8% की मजबूत वृद्धि देखी है, इस प्रकार, स्पष्ट रूप से कोई क्षति न होना स्वीकार किया है।
- lviii. कतर से आयात जांच अवधि में 1% बाजार हिस्सेदारी रखते हैं और इसलिए, यह घरेलू विक्रय मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकते और वास्तव में, घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों का अनुसरण करते हैं।
- lix. यदि निर्यातक भारत में विचाराधीन उत्पाद को पाटित कीमतों पर बेच रहे होते और कीमतों को न्यून कर रहे होते, तो आयात मात्राएँ गिरने के बजाय बढ़ी होतीं।
- lx. आयातों की बाजार हिस्सेदारी निरंतर 10-20% की सीमा में बनी रही है जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 0-10% से बढ़कर 20-30% हो गई है। इसी प्रकार, भारतीय एलएलडीपीई उद्योग का हिस्सा भी जांच अवधि में सुधरा है।
- lxi. संबद्ध देशों से आयात अपेक्षाकृत छोटा और स्थिर हिस्सा बनाए हुए हैं; ऐसी सीमित आयात पैठ को प्रतिकूल मात्रा प्रभाव उत्पन्न करने वाला नहीं माना जा सकता।
- lxii. आवेदक 22% की बाजार हिस्सेदारी का उपभोग करते हैं, जांच अवधि में घरेलू खिलाड़ियों की हिस्सेदारी 83% रही है।
- lxiii. आवेदकों की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष में 3% से बढ़कर जांच अवधि में 22% हो गई है, जो इंगित करता है कि आवेदकों को कोई क्षति नहीं है।
- lxiv. आवेदक आधार वर्ष में लाभ कमा रहा था, और वित्त वर्ष 2022-23 में हानि बिक्री लागत में 25% वृद्धि के कारण थी। प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए कि क्या ऐसी हानियाँ आंतरिक कारकों या आंतरिक अक्षमताओं के कारण थीं।

- lxv. आवेदक द्वारा दावा किया गया कोई भी कीमत प्रभाव आयातों पर आरोपित नहीं किया जा सकता बल्कि आवेदक द्वारा स्वीकृत मूल्य निर्धारण निर्णयों, क्षमता समायोजनों और लागत गतिकी के कारण है।
- lxvi. आवेदकों ने स्वीकार किया है कि मूल्य गिरावट लगभग उस समय शुरू हुई जब एचएमईएल ने उत्पादन शुरू किया। इस प्रकार, नई क्षमता का जुड़ना संपाती रहा और संभावित रूप से आवेदकों की हानियों में योगदान दिया।
- lxvii. प्राधिकारी को एचएमईएल के निष्पादन की तुलना परियोजना रिपोर्ट में इसके अनुमानित निष्पादन से करनी चाहिए और सत्यापित करना चाहिए कि क्या एचएमईएल की हानियाँ वास्तव में अप्रत्याशित थीं।
- lxviii. आवेदक की मूल्यहास और ब्याज लागत में क्रमशः 82% और 41% की पर्याप्त वृद्धि हुई।
- lxix. घरेलू उद्योग आधार वर्ष से ही ऋणात्मक प्रत्याय अर्जित कर रहा है जब आयात आधार वर्ष में अपने न्यूनतम स्तर पर थे, इसलिए, आयातों को कोई क्षति आरोप्य नहीं है।
- lxx. घरेलू उद्योग बाद के वर्षों में उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में सुधारों की अवहेलना करना चाहता है और इसे एचएमईएल के प्रवेश और विस्तार पर आरोपित करता है। तथापि, नए उत्पादक के प्रवेश के बावजूद वित्तीय मापदंडों में गिरावट पर क्षति का दावा करने के लिए भरोसा किया जाता है।
- lxxi. घरेलू उद्योग अनुकूल रुझानों पर भरोसा कर रहा है और प्रतिकूल रुझानों की बिना संदर्भ के अवहेलना कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप एक विकृत और अविश्वसनीय क्षति विश्लेषण हो रहा है।
- lxxii. वित्तीय मापदंडों में कथित गिरावट प्रारंभिक मूल्य निर्धारण दबावों, उच्चतर नियत लागतों, उच्चतर इनपुट लागतों और प्रारंभिक प्रचालन, स्थिरीकरण चुनौतियों के कारण है।
- lxxiii. वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बीच विक्रय मूल्य में वृद्धि के बावजूद, आवेदकों की लाभप्रदता में तेजी से गिरावट आई।
- lxxiv. बिक्री लागत में गिरावट के बावजूद, आवेदक हानियाँ उठाना जारी रखे हुए हैं। इसलिए, ये कथित हानियाँ आयात कीमतों की गतियों के अनुरूप नहीं हैं और कथित पाटन पर आरोपित नहीं की जा सकतीं।
- lxxv. घरेलू उद्योग की हानियाँ 2023-24 में ठीक उस समय चरम पर थीं जब एचएमईएल का संयंत्र चालू हुआ। यदि मात्रा मापदंडों में सुधार एचएमईएल के प्रवेश के लिए

- आरोप्य हैं, तो वित्तीय मापदंडों में कथित गिरावट पर भी इसी कारण से विचार किया जाना चाहिए।
- lxxvi. जबकि 2022-23 में कतर की आयात कीमतें स्थिर रहीं, और कुवैत की आयात कीमतें थोड़ी बढ़ीं, उस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का कर पूर्व ब्याज लाभ काफी गिर गया।
- lxxvii. जांच अवधि के दौरान कतर से आयातों की कीमतों में गिरावट के बावजूद, घरेलू उद्योग के कर पूर्व ब्याज लाभ में सुधार हुआ है। यदि कतर से आयात कीमतें घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रही होतीं, तो इसका कर पूर्व ब्याज लाभ गिरना चाहिए था।
- lxxviii. जबकि जांच अवधि में कुवैत की कीमतें मामूली रूप से गिरीं, घरेलू उद्योग के कर पूर्व ब्याज लाभ में गिरावट कहीं अधिक थी। तदनुसार, क्षति कुवैत से आयातों के कारण नहीं है।
- lxxix. 2022-23 से ओमान से निर्यातों की कीमतों में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग का कर पूर्व ब्याज लाभ गिरा है। इस प्रकार, क्षति ओमान की आयात कीमतों के लिए आरोप्य नहीं है।
- lxxx. यदि ओमान से निर्यातक विचाराधीन उत्पाद को भारत में पाटित करने का आशय रखते, तो कीमतें गिरने पर आयात मात्राएँ बढ़नी चाहिए थीं।
- lxxxii. आवेदक की कीमतों की बिक्री लागत में वृद्धि वैश्विक रूप से ऊर्जा और फीडस्टॉक कीमतों में वृद्धि के कारण थी जैसा कि एचपीएल की वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है।
- lxxxiii. एचएमईएल और एचपीएल के बीच लागत अंतर मामूली नहीं बल्कि महत्वपूर्ण हैं और सामान्य उद्योग व्यवहार से असंगत हैं।
- lxxxiiii. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई वित्तीय हानि स्वतःकृत है और प्रारंभिक पूंजी निवेशों के कारण है, जो ब्याज लागत और मूल्यहास में तेज वृद्धि से स्पष्ट है।
- lxxxv. जांच अवधि के दौरान प्रति इकाई हानियों में कमी का बढी हुई बिक्री और बाजार हिस्सेदारी के साथ होना संबद्ध आयातों के कारण क्षति के आरोप से असंगत है।
- lxxxvi. वित्त वर्ष 2022-23 में आवेदकों की हानियाँ बढ़ीं, भले ही इसका विक्रय मूल्य 11 सूचकांक अंकों से बढ़ा।
- lxxxvii. यह तथ्य कि ब्याज लागत हटाने के बाद भी घरेलू उद्योग हानि में बना रहता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि क्षति संबद्ध आयातों के कारण है।
- lxxxviii. हानियाँ कम क्षमता उपयोग, उच्च नियत उपरिव्यय अवशोषण, उत्पाद मिश्रण मुद्दों, उच्चतर परिचालन लागतों, अपनी स्वयं की विपणन रणनीति से उत्पन्न मूल्य

निर्धारण दबाव और मौजूदा घरेलू उत्पादकों के साथ आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण हो सकती हैं।

lxxxviii. एचएमईएल द्वारा उत्पादन शुरू करने के कारण मालसूचियाँ बढ़ी हैं।

lxxxix. औसत मालसूची में वृद्धि संबद्ध आयातों के कारण नहीं है जो भारतीय बाजार में केवल 15% हिस्सा रखते हैं और क्षति अवधि के दौरान गिर रहे हैं। आवेदक विचाराधीन उत्पाद की बढ़ती घरेलू और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए अपने पास स्वस्थ मालसूची तैयार रखते हैं।

xc. याचिका में कथित पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारण पर अपर्याप्त साक्ष्य हैं। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि कथित पाटित किए गए आयातों में किसी कथित रूप से नकारात्मक प्रवृत्ति वाले क्षति कारकों के लिए "व्याख्यात्मक बल" कैसे था।

xc. भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक नैप्था के कच्चे माल के रूप में उपयोग के कारण अंतर्निहित लागत हानि का सामना करते हैं, जबकि अन्य देशों में उत्पादक ईथेन का उपयोग करते हैं, जिसकी उत्पादन लागत कम होती है।

xcii. सऊदी अरब में ईथेन को विदारण मार्ग के रूप में उपयोग करके एथिलीन उत्पादन की नकद लागत लगभग 240-250 \$/मी.टन है। कच्चे माल की उपलब्धता और चयनित फीडस्टॉक दक्षताओं के संबंध में प्राकृतिक लाभ भारतीय उत्पादकों की तुलना में सऊदी अरब में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों के लिए एक अंतर्निहित लाभ है।

xciii. आवेदक कंपनियों का वित्तीय निष्पादन पाटित किए गए आयातों से संचालित होने के बजाय आंतरिक वाणिज्यिक और संरचनात्मक कारकों से प्रभावित था।

xciv. एचएमईएल और एचपीएल प्रचालनात्मक परिपक्वता, पैमाने और लागत व्यवहार के संदर्भ में मूलतः भिन्न हैं, और इसलिए विश्लेषण को विकृत किए बिना इन्हें समग्र नहीं किया जा सकता।

xcv. एचएमईएल 2023-24 के दौरान अपने प्रचालन के पहले वर्ष में था, इसलिए, इसकी लागत का अत्यधिक कुशल होना अपेक्षित नहीं किया जा सकता।

xcvi. जबकि जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत 16% गिरी, एचपीएल की बिक्री लागत केवल 5% गिरी, जो इंगित करता है कि लागत में कमी मुख्यतः एचएमईएल, एक प्रथम-वर्ष उत्पादक, द्वारा संचालित है, न कि स्थापित उत्पादक की लागत में किसी वास्तविक सुधार से।

- xcvii. एचएमईएल के नव चालू संयंत्र ने लागत दक्षता के संदर्भ में एचपीएल से बेहतर प्रदर्शन किया है, जो आवेदक द्वारा भरोसा किए गए लागत आंकड़ों की विश्वसनीयता और प्रतिनिधित्वशीलता पर प्रश्न उठाता है।
- xcviii. घरेलू उद्योग के बीच भिन्न निष्पादन इंगित करता है कि कथित क्षति आयातों से असंबंधित कंपनी-विशिष्ट कारकों द्वारा संचालित है।
- xcix. हानियों का परिमाण अकेले विक्रय मूल्यों की गति से असंगत है और उस अवधि के दौरान भी बना रहता है जब बिक्री लागत मध्यम स्तरों पर थी।
- c. एचएमईएल ने प्रारंभिक अक्षमताओं के कारण पहले वर्ष के दौरान हानियाँ उठाईं जो प्रारंभिक लागतों से जुड़ी थीं, जो पाटन, कीमत कटौती के आरोपों के बावजूद जांच अवधि में कम हो गईं। क्षति अवधि के दौरान एचएमईएल प्रचालनात्मक अवस्था में था, इसलिए, क्षति संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं है।
- ci. ब्याज लागत और मूल्यहास में चौंका देने वाली वृद्धि घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट करती है। ये एक बड़े पूंजी विस्तार के स्वाभाविक परिणाम हैं न कि आयातों के प्रभाव।
- cii. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऋणपात्रता निर्धारण और स्वयं एचएमईएल इस बात की पुष्टि करते हैं कि एचएमईएल के वित्तीय संकट का प्रमुख कारण इसकी 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जीजीएसपीएपी पेट्रोकेमिकल परियोजना का चालू होना है।
- ciii. आयात मात्राओं में गिरावट के बावजूद, एचपीएल हानियाँ उठाना जारी रखे हुए है, जो इसकी उच्च उत्पादन लागत के लिए आरोप्य हैं।
- civ. क्षति कतर राज्य से आयातों के कारण नहीं है बल्कि अन्य संबद्ध देशों के कारण है।
- cv. क्षति कुवैत, ओमान से आयातों के कारण नहीं है बल्कि सऊदी अरब और यूएई जैसे अन्य संबद्ध देशों के कारण है, जिनकी मात्राएँ निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में पर्याप्त रूप से बढ़ी हैं।
- cvi. कुवैत से आयात अन्य संबद्ध देशों से महत्वपूर्ण उछाल की तुलना में केवल मामूली रूप से बढ़े हैं।
- cvii. यूएई को क्षति आरोप्य नहीं है क्योंकि यूएई के अतिरिक्त अन्य संबद्ध देशों से आयात बढ़े हैं, भले ही इन संबद्ध देशों से कोई तुलनीय एफटीए लाभ मौजूद नहीं है।
- cviii. क्षति कमजोर वैश्विक उपभोग के कारण है जैसा कि एचपीएल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में मान्यता दी है। इसके अलावा, एचपीएल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में दावा किया है कि भारत के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में से एक के चालू होने

और स्थिरीकरण के कारण मालसूची निर्माण के कारण घरेलू बाजार को अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ा है।

- cix. एचएमईएल, एक नया प्रवेशी होने के नाते, स्थापित खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आक्रामक मूल्य निर्धारण का सहारा लिया है।
- cx. एचपीएल को कोविड-19 के दौरान किए गए बंदियों के कारण क्षति उठानी पड़ी है।
- cxii. प्राधिकारी केवल एचएमईएल पर अनुबंध III लागू नहीं कर सकता क्योंकि इसने अगस्त 2023 में उत्पादन शुरू किया और यह एक स्थापित उत्पादक नहीं है।
- cxiii. यह प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा है कि नव स्थापित घरेलू उद्योग के मामले में, क्षमता का इष्टतमीकरण उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, परियोजना रिपोर्ट में अनुमानों के साथ पठित, किया जाना चाहिए।
- cxiii. कच्चे माल और उपयोगिताओं के इष्टतम उपयोग के लिए, केवल स्थापित उत्पादक, एचपीएल, के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए, और एचएमईएल की क्षति रहित कीमत को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं आंका जाना चाहिए।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

122. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं;
- i. भारत में वर्तमान में लगभग 29 लाख मीट्रिक टन की मांग के विरुद्ध एलएलडीपीई की लगभग 31 लाख मीट्रिक टन की समर्पित क्षमता है। इस प्रकार, भारत में कोई मांग आपूर्ति अंतराल नहीं है, और भारतीय निर्माता संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं।
- ii. चूंकि वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के आंकड़े केवल एचपीएल से संबंधित हैं, वित्त वर्ष 2023-24 और सीवाई 2024 के वर्षों में मात्रात्मक आंकड़े स्पष्ट सुधार दिखाते हैं और यह सुझाव देने के लिए गलत अर्थ लगाया जा सकता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है। मात्रात्मक मापदंडों के विपरीत, वित्तीय मापदंड संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण मूल्य क्षति दर्शाते हैं।
- iii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अधिकांशतः यह कथित रूप से प्रदर्शित करने के लिए कि ऐसे निर्यातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, अन्य देशों और घरेलू उद्योग के क्षति मापदंडों के विरुद्ध व्यक्तिगत संबंध देशों की कीमत और मात्रा गति की जांच की है।

- iv. ऐसी जांच एडी नियमावली, 1995 के तहत निर्धारित संचयी आकलन के सिद्धांतों के मद्देनजर पूर्णतः गलत है।
- v. भारतीय उत्पादन क्षमता में लगभग 25% वृद्धि के बावजूद, बाजार हिस्सेदारी गिरी है और संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। इस प्रकार, भारतीय उद्योग संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद मात्रात्मक क्षति का भी सामना कर रहा है।
- vi. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात आधार वर्ष की तुलना में काफी बढ़ गए हैं।
- vii. 2023-24 से आयात मात्राओं में गिरावट एचएमईएल द्वारा उत्पादन शुरू करने के कारण है। आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच, जहाँ आयात 48% बढ़े हैं, मांग केवल 19% बढ़ी है।
- viii. संबद्ध वस्तुओं की मांग संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है। आयातों की वृद्धि दर मांग की वृद्धि दर से अधिक रही है।
- ix. संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयातों के कारण, घरेलू उद्योग भारतीय मांग में वृद्धि से पर्याप्त रूप से लाभान्वित होने में सक्षम नहीं रहा है, अपनी बिक्री बढ़ाने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, यहाँ तक कि गैर-पारिश्रमिक कीमतों पर भी।
- x. अन्य हितबद्ध पक्षकार यह समझने में विफल रहे हैं कि जब भी कोई नया उत्पादक पर्याप्त निवेश करने के बाद किसी बाजार में प्रवेश करता है, तो उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपनी क्षमताओं को निष्क्रिय रखे। एक नया प्रवेशी होने के नाते, वह कम से कम अपनी नियत लागत की आंशिक वसूली का प्रयास करेगा, ताकि व्यवहार्य बना रहे।
- xi. एचएमईएल की एलएलडीपीई उत्पादन सुविधा स्थापित करने की योजना 2017 से प्रभावी रही है। एचएमईएल ने अगस्त 2023 में वाणिज्यिक एलएलडीपीई उत्पादन शुरू किया। वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 से संबंधित आंकड़े केवल एचपीएल से संबंधित हैं। इस प्रकार, जब एचएमईएल ने उत्पादन शुरू किया, तब उत्पादन, बिक्री आदि जैसे मात्रात्मक मापदंड एक उर्ध्वगामी प्रक्षेप पथ प्रदर्शित करने के लिए बाध्य हैं।
- xii. आयात कीमतें बहुत महत्वपूर्ण अंतर से घरेलू कीमतों को न्यून कर रही हैं।
- xiii. घरेलू उद्योग तब भी न्यूनीकरण का सामना कर रहा है जब वह हानियों पर बिक्री कर रहा है।

- xiv. घरेलू उद्योग वास्तव में संबद्ध देशों द्वारा निर्यात किए गए कम कीमत वाले पाटित किए गए आयातों के समक्ष बिक्री-पश्चात छूट प्रदान करने के लिए बाध्य हुआ था।
- xv. भारतीय उपयोगकर्ता घरेलू उद्योग के साथ बातचीत करते समय संबद्ध देशों द्वारा प्रस्तावित कीमतों को उद्धृत करते हैं जिसके विरुद्ध घरेलू उद्योग के पास घरेलू बाजार में बिक्री करने के लिए छूट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
- xvi. संघ द्वारा प्रदान किए गए प्रपत्र-पश्चात छूटों का साक्ष्य किसी भी प्रकार से घरेलू उद्योग के मामले को कमजोर नहीं करता, बल्कि इसे मजबूत करता है, आर्थिक वास्तविकता और संबद्ध देशों से आयातों द्वारा डाले गए मूल्य दबाव को दर्शाता है, जो घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें और कम करने के लिए बाध्य करता है।
- xvii. संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत में गिरावट के कारण, घरेलू उद्योग अपनी लागत से नीचे बेचने के लिए बाध्य हुआ है, जो स्पष्ट रूप से मूल्य अवसाद को प्रमाणित करता है।
- xviii. कीमतों में गिरावट उस अवधि से शुरू हुई जैसे ही एचएमईएल ने उत्पादन शुरू किया।
- xix. जबकि जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ी है, यह वृद्धि भारत में गैर-पारिश्रमिक कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं को बेचकर प्राप्त की गई है।
- xx. आधार वर्ष की तुलना में, जहाँ भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी गिरी है, संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है।
- xxi. घरेलू उद्योग को क्षति इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि भारतीय उद्योगों की बाजार हिस्सेदारी गिर गई है।
- xxii. घरेलू उद्योग केवल अपनी लागत से काफी नीचे गैर-पारिश्रमिक हानिकारक बिक्री करके ही अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम रहा है। तथापि, अपनी हानिकारक बिक्री के बावजूद, भारतीय उद्योग भारतीय मांग में अपना हिस्सा नहीं बढ़ा सका।
- xxiii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता घाटे में है और जांच अवधि के दौरान नकद हानियाँ, ऋणात्मक पीबीडीआईटी और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक प्रत्याय अर्जित कर रहा है।
- xxiv. घरेलू उद्योग न केवल हानियाँ अर्जित कर रहा है बल्कि ऋणात्मक पीबीडीआईटी और नकद हानियाँ भी हैं जिनकी जांच ब्याज तत्वों को हटाने के बाद की गई है। इस

- प्रकार, एचएमईएल के हाल ही में उत्पादन शुरू करने पर कोई क्षति आरोपित नहीं की जा सकती।
- xxv. 2023-24 के दौरान एनएफए में वृद्धि पूर्णतः एचएमईएल के एलएलडीपीई संयंत्र के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर पूंजीकरण के कारण हुई, जो निवेश निर्णयों और पूंजीगत व्यय के अनुसरण में था जिसकी योजना बहुत पहले, 2017 में बनाई गई थी और किया गया था।
- xxvi. ऐसे ऐतिहासिक पूंजीकरण को घरेलू उद्योग की नए निवेश करने की वर्तमान वित्तीय क्षमता के साक्ष्य के रूप में नहीं लगाया जा सकता।
- xxvii. एचएमईएल की हानियाँ जांच अवधि में अपनी बिक्री लागत को कम करने के संदर्भ में अधिक कुशल बनने के कारण कम हुई हैं। तथापि, बिक्री लागत में गिरावट के बावजूद, एचएमईएल ने अपनी लागत से नीचे बिक्री करना जारी रखा, जिससे महत्वपूर्ण हानियाँ हुईं।
- xxviii. भले ही मूल्यहास और ब्याज लागत का प्रभाव हटा दिया जाए, क्षति अवधि के दौरान उत्पादन शुरू करने के कारण, एचएमईएल जांच अवधि के दौरान अभी भी नकद हानियाँ उठा रहा था।
- xxix. जहाँ घरेलू उद्योग लगभग पंद्रह महीनों के उत्पादन के दौरान युक्तियुक्त प्रत्याय अर्जित करने या अपनी लागतों की वसूली करने में भी असमर्थ रहा है, वहाँ उसकी निधियाँ जुटाने और भविष्य के पूंजी निवेश करने की क्षमता भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त है।
- xxx. घरेलू उद्योग के पास विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पहुँच है।
- xxxi. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिकांश प्राकृतिक गैस और अन्य फीडस्टॉक कीमतें संबद्ध देशों की संबंधित सरकारों द्वारा नियंत्रित होती हैं।
- xxxii. सऊदी अरब साम्राज्य अरामको, पेट्रो राबिघ और अन्य सैबिक समूह उत्पादकों को फीडस्टॉक आपूर्तिकर्ता, को सरकार द्वारा विनियमित कीमतों पर फीडस्टॉक बेचने में अरामको द्वारा उठाई गई हानियों की क्षतिपूर्ति करता है।
- xxxiii. इसी प्रकार का मूल्य निर्धारण अंतर प्राधिकारी द्वारा कुवैत के मामले में कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा इक्वेट और द कुवैत ओलेफिंस कंपनी को ईथेन की आपूर्ति के संबंध में पाया गया था।
- xxxiv. भारतीय उत्पादक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल तक पहुँचते हैं, जबकि सऊदी अरब और अन्य संबद्ध देशों में उत्पादक अपनी सरकारों द्वारा

- विकृत इनपुट कीमतों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार, अंतर्निहित लाभ भौगोलिक स्थान का नहीं है, बल्कि विकृत इनपुट मूल्य व्यवस्था का है।
- xxxv. नैप्था-आधारित उत्पादन प्रक्रिया घरेलू उद्योग की एक अंतर्निहित विशेषता है और गैर-आरोपण विश्लेषण उन कारकों के लिए किए जाने की आवश्यकता नहीं है जो घरेलू उद्योग की अंतर्निहित विशेषताएँ हैं।
- xxxvi. अन्य हितबद्ध पक्षकार, बिना साक्ष्य के, यह मान रहे हैं कि प्रथम-वर्ष के संयंत्र को आवश्यक रूप से अक्षमताएँ प्रदर्शित करनी चाहिए।
- xxxvii. अन्य हितबद्ध पक्षकार यह समझने में विफल रहे हैं कि जबकि एचएमईएल एलएलडीपीई के लिए एक नया उत्पादक हो सकता है, यह एक दशक से अधिक समय से पॉलिमर व्यवसाय में एक स्थापित संस्था है और किसी भी प्रारंभिक और स्थिरीकरण मुद्दों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी जानकारी रखता है।
- xxxviii. क्षति अवधि के दौरान, एचएमईएल 8 महीनों की अवधि के भीतर शीघ्रता से लगभग 65%-75% का क्षमता उपयोग प्राप्त करने में सक्षम रहा और इस प्रकार अपने उत्पादन को स्थिर करने में सक्षम रहा।
- xxxix. जांच अवधि के दौरान एचएमईएल ने लगभग 80-90% का क्षमता उपयोग प्राप्त किया, जो स्वयं में इसकी तकनीकी सक्षमता, प्रचालन दक्षता और उत्पादन के सफल स्थिरीकरण का स्पष्ट साक्ष्य है।
- xl. प्राधिकारी ने मेलामाइन में निर्णय दिया था जिसमें घरेलू उद्योग पर्याप्त समयावधि से उत्पादन में रहा है और जिसमें उसने जांच अवधि के दौरान उच्च क्षमता उपयोग प्राप्त किया है, प्रारंभिक प्रभावों का प्रभाव पर्याप्त रूप से शामिल हो जाता है।
- xli. एलएलडीपीई जैसे उत्पाद के लिए, जहाँ लागत का प्रमुख घटक कच्चा माल है, प्रचालन दक्षता का अधिक उपयुक्त रूप से कच्चे माल के उपभोग मानदंडों के माध्यम से आकलन किया जाता है, जो दोनों उत्पादकों के लिए तुलनीय स्तरों पर हैं।
- xlii. एचएमईएल की निम्नतर बिक्री लागत मुख्यतः उच्चतर उत्पादन मात्राओं और उच्चतर क्षमता उपयोग से उत्पन्न प्रति इकाई निम्नतर नियत लागत के कारण है। इसके विपरीत, एचपीएल 2022-23 से निरंतर पाटित किए गए आयातों के कारण हानियाँ उठा रहा है, जिन्होंने इसके उत्पादन स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और क्षमता के इष्टतम उपयोग को रोका है।
- xliii. संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयातों के मूल्य-दमनकारी प्रभाव ने एचपीएल के एलएलडीपीई उत्पादन को कम किया है, जिससे प्रति इकाई नियत लागत अवशोषण और, परिणामस्वरूप, इसकी समग्र बिक्री लागत बढ़ गई है।

- xliv. पर्याप्त पूंजी निवेश करने के बाद, एचएमईएल के लिए प्रचालनों को स्थिर करने, क्षमता उपयोग को इष्टतम करने और नियत लागतों का कुशल अवशोषण प्राप्त करने के लिए उत्पादन बढ़ाना वाणिज्यिक रूप से अनिवार्य था। पूंजी-गहन पेट्रोकेमिकल प्रचालनों में, चालू होने के बाद तीव्र गति से उत्पादन बढ़ाना प्रचालन संतुलन प्राप्त करने के लिए सामान्य और आवश्यक दोनों हैं।
- xlv. वर्तमान जांच संबद्ध देशों से निर्यातकों की अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित है। पिछले कई वर्षों से, भारतीय घरेलू एलएलडीपीई बाजार अनेक घरेलू उत्पादकों से युक्त रहा है और घरेलू उत्पादकों के बीच आंतरिक प्रतिस्पर्धा घरेलू बाजार की एक अंतर्निहित विशेषता है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

123. एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के साथ पठित नियम 11 प्रावधान करता है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें पाटित किए गए आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है। पाटित किए गए आयातों के कीमतों पर प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित किए गए आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुआ है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक अवसादित करना या मूल्य वृद्धियों को, जो अन्यथा घटित होतीं, महत्वपूर्ण स्तर तक रोकना है। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के अनुसार उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांक जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन का परिमाण और अंतर आदि पर विचार किया गया है।

छ.3.1 क्षति का संचयी आकलन

124. विश्व व्यापार संगठन समझौते का अनुच्छेद 3.3 और एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध II का पैरा (iii) प्रावधान करता है कि ऐसे मामले में जहाँ एक से अधिक देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात एक साथ पाटन रोधी जांच के अधीन किए जा रहे हैं, प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेगा, यदि वह यह निर्धारित करता है कि:

- क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का अंतर निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहाँ व्यक्तिगत देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक हैं, और
- ख. आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के प्रकाश में आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उपयुक्त है।

125. तदनुसार, प्राधिकारी ने कतर के विरुद्ध जाँच समाप्त कर दी है और क्षति की जाँच के प्रयोजन से कतर को विचाराधीन देशों में शामिल नहीं किया गया है। प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद इच्छुक पक्षों ने बताया कि कुवैत और ओमान से आयातों का व्यक्तिगत हिस्सा कुल भारतीय आयात के 3% से कम तथा उनका सामूहिक हिस्सा 7% से कम था। अतः उन्होंने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 14 के अंतर्गत, नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii)(क) में निर्धारित मानदंड पूरे न होने के आधार पर कुवैत और ओमान के विरुद्ध जाँच समाप्त करने का अनुरोध किया।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच प्रारंभ किए जाने के समय कुवैत, ओमान और कतर से आयात पाटित पाए गए थे और उनका संयुक्त हिस्सा भारत के कुल आयात की मात्रा के 7% से अधिक था। तथापि, कतर के लिए ऋणात्मक पाटन मार्जिन निर्धारित होने के बाद, 3% से कम पाटित आयात हिस्सेदारी वाले देशों का सामूहिक हिस्सा 7% से कम हो गया। तदनुसार, प्राधिकारी कुवैत, ओमान और कतर के विरुद्ध जाँच समाप्त करते हैं।

126. कतर, कुवैत और ओमान से विचाराधीन वस्तुओं के आयातों को अन्य देशों से हुए आयातों के अंतर्गत माना गया है।

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से भारत में पाटित किया जा रहा है। प्रत्येक अन्य संबद्ध देश से पाटन का अंतर, एडी नियमावली, 1995 के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. आगे यह नोट किया जाता है कि कुछ संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा भारत में कुल संबद्ध आयातों की मात्रा के 3% से कम है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे संबद्ध देशों से आयातों की कुल मात्रा 7% से अधिक है।

ग. आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तावित समान वस्तुओं से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित समान वस्तुओं से भी सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं।

128. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित किए गए आयातों के संचयी प्रभाव का आकलन करना उपयुक्त है।
129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ओक्यू पॉलिमर्स ने दावा किया है कि ओमान से आयात क्षति अवधि के दौरान स्थिर बने रहे हैं और तदनुसार, घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकते। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी भी संबद्ध देश से आयातों के गैर-संचयन के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, आयातों के संचयी आकलन की शर्तें पूरी हो गई हैं। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि व्यक्तिगत संबद्ध देशों से व्यक्तिगत आयात मात्रा और मूल्य निर्धारण रुझानों की जांच किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
130. इसके अलावा, वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए, जहाँ क्षति अवधि के दौरान भारतीय घरेलू उत्पादकों के गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, प्राधिकारी ने, क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग, जांच के समर्थक और समग्र रूप से भारतीय उद्योग से संबंधित सत्यापित सूचना पर विचार किया है, जहाँ भी ऐसी सूचना उपलब्ध थी और विधिवत सत्यापित की जा सकती थी।

छ.3.2 पाटित किए गए आयातों का मात्रा प्रभाव

क) मांग/प्रत्यक्ष उपभोग का आकलन

131. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए वित्त वर्ष 2024-25³ और वित्त वर्ष 2023-24⁴ के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में प्रदान की गई मांग का अवलोकन करने पर,

³ https://chemicals.gov.in/sites/default/files/inline-files/Glance-2025_1.pdf

⁴ <https://chemindia.chemicals.gov.in/Publicationspdf/Statistics-at-a-Glance-2024.pdf>

प्राधिकारी ने ध्यान दिया कि रिपोर्ट में मांग की गणना में विचार किए गए आयात आंकड़े क्षति अवधि के दौरान किए गए आयातों की वास्तविक मात्रा से मेल नहीं खाते थे। तदनुसार, प्राधिकारी ने भारतीय मांग की गणना के लिए रिपोर्ट में विचार किए गए आयात आंकड़ों को डीजी सिस्टम आयात आंकड़ों से समायोजित किया। इसके अलावा, यह देखते हुए कि जांच अवधि एक कैलेंडर वर्ष है, प्राधिकारी ने जांच अवधि की मांग पर पहुँचने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के आधार पर समायोजित मांग का आनुपातिक विभाजन किया।

132. इस प्रकार निर्धारित मांग नीचे दी गई तालिका में प्रदान की गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
संबद्ध देश	मी.टन	1,60,803	2,73,231	2,83,797	2,36,986
सूचकांक	मी.टन	100	170	176	147
मलेशिया	मी.टन	6,017	19,092	48,600	26,739
सऊदी अरब	मी.टन	76,614	1,60,171	1,47,038	1,16,418
संयुक्त अरब अमीरात	मी.टन	78,172	93,968	88,160	93,829
अन्य देश	मी.टन	3,70,200	6,07,483	5,88,368	4,79,863
कुल आयात	मी.टन	5,31,004	8,80,714	8,72,165	7,16,849
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
सूचकांक	मी.टन	100	152	511	798
समर्थक की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
सूचकांक	मी.टन	100	104	99	106
घरेलू उद्योग + समर्थक की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
सूचकांक	मी.टन	100	108	133	164
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
सूचकांक	मी.टन	100	72	76	72
भारतीय उद्योग की कुल बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
सूचकांक	मी.टन	100	84	95	102
कुल मांग/उपभोग	मी.टन	33,78,651	32,65,325	35,74,741	36,31,353
सूचकांक	मी.टन	100	97	106	107

133. यह देखा गया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग वित्त वर्ष 2022-23 में प्रारंभिक गिरावट के बाद, जांच अवधि सहित शेष क्षति अवधि में निरंतर बढ़ी है। आधार वर्ष की तुलना में, संबद्ध देशों से संबद्ध आयात जांच अवधि में 42% बढ़ गए। इसी अवधि के दौरान, भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग 7% बढ़ी। यह भी ध्यान दिया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में एचएमईएल के प्रचालन शुरू करने के बाद, वित्त वर्ष 2022-23 और आधार वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 और जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री में काफी वृद्धि हुई। तथापि, भारतीय क्षमताओं में लगभग 25% वृद्धि के बावजूद, भारतीय उद्योग की बिक्री में कोई आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है जो आधार वर्ष के लगभग समान स्तर पर बनी रही है।

ख) संबद्ध देशों से आयात मात्राएँ

134. पाटित किए गए आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित किए गए आयातों की मात्रा में, या तो निरपेक्ष रूप में या भारत में उत्पादन या उपभोग के सापेक्ष, महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित किए गए आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

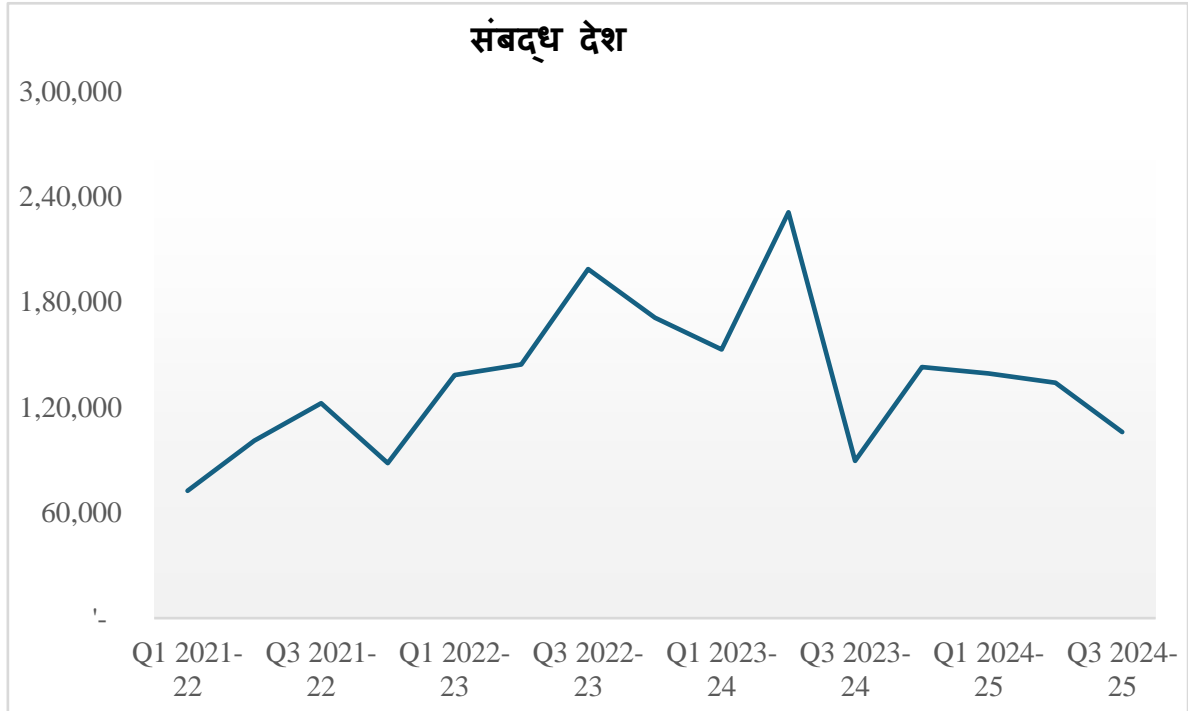
विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
मलेशिया	मी.टन	6,017	19,092	48,600	26,739
सऊदी अरब	मी.टन	76,614	1,60,171	1,47,038	1,16,418
संयुक्त अरब अमीरात	मी.टन	78,172	93,968	88,160	93,829
संबद्ध देश	मी.टन	1,60,803	2,73,231	2,83,797	2,36,986
गैर-संबद्ध देश	मी.टन	3,70,200	6,07,483	5,88,368	4,79,863
कुल आयात	मी.टन	5,31,004	8,80,714	8,72,165	7,16,849
कुल मांग	मी.टन	33,78,651	32,65,325	35,74,741	36,31,353
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	97	106	107
आयातों का संबंध:					
घरेलू उद्योग उत्पादन	%	***	***	***	***
सीमा	%	50-60%	80-90%	40-50%	20-30%

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
घरेलू उद्योग + समर्थक का उत्पादन	%	***	***	***	***
सीमा	%	10-20%	20-30%	20-30%	10-20%
कुल भारतीय उत्पादन	%	7%	15%	13%	11%
सीमा	%	0-10%	10-20%	10-20%	10-20%
मांग	%	5%	8%	8%	7%
सीमा		0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
कुल आयात	%	32%	36%	36%	35%

135. उपरोक्त से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. संबद्ध वस्तुओं के आयात आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बढ़ गए हैं।
- ख. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात भारत में कुल आयातों का 38% थे।
- ग. वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में, वित्त वर्ष 2023-24 और जांच अवधि में, निरपेक्ष रूप में और साथ ही घरेलू उत्पादन के सापेक्ष संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है। यह ध्यान दिया जाता है कि आयातों की मात्रा में गिरावट वित्त वर्ष 2023-24 में एचएमईएल द्वारा उत्पादन शुरू करने के साथ संपाती है। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की कुल मात्रा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बढ़ गई है।
- घ. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में एचएमईएल की क्षमता वृद्धि के साथ, कुल भारतीय उत्पादन जांच अवधि में बढ़ना चाहिए था और बढ़ती मांग को देखते हुए, आधार वर्ष के उत्पादन स्तरों को पार कर

जाना चाहिए था। तथापि, स्थापित क्षमता में लगभग 25% वृद्धि के बावजूद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में कुल भारतीय उत्पादन आधार वर्ष के उत्पादन स्तरों से नीचे है।



- ड. इसके अलावा, उक्त क्षमता वृद्धि के बावजूद, भारतीय उत्पादन के सापेक्ष पाटित किए गए आयात जांच अवधि में 50% बढ़ गए।
- च. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयात वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में गिर गए हैं। जैसा कि नीचे चार्ट से देखा जा सकता है, यह गिरावट पहली बार वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में एचएमईएल द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद हुई। तथापि, इसके बाद, आयात बढ़ गए और काफी उच्च स्तरों पर बने रहे।

136. कतौफिन और आरआरपीसी ने तर्क दिया है कि याचिका में सापेक्ष या निरपेक्ष रूप में बढ़ी हुई मात्राओं का कोई साक्ष्य नहीं है। जैसा कि ऊपर तालिका से देखा जा सकता है, संबद्ध देशों से आयात वित्त वर्ष 22-23 की तुलना में जांच अवधि में वास्तव में गिर गए हैं। आयातों में यह गिरावट एचएमईएल द्वारा उत्पादन और बिक्री शुरू करने की अवधि के साथ संपाती है। तथापि, जांच अवधि में ऐसे आयातों की निरपेक्ष मात्रा आधार वर्ष की तुलना में 42% बढ़ गई है।

137. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान, भारतीय एलएलडीपीई उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच, भारतीय क्षमताओं में 30% की वृद्धि हुई, तथापि, इस वृद्धि के बावजूद, संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात 33% बढ़े और संबद्ध देशों से आयात 42% बढ़ गए। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय उत्पादन क्षमता में वृद्धि के परिणामस्वरूप, यह ध्यान दिया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग अपनी घरेलू बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा, ऐसी बिक्री लागत से नीचे कीमतों पर की गई।
138. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि यद्यपि वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में जांच अवधि में भारतीय उत्पादन और मांग के प्रतिशत के रूप में संबद्ध आयातों की मात्रा गिर गई, ऐसी गिरावट को भारतीय क्षमता और मांग में पर्याप्त वृद्धि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाता है कि संबद्ध आयातों ने आधार वर्ष से अधिक बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी।
139. अधिक महत्वपूर्ण रूप से, संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करते रहे। ऐसे कम कीमत वाले पाटित किए गए आयातों की निरंतर उपस्थिति ने घरेलू उद्योग को पारिश्रमिक कीमतें प्राप्त करने से रोका है और उसे लागत से नीचे के स्तरों पर बेचने के लिए बाध्य किया है। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध आयात महत्वपूर्ण बने रहे, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँच रही है।
140. याचिका में शामिल ओमान के लिए मिश्रित आंकड़ों के संबंध में ओक्यू पॉलिमर्स की अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि इस अंतिम जाँच परिणाम में शामिल आयात आंकड़े डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, इसकी तुलना ओक्यू पॉलिमर्स द्वारा रिपोर्ट की गई आयात मात्रा से की गई और वह समान सीमा में पाई गई।
141. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आयातों ने क्षति अवधि के दौरान निरंतर बढ़ता प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं किया है, और इसलिए, कोई सतत चोटिल आयात दबाव नहीं है। प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों से असहमत हैं और ध्यान देते हैं कि न तो पाटन रोधी समझौता और न ही एडी नियमावली, 1995 संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान आयातों में निरंतर वृद्धि के निष्कर्ष की आवश्यकता रखता है।

142. आरआरपीसी ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग बढ़ी हुई भारतीय मांग का एकमात्र लाभार्थी रहा है। प्राधिकारी इस दावे से असहमत हैं क्योंकि संबद्ध देशों से संबद्ध आयात भी आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच भारतीय मांग में वृद्धि के साथ बढ़े हैं। संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि नीचे से स्पष्ट है:

	2022- 23	2023- 24	जांच अवधि	जांच अवधि आधार वर्ष की तुलना में
संबद्ध देश आयात	104%	-6%	-26%	42%

143. जहाँ तक इस अनुरोध का प्रश्न है कि संबद्ध देशों से आयातों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूंजी-गहन उद्योग में, नव प्रचालित क्षमता को निष्क्रिय रखने की लागत काफी अधिक होती है। इसलिए उत्पादन और बिक्री में वृद्धि, अपने आप में, क्षति की अनुपस्थिति का संकेत नहीं देती। प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या ऐसी बिक्री पारिश्रमिक कीमतों पर की गई थी। जैसा कि नीचे के अनुभागों में देखा जा सकता है, घरेलू उद्योग पाटित किए गए आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए लागत से नीचे बेचने के लिए बाध्य हुआ था। इस प्रकार, मूल्य और वित्तीय मापदंडों में गिरावट के माध्यम से प्राप्त मात्रा मापदंडों में सुधार क्षति की अनुपस्थिति का संकेत नहीं देता।
144. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आरआरपीसी ने तर्क दिया है कि मूल्य और मात्रा प्रभाव से संबंधित मुद्दे पृथक हैं और प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि केवल घरेलू उद्योग की बढ़ी हुई बिक्री और उसके परिणामस्वरूप बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि के तथ्य पर विचार करें। प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए ऐसे पृथक दृष्टिकोण से असहमत हैं। बिक्री/बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि की जांच कीमतों में गति का हिसाब रखे बिना स्वतंत्र रूप से नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसी गतियाँ विशेष रूप से जिंस उत्पादों के संबंध में हमेशा परस्पर जुड़ी होती हैं।

छ.3.3 पाटित किए गए आयातों का कीमत प्रभाव

145. एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध II (ii) के अनुसार पाटित किए गए आयातों के कीमतों पर प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को इस पर विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित किए गए आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुआ है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक अवसादित करना या मूल्य वृद्धियों को, जो अन्यथा घटित होतीं, महत्वपूर्ण स्तर तक रोकना है।

क) कीमत कटौती

146. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को न्यून कर रहे हैं, जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग के तुलनीय पीसीएन के विक्रय मूल्य से करके कीमत कटौती पीसीएन-वार निकाला गया है। इस प्रकार निर्धारित कीमत कटौती नीचे प्रदान किया गया है:

पीसीएन	पहुँच कीमत (₹/मी.टन)	निवल बिक्री वसूली (₹/मी.टन)	कीमत कटौती (₹/मी.टन)	कीमत कटौती (%)	कीमत कटौती सीमा
विचाराधीन उत्पाद (भारित औसत)	93,123	***	***	***	0-5

* आयात मात्राओं पर आधारित भारित औसत कीमत

147. देश-वार कीमत कटौती नीचे दिया गया है:

देश	पहुँच कीमत (भारित औसत) (₹/मी.टन)	निवल बिक्री वसूली (भारित औसत) (₹/मी.टन)	कीमत कटौती (₹/मी.टन)	कीमत कटौती (%)	कीमत कटौती सीमा
मलेशिया	78,860	***	***	***	20-30
सऊदी अरब	97,871	***	***	***	(10)-0
संयुक्त अरब अमीरात	93,659	***	***	***	0-10
संबद्ध देश	94,075	***	***	***	0-10

148. उपरोक्त से यह ध्यान दिया जाता है कि समग्र रूप से संबद्ध देशों से भारत औसत कीमत कटौती जांच अवधि के दौरान सकारात्मक है। आगे यह नोट किया जाता है कि सभी संबद्ध देशों में से केवल एक देश, अर्थात् सऊदी अरब के संबंध में कीमत कटौती ऋणात्मक है।

149. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि आवेदक ने संपूर्ण क्षति अवधि के लिए कीमत कटौती प्रदान नहीं किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के पैरा (ii) को स्मरण करते हैं, जिसमें "पाटित किए गए आयातों द्वारा कीमत कटौती" के निर्धारण की आवश्यकता है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि चूंकि पाटन का आकलन जांच अवधि के संबंध में किया जाता है, तदनुसार, कीमत कटौती भी केवल जांच अवधि के लिए निर्धारित किया जा सकता है न कि संपूर्ण क्षति अवधि के लिए।

150. एडीपीसीएल ने तर्क दिया है कि जांच अवधि में यूई की पहुँच कीमत सर्वोच्च है और इसलिए, यूई से आयातों को कोई क्षति आरोप्य नहीं है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते

हैं कि एक बार जब वे संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयातों की मात्रा को संचयित करने का निर्णय लेते हैं, तब व्यक्तिगत कीमत कटौती के रुझानों की जांच महत्वहीन हो जाती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो एडीपीसीएल और न ही यूई दूतावास ने यूई से संबद्ध आयातों के गैर-संचयन के लिए कोई तर्क प्रस्तुत किए हैं।

151. इसी प्रकार, सदारा ने दावा किया है कि भारत को उसके निर्यात उच्चतर कीमतों पर हैं और उसने घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुँचाई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्हें निर्यातक विशिष्ट कीमत कटौती की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

ख) कीमत हास/न्यूनीकरण

152. घरेलू बाजार में मूल्य दमन और अवसाद का विश्लेषण करने के प्रयोजन के लिए, आवेदकों ने (क) बिक्री लागत, (ख) घरेलू विक्रय मूल्य के बारे में सूचना प्रदान की है जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है।

कीमत हास/कीमत न्यूनीकरण

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
बिक्री लागत	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	125	106	105
पहुँच कीमत	₹/मी.टन	1,02,938	1,03,508	89,898	90,394
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	87	88
विक्रय मूल्य	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	111	90	91

153. यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत 2022-23 तक बढ़ी, और इसके बाद गिरी, तथापि, जांच अवधि में यह आधार वर्ष से ऊपर बनी रही है। इसके अलावा, आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच, विक्रय मूल्य 12 सूचकांक अंकों से गिरा है, और इसने

लगभग वही प्रवृत्ति अपनाया है जो आयातों की पहुँच कीमत का रहा है। इस प्रकार, जहाँ बिक्री लागत बढ़ी है, संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की कीमतों में गिरावट के कारण, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप अपने विक्रय मूल्य बढ़ाने में सक्षम नहीं था।

154. याचिका में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2022-23 में बिक्री लागत में वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागतों में वृद्धि से संचालित थी। इसके बाद, कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत गिर गई है। साथ ही, यह ध्यान दिया जाता है कि जहाँ संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत आधार वर्ष में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से ऊपर थी, 2022-23 से वे घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे रही हैं। इस प्रकार, संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग पर निरंतर मूल्य दबाव डाला है।
155. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग अपने विक्रय मूल्य को अपनी बिक्री लागत के अनुरूप बढ़ाने और घटाने में सक्षम रहा है और इसलिए, पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग पहुँच कीमत में गिरावट के बावजूद अपनी कीमत बढ़ाने में सक्षम रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों की पहुँच कीमत, वित्त वर्ष 2022-23 से, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे बनी हुई है। इसके अलावा, 2023-24 की तुलना में जांच अवधि के दौरान पाटित किए गए आयातों की पहुँच कीमत में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम रहा है।
156. प्राधिकारी अखिल भारतीय एचडीपीई/पीपी बुने कपड़े निर्माता संघ की अनुरोधों पर भी ध्यान देते हैं जिसमें यह कहा गया है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें आयात मूल्य समता पर निर्धारित करता है, इस प्रकार यह इंगित करता है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की पहुँच कीमतों का मिलान करने के लिए बाध्य है, और इस प्रकार घरेलू उद्योग की कीमत गतियाँ आवश्यक रूप से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमत की गति से जुड़ी हुई हैं।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

157. एडी नियमावली, 1995 का अनुबंध II प्रावधान करता है कि घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रत्याय या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन का परिमाण; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों की चर्चा नीचे की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्राएँ

158. प्राधिकारी ने क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	238	307
उत्पादन (विचाराधीन उत्पाद + गैर-विचाराधीन उत्पाद)	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	108	219	321
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	108	92	105
उत्पादन (पीयूसी)	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	155	503	826
घरेलू बिक्री	मी.टन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचकांक	100	152	511	798
-----------	---------	-----	-----	-----	-----

159. उपरोक्त से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- i. घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता और उत्पादन क्षति अवधि में बढ़े हैं। परिणामस्वरूप, घरेलू बिक्री भी क्षति अवधि में बढ़ी है।
- ii. घरेलू उद्योग ने समझाया है कि वित्त वर्ष 2023-24 और जांच अवधि के बीच सुधार एचएमईएल द्वारा विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री शुरू करने के कारण था।

160. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि एचएमईएल आधार वर्ष में अस्तित्व में नहीं था, इसलिए, प्राधिकारी जांच अवधि के क्षति मापदंडों की आधार वर्ष से तुलना नहीं कर सकता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष में किसी उत्पादक का अस्तित्व न होना प्राधिकारी को क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच करने से रोकता नहीं है। यह ध्यान दिया जाता है कि एडी नियमावली, 1995 और पाटन रोधी पर विश्व व्यापार संगठन समझौता दोनों प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच करने की अपेक्षा करते हैं न कि व्यक्तिगत घरेलू उत्पादकों की स्थिति की। तथापि, नीचे क्षति जांच के लिए, घरेलू उद्योग की स्थिति को, जैसा कि वह क्षति जांच अवधि के दौरान अस्तित्व में थी, उचित महत्व दिया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी को उन सभी तथ्यों की जांच करना आवश्यक है जो घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डाल सकते हैं जिसमें क्षति अवधि के दौरान किसी घरेलू उत्पादक द्वारा उत्पादन शुरू करने से संबंधित तथ्य शामिल हैं।

ख) बाजार हिस्सेदारी

161. घरेलू उद्योग और आयातों की बाजार हिस्सेदारी नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

बाजार हिस्सेदारी	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***

बाजार हिस्सेदारी	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	152	511	798
समर्थकों की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	104	99	106
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	72	76	72
कुल भारतीय बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	103	116
संबद्ध देशों से आयात	मी.टन	1,60,803	2,73,231	2,83,797	2,36,986
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	170	176	147
अन्य देशों से आयात	मी.टन	3,70,200	6,07,483	5,88,368	4,79,863
कुल आयात	मी.टन	5,31,004	8,80,714	8,72,165	7,16,849
भारत में मांग	मी.टन	33,78,651	32,65,325	35,74,741	36,31,353
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	97	106	107
बाजार हिस्सेदारी					

बाजार हिस्सेदारी	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
%					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
सीमा		0-10%	0-10%	10-20%	10-20%
घरेलू उद्योग + समर्थक	%	***	***	***	***
सीमा		70-80%	60-70%	50-60%	50-60%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
सीमा		50-60%	40-50%	30-40%	30-40%
भारतीय एलएलडीपीई उद्योग		***	***	***	***
सीमा		80-90%	70-80%	70-80%	70-80%
संबद्ध देश	%	5%	8%	8%	7%
सीमा		0-10%	10-20%	10-20%	0-10%
अन्य देश आयात	%	11%	19%	16%	13%
सीमा		10-20%	10-20%	10-20%	10-20%

162. उपरोक्त से, यह ध्यान दिया जाता है:

- i. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी जांच अवधि सहित क्षति अवधि में बढ़ी है, जबकि भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में गिर गई है।
- ii. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2022-23 तक लगभग स्थिर रही लेकिन इसके बाद बढ़ गई। इसके बाद, वित्त वर्ष 2023-24 में एचएमईएल द्वारा उत्पादन और बिक्री शुरू करने के साथ, पहले वित्त वर्ष 2022-23 में गिरने के बाद, वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू उद्योग और भारतीय एलएलडीपीई उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी।
- iii. घरेलू उद्योग और भारतीय एलएलडीपीई उद्योग की बाजार हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में जांच अवधि में बढ़ी। बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि मुख्यतः एचएमईएल के कारण है। तथापि, आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच भारतीय एलएलडीपीई उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की गई है।

163. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने टिप्पणी की है कि आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि घरेलू उद्योग को कोई क्षति न होने का संकेत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में एचएमईएल द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद, जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी वास्तव में बढ़ी है। तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि मुख्यतः एचएमईएल के कारण थी और ऐसी बढ़ी हुई बिक्री लागत से नीचे बिक्री करके प्राप्त की गई थी। इसी प्रकार, समग्र रूप से भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी भी 2023-24 और जांच अवधि में बढ़ी है। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में, अन्य भारतीय उत्पादकों और भारतीय एलएलडीपीई उद्योग की बाजार हिस्सेदारी गिर गई है।

164. आगे यह नोट किया जाता है कि यद्यपि वित्त वर्ष 2023-24 और जांच अवधि के बीच संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, आधार वर्ष की तुलना में, जांच अवधि में संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष के स्तरों से ऊपर बनी हुई है।

165. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि संबद्ध देशों से आयात अपेक्षाकृत स्थिर हिस्सा रखते हैं, और ऐसे सीमित हिस्से को घरेलू उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने

वाला नहीं माना जा सकता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पहले, भारतीय मांग में संबद्ध आयातों का हिस्सा महत्वपूर्ण है और आधार वर्ष की तुलना में बढ़ा है। इसके अलावा, जबकि संबद्ध देशों से आयात 2023-24 से गिरे हैं, जिस पहुँच कीमत पर ऐसे आयात भारत में प्रवेश किए हैं वह भी गिरी है। घरेलू उद्योग ने समझाया है कि उसे ऐसे आयातों से प्रतिस्पर्धा करने और अपनी बाजार हिस्सेदारी के लिए अपनी कीमतें कम करनी पड़ीं और लागत से नीचे बिक्री करनी पड़ी।

ग) मालसूची

166. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
औसत मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	113	1,115	1,040

167. यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में जांच अवधि में गिरी है और आधार वर्ष तथा 2022-23 की तुलना में बढ़ी है।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रत्याय

168. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर प्रत्याय और नकद लाभ नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
कर पूर्व लाभ	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(2509)	(5728)	(4950)
कर पूर्व ब्याज लाभ	₹/मी.टन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(431)	(921)	(864)
कर पूर्व लाभ	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(141)	(433)	(394)
नकद लाभ	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(674)	(1957)	(1645)
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
सीमा	%	0-10	(10)-0	(20)-(10)	(20)-(10)

169. उपरोक्त से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- i. यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान महत्वपूर्ण हानियाँ दर्ज की हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान नकद हानियाँ उठाईं और जांच अवधि के दौरान ऋणात्मक प्रत्याय संचित किया है।
- ii. प्राधिकारी आगे इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि एक नए उत्पादक, एचएमईएल, ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया है। यह जांच करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में गिरावट मूल्यहास और ब्याज लागत के कारण थी, प्राधिकारी ने एचएमईएल और एचपीएल की लागतों की तुलना की और मूल्यहास और ब्याज लागत को समान सीमा में पाया।
- iii. आगे यह नोट किया जाता है कि बिक्री मात्रा में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग का नियोजित पूंजी पर प्रत्याय ऋणात्मक बना हुआ है।

170. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बिक्री लागत में वृद्धि के कारण हानियाँ अर्जित कीं और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति आंतरिक अक्षमताओं के कारण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री लागत में वृद्धि वित्त वर्ष 2022-23 में कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण थी। आगे यह नोट किया जाता

है कि जबकि घरेलू उद्योग स्वउपभोग के लिए एथिलीन और प्रोपिलीन का निर्माण करता है, यह एथिलीन और प्रोपिलीन के लिए फीडस्टॉक बाजार कीमतों पर खरीदता है। इस प्रकार, लागत में वृद्धि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण थी और आंतरिक अक्षमताओं के कारण नहीं थी।

171. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि जांच अवधि के दौरान बिक्री लागत में गिरावट के बावजूद, घरेलू उद्योग हानियाँ उठाना जारी रखे हुए है और इसलिए, घरेलू उद्योग को हानियाँ संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत की गति के कारण नहीं हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत गिरी, संबद्ध देशों से संबद्ध आयात जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करते रहे। अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए, घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी लागत से नीचे बिक्री करना जारी रखा।
172. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि एचपीएल और एचएमईएल के बीच महत्वपूर्ण लागत और मूल्य अंतर मौजूद है। यह दावा किया गया है कि जबकि जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत 16% गिरी, एचपीएल की बिक्री लागत मात्र 5% गिरी, जो इंगित करता है कि लागत में कमी मुख्यतः एचएमईएल द्वारा संचालित थी, जो एक नया उत्पादक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्चा माल और उपयोगिताएँ घरेलू उद्योग की बिक्री की कुल लागत का 80-90% होती हैं और इस प्रकार, कच्चे माल की कीमतों और उपभोग लागत के प्रमुख चालक थे। प्राधिकारी ने आगे दोनों संस्थाओं के कच्चे माल के उपभोग मानदंडों की तुलना की और उन्हें समान पाया। दोनों संस्थाओं की लागत में अंतर मुख्यतः नियत लागत अवशोषण के स्तरों में अंतर के कारण है जो एचपीएल के मामले में अधिक था, जो कम कीमत वाले पाटित किए गए आयातों के निरंतर दबाव के कारण इसके निम्न उत्पादन और क्षमता उपयोग के कारण था।
173. एचपीएल के विपरीत, एचएमईएल ने 2017 में अपना संयंत्र चालू किया और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उत्पादन शुरू किया। एचएमईएल ने समझाया है कि एक बार जब उसने वित्त वर्ष 2023-24 में उत्पादन शुरू किया, तो स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए अपना उत्पादन और क्षमता उपयोग बढ़ाना आवश्यक था। इसके अलावा, उत्पादन में ऐसी वृद्धि भारत में संबद्ध वस्तुओं की बढ़ती मांग के अनुरूप थी।

174. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग जांच अवधि में बढ़ी हुई मूल्यहास और ब्याज लागत के कारण क्षति का सामना कर रहा है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्थापित क्षमता में वृद्धि के परिणामस्वरूप, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की ब्याज लागत और मूल्यहास वास्तव में बढ़े हैं। आगे यह नोट किया जाता है कि एचएमईएल और एचपीएल दोनों मूल्यहास के आवंटन के लिए सीधी रेखा पद्धति का पालन करते हैं और इस प्रकार इसे परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर आवंटित किया जाता है। जहाँ तक इस अनुरोध का प्रश्न है कि घरेलू उद्योग को हानियाँ पूर्णतः मूल्यहास और ब्याज लागत के कारण हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग न केवल नकद हानियों में है, बल्कि इसका मूल्यहास ब्याज कर पूर्व लाभ भी काफी ऋणात्मक है, जैसा कि नीचे तालिका से स्पष्ट है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
नकद लाभ	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(674)	(1,957)	(1,645)
ब्याज लागत	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	141	373	268
कर पूर्व लाभ (ब्याज लागत से पहले नकद लाभ)	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(141)	(433)	(394)

175. उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह नहीं मानते कि घरेलू उद्योग को क्षति बढ़े हुए मूल्यहास या ब्याज लागतों के कारण है।

ड) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

176. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	363	363
2	वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	103	765	739
3	प्रति दिन उत्पादकता	मी.टन/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	155	503	552
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	155	139	152

177. यह ध्यान दिया जाता है कि कर्मचारियों की संख्या और उनकी मजदूरी आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बढ़ी है।

178. प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता भी घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान निरंतर बढ़ी है।

च) वृद्धि

विवरण	2022-23	2023-24	जांच अवधि	जांच अवधि आधार वर्ष के संबंध में
उत्पादन	***	***	***	***
घरेलू बिक्री	***	***	***	***
कर पूर्व लाभ	(***)	(***)	(***)	(***)
नकद हानियाँ	***	(***)	(***)	(***)
नियोजित पूंजी पर आय	(***)	(***)	(***)	(***)

179. घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री स्थापित क्षमता और संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि के अनुरूप बढ़ी है। यह ध्यान दिया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों द्वारा डाले गए मूल्य दबाव के कारण, लाभप्रदता मापदंडों में काफी गिरावट आई है। इसके अलावा, जबकि उत्पादन और बिक्री बढ़ी है, बिक्री में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से कम थी।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

180. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि वह लाभ पर पर्याप्त प्रत्याय अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है और इसलिए, उसकी पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता काफी क्षतिग्रस्त हुई है। यह ध्यान दिया जाता है कि एचएमईएल ने 2017 में अपना संयंत्र चालू किया और अंततः वित्त वर्ष 2023-24 में उत्पादन शुरू किया। तथापि, लगभग 80-90% क्षमता उपयोग प्राप्त करने के बावजूद, एचएमईएल ऋणात्मक प्रत्याय अर्जित कर रहा है और नकद हानियों में है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि पाटित किए गए आयातों के कारण बढ़ती मांग के बावजूद कोई नया निवेश नहीं किया जा रहा है क्योंकि घरेलू उत्पादक पहले से किए गए निवेशों पर प्रत्याय अर्जित करने में सक्षम नहीं रहे हैं।

ज) पाटन का परिमाण

181. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की महत्वपूर्ण पाटन है, जिसने बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को प्रभावित किया है।
182. पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष करते हैं कि घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति पहुँची है।

छ.3.5 क्षति का समग्र आकलन

183. संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच निम्नलिखित दर्शाती है:
- संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान निरंतर उच्च स्तरों पर बने रहे हैं। जबकि संबद्ध देशों से संबद्ध आयात वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़ने के बाद गिर गए हैं, जांच अवधि में ऐसे आयातों की मात्रा आधार वर्ष के स्तर से ऊपर बनी हुई है।
 - संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत वित्त वर्ष 2023-24 में गिरी। यद्यपि, जांच अवधि के दौरान पहुँच कीमत में सुधार हुआ, संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करते रहे।
 - जांच अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्री शेष क्षति अवधि की तुलना में बढ़े हैं। तथापि, बिक्री में वृद्धि लागत से नीचे बिक्री करके प्राप्त की गई।
 - घरेलू उद्योग की मालसूची आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बढ़ी है।
 - घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन काफी खराब हुआ है। घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान ऋणात्मक प्रत्याय अर्जित कर रहा है और नकद हानियाँ उठा रहा है।

ज. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

184. प्राधिकारी ने जांच की कि क्या एडी नियमावली, 1995 के तहत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकते थे। प्राधिकारी ने पाटित किए गए आयातों के अतिरिक्त अन्य ज्ञात कारकों की जांच की है और पता लगाया है कि क्या ऐसे कारक घरेलू उद्योग को क्षति का कारण हो सकते थे, ताकि अन्य कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो, पाटित किए गए आयातों पर आरोपित न की जाए। इस संबंध में प्रासंगिक कारकों में, अन्य बातों के साथ,

पाटित कीमतों पर न बेची गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा, मांग में संकुचन या उपभोग के प्रतिरूप में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

185. यह नोट किया गया है कि गैर-विचाराधीन देशों से आयात भारत के कुल आयात का लगभग 65% हैं। ओमान, कतर और कुवैत से आयातों को छोड़कर, इन देशों से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और क्षतिरहित कीमत से 10% से 20% अधिक पहुँच मूल्य पर भारत में आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि इन वस्तुओं का भारत में पाटन किया जा रहा है। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण अन्य देशों से हुए आयातों को नहीं माना जा सकता।
186. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान कतर से आयातों की कीमतें पाटित आयातों की कीमतों के तुलनीय थीं। तथापि, कतर से आयात भारत में पाटित नहीं पाए गए। इसके अतिरिक्त, ये आयात भारत के कुल आयात के 3% से कम तथा भारतीय माँग के लगभग 0.5% हैं।
187. कुवैत और ओमान से विचाराधीन आयात पाटित पाए गए हैं। तथापि, प्रत्येक देश से ऐसे आयात भारत के कुल आयात के 3% से कम हैं।

ख) मांग में संकुचन

188. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग, वित्त वर्ष 2022-23 में मामूली गिरावट के बाद, शेष क्षति जांच अवधि में निरंतर बढ़ी है। इसलिए, घरेलू उद्योग को मांग में संकुचन के कारण क्षति नहीं पहुँची है।

ग) उपभोग का प्रतिरूप

189. यह ध्यान दिया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोग के प्रतिरूप में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकता था।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

190. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी हो सकता था।

ड) प्रौद्योगिकी में विकास

191. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकता था।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

192. ऊपर जांची गई क्षति सूचना केवल घरेलू उद्योग के उसके घरेलू बाजार के संदर्भ में निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, पहुँचाई गई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन पर आरोपित नहीं की जा सकती।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

193. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।
194. उपर्युक्त कारकों के अलावा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित ज्ञात कारकों की जांच का अनुरोध किया है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकते थे:

क. घरेलू उद्योग को क्षति एथिलीन के लिए कच्चे माल के रूप में नैप्था के उपयोग के कारण अंतर्निहित लागत हानि के कारण है

195. आरआरपीसी ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग एथिलीन के निर्माण के लिए नैप्था का उपयोग करने के कारण क्षति का सामना कर रहा है, जबकि सऊदी उत्पादक कच्चे माल के निर्माण के लिए ईथेन का उपयोग करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कारणात्मक संबंध विश्लेषण के तहत, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों से निर्यातकों की संरचना में अंतर को संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में, प्राधिकारी ईयू - बायोडीजल (अर्जेटीना) में पैनल की टिप्पणियों को स्मरण करते हैं:

"7.522. अर्जेटीना मुख्य रूप से ईयू प्राधिकारियों के इस निष्कर्ष पर आपत्ति उठाता है कि ईयू उद्योग की संरचना क्षति का कारण नहीं थी। अर्जेटीना द्वारा पहचाने गए दो कारक, अर्थात् ऊर्ध्वधर एकीकरण की कमी और कच्चे माल तक पहुँच की कमी,

अनिवार्य रूप से ईयू घरेलू उद्योग की अंतर्निहित विशेषताएँ हैं जो, अर्जेंटीना के अनुसार, इसे अर्जेंटीनी उत्पादकों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी बनाती हैं। तथापि, हमारे विचार में, तर्क की यह पंक्ति पाटन रोधी समझौते के अनुच्छेद 3 और इसके विभिन्न पैराग्राफों, जिसमें अनुच्छेद 3.5 शामिल है, के गलत पठन पर आधारित है। अनुच्छेद 3 द्वारा परिकल्पित क्षति की अवधारणा घरेलू उद्योग की स्थिति में नकारात्मक घटनाक्रमों से संबंधित है। अनुच्छेद 3 का आशय निर्यातक सदस्य की तुलना में घरेलू उद्योग की संरचना में अंतर को संबोधित करना नहीं है। बल्कि, अनुच्छेद 3.5 के पाठ से और ऐसे 'अन्य कारकों' की इसकी संकेतात्मक सूची से - जो सभी घरेलू उद्योग की स्थिति के घटनाक्रमों से संबंधित हैं - यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी को उन विशेषताओं के संबंध में गैर-आरोपण विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है जो घरेलू उद्योग में अंतर्निहित हैं और जांच प्राधिकारी द्वारा अपने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए विचार की गई अवधि के दौरान अपरिवर्तित रही हैं।"

196. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तथ्य यह है कि घरेलू उद्योग के दोनों घटक आधार वर्ष की शुरुआत से (एचएमईएल के मामले में उत्पादन शुरू होने से) एक ही फीडस्टॉक से एथिलीन का निर्माण करते हैं। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की फीडस्टॉक संरचना स्थिर थी। एक कारक जो प्रकृति में स्थैतिक है, जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता में गिरावट की व्याख्या नहीं कर सकता। तदनुसार, इस कारक के लिए कोई गैर-आरोपण विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

ख. क्षति कमजोर वैश्विक मांग के कारण है

197. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति कमजोर वैश्विक मांग के कारण है और यह तथ्य स्वयं एचपीएल की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में मांग क्षति अवधि में निरंतर बढ़ी है। आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच, मांग 7% बढ़ी है। इसके अलावा, भारतीय मांग ने सकारात्मक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की है। जबकि किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने वैश्विक उपभोग के संबंध में कोई आंकड़ा प्रदान नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच कर रहे हैं, जिसने मांग में स्थिर वृद्धि देखी है। तदनुसार, यह नहीं माना जा सकता कि क्षति कमजोर वैश्विक मांग के कारण है।

ग. क्षति अन्य घरेलू उत्पादकों के कारण और एचएमईएल के भारतीय बाजार में प्रवेश के कारण है

198. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति घरेलू उत्पादकों के बीच अंतर-प्रतिस्पर्धा के कारण है। यह आरोप लगाया गया है कि एचएमईएल, एक नया बाजार प्रवेशी होने के नाते, स्थापित खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आक्रामक मूल्य निर्धारण का सहारा लिया है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार में विभिन्न खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा बाजार शक्तियों का स्वाभाविक परिणाम है और इसलिए, सामान्य बाजार स्थिति है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उपयोगकर्ता उद्योग की अनुरोधों से कि घरेलू उत्पादक आयात मूल्य समता का अनुसरण करते हैं। तथापि, यह जांच करने के लिए कि क्या एचएमईएल ने अन्य भारतीय उत्पादकों के हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था, प्राधिकारी ने तीन घरेलू उत्पादकों की बिक्री की तुलना की है:

बिक्री (मी.टन)	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	***	***	***	***
सूचकांक	100	104	99	106
एचपीएल	***	***	***	***
सूचकांक	100	152	90	97
एचएमईएल	-	-	***	***
सूचकांक	-	-	100	167

199. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि एचएमईएल आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीति अपना रहा होता, तो अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री नहीं बढ़ी होती। तथापि, जैसा कि ऊपर आंकड़ों से देखा जा सकता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और

एचपीएल दोनों जांच अवधि के दौरान अपनी घरेलू बिक्री बढ़ाने में सक्षम थे। तदनुसार, यह नहीं कहा जा सकता कि क्षति एचएमईएल की मूल्य निर्धारण रणनीति के कारण है।

घ. एचएमईएल एक नया प्रवेशी है और क्षति अवधि के दौरान प्रचालनात्मक अवस्था में था

200. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि एचएमईएल क्षति अवधि के दौरान प्रचालनात्मक अवस्था में था और इसलिए, क्षति यदि कोई है, पाटित किए गए आयातों के कारण नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचएमईएल ने जांच अवधि के दौरान 80-90% का क्षमता उपयोग प्राप्त किया। इसके अलावा, प्राधिकारी ने एचएमईएल और एचपीएल के उपभोग मानदंडों की तुलना की है और उन्हें तुलनीय पाया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यदि घरेलू उद्योग को क्षति नए निवेश के कारण होती, तो ऐसी क्षति, वर्तमान तथ्यों के विपरीत, नकद हानियों और ऋणात्मक मूल्यहास ब्याज कर पूर्व लाभ में परिणत नहीं होती। तदनुसार, यह नहीं माना जा सकता कि एचएमईएल को क्षति उसके हाल ही में उत्पादन शुरू करने के कारण है।

201. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि एचएमईएल को उसके उत्पादन के पहले वर्ष में हानियाँ प्रारंभिक अक्षमताओं के कारण थीं जो पाटन के बावजूद जांच अवधि में कम हो गई हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचएमईएल ने वित्त वर्ष 2023-24 में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन शुरू किया। कच्चे माल और उपयोगिता मानदंड, उत्पादन के प्रारंभिक वर्ष के लिए भी, अन्य घरेलू उत्पादक के साथ तुलना किए गए और तुलनीय पाए गए। इसके अलावा, एचएमईएल की रूपांतरण लागत भी भाग लेने वाले विदेशी उत्पादकों से तुलनीय पाई गई।

ड. क्षति अन्य संबद्ध देशों के कारण है

202. कुवैत, ओमान, कतर और यूई के भाग लेने वाले निर्यातकों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति अन्य संबद्ध देशों के कारण है न कि उनके संबंधित संबद्ध देशों के कारण। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के पैरा (ii) के अनुसरण में उन्होंने संबद्ध देशों से आयातों को संचयित किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों

ने व्यक्तिगत संबद्ध देशों के आयातों के गैर-संचयन के संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने ऐसे तर्कों पर विचार नहीं किया है।

ज.1 कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

203. जबकि एडी नियमावली, 1995 के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचाई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित किए गए आयातों के कारण पहुँची है।
- i. संबद्ध देशों से संबद्ध आयात निरपेक्ष रूप में बढ़े हैं और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में सापेक्ष रूप में महत्वपूर्ण बने रहे हैं। विशेष रूप से, भारतीय उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद आयात बढ़े हुए स्तरों पर बने रहे हैं।
 - ii. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन हो रहा है।
 - iii. समग्र रूप से संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक है।
 - iv. संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी नीचे है और इस प्रकार, घरेलू उद्योग को लागतों की वसूली और युक्तियुक्त प्रत्याय अर्जित करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक रही है।
 - v. भारतीय एलएलडीपीई उद्योग की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में गिर गई है, जबकि संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ गई है।
 - vi. लागतों में कमी और विक्रय मूल्यों में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग ऋणात्मक प्रत्याय अर्जित करता रहा है और जांच अवधि के दौरान नकद हानियाँ उठाई हैं।
204. प्राधिकारी, पूर्वोक्त के मद्देनजर, यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध विद्यमान है।

झ. क्षति अंतर का परिमाण

205. प्राधिकारी ने एडी नियमावली, 1995 के साथ पठित अनुबंध III, यथासंशोधित, में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति अंतर की गणना के लिए

व्यक्तिगत संबद्ध देशों से पहुँच कीमत की तुलना करने हेतु क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि में कच्चे माल और उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या अनावर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध III में निर्धारित अनुसार क्षति रहित कीमत पर पहुँचने के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात्, औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियाँ जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर युक्तियुक्त प्रत्याय (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमत किया गया था।

206. एडीपीसीएल और सदारा ने तर्क दिया है कि अगस्त 2023 में एचएमईएल का उत्पादन शुरू होने को देखते हुए, इसके क्षति अंतर की गणना के लिए अनुबंध III को सीधे तौर पर लागू नहीं किया जा सकता और उन्होंने एचएमईएल के आंकड़ों को इसकी परियोजना रिपोर्ट में अनुमानों के साथ इष्टतम करने का अनुरोध किया है। उन्होंने आगे अनुरोध किया है कि केवल स्थापित उत्पादक, एचपीएल, के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए ताकि एचएमईएल की क्षति रहित कीमत बढ़ा-चढ़ाकर न आंकी जाए। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचएमईएल और एचपीएल दोनों विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए समान कच्चे माल और उपयोगिताओं का उपयोग करते हैं। प्राधिकारी ने आगे दोनों घरेलू उत्पादकों के कच्चे माल के उपभोग मानदंडों की तुलना की है और ऐसे उपभोग को समान सीमा में पाया है।
207. जहाँ तक एचएमईएल के आंकड़ों के इष्टतमीकरण का प्रश्न है, प्राधिकारी ने अनुबंध-III के प्रयोजन के लिए कच्चे माल और उपयोगिताओं के इष्टतमीकरण और एचएमईएल के लिए क्षति रहित कीमत के निर्धारण हेतु जांच अवधि के तिमाही आंकड़ों पर विचार किया है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि एचपीएल और एचएमईएल दोनों के उपभोग मानदंड समान सीमा में हैं और इसलिए, एचएमईएल की क्षति रहित कीमत की गणना के लिए एचपीएल के आंकड़ों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, प्राधिकारी के लिए सदारा और एडीपीसीएल की अनुरोधों को स्वीकार करने का कोई कानूनी या व्यावहारिक आधार नहीं है।

208. उपरोक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एकल संस्था माना गया है और एकल क्षति अंतर आरोपित किया गया है जिसकी गणना सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के क्षति अंतरों के भारत औसत के आधार पर की गई थी।
209. पहुँच कीमत और ऊपर निर्धारित क्षति रहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति अंतर नीचे तालिका में प्रदान किया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक	पीसीएन	क्षति रहित कीमत (\$/मी.टन)	पहुँच कीमत (\$/मी.टन)	क्षति मार्जिन (\$/मी.टन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (सीमा)
सऊदी अरब						
अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या")	एनएमजी	***	***	***	***	10-20
अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी ("पेट्रोकेम्या")	एनएमजी	***	***	***	***	20-30
ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी ("शर्क")	एनएमजी	***	***	***	***	20-30
जुबैल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी ("यूनाइटेड")	एनएमजी	***	***	***	***	20-30
राबिघ रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कंपनी	एनएमजी	***	***	***	***	20-30

सदारा केमिकल कंपनी	एनएमजी	***	***	***	***	0-10
यान्बू राष्ट्रीय पेट्रोकेमिकल कंपनी ("यानसाब")	एनएमजी	***	***	***	***	20-30
सऊदी अरामको - सैबिक समूह	एनएमजी	***	***	***	***	10-20
अन्य	सभी	***	***	***	***	20-30
यूई						
अबू धाबी पॉलिमर्स कंपनी लिमिटेड	एनएमजी	***	***	***	***	10-20
अबू धाबी पॉलिमर्स कंपनी लिमिटेड	एमपीजी	***	***	***	***	20-30
अबू धाबी पॉलिमर्स कंपनी लिमिटेड	भारित औसत	***	***	***	***	10-20
अन्य	सभी	***	***	***	***	30-40
मलेशिया						10-20
सभी	सभी	***	***	***	***	30-40

ज. शुल्क प्रभाव आकलन
सार्वजनिक हित और घरेलू उद्योग हित

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

210. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि एलएलडीपीई पैकेजिंग, फिल्मों, ढले हुए वस्तुओं और अन्य प्लास्टिक प्रसंस्करण अनुप्रयोगों सहित कई अनुप्रवाह क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है।
- ii. यह तर्क दिया गया कि पाटन रोधी शुल्क लगाने से अनुप्रवाह उपयोगकर्ता उद्योगों की इनपुट लागत बढ़ेगी और भारतीय उपयोगकर्ताओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है।
- iii. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने भारत में मांग-आपूर्ति की स्थिति पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि घरेलू उत्पादन कुल उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने तर्क दिया कि आयातों पर कोई भी शुल्क आपूर्ति बाधाओं को और बढ़ा सकता है।
- iv. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि भारत में एलएलडीपीई की मांग बढ़ने की अपेक्षा है और इसलिए, घरेलू आपूर्ति अंतराल को पाटने के लिए आयात आवश्यक बने रहते हैं।
- v. हितबद्ध पक्षकारों ने एलएलडीपीई आयातों पर मूल सीमा शुल्क की अस्थायी छूट का भी उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि सरकार का नीतिगत उद्देश्य पेट्रोरासायनिक इनपुटों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना, अनुप्रवाह उद्योगों पर लागत दबाव कम करना और आपूर्ति स्थिरता बनाए रखना था।
- vi. यह तर्क दिया गया कि यह जांच करते समय कि क्या पाटन रोधी शुल्क वाणिज्यिक और नीतिगत रूप से उचित है, प्रचलित भूराजनीतिक घटनाक्रमों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान पर विचार किया जाना चाहिए।
- vii. एसआरटीपीएल ने प्रस्तुत किया कि यह एक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र है और कोई भी पाटन रोधी शुल्क लगाने से इसकी अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं।
- viii. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी प्रस्तुत किया कि घरेलू उद्योग का यह दावा कि शुल्क प्रभाव 1% से कम होगा, प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, चूंकि गणना निर्यातकों को प्रकट नहीं की गई थी।
- ix. भारतीय प्रसंस्कर्ता पहले से ही व्यवस्थित रूप से उच्च इनपुट लागतों के अधीन हैं, जहाँ विदेशी आपूर्तिकर्ता भारत को ऐसी कीमतों पर सामग्री प्रदान करते हैं जो चीन

- जैसे बाजारों को प्रस्तावित कीमतों से 150-200 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन अधिक हैं। यह अंतर बाजार-चालित नहीं है बल्कि भारत में पाटन रोधी कार्रवाइयों के अनुमानित जोखिम का परिणाम है।
- x. घरेलू उद्योग सीमा शुल्क (7.5%) और भाड़े सहित आयात मूल्य समता पर सामग्री की आपूर्ति करता है। यह प्रभावी रूप से सुनिश्चित करता है कि घरेलू उत्पादक संपूर्ण शुल्क संरक्षण प्राप्त करें, जबकि अनुप्रवाह उपयोगकर्ता वैश्विक मानकों के सापेक्ष बढ़ी हुई कीमतों पर कच्चे माल की खरीद जारी रखते हैं।
- xi. शुल्क लगाने से कृत्रिम रूप से घरेलू कीमतें बढ़ेंगी, प्रतिस्पर्धी अनुशासन समाप्त होगा, और अनुप्रवाह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कीमत पर घरेलू उद्योग को अनुचित मूल्य निर्धारण शक्ति प्रदान करेगा।
- xii. घरेलू इनपुट लागतों में वृद्धि भारतीय प्रसंस्कर्ताओं को वियतनाम और अन्य आसियान अर्थव्यवस्थाओं जैसे देशों की तुलना में संरचनात्मक रूप से अप्रतिस्पर्धी बना देगी, जो मुक्त व्यापार समझौतों के तहत अधिमान्य व्यापार पहुँच से लाभान्वित होते हैं और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल तक पहुँच रखते हैं।
- xiii. यदि कच्चे माल के आयात प्रतिबंधित होते हैं, तो तैयार वस्तुओं का आयात बढ़ जाएगा, जिससे घरेलू उत्पादन का प्रत्यक्ष विस्थापन होगा। अनुप्रवाह उद्योग, जो मूल्य जोड़ता है और बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करता है, पीड़ित होगा।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

211. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई परिमाणित अंतिम-उपयोगकर्ता प्रभाव आकलन प्रदान नहीं किया था।
 - यह प्रस्तुत किया गया कि, इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने यह स्थापित करने वाली विस्तृत गणनाएँ अभिलेख पर रखी थीं कि अंतिम उपयोगकर्ताओं पर पाटन रोधी शुल्क का प्रभाव 1% से कम होगा।
 - घरेलू उद्योग ने आगे प्रस्तुत किया कि पाटन रोधी शुल्क एक सुधारात्मक व्यापार उपचार है और आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता। यह केवल सुनिश्चित करता है कि आयात निष्पक्ष और क्षति रहित कीमतों पर भारत में प्रवेश करें।

- iv. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि एलएलडीपीई पर सीमा शुल्क को अस्थायी रूप से हटाना केवल मध्य पूर्व की स्थिति से जुड़ा एक अस्थायी उपाय था और इसे पाटन रोधी संरक्षण से इनकार करने का कारण नहीं माना जा सकता।
- v. यह भी तर्क दिया गया कि पाटन रोधी शुल्क प्रकृति में भावी हैं और भूराजनीतिक स्थिति काफी हद तक स्थिर हो गई थी।
- vi. घरेलू उद्योग ने आगे प्रस्तुत किया कि सीमा शुल्क हटाने से पाटित किए गए आयातों के विरुद्ध घरेलू उद्योग को उपलब्ध सीमित संरक्षण कम हो गया था और इसलिए, उपयुक्त पाटन रोधी शुल्क की आवश्यकता और मजबूत हो गई थी।
- vii. यह भी प्रस्तुत किया गया कि संबद्ध देशों से निर्यातक जहाजरानी मार्गों में अचानक व्यवधान के कारण उच्च मालसूची धारण कर रहे थे और, एक बार स्थिति सामान्य होने पर, ऐसी मालसूची आक्रामक रूप से भारत में पाटित की जा सकती थी, जिससे घरेलू उत्पादकों को क्षति और बढ़ सकती थी।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

212. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरू करने की सूचना जारी की। इसके अलावा, प्राधिकारी ने उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं से वर्तमान जांच से संबंधित प्रासंगिक सूचना प्रदान करने का भी अनुरोध किया जिसमें अंतिम उपयोगकर्ताओं पर पाटन रोधी शुल्क लगाने का संभावित प्रभाव, विचाराधीन उत्पाद की प्रतिस्थापनीयता, मांग की कीमत-संवेदनशीलता, दीर्घकालिक अनुबंध आदि शामिल हैं।
213. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार उपचारात्मक उपाय लगाने का उद्देश्य आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है बल्कि अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को पहुँचाई गई क्षति को दूर करना और भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा स्थापित करना है। प्राधिकारी वास्तव में इस बात से अवगत हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों तक सीमित नहीं है बल्कि विचाराधीन उत्पाद के उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है। जबकि शुल्क लगाने से घरेलू रूप से प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं लेकिन यह समवर्ती रूप से देश के भीतर नए उत्पादकों के उद्भव या आगे के निवेशों को भी प्रोत्साहित कर सकता है।

214. प्राधिकारी नोट करते हैं कि दो उपयोगकर्ता उद्योगों, अर्थात् एसआरटीपीएल और ईएमसीआईपीएल, ने वर्तमान जांच में भाग लिया है। जबकि एसआरटीपीएल ने आर्थिक हित प्रश्नावली दाखिल की है, ईएमसीआईपीएल ने आर्थिक हित प्रश्नावली दाखिल नहीं की है और स्वीकार्य रूप से, यह विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन या उपयोग में शामिल नहीं है। इसके अलावा, एसआरटीपीएल, स्वीकार्य रूप से, एक अनुसंधान केंद्र ने पाटन रोधी शुल्कों के प्रभाव की कोई गणना दाखिल नहीं की है। उपरोक्त उपयोगकर्ताओं के अलावा, अखिल भारतीय एचडीपीई/पीपी बुने कपड़े निर्माता संघ, एक उपयोगकर्ता उद्योग संघ ने भी वर्तमान जांच में भाग लिया है। तथापि, इसने संबद्ध वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्कों के प्रभाव से संबंधित कोई गणना प्रदान नहीं की है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने अंतिम-उपयोगकर्ता प्रभाव आकलन प्रदान किया है, जो दर्शाता है कि पाटन रोधी शुल्कों का प्रभाव, यदि अनुशंसित किया जाए, 1% से कम होगा।
215. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी शुल्क एक उपचारात्मक व्यापार उपाय है न कि आयातों पर प्रतिबंध। इसका उद्देश्य पाटित किए गए आयातों से उत्पन्न अनुचित मूल्य निर्धारण लाभ को निष्प्रभाव करने और भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करने तक सीमित है। यह संबद्ध देशों से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता, न ही यह उपयोगकर्ताओं को वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से एलएलडीपीई प्राप्त करने से रोकता है।
216. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि शुल्क लगाने के बाद भी भारतीय बाजार में घरेलू उत्पादकों, शुल्क-भुगतान वाले देशों से आयात और असंबद्ध देशों से आयात जारी रहेगा। इसलिए, यह आशंका कि पाटन रोधी शुल्क के परिणामस्वरूप एलएलडीपीई की अनुपलब्धता या आपूर्ति व्यवधान होगा, समर्थित नहीं है।
217. प्राधिकारी का कहना है कि उपयोगकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में अनुरोध सामान्य प्रकृति के हैं। किसी भी प्रयोक्ता ने ऐसा सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध हो कि निर्धारित शुल्क के कारण डाउनस्ट्रीम परिचालन अव्यवहार्य हो जाएंगे, उत्पादन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी अथवा उपभोक्ता मूल्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
218. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एलएलडीपीई डाउनस्ट्रीम उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले कई इनपुट में से केवल एक है। ऐसे उत्पादों की अंतिम कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें रूपांतरण लागत, श्रम, बिजली, योज्य, माल भाड़ा, वितरण लागत,

प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी और मार्जिन शामिल हैं। इसलिए, एलएलडीपीई में किसी भी वृद्धि को तैयार उत्पादों की कीमत में समतुल्य वृद्धि के साथ यांत्रिक रूप से नहीं जोड़ा जा सकता है।

219. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई गणनाओं की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैकेजिंग, मोल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद आम तौर पर विभिन्न प्रकार के एलएलडीपीई और अन्य पॉलीइथाइलीन जैसे एलडीपीई का संयोजन हैं। प्राधिकरण ने विभिन्न उत्पादों पर प्रभाव का आकलन निम्नानुसार किया है। इसे नीचे दर्शाया गया है:

Impact of Anti-Dumping Duty (ADD) on LLDPE Users & Consumers in India

Illustrative downstream impact analysis at ADD = USD 100/MT



₹ USD 100/MT ADD = approx. ₹9.68 per kg of LLDPE



Assumptions: Exchange rate: ₹96.8441/USD

#	Product	₹ Indicative Product Value	Article Weight	LLDPE Content	₹ Impact at USD 100/MT ADD (₹ increase per unit & % Impact)	
1	1 litre milk pouch	₹60	5 g	60%	₹0.03 per pouch (0.05%)	✓ Low Impact
2	1 kg rice / pulses pouch	₹60	8 g	60%	₹0.05 per pouch (0.08%)	✓ Low Impact
3	500 g snack / frozen food pouch	₹100	6 g	50%	₹0.03 per pouch (0.08%)	✓ Low Impact
4	Small retail carry bag	Goods value ₹300	10 g	70%	₹0.07 per bag (0.02%)	✓ Low Impact
5	Courier / e-commerce poly mailer	Shipment value ₹500	15 g	70%	₹0.10 per mailer (0.02%)	✓ Low Impact
6	25 kg industrial liner / bag	Packed goods value ₹1,000	60 g	70%	₹0.41 per bag (0.04%)	✓ Low Impact
7	50 kg heavy duty sack / liner	Packed goods value ₹1,125	120 g	70%	₹0.81 per bag (0.07%)	✓ Low Impact
8	Shrink film for multipack / carton	Packed goods value ₹500	20 g	90%	₹0.17 per pack (0.03%)	✓ Low Impact
9	Pallet stretch wrapping film	Goods value ₹50,000	500 g	90%	₹4.36 per pallet (0.009%)	✓ Low Impact

Absolute impact per unit at USD 100/MT ADD (₹ increase per unit)



CONSUMER PACKAGING
mostly **0.02%** to **0.08%**
of product value



INDUSTRIAL PACKAGING
around **0.03%** to **0.07%**
of packed product value



For most consumer and industrial applications, the impact of ADD at USD 100/MT is only **below 0.1%** of product value.



220. जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, अंतिम उपभोक्ता उत्पाद पर शुल्कों का प्रभाव 0.5% से कम होगा।
221. अखिल भारतीय एचडीपीई संघ ने प्रस्तुत किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातक भारत में पाटन रोधी कार्रवाइयों के अनुमानित जोखिम के कारण, उन कीमतों से 150-200 अमेरिकी डॉलर अधिक कीमत वसूलते हैं जिन पर ऐसी वस्तुएँ चीन को निर्यात की जाती हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन में कीमतें भारतीय बाजार की तुलना में अनेक कारकों जैसे आदेशों की मात्रा, मांग, वाणिज्यिक शर्तों आदि के कारण भिन्न हो सकती हैं। इसके अलावा, यदि निर्यातक दोनों बाजारों में निष्पक्ष व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसे अंतर कीमत का कोई कारण नहीं है।
222. पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भारतीय बाजार में कीमतों में वृद्धि के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-संबद्ध देशों के माध्यम से आयातों की एक महत्वपूर्ण मात्रा आती रहेगी। जांच अवधि के दौरान, लगभग 65% संबद्ध आयात गैर-संबद्ध देशों से आयात किए गए थे। इसके अलावा, भारतीय एलएलडीपीई बाजार अनेक एलएलडीपीई निर्माताओं की उपस्थिति से चित्रित है। इस प्रकार, घरेलू उत्पादकों के बीच आंतरिक प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ गैर-संबद्ध देशों से प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करेगी कि संबद्ध वस्तुएँ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध रहेंगी।
223. इसके अलावा, चूंकि लगभग 62% संबद्ध आयात गैर-संबद्ध देशों से आयातित होते रहेंगे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपभोक्ताओं के पास घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के अलावा संबद्ध वस्तुओं की खरीद के लिए अनेक स्रोत बने रहेंगे।
224. प्राधिकारी हाल के पश्चिम एशिया संकट के प्रकाश में, विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई मूल सीमा शुल्कों से छूट पर भी ध्यान देते हैं। यह ध्यान दिया जाता है कि उक्त छूट प्रकृति में अस्थायी है और जांच अवधि में घटित पाटन और क्षति के तथ्य पर कोई प्रभाव नहीं डालती।
225. प्राधिकारी यह भी मान्यता देते हैं कि दीर्घकालिक आपूर्ति सुरक्षा के लिए एक व्यवहार्य घरेलू एलएलडीपीई उद्योग महत्वपूर्ण है। निरंतर पाटन कुछ उपयोगकर्ताओं को अस्थायी मूल्य

लाभ दे सकती है, लेकिन यह घरेलू उत्पादन को कमजोर करेगी, निवेश घटाएगी, क्षमता उपयोग को क्षतिग्रस्त करेगी और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता बढ़ाएगी।

226. इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि सार्वजनिक हित का आकलन व्यापक रूप से किया जाना चाहिए, जिसमें निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, घरेलू विनिर्माण क्षमता, रोजगार, निवेश, आपूर्ति स्थिरता और भारतीय मूल्य श्रृंखला की दीर्घकालिक सुदृढ़ता शामिल है।
227. तदनुसार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष करते हैं कि उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं पर कथित प्रतिकूल प्रभाव अप्रमाणित और अतिरंजित है। पाटन रोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे, कमी उत्पन्न नहीं होगी या उपयोगकर्ताओं पर असंगत बोझ नहीं पड़ेगा। यह केवल सुनिश्चित करेगा कि आयात निष्पक्ष कीमतों पर भारत में प्रवेश करें और घरेलू उद्योग को क्षति न पहुँचाएँ।

ट. प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियाँ

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

228. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

सामान्य

- i. भारत ने सऊदी अरब से निर्यात, विशेष रूप से रसायनों और पेट्रो-रसायनों, के विरुद्ध बड़ी संख्या में व्यापार उपचार जाँचें प्रारंभ की हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि बार-बार जाँचें प्रारंभ किए जाने से द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इनका उपयोग संरक्षणवादी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

पात्रता

- ii. प्राधिकारी को समान वस्तु के सभी प्रासंगिक घरेलू उत्पादकों को शामिल करने के बाद स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित करना चाहिए कि एचपीएल और एचएमईएल कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात रखते हैं या नहीं।
- iii. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा घरेलू बिक्री को प्रतिबंधित नहीं करता। ऐसी बिक्री का कानूनी परिणाम केवल यह है कि उस पर लागू सीमा-शुल्क देय होता है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि संबंधित उत्पादक पाटनरोधी जाँच में घरेलू उद्योग की पात्रता के निर्धारण के लिए अप्रासंगिक हो जाता है।

- iv. ओपीएएल भारत में एलएलडीपीई का उत्पादन कर रहा था और भारतीय बाजार में इसकी पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति कर रहा था। ऐसे उत्पादक को कुल घरेलू उत्पादन से बाहर रखने पर भारतीय उद्योग की वास्तविक स्थिति का पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं होता।
- v. आरआईएल के आँकड़ों के संबंध में पूर्ण और सत्यापन योग्य प्रकटीकरण के अभाव में, आरआरपीसी घरेलू उद्योग की पात्रता पर सार्थक टिप्पणी नहीं कर सकता।

न्यून मात्रा वाले आयात

- vi. कुवैत से आयात की मात्रा कुल आयात का 2.44% तथा ओमान से आयात की मात्रा 2.90% है। चूँकि प्रत्येक देश से आयात का हिस्सा 3% से कम है और दोनों देशों का सामूहिक हिस्सा कुल आयात की मात्रा के 7% से कम है, अतः प्राधिकारी को नगण्य आयात मात्रा के आधार पर कुवैत और ओमान के विरुद्ध जाँच समाप्त करनी चाहिए।

उत्पादक/निर्यातक-विशिष्ट मुद्दे

- vii. केम्या ने विक्रय एवं वितरण व्यय समायोजन का विरोध करते हुए कहा कि उसने ये व्यय वहन नहीं किए। यदि समायोजन बनाए रखे जाते हैं, तो सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और सामान्य व्यापार क्रम परीक्षण में समान पद्धति अपनाई जानी चाहिए।
- viii. शार्क और एसपीडीसी ने मित्सुबिशी को संबद्ध पक्ष मानने का विरोध किया और अनुरोध किया कि उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग, यदि किया जाए, तो केवल मित्सुबिशी के माध्यम से किए गए निर्यात तक सीमित रहे।
- ix. आरआरपीसी ने कहा कि सुमितोमो माध्यम उसके निर्यात के केवल एक भाग से संबंधित था। उसने उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग उसी माध्यम तक सीमित रखने और सहयोगी समूह उत्पादकों पर लागू भारित औसत दर देने का अनुरोध किया।
- x. सदारा ने सऊदी अरामको-सैबिक समूह के लिए एक समान दर का विरोध किया। उसके अनुसार, केवल समान शेरधारिता परिचालन नियंत्रण या निर्यात को अन्य उत्पादक के माध्यम से मोड़ने की क्षमता सिद्ध नहीं करती।
- xi. सदारा ने यह भी दावा किया कि डाउ और सैबिक की विपणन संस्थाएँ उसकी विस्तारित विक्रय शाखाओं के रूप में कार्य करती हैं। इसलिए उनके विक्रय, सामान्य

एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ की कटौती नहीं की जानी चाहिए और विपणन शुल्क के साथ इनकी कटौती दोहरी कटौती होगी।

- xii. डीसीआईपीएल ने कहा कि उसने केवल ऋण लागत का दावा किया था और प्रकटीकरण में माल-भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन तथा बंदरगाह व्यय के उल्लेख को सुधारने का अनुरोध किया।

गैर-क्षतिकारक कीमत, मूल्य प्रभाव, क्षति और सार्वजनिक हित

- xiii. उत्पादन लागत और गैर-क्षतिकारक कीमत निर्धारित करते समय उप-उत्पाद, स्ट्रैप और संयुक्त उत्पादों से प्राप्त वसूली का उचित समायोजन किया जाना चाहिए।
- xiv. सऊदी अरब से आयात पिछले दो वर्षों की तुलना में घटे और उनका मूल्य कटौती मार्जिन नकारात्मक था। इसलिए ऐसे आयातों से प्रतिकूल मात्रा या मूल्य प्रभाव नहीं पड़ा।
- xv. अधिकांश परिचालन मानदंडों में सुधार हुआ। कथित वित्तीय क्षति को एचएमईएल के आरंभिक संचालन, वित्तपोषण और मूल्यहास लागत, फीडस्टॉक अंतर, घरेलू प्रतिस्पर्धा, परिचालन व्यवधान तथा वैश्विक बाजार परिस्थितियों का परिणाम बताया गया। पक्षकारों ने यह भी प्रश्न उठाया कि क्या निर्यात प्रदर्शन से क्षति हुई।
- xvi. भारत में एलएलडीपीई की माँग-आपूर्ति में अंतर है और डाउनस्ट्रीम उद्योग आयात पर निर्भर है। शुल्क से कच्चे माल की लागत और प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का दावा किया गया तथा वैकल्पिक रूप से शुल्क की अवधि दो वर्ष तक सीमित रखने का अनुरोध किया गया।

ट.2 घरेलू उद्योग के विचार

229. घरेलू उद्योग ने मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

उत्पाद दायरा, पीसीएन और घरेलू उद्योग

- i. बहिष्करण के अनुरोध साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं और प्रकटीकरण में निर्धारित उत्पाद दायरे की पुष्टि की जानी चाहिए।
- ii. निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट किए गए पीसीएन का वास्तविक उत्प्रेरक, तकनीकी विशेषताओं और विनिर्माण प्रक्रिया के आधार पर सत्यापन किया जाना चाहिए।
- iii. एचपीएल और एचएमईएल को नियम 2(ख) के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग के रूप में पुष्टि की जानी चाहिए।

पाटन मार्जिन और बिक्री शृंखला संबंधी मुद्दे

- iv. कतर को छोड़कर अन्य संबद्ध देशों के भागीदार निर्यातकों के पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण हैं। क्यूटोफिन के नकारात्मक मार्जिन की पुष्टि से पहले उसके समायोजनों की पुनः जाँच की जानी चाहिए।
- v. सुमितोमो की शेयरधारिता और वाणिज्यिक लेनदेन आरआरपीसी में उसकी निरंतर रणनीतिक भागीदारी दर्शाते हैं। मित्सुबिशी की वित्तीय रिपोर्टिंग में एसपीडीसी को संबद्ध संस्था बताया गया है।
- vi. अपूर्ण बिक्री शृंखला के कारण शार्क और आरआरपीसी की प्रश्नावली प्रतिक्रियाएँ उचित रूप से अस्वीकार की गईं। घरेलू उद्योग ने पूरे सऊदी अरामको-सैबिक समूह की प्रतिक्रिया अस्वीकार करने का अनुरोध किया।
- vii. पीरेफकेम और एसएपीपीएल के माध्यम से भेजी गई वस्तुओं की उत्पत्ति और बिक्री मार्ग स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हुए। इसलिए संबंधित बिक्री शृंखला को अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया।
- viii. सदारा एनएमजी और एमपीजी दोनों श्रेणियों का उत्पादन करता है। सामान्य मूल्य सही पीसीएन के आधार पर निर्धारित होना चाहिए और महत्वपूर्ण गलत रिपोर्टिंग पाए जाने पर उसकी प्रतिक्रिया अस्वीकार की जानी चाहिए।

क्षति, गैर-क्षतिकारक कीमत और सार्वजनिक हित

- ix. पाटित आयात आधार वर्ष की तुलना में बढ़े, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर आए और मूल्य कटौती, दमन तथा अवनमन का कारण बने। उत्पादन और बिक्री में वृद्धि नई क्षमता और लागत से कम बिक्री के कारण हुई, जबकि हानि, नकद हानि और नकारात्मक प्रतिफल जारी रहे।
- x. निर्धारित गैर-क्षतिकारक कीमत घरेलू उद्योग के दावे से काफी कम है और इसकी पुनः जाँच की जानी चाहिए।
- xi. अंतिम उपभोक्ता पर शुल्क का अनुमानित प्रभाव 0.1% से कम है और कच्चे माल की कीमतों में बदलाव सामान्यतः रूपांतरण-लागत आधारित मूल्य निर्धारण के माध्यम से आगे हस्तांतरित हो जाते हैं।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

230. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों की जाँच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटीकरण-पश्चात चरण में किए गए

अनेक प्रस्तुतीकरण, जाँच के दौरान पहले किए गए और प्रकटीकरण विवरण में पहले ही परीक्षण किए जा चुके प्रस्तुतीकरणों की पुनरावृत्ति हैं। तथापि, प्राधिकारी ने उन सभी प्रासंगिक टिप्पणियों पर विचार किया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से समर्थित हैं और अंतिम निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उत्पादक/निर्यातक-विशिष्ट मुद्दे

231. केम्या ने तर्क दिया है कि उसके कारखाना-बाह्य घरेलू बिक्री मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण में समायोजन सही ढंग से लागू नहीं किए गए हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन अंतिम निष्कर्षों के पैरा 68 में वर्णित पद्धति के अनुसार, प्रत्येक व्यापारी के स्तर पर कारखाना-बाह्य मूल्य निर्धारित करने के लिए व्यापारी द्वारा वहन किए गए व्ययों को उसकी निर्यात कीमत अथवा सामान्य मूल्य से समायोजित किया गया है। इसके बाद उत्पादक द्वारा वहन किए गए व्ययों का समायोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, केम्या ने अपने संबद्ध उत्पादकों के विपरीत, अपने परिशिष्टों में किसी बिक्री, वितरण अथवा अन्य व्यय की सूचना नहीं दी। केम्या ने प्रकटीकरण विवरण पर अपनी टिप्पणियों में यह स्पष्ट नहीं किया कि जब उसने कोई बिक्री और वितरण व्यय वहन नहीं किया, तो घरेलू और निर्यात लेनदेन एफओबी आधार पर क्यों रिपोर्ट किए गए।
232. केम्या ने यह भी दावा किया है कि प्राधिकारी ने उसके सामान्य मूल्य में बिक्री और वितरण व्यय जोड़े हैं, जबकि निर्यात कीमत से इन्हें घटाया है। केम्या ने प्रस्तुत किया कि यदि प्राधिकारी सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत से ऐसे व्ययों की कटौती को उचित मानते हैं, तो यह समायोजन दोनों पर समान रूप से किया जाना चाहिए। प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि केम्या द्वारा सुझाई गई पद्धति ही अपनाई गई है। बिक्री और वितरण व्यय को केम्या के सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत, दोनों से घटाया गया है और इस प्रकार दोनों की तुलना समान व्यापार स्तर पर की गई है।
233. केम्या के संबद्ध व्यापारी ईएमसीएपी ने कहा है कि केम्या का संयंत्र बंदरगाह के निकट स्थित है और इसलिए वह बिक्री एवं वितरण व्यय वहन नहीं करता। प्राधिकारी ने केम्या और उसके संबद्ध उत्पादकों की भौगोलिक स्थिति की जाँच की और पाया कि वे एक ही क्षेत्र में स्थित हैं। केवल संयंत्र का बंदरगाह के निकट होना यह सिद्ध नहीं करता कि माल के परिवहन शुल्क को छोड़कर। ईएमसीएपी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यदि केम्या इन व्ययों

को वहन नहीं करता, तो इन्हें कौन वहन करता है। अतः प्राधिकारी ने ईएमसीएपी के प्रस्तुतीकरण को स्वीकार नहीं किया है।

234. शार्क और एसपीडीसी ने तर्क दिया है कि मित्सुबिशी कॉरपोरेशन, जिसके माध्यम से वस्तुओं का भारत को निर्यात किया गया, उनका संबद्ध पक्ष नहीं है। इसलिए उनके निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अंतर्गत नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि एसपीडीसी ने प्रश्नावली के परिशिष्टों में मित्सुबिशी के साथ अपने संबंध की प्रकृति नहीं बताई थी, तथापि संबंध निर्धारित करने के लिए अन्य साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध थे। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि एसपीडीसी मित्सुबिशी को असंबद्ध पक्ष मानता था, तो उसे प्रश्नावली के परिशिष्टों में उसी रूप में घोषित किया जा सकता था। इसके विपरीत, एसपीडीसी ने दो अलग-अलग अवसरों पर आपूर्तिकर्ता एसपीडीसी और ग्राहक मित्सुबिशी के बीच संबंध से संबंधित कॉलम हटा दिए। एसपीडीसी द्वारा 6 नवंबर 2025 के ई-मेल में दिया गया स्पष्टीकरण बाद में दिया गया स्पष्टीकरण है, जो प्रथमदृष्टया गलत है और एसपीडीसी की वार्षिक रिपोर्ट के विपरीत है, जिसमें मित्सुबिशी कॉरपोरेशन को स्पष्ट रूप से संबद्ध पक्ष बताया गया है। इसके अतिरिक्त, सऊदी अरब से मोनो एथिलीन ग्लाइकोल के आयात से संबंधित पूर्व जाँच के अंतिम निष्कर्ष दिनांक 23 सितंबर 2025 में, जिसकी जाँच अवधि वर्तमान जाँच अवधि से आंशिक रूप से समान थी, मित्सुबिशी ने प्रश्नावली उत्तर में स्वयं को एसपीडीसी का संबद्ध पक्ष बताया था। प्राधिकारी द्वारा यह तथ्य प्रकट किए जाने के बाद भी एसपीडीसी ने न तो प्रकटीकरण विवरण के समय और न ही अंतिम निष्कर्षों के बाद इसका विरोध किया। यह स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि स्वीकृत तथ्यों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। चूँकि मित्सुबिशी एसपीडीसी का संबद्ध पक्ष है और उसमें महत्वपूर्ण शेरधारिता रखता है, प्राधिकारी मानते हैं कि मित्सुबिशी, एसपीडीसी के माध्यम से शार्क पर प्रभाव डालने की स्थिति में है। अतः मित्सुबिशी को शार्क का संबद्ध पक्ष माना गया है।

235. आरआरपीसी ने प्रस्तुत किया है कि उसकी प्रश्नावली प्रतिक्रिया को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि सत्यापन दस्तावेजों में सुमितोमो के पुनर्विक्रय मूल्य और लाभप्रदता से संबंधित सूचना दी गई थी। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच 30 जून 2025 को प्रारंभ की गई थी और सभी इच्छुक पक्षों को 6 सितंबर 2025 तक प्रश्नावली उत्तर दाखिल करना था। इच्छुक पक्षों के अनुरोध पर यह समय-सीमा 12 सितंबर 2025 तक बढ़ाई गई। विचाराधीन वस्तु का संबद्ध निर्यातक होने के बावजूद सुमितोमो ने इस चरण में

प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया। प्रश्नावली उत्तरों की प्रथमदृष्टया जाँच के बाद प्राधिकारी ने 15 अक्टूबर 2025 के ई-मेल द्वारा सभी भाग लेने वाले निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली जारी कर अपनी प्रतिक्रियाएँ पूर्ण करने को कहा। आरआरपीसी ने 27 अक्टूबर 2025 के अपने पूरक उत्तर में भी सुमितोमो की ओर से कोई आँकड़ा नहीं दिया और न ही सुमितोमो ने स्वयं कोई उत्तर दाखिल किया। इसके बाद, उत्पादकों और निर्यातकों के आँकड़ों के डेस्क सत्यापन के दौरान, प्राधिकारी ने आरआरपीसी को सत्यापन प्रश्नावली जारी कर उसके दावों के समर्थन में साक्ष्य माँगे। सत्यापन उत्तर के साथ आरआरपीसी ने सुमितोमो के कथित पुनर्विक्रय मूल्यों और लाभप्रदता संबंधी आँकड़े तथा उनकी सहायक गणनाएँ प्रस्तुत कीं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सत्यापन का उद्देश्य अभिलेख पर पहले से प्रस्तुत आँकड़ों की संबंधित कंपनियों के वित्तीय अभिलेखों और सहायक दस्तावेजों से जाँच करना है, न कि नए तथ्य एकत्र करना। सुमितोमो के कथित पुनर्विक्रय और लाभप्रदता संबंधी सूचना आरआरपीसी द्वारा 10 अप्रैल 2026 को, जाँच प्रारंभ होने के लगभग दस महीने बाद, प्रस्तुत की गई। प्राधिकारी ने सुमितोमो और आरआरपीसी दोनों को अपनी प्रतिक्रियाएँ पूर्ण करने के अनेक अवसर दिए। इसके बावजूद, सुमितोमो ने न तो जाँच में भाग लिया और न ही संबद्ध निर्यातकों पर लागू व्यापार सूचना के अनुसार आवश्यक सूचना प्रस्तुत की। अतः इतनी विलंबित अवस्था में प्रस्तुत सूचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सुमितोमो से संबंधित सूचना अधूरी भी थी। आरआरपीसी ने सुमितोमो के लाभ-हानि विवरण का डेटा प्रस्तुत किया, परंतु सुमितोमो की गैर-भागीदारी के कारण इसे उसके वित्तीय अभिलेखों से सत्यापित नहीं किया जा सका। प्रस्तुत लाभ-हानि, बिक्री और खरीद आँकड़ों के समर्थन में एसएपी अथवा ईआरपी आधारित स्क्रीनशॉट उपलब्ध नहीं थे। आरआरपीसी ने जाँच अवधि के लिए सुमितोमो के वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत नहीं किए। इन महत्वपूर्ण कमियों के कारण आरआरपीसी की प्रतिक्रिया को पूर्ण नहीं माना जा सकता था। तदनुसार, प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आरआरपीसी के निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अंतर्गत सही रूप से किया गया है।

236. केम्या ने यह भी दावा किया है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उसकी उत्पादन लागत में बिक्री एवं वितरण व्यय जोड़कर वृद्धि की जानी चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य व्यापार क्रम का परीक्षण कारखाना-बाह्य स्तर पर किया जाता है। अतः केम्या की उत्पादन लागत में ऐसा समायोजन करने का कोई औचित्य नहीं है।

237. सदारा ने तर्क दिया है कि उसके निवल निर्यात मूल्य की गणना करते समय संबंधित व्यापारियों के लाभ मार्जिन तथा विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों का समायोजन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि डाउ समूह और एसएबीआईसी समूह के माध्यम से की गई बिक्री सदारा की विस्तारित बिक्री शाखाओं के रूप में की जाती है। प्राधिकारी इस तर्क से सहमत नहीं हैं। एसएबीआईसी समूह और डाउ समूह विभिन्न उत्पादों तथा अनेक उत्पादकों के लिए बिक्री करते हैं और केवल सदारा की वस्तुओं का व्यापार नहीं करते। इसके अतिरिक्त, इन समूहों की शेयरधारिता संरचना सदारा से भिन्न है। सदारा स्वयं भी वस्तुओं की बिक्री से संबंधित अंतर्देशीय माल-भाड़े जैसे व्यय वहन करता है, जो उसके वित्तीय विवरणों में दर्ज हैं। अतः डाउ समूह और एसएबीआईसी समूह को सदारा की ओर से बिक्री करने के लिए गठित उसकी विस्तारित बिक्री शाखाएँ नहीं माना जा सकता।
238. सदारा ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उसके निवल निर्यात मूल्य की गणना करते समय उसके द्वारा रिपोर्ट किए गए विपणन शुल्क की कटौती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह उसके व्यापारियों द्वारा रखे गए लाभ को दर्शाता है। उसने तर्क दिया कि विपणन शुल्क के साथ-साथ डाउ समूह और एसएबीआईसी समूह के अप्रत्यक्ष विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और लाभ की कटौती करने से एक ही व्यय की दोहरी कटौती होती है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डाउ समूह और एसएबीआईसी समूह के अप्रत्यक्ष विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय सदारा से वास्तविक खरीद मूल्य तथा विभिन्न बिक्री माध्यमों में व्यापारियों द्वारा प्राप्त वास्तविक पुनर्विक्रय मूल्य के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। खरीद मूल्य के रूप में विपणन शुल्क के समायोजन से पहले का निवल बीजक मूल्य लिया गया है। यही पद्धति सदारा के सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य, दोनों के निर्धारण में अपनाई गई है। इस पद्धति के आधार पर सदारा की सभी घरेलू बिक्री हानि वाली पाई गई, जिसका सदारा ने विरोध नहीं किया है।
239. यह भी उल्लेखनीय है कि उत्पादक का निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य स्वतंत्र ग्राहकों को प्रथम पुनर्विक्रय के स्तर से निर्धारित किया गया है। सदारा और उसके संबद्ध निर्यातकों के अभिलेखों में रिपोर्ट किए गए सभी प्रत्यक्ष बिक्री व्ययों को संबद्ध निर्यातकों के परिशिष्ट 5 के अनुसार अप्रत्यक्ष बिक्री व्ययों की गणना में उचित रूप से समायोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध निर्यातकों के लाभ का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने आपूर्तिकर्ताओं के लिए रिपोर्ट किए गए खरीद मूल्यों तथा परिशिष्ट 3ए/3बी/4ए/4बी में रिपोर्ट

किए गए निवल बीजक मूल्यों पर विचार किया है। चूँकि संबंधित बिक्री मूल्य में विपणन शुल्क पहले ही शामिल है, इसलिए लाभ की दोहरी गणना का प्रश्न नहीं उठता।

240. सदारा ने अनुरोध किया है कि उसे सऊदी अरामको-एसएबीआईसी समूह के लिए निर्धारित भारत औसत शुल्क के स्थान पर अलग शुल्क दिया जाए। सदारा ने यह भी कहा है कि वह कानूनी रूप से एक अलग इकाई है और सऊदी अरामको उसकी परिचालन गतिविधियों को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सऊदी अरामको की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस केमिकल्स कंपनी में 100% शेयरधारिता है, जो बदले में सदारा में 50% से अधिक शेयरधारिता रखती है। इसी प्रकार, सऊदी अरामको की एसएबीआईसी में 70% शेयरधारिता है। अतः सदारा को सऊदी अरब के अन्य उत्पादकों से असंबद्ध नहीं माना जा सकता। सदारा ने भी इस तथ्य का विरोध नहीं किया है कि वह सऊदी अरामको-एसएबीआईसी समूह से संबद्ध है। तदनुसार, प्राधिकारी ने सऊदी अरामको-एसएबीआईसी समूह के लिए एक समान शुल्क मार्जिन की सिफारिश की है।

उत्पाद दायरा और पीसीएन रिपोर्टिंग

241. प्राधिकारी ने भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट किए गए पीसीएन की तकनीकी विनिर्देशों और सत्यापित अभिलेखों के आधार पर पुनः जाँच की है। अंतिम गणनाओं में केवल सही वर्गीकृत पीसीएन का उपयोग किया गया है।

घरेलू उद्योग और ओपीएएल का उपचार

242. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पात्रता के निर्धारण हेतु ओपीएएल को बाहर रखने से क्षति विश्लेषण प्रभावित नहीं होता और न ही इससे कोई विकृति उत्पन्न होती है, क्योंकि ओपीएएल की बिक्री और उत्पादन को भारतीय एलएलडीपीई उद्योग के व्यापक आर्थिक आँकड़ों में शामिल किया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी उत्पादक के पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का पात्र घटक न होने मात्र से उसकी बिक्री अथवा उत्पादन को माँग के आकलन से बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से आकलन विकृत हो जाएगा।
243. आरआरपीसी ने तर्क दिया है कि ओपीएएल को केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई होने के कारण घरेलू उद्योग से बाहर नहीं किया जाना चाहिए था और आवेदन दाखिल किए जाने के समय तक ओपीएएल विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर आ चुका था। इस संबंध में, प्राधिकारी

नोट करते हैं कि ओपीएल विशेष आर्थिक क्षेत्र से जाँच अवधि समाप्त होने के बाद बाहर आया था। यह भी नोट किया जाता है कि क्षति और पाटन से संबंधित सभी परीक्षण जाँच अवधि के संदर्भ में किए जाने हैं, न कि जाँच अवधि के बाद की परिस्थितियों के आधार पर। अतः जाँच अवधि के बाद ओपीएल के विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर आने से जाँच अवधि के लिए क्षति और पात्रता का निर्धारण प्रभावित नहीं होता। प्राधिकारी पुनः स्पष्ट करते हैं कि किसी इकाई का भारत में निगमित होना अथवा भारत में वस्तुओं का भौतिक उत्पादन करना उसे स्वतः ही व्यापार उपचार के प्रयोजन से घरेलू उद्योग का भाग नहीं बनाता, विशेषकर जब लागू कानूनी व्यवस्था उस इकाई को भारत के सीमा-शुल्क क्षेत्र से बाहर संचालित मानती हो। तदनुसार, प्राधिकारी विचार करते हैं कि कुल पात्र घरेलू उत्पादन की गणना से ओपीएल को उचित रूप से बाहर रखा गया है।

244. आरआरपीसी ने यह भी तर्क दिया है कि आरआईएल के समर्थन-पत्र पर निर्भरता से पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग द्वारा “प्रमुख अनुपात” की शर्त पूरी न करने की कमी दूर नहीं हो सकती। इस संबंध में, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि एचपीएल और एचएमईएल द्वारा “प्रमुख अनुपात” की शर्त पूरी किए जाने के निर्धारण हेतु आरआईएल के समर्थन-पत्र पर निर्भरता नहीं रखी गई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एचपीएल और एचएमईएल कुल पात्र भारतीय उत्पादन का लगभग 25% से 30% भाग रखते हैं और पात्र घरेलू उत्पादन में उनका हिस्सा महत्वपूर्ण एवं पर्याप्त है। तदनुसार, प्राधिकारी ने एचपीएल और एचएमईएल को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग माना है।
245. आरआरपीसी ने यह भी तर्क दिया है कि वह आरआईएल की स्थापित क्षमता, उत्पादन और बिक्री के आँकड़ों का सत्यापन नहीं कर सका, जिससे सार्थक प्रस्तुतीकरण करने का उसका अधिकार प्रभावित हुआ। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त सूचना गोपनीय प्रकृति की है और आरआईएल द्वारा इसे सूचकांकित रूप में परिचालित किया गया था। आरआरपीसी सहित सभी इच्छुक पक्ष अपनी समान प्रकार की सूचना को गोपनीय बताते हैं और प्राधिकारी द्वारा भी उसे गोपनीय माना जाता है। अतः प्राधिकारी यह नहीं मानते कि आरआरपीसी के प्रस्तुतीकरण करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

मात्रा और मूल्य प्रभाव

246. अन्य इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने मात्रा प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए मूल्य-संबंधी कारकों पर निर्भरता रखी है, जबकि आयातों की मात्रा में निरपेक्ष अथवा सापेक्ष रूप से हुई उल्लेखनीय वृद्धि को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि में विचाराधीन देशों से आयात आधार वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़े हैं। प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों को केवल घरेलू बिक्री की मात्रा में हुई वृद्धि के कारण को स्पष्ट करने के लिए परस्पर संबद्ध किया है।
247. सऊदी अरब के उत्पादकों ने तर्क दिया है कि सऊदी अरब से विचाराधीन वस्तुओं का भारत में आयात घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से अधिक कीमतों पर हो रहा है और इसलिए ऐसे आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकते। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन देशों से आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन किया गया है। सऊदी अरब के उत्पादकों ने सऊदी अरब से आयातों को संचयी आकलन से अलग करने के समर्थन में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन देशों से समग्र आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पाया गया है।

आर्थिक मानदंड, भौतिक क्षति और कार्य-कारण संबंध

248. आरआरपीसी ने यह भी तर्क दिया है कि निर्यात बिक्री से संबंधित प्रवृत्ति संबंधी आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जाँच नहीं कर सका। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात बिक्री से संबंधित विवरण घरेलू उद्योग द्वारा परिचालित आवेदन के अगोपनीय संस्करण में उपलब्ध थे। वास्तव में, आरआरपीसी ने स्वयं अपने प्रकटीकरण-पश्चात प्रस्तुतीकरण के पैरा 188 में घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री की प्रवृत्तियों पर निर्भरता रखी है।
249. अन्य इच्छुक पक्षों ने प्रस्तुत किया है कि पाटित आयातों की उपस्थिति के बावजूद जाँच अवधि में भारतीय उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचएमईएल ने अपना एलएलडीपीई संयंत्र वर्ष 2018 में स्थापित किया था और क्षति अवधि के दौरान उत्पादन प्रारंभ किया।

250. आरआरपीसी ने तर्क दिया है कि जाँच अवधि में घरेलू उद्योग का बिक्री मूल्य बढ़कर 91 सूचकांक अंक हो गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि घरेलू उद्योग की कीमतों का दमन हुआ। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की कीमतों में वृद्धि, विचाराधीन देशों से आयातों के पहुँच मूल्य में हुई वृद्धि के अनुरूप थी। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन देशों से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर भारतीय बाजार में प्रवेश करते रहे।
251. अन्य इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई, क्योंकि उसकी बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, मजदूरी और उत्पादकता में वृद्धि हुई है तथा ये सकारात्मक मानदंड लाभप्रदता में गिरावट से अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मात्रा संबंधी मानदंडों में सुधार वित्त वर्ष 2023-24 में एचएमईएल द्वारा उत्पादन प्रारंभ किए जाने के कारण हुआ। प्राधिकारी नोट करते हैं कि महत्वपूर्ण पूँजी निवेश के बाद बाजार में प्रवेश करने वाले नए घरेलू उत्पादक से अपनी क्षमता निष्क्रिय रखने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः क्षति के आकलन के लिए मात्रा और वित्तीय, दोनों मानदंडों की जाँच आवश्यक है। वर्तमान मामले में एचएमईएल द्वारा उत्पादन प्रारंभ किए जाने से घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मानदंडों में सुधार हुआ, परंतु घरेलू उद्योग अपनी लागत की वसूली नहीं कर सका, जिससे उसके वित्तीय मानदंड प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए।
252. अन्य इच्छुक पक्षों ने यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की हानियाँ वित्त वर्ष 2023-24 में एचएमईएल द्वारा उत्पादन प्रारंभ किए जाने के कारण हुईं, क्योंकि उसी वर्ष घरेलू उद्योग की हानियाँ सर्वाधिक थीं। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में विचाराधीन देशों से आयातों की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट हुई। फलस्वरूप, घरेलू उद्योग को विचाराधीन आयातों के पहुँच मूल्य के अनुरूप अपनी कीमतें कम करनी पड़ीं।
253. अन्य इच्छुक पक्षों ने यह भी तर्क दिया है कि प्राधिकारी क्षति की जाँच में अन्य घरेलू उत्पादकों से संबंधित सूचना पर निर्भरता नहीं रख सकते थे। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की जाँच घरेलू उद्योग के संबंध में की गई है। तथापि, बाजार हिस्सेदारी और माँग में हुए परिवर्तनों का आकलन करने के लिए अन्य भारतीय एलएलडीपीई उत्पादकों के व्यापक आर्थिक और मात्रा संबंधी आँकड़ों की जाँच करना आवश्यक था।

254. अन्य इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया है कि केवल उच्च क्षमता उपयोग तथा अन्य घरेलू उत्पादक के समान उपभोग मानदंड और रूपांतरण लागत प्राप्त कर लेने से यह सिद्ध नहीं होता कि एचएमईएल के परिचालन और वित्तीय मानदंड स्थिर हो गए थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने एचएमईएल के चुनिंदा वित्तीय मानदंडों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि नव-स्थापित पेट्रोकेमिकल संयंत्र के आरंभिक वर्षों से सामान्यतः जुड़ी लागतों और अक्षमताओं का उसके प्रदर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचएमईएल के सभी लागत संबंधी मानदंडों की जाँच की गई और उनकी तुलना अन्य घरेलू उत्पादक से की गई। उत्पादन प्रारंभ करने का प्रभाव उच्च ब्याज लागत और अधिक मूल्यहास के रूप में परिलक्षित होता है। अतः प्राधिकारी ने एचएमईएल के मूल्यहास, ब्याज और कर से पूर्व लाभ (पीबीडीआईटी) की जाँच की और उसे ऋणात्मक पाया।
255. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अन्य इच्छुक पक्ष इस तथ्य से सहमत हैं कि क्षमता उपयोग, उपभोग मानदंडों और रूपांतरण लागत में सुधार से यह संकेत मिलता है कि एचएमईएल ने तकनीकी स्थिरता प्राप्त कर ली है। तथापि, उनका तर्क है कि इससे परिपक्व वाणिज्यिक परिचालन स्थिति सिद्ध नहीं होती। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचएमईएल ने जाँच अवधि में अपने कुल उत्पादन का लगभग 97% घरेलू और निर्यात बाजारों में बेचा। इससे स्पष्ट है कि उसने न केवल तकनीकी स्थिरता, बल्कि वाणिज्यिक परिचालन स्थिरता भी प्राप्त कर ली थी।
256. समग्र आकलन के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन देशों से पाटित आयात महत्वपूर्ण मात्रा में भारत में आए, घरेलू समान वस्तु से प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा की तथा घरेलू उद्योग को अपनी लागत की वसूली और उचित प्रतिफल अर्जित करने के लिए कीमतें पर्याप्त रूप से बढ़ाने से रोका। अतः प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि विचाराधीन देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

गैर-क्षतिकारक कीमत

257. अन्य इच्छुक पक्षों ने यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत के निर्धारण में उप-उत्पादों से प्राप्त आय का समायोजन किया जाना चाहिए था। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में घरेलू उद्योग द्वारा कोई उप-उत्पाद उत्पन्न नहीं किया जाता। ऐसे उप-उत्पाद आंतरिक उपयोग के आदानों के निर्माण के

चरण में उत्पन्न होते हैं और उनसे संबंधित आय को क्षतिरहित कीमत की गणना में उचित रूप से समायोजित किया गया है।

258. घरेलू उद्योग ने यह भी आरोप लगाया है कि प्राधिकारी ने उसकी क्षतिरहित कीमत में अनुचित समायोजन किए हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का दावा सामान्य प्रकृति का है और उसके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग के प्रस्तुतीकरण से सहमत नहीं हैं।

सार्वजनिक हित, प्रयोक्ता प्रभाव और शुल्क की अवधि

259. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विभिन्न प्रकार के उत्पादों पर शुल्क के प्रभाव की उचित गणना की गई है और इस गणना में अपनाई गई मान्यताओं के आधार को भी समुचित रूप से स्पष्ट किया गया है।
260. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इच्छुक पक्षों ने माँग और आपूर्ति के बीच अंतर होने के कारण पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश न किए जाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल माँग-आपूर्ति अंतर का होना विदेशी निर्यातकों की अनुचित व्यापार पद्धतियों के प्रतिकार हेतु उपायों की सिफारिश न करने का आधार नहीं है।
261. मूल सीमा-शुल्क से अस्थायी छूट, गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी उपाय तथा जाँच अवधि के बाद के भू-राजनीतिक घटनाक्रम अलग-अलग नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ये कारक क्षतिकारक पाटन को जारी रहने देने को उचित नहीं ठहराते। इसके अतिरिक्त, उपाय की अवधि को दो वर्ष तक सीमित करने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति स्थापित नहीं की गई है।

ठ. निष्कर्ष

262. सभी इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों, उनमें उठाए गए मुद्दों तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों की जाँच करने के बाद, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:
- क. विचाराधीन उत्पाद 908.4 से 940.4 किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व वाला रैखिक निम्न-घनत्व पॉलीएथिलीन है।
- ख. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए बहिष्करण अनुरोधों की जाँच की गई है। प्राधिकारी ने पाया कि घरेलू उद्योग उन उत्पादों के समान वस्तु का उत्पादन और

- बिक्री करता है, जिनके बहिष्करण का अनुरोध किया गया था। अतः किसी भी बहिष्करण अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।
- ग. वर्तमान जाँच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति मेटालोसीन-आधारित तथा गैर-मेटालोसीन उत्प्रेरकों पर आधारित है।
- घ. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का आवेदन भारतीय एलएलडीपीई उत्पादकों की ओर से केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इंडिया द्वारा दाखिल किया गया। क्षति संबंधी सूचना हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और एचपीसीएल-मितल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आवेदन का समर्थन किया तथा निर्धारित प्रारूप में समर्थक आँकड़े दिए। एचपीएल और एचएमईएल पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत भारतीय एलएलडीपीई उत्पादन का प्रमुख अनुपात रखते हैं और आवेदन नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।
- ङ. प्राधिकारी ने विचाराधीन वस्तुओं के आयात की जाँच के लिए लेनदेन की उचित समीक्षा के बाद डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों पर निर्भरता रखी है।
- च. जाँच कुवैत, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विरुद्ध प्रारंभ की गई थी। जाँच प्रारंभ करते समय कुवैत, कतर और ओमान से आयात का व्यक्तिगत हिस्सा कुल आयात के 3% से कम, किंतु उनका सामूहिक हिस्सा 7% से अधिक था। जाँच के दौरान कतर से आयात अपाटित पाए गए। फलस्वरूप, 3% से कम हिस्सेदारी वाले कुवैत और ओमान का सामूहिक हिस्सा 7% से कम हो गया। अतः पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 14 के अंतर्गत कुवैत, ओमान और कतर के विरुद्ध जाँच समाप्त कर दी गई है। वर्तमान जाँच के विचाराधीन देश मलेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं।
- छ. विचाराधीन देशों के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण हैं।
- ज. जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है:
- (i) आधार वर्ष की तुलना में विचाराधीन देशों से पाटित आयातों की मात्रा निरपेक्ष रूप से बढ़ी है।
 - (ii) क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता और माँग में वृद्धि के बावजूद, जाँच अवधि में उसकी क्षमता का महत्वपूर्ण भाग निष्क्रिय रहा।
 - (iii) विचाराधीन देशों से आयातित वस्तुएँ घरेलू उद्योग की कीमतों का मूल्य कटौती कर रही हैं।
 - (iv) विचाराधीन देशों से आयातित वस्तुओं के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट हुई है।

(v) क्षति अवधि के दौरान एचएमईएल द्वारा उत्पादन प्रारंभ किए जाने से घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मानदंडों में सुधार हुआ। तथापि, समग्र भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई। कुछ मात्रा संबंधी मानदंडों में सुधार से वास्तविक क्षति समाप्त नहीं हो जाती, विशेषकर जब मूल्य और लाभप्रदता संबंधी मानदंडों में महत्वपूर्ण गिरावट हुई हो।

(vi) जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय और नकद हानियाँ हुईं तथा नियोजित पूँजी पर ऋणात्मक प्रतिफल संचित हुआ।

(vii) भारत में उत्पाद की माँग होने के बावजूद घरेलू उद्योग उचित प्रतिफल अर्जित नहीं कर सका।

झ. किसी अन्य ज्ञात कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति भारत में विचाराधीन आयातों के पाटन के कारण हुई है।

ञ. विचाराधीन देशों के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण हैं।

ट. पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना व्यापक जनहित में है, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:

(i) किसी भी इच्छुक पक्ष ने यह सिद्ध नहीं किया है कि शुल्क लगाए जाने से जनहित पर असंगत रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ii) शुल्क लगाए जाने से विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों को पाटन के माध्यम से मिलने वाला अनुचित लाभ समाप्त होगा तथा भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग को समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसर मिलेगा।

(iii) पाटनरोधी शुल्क आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाता। उचित और अपाटित कीमतों पर आयात भारतीय बाजार में जारी रह सकते हैं।

ड. सिफारिशें

263. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच प्रारंभ की गई और इसकी सूचना सभी इच्छुक पक्षों को दी गई। घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य इच्छुक पक्षों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच प्रारंभ तथा संचालित करने के बाद, प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और उससे हुई क्षति के प्रतिकार के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है। अतः प्राधिकारी विचाराधीन देशों से विचाराधीन वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

264. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो कम हो, उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है। तदनुसार, प्राधिकारी विचाराधीन देशों में उत्पन्न अथवा वहाँ से निर्यात की गई विचाराधीन वस्तुओं के आयात पर, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 पाँच वर्ष की अवधि के लिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के स्तंभ 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं:

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण	उद्गम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि (अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	3901 10 10 3901 40 10	लीनियर लो-डेंसिटी पॉलीइथिलीन, जिसकी डेंसिटी 908.4 से 940.4 kg/m ³	सऊदी अरब साम्राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	अलजुबैल-पेट्रोकेमिकल कंपनी (केम्या)	75
2	-वही-	-वही-	सऊदी अरब साम्राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी (पेट्रोकेम्या)	75
3	-वही-	-वही-	सऊदी अरब साम्राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी (शर्क)	75
4	-वही-	-वही-	सऊदी अरब साम्राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	जुबैल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी (यूनाइटेड)	75

5	-वही-	-वही-	सऊदी अरब साम्राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	राबिग रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी	75
6	-वही-	-वही-	सऊदी अरब साम्राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	सदारा केमिकल कंपनी	75
7	-वही-	-वही-	सऊदी अरब साम्राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	यानबू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानसाब)	75
8	-वही-	-वही-	सऊदी अरब साम्राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	क्रम सं. 1 से 7 के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	225
9	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई भी देश	सऊदी अरब साम्राज्य	कोई भी	225
10	-वही-	-वही-	संयुक्त अरब अमीरात	संयुक्त अरब अमीरात सहित कोई भी देश	अबू धाबी पॉलिमर्स कंपनी लिमिटेड (बोरोज़) - सोल प्रोप्राइटरशिप L.L.C.	41
11	-वही-	-वही-	संयुक्त अरब अमीरात	संयुक्त अरब अमीरात सहित कोई भी देश	क्रम सं. 10 के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	94
12	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई भी देश	संयुक्त अरब अमीरात	कोई भी	94

13	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	कोई भी	368
14	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	368

टिप्पणी— उपर्युक्त कंपनियों के लिए निर्दिष्ट अलग-अलग शुल्क दरों का लाभ सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने पर ही उपलब्ध होगा। ऐसे बीजक पर बीजक जारी करने वाली इकाई के किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा उसके नाम और पदनाम सहित दिनांकित एवं हस्ताक्षरित निम्नलिखित घोषणा अंकित होनी चाहिए:

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस बीजक के अंतर्गत भारत को निर्यात के लिए बेची गई (विचाराधीन उत्पाद) की (मात्रा) का निर्माण (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया है। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।” ऐसा बीजक प्रस्तुत न किए जाने पर अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क दर लागू होगी। यह शर्त लागू सीमा-शुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होगी।

ढ. आगे की प्रक्रिया

265. इन अंतिम निष्कर्षों में नामित प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
FINAL FINDINGS

New Delhi, the 25th June, 2026

Case No. AD(OI)-23/2025

Subject: Anti-dumping Investigation Concerning Imports of “Linear Low-Density Polyethylene” (LLDPE) originating in or exported from the State of Kuwait, Malaysia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates.

F. No. 6/26/2025-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, framed thereunder, as amended from time to time (hereinafter referred as the “AD Rules, 1995”):

BACKGROUND OF THE CASE

1. Chemicals and Petrochemicals Association of India (CPMA) (hereinafter referred to as the “applicant association”) filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the ‘Authority’) on behalf of Indian LLDPE Manufacturers, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and AD Rules, 1995 for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Linear Low-Density Polyethylene” (hereinafter also referred to as the ‘product under consideration’ or the ‘PUC’ or the ‘subject goods’ or ‘LLDPE’) originating in or exported from the State of Kuwait (“Kuwait”), Malaysia, the Sultanate of Oman (“Oman”), the State of Qatar (“Qatar”), the Kingdom of Saudi Arabia (“Saudi Arabia”) and United Arab Emirates (“UAE”), hereinafter collectively referred to as the “subject countries”. Haldia Petrochemicals Limited (hereinafter referred to as “HPL”) and HPCL-Mittal Energy Limited (hereinafter referred to as “HMEL”), collectively referred to as the “domestic industry” provided the injury information and Reliance Industries Limited has filed a support letter.
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/26/2025-DGTR dated 30th June 2025, published in the Gazette of India, initiating an anti-dumping investigation into imports of PUC from the subject countries in accordance with Rule 5 of the anti-dumping rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

A.1 Initiation

- i. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of AD Rules, 1995.
- ii. Further, pursuant to a request by the Government of United Arab Emirates for pre-initiation consultation under para 3 of Art. 7.2 of India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement, a consultation was conducted with the Government of UAE on 29.06.2025.
- iii. A request was made to DGCI&S and DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period as well as the period of investigation. The Authority has relied on the DG Systems data for determination of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- iv. In accordance with Rule 6, upon examination of the application and finding prima facie evidence of dumping, injury, likelihood and causal link, the Authority issued a public notice dated 30th June 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from the subject countries.
- v. In accordance with Rule 6(2) of AD Rules, 1995, the Authority sent a copy of the initiation notification to the governments of the subject countries, through their embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers/users, the domestic industry, other Indian producers as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limits.

A.2 Period of Investigation

- vi. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st January 2024 to 31st December 2024 (12 months). The injury investigation period [IIP] covers a period of FY 2021-22, FY 2022-23, FY 2023-24 and the POI.

A.3 Circulation of non-confidential version of the application

- vii. Pursuant to Rule 6(3) of AD Rules, 1995, the Authority furnished a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the governments of the subject countries, through their embassies in India.
- viii. Pursuant to Rule 6(4), questionnaires were issued to known producers, exporters, importers, and users of the PUC in India to obtain necessary information, including details of normal value and net export price. A copy of the non-confidential version of the application was provided to other interested parties, wherever requested.

A.4 Participation by the interested parties

- ix. The following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire responses:

Kuwait	Equate Petrochemical Co. ("Equate")
Malaysia	No producer has participated from Malaysia
Oman	M/s OQ Polymer L.L.C. ("OQ Polymer")
	OQ Marketing L.L.C. ("OQ Marketing")
Qatar	Qatofin Company Limited Q.P.J.S.C ("Qatofin")
	Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.P.J.S.C ("Muntajat")
	QatarEnergy Marketing ("QEM")
	TotalEnergies Petrochemicals France - Qatar Branch Office ("Total Energies")
Saudi Arabia	Al-Jubail Petrochemical Company ("Kemya")
	Arabian Petrochemical Company ("Petrokemya")
	Eastern Petrochemical Company ("Sharq")
	Jubail United Petrochemical Company ("United")
	Rabigh Refinery & Petrochemical Company ("RRPC")
	Sadara Chemical Company ("Sadara")
	Yanbu National Petrochemical Company ("Yansab")
	Saudi Basic Industries Corporation ("SABIC")
	SABIC Asia Pacific Pte. Ltd. ("SAPPL")
	SPDC
	ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.
	Dow Saudi Arabia Product Marketing B.V. ("DSA")
	Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited ("DCP (S)")
	Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Dubai branch ("DCP (D)")
	Dow Chemical International Pvt. Ltd. Dubai Branch ("DCIPL")
UAE	Abu Dhabi Polymers Co. Ltd ("ADPCL")
	Borouge PTE Ltd.
	SRJ Global F.Z.E.

x. The following importers/users have responded by filing questionnaire responses:

- i. SABIC Research and Technology Pvt. Limited ("SRTPL")
- ii. ExxonMobil Company India Private Limited ("EMCIPL")

- xi. In response to the initiation notification, no association has participated or filed questionnaire submissions in the present investigation. All India HDPE/PP Woven Fabric Manufacturers Association has made legal submissions which have been considered by the Authority.
- xii. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.
- xiii. An economic interest questionnaire was issued to all the known producers and exporters, importers, and the domestic industry. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. The economic interest questionnaire was filed only by the domestic industry.
- xiv. Foreign producers, exporters and other interested parties who have not responded, or have not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperative.

A.5 Further procedure

- xv. The non-confidential versions of the submissions filed by the various interested parties were made available to all participating interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with a request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- xvi. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 15th April 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xvii. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, such parties have been considered as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- xviii. In accordance with Rule 7, the information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.
- xix. In accordance with Rule 8, the accuracy of information and data provided by the domestic industry and interested parties were verified by the Authority during the course of the investigation to the extent considered relevant, practicable, and necessary. The verification of submitted data and documents forms the basis of the final finding and the Authority has relied on the verified data of the domestic industry for its analysis in the present proceedings.
- xx. The Authority vide para 5 of the initiation notification dated 30th June 2025 sought comments on the scope of the PUC within 15 days of initiation. The interested parties were further granted additional time to file comments on PUC and PCN (Product Control Number) methodology till 20th July 2025. The Authority, after considering the

submissions made by the interested parties, *vide* notification dated 22nd August 2025, notified the final scope of PUC and PCN. All the interested parties were directed to file questionnaire responses in accordance with the PUC as finalized, within 15 days of notifying the PCN methodology. At the request of some interested parties, the time limit was further extended to 12th September 2025.

- xxi. The non-injurious price has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce and sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicants and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and as per the principles laid down in Annexure III of the AD Rules, 1995.
- xxii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final findings.
- xxiii. A disclosure statement dated 19.06.2025 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of AD Rules, 1995, disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation. The comments to the disclosure statement received from all interested parties, to the extent found to be relevant and non-repetitive, have been considered in these final findings.
- xxiv. ‘***’ in this document, represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules, 1995.
- xxv. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 84.58.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

B.1 Views of other interested parties

4. The following submissions have been made by the other interested parties:
 - i. LLDPE is primarily of three types, based on the comonomer used during its polymerization, viz. C-4(Butene based), C-6(Hexene based) and C-8(Octene based). The applicants do not manufacture C-8 based LLDPE and had admitted the same during the oral hearing. Product scope cannot include products which are not produced and sold in commercial quantities.
 - ii. C-8 based LLDPE has enhanced properties compared to standard LLDPE and commands a significant price premium over the base grades.
 - iii. As C-8 based LLDPE has not been exported to India it cannot be subjected to anti-dumping duties. Accordingly, all C-8 based LLDPE must be excluded from the product scope.
 - iv. As the C-4 and C-6 LLDPE produced by the applicants cannot individually directly substitute C-8 based LLDPE and only a combination of the two can substitute C-8 based LLDPE, it cannot be said that physical and chemical characteristics of C-4 and C-6 LLDPE are similar to those of C-8 based LLDPE.
 - v. Production of C8 LLDPE by Reliance Industries Ltd., which is not a constituent of domestic industry, cannot provide the ground for including LLDPE within the scope of the PUC. It is not sufficient if only supporters to the investigation are manufacturing C-8 based LLDPE. Supporters should be part of the investigation in entirety.

- vi. In the absence of participation by other producers, the Authority cannot verify whether the other producers are manufacturing C-8 based LLDPE or not.
- vii. The applicants do not manufacture powder form of LLDPE and accordingly, the same should be excluded. HMEL's grades M2024L and M5026L have high flow index however, the form and usage of such grades is different. As such, MG200024 and MG500026 (powder form for compounding) should be excluded from the scope of the PUC.
- viii. The applicants' claim that pellet and powder forms are interchangeable does not address the fact that the form and usage of the grades produced by the Respondents is different and accordingly, the same should be excluded from the scope of the PUC.
- ix. SABIC's grades 6821NJ and 6318B which are C-6 based LLDPE must be excluded as they have higher tear and tensile strength, which is not produced by the domestic industry.
- x. The domestic industry has not countered the argument that there exists a substantial demand-supply gap in India for C6 LLDPE. It has neither provided grade-wise production or demand data.
- xi. There is significant price difference between non-metallocene grades N0118L / N0120L and metallocene grades (such as F0120LM / F0118LM / N0118LM / N0120LM). This price difference is as high as 15% on the basis of HMEL price circular.
- xii. Sadara is primarily engaged in the exports of Higher Alpha Olefin LLDPE ("HAO LLDPE"), whereas HMEL and HPL primarily produce C4 LLDPE. C4 based LLDPE is used for applications in plastic bags, grocery bags, secondary bags etc. whereas C6 and C8 based LLDPE are primarily used in high-performance applications with demanding requirements because of its significantly higher toughness, higher impact resistance and better heat seal properties, such as standup pouches (SUP), heavy duty shipping sacks (HDSS), powder/liquid sachet, pillow pouch, back sheet film for diaper/feminine hygiene etc.
- xiii. HAO LLDPE is a premium product, offering enhanced performance and command higher prices. Also, there is a substantial demand and supply gap for HAO LLDPE in India.
- xiv. Borstar® LLDPE grades "having MFI/MFR of 0.25 g/10min or lower (FB2230, FB1200 and FB1350) are produced using proprietary Borstar® bimodal technology. These have high molecular weight with bimodal molecular weight distribution and low melt flow ratio. They are not produced by the domestic industry in India.
- xv. These grades have superior mechanical properties which also provides a matt finish. It also allows production of thicker film sheets, that, is up to 2mm thickness. All this is not possible with the use of conventional LLDPE. Moreover, Borstar® LLDPE grades allow for easy write-on with excellent print registration and definition. This requirement is not met by conventional LLDPE produced by the domestic industry.
- xvi. Unlike the LDPE investigation, maximum density has not been prescribed. Accordingly, the Authority should clarify the maximum density of LLDPE which is covered within the scope of the PUC.

B.2 Views of the domestic industry

5. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry:

- i. No importer or user has made a single submission concerning product exclusion or alleged that grades supplied by the domestic producers including the applicants are not comparable or are not technically/ commercially substitutable.
- ii. Since the recent Middle East crisis, the Indian producers have been the exclusive supplier to the user industry and meeting the Indian demand for all grades. In these facts, no exclusion is warranted.
- iii. Exclusion of C-8 based LLDPE and Higher Alpha Olefin (HAO) based LLDPE is not warranted as the applicant producers manufacture C4 and C6 Metallocene grades, which, when proportionately mixed, competes directly with C8 based LLDPE.
- iv. LLDPE used to manufacture standup pouches, heavy duty shipping sacks, liquid sachets are not manufactured by using any single monomer based LLDPE. Rather, a combination of butene and other grades are used to manufacture such products.
- v. The Indian industry does manufacture grades identical to or those that directly competes with C6, C8 LLDPE and Enhanced LLDPE being imported into India. HMEL has submitted invoices pertaining to C6 based LLDPE. Further, Reliance Industries Limited produces C8 based LLDPE.
- vi. HPL manufactures the PUC in compounded form.
- vii. The applicants have not only manufactured powdered form of LLDPE but also the pellet form of LLDPE and that competes directly with the powder form of LLDPE exported by SABIC.
- viii. With respect to exclusion of SABIC Grades MG200024 and MG500026, it is submitted that powder form is used by masterbatch manufacturers, who can either choose to import the powder form and add the additives by themselves or directly use the pellet form of LLDPE. Thus, the pellet form of LLDPE sold by applicants competes directly with the powder form of LLDPE exported by SABIC.
- ix. SABIC Grades 6821NJ and 6318BJ have not been imported into India and therefore, the question of exclusion of such grades does not arise. Regardless of this fact, it is submitted that HMEL produces similar and comparable grades.
- x. HMEL produces similar grades having similar characteristics, 6821NJ and 6318B, particularly tensile strength, which usually is the determinative factor. As such, if these grades were to be imported, they would directly compete with the grades being manufactured by HMEL.
- xi. While ADPCL and Borouge have pointed out minor technical differences between the products, no evidence has been provided to establish that the comparable grades available domestically are commercially non-substitutable.
- xii. Matte or gloss finish of the end product (film) is not an inherent characteristic of the subject goods, rather it depends on the finish desired by the processor itself, and the goods manufactured by the applicants' or other Indian producers are also used for making matte- based films.
- xiii. Melt flow index does not play a significant role in the decision of the customers' use of the subject goods, which is evident from the fact that applicant companies have sold their subject goods to the same customers, who use both imported and domestic products interchangeably.
- xiv. Proprietary technology cannot be a ground for exclusion when products manufactured by the Indian LLDPE producers and by Borouge are being used interchangeably and compete in the same market.
- xv. Metallocene and other high-performance-based grades are commercially referred to as metallocene grades, the technically name of such grades might be different as "Metallocene" is an exclusive trademark used by Exxon.

- xvi. Metallocene LLDPEs or high-performance LLDPEs are manufactured either through Metallocene catalysts or other metallocene family catalysts and therefore, must be classified as Metallocene Grade.
- xvii. Metallocene grades supplied by Abu Dhabi Polymers Company Ltd. and Borouge is traded under the name “Anteo”. Similarly, Sadara Chemicals supplies such goods under the names such as Dowlex 5400 G and classified them as high-performance LLDPE, whereas SABIC supplies them under the name SUPEER and mentions the same as metallocene
- xviii. The domestic industry had requested for clubbing of performance enhanced grades with Metallocene grades and no interested party has made any objections to the same.
- xix. The Authority must verify whether exporters have correctly classified their product into the appropriate PCN category and ensure that high-performance or metallocene grades are classified under the metallocene category.
- xx. The demand is pre-dominantly for C4 based LLDPE which accounts for 80–90% of total demand and imports. The properties of C6 and C8 based LLDPE are same as the product manufactured by the applicants, the specific technical qualities can be achieved by combining C4 based LLDPE with Metallocene grades in appropriate proportion.
- xxi. The domestic industry, though not manufacturing C8-based LLDPE, produce C4 and C6 Metallocene grades, which when proportionately combined are technically and commercially substitutable with C8 based LLDPE. Other domestic producers, including Reliance Industries Ltd., which is part of the Indian industry and a supporter in the investigation, manufacture and sell C8-based LLDPE in commercial quantities. As per Rule 2(b) of the AD Rules, 1995, the domestic industry covers all domestic producers of the like article, not only the applicants before the DGTR. Since the objective of anti-dumping duties is to protect the entire domestic industry, C8-based LLDPE cannot be excluded from the product scope.
- xxii. The powder form of LLDPE is an intermediate product to which additives and pigments are added to make pellets. The domestic industry manufactures comparable grades in pellet form, which directly compete with the powder form exported by SABIC, as masterbatch manufacturers can use either form.
- xxiii. Other interested parties have submitted that products manufactured by applicants cannot be used for high-performance application. The said assertion is inaccurate. LLDPE used in the such applications are not manufactured from a single monomer but a combination of C4 based LLDPE and other grades such as C6 Metallocene Grade produced by the applicants or C8 based LLDPE manufactured by other Indian manufacturers. Therefore, goods manufactured by the applicants are substitutable with products exported by other producers.
- xxiv. No evidence is provided that comparable domestic grades are commercially non-substitutable or differ in price or cost. As per the definition of “like article,” goods need not be identical but need to have similar characteristics. Claims based on lower melt flow index from Borouge’s proprietary technology are irrelevant, as such products and domestic goods are used interchangeably by the same customers.
- xxv. The domestic industry can produce LLDPE of any density within the Indian Standard range of 908.4 to 940.4 kg/m³, with applicants having produced up to 938 kg/m³ during the POI and capable of reaching 940.4 kg/m³ without any additional machinery changes.

- xxvi. There exist significant price differences between Metallocene and Non-Metallocene grades. The two grades were initially not separated due to negligible imports of Metallocene grades from the subject countries.

B.3 Examination by the Authority

6. The product under consideration as clarified through PUC/ PCN Methodology Notification dated 22nd August 2025 is as below:

“The product under consideration (hereinafter referred to as ‘PUC’) in the present investigation is Linear Low-Density Polyethylene, having density of 908.4 to 940.4 kg/m³ (hereinafter also referred to as ‘subject goods’).”

LLDPE is a copolymer of ethylene and other alkenes such as butene, hexene or octene. This results in an essentially linear chain arrangement, with the comonomer (i.e. the butene, hexene or octene) forming short, regular chains on the main carbon backbone. It is a colourless, non-flammable, non-reactive solid with no odour. It is primarily used in raw material for plastic processing industry to make a variety of products such as packaging films, profiles, wire & cable, extrusion coating, rotational moulded, product, hi-low grades for injection moulding, master batches etc.”

7. The PUC is classified in Chapter 39 titled “Plastics and Articles thereof” under HS Codes 3901 40 10 and 3901 10 10. The customs classification is indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
8. Additionally, to address the price difference between Metallocene and Non-Metallocene Grades, at the request of the interested parties the following PCNs were adopted:
- Metallocene Grades:** LLDPE Grades produced using Metallocene catalyst.
 - Non-metallocene Grades:** Conventional LLDPE Grades produced using catalysts other than Metallocene.

S.No.	Description	Grades	Code
1.	LLDPE Grades produced using Metallocene as catalyst	Metallocene Grades	MPG
2.	Conventional LLDPE Grades produced using catalyst other than Metallocene	Non-Metallocene Grades	NMG

9. The arguments made by the interested parties on the PUC and PCN methodology were examined carefully. It is noted that the claims have been primarily for exclusion of certain grades on the grounds that the domestic industry allegedly is not manufacturing the same or the grades produced by the applicants are technically or commercially not substitutable. The domestic industry on the other hand has refuted the submissions and claimed that products manufactured by them is interchangeably used by the same end users. They have claimed LLDPE of different monomers can be combined together to achieve the desired characteristics as the imported products. Further, the domestic industry has provided evidence of comparable grades being produced and sold by them in the Indian market by providing invoices and technical data sheet.
10. **Exclusion of powder form of LLDPE:** With regards to SABIC's submissions concerning exclusion of powder grade LLDPE, it is noted that the domestic industry also manufactures powder form of LLDPE. The domestic industry has provided evidence in the form of sales invoices of powder form of LLDPE. It is further noted that the powder form of LLDPE is primarily used by masterbatch manufacturers for compounding processes in which additives and color pigments are melted and then mixed into LLDPE, and subsequently LLDPE pellets are manufactured. Thus, a user has option to either carry out the compounding process itself or the same may be carried out by the LLDPE manufacturers who directly manufacture LLDPE pellets for such user. Accordingly, as the domestic industry is manufacturing powder form of LLDPE and since pellet and powder form of LLDPE are merely two forms of LLDPE, the Authority has not excluded the powder form of LLDPE from the product scope.
11. **Exclusion of Higher Alpha Olefin ("HAO") based LLDPE:** With regards to SABIC Group's and Sadara's request for exclusion of high alpha olefin, that is, C6 and C8 based LLDPE, it is noted that the domestic industry is indeed manufacturing C6 based LLDPE. With regards to C8 based LLDPE, the domestic industry has submitted that although it does not manufacture C8 based LLDPE, it is used in combination with other LLDPE monomers such C4 or C6 and the properties exhibited by C8 based LLDPE can be achieved by a combination of C4 and C6 metallocene grades. It is noted that none of the individual users have participated in the present investigation and the user Association, All India HDPE/PP Woven Fabric Manufacturers Association has not objected to this claim of the domestic industry. It is further noted that none of the interested parties have also provided any evidence to contradict this claim of the domestic industry.
12. The Authority notes that SABIC Group has requested for exclusion of C8 based LLDPE also on the ground that domestic industry is not producing and selling such grades in commercial quantity. While the domestic industry does not manufacture C8 based LLDPE, it does manufacture C4 and C6 grades which they have claimed that when combined in certain proportions are technically and commercially substitutable with the imported C8 based LLDPE. The said assertion by the domestic industry has not been rebutted by the other interested parties. The applicant association has also submitted invoices for C8 based LLDPE which is being manufactured and sold by Reliance Industries Limited, supporter of the present investigation. Irrespective of the production of C8 based LLDPE by the supporter, the Authority notes that the properties of C8 based LLDPE can be achieved by a combination of C4 and C6 metallocene grades, and accordingly, has not excluded C8 based LLDPE from the product scope.
13. Regarding the argument of Sadara that there exists a significant demand supply gap for C6 based LLDPE in India and that the domestic industry has not countered this argument or

provided grade wise production or demand data, it is noted that the question of exclusion from product scope does not depend upon demand of subject goods in India, rather the same is decided based on whether the domestic industry is producing and selling like article to the goods being imported into India.

14. **Exclusion of 6821NJ and 6318BJ Grades:** With regards to exclusion of SABIC Group's exclusion request for grades 6821NJ and 6318BJ, the Authority notes that admittedly these grades have not been exported to India. It is further noted that SABIC Group has requested exclusion of these goods primarily on the grounds that SABIC grades have a higher tear strength. On the other hand, the domestic industry has provided evidence of comparable grades sold by them. In this regard, the Authority recalls Rule 2(d) of AD Rules, 1995 which states:

““like article” means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such an article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation”

15. It is noted from the above definition that two products can be considered like articles to each other, not only when they are identical or alike in all respects but also when such articles have closely resembling characteristics. In the present case, both SABIC grades and domestically produced comparable grades have high tear strength. The Authority notes that while tear strength of these grades differ, such difference by itself does not make the products not like article to each other. It is further noted that the tear strength also depends upon the thickness of the film. It is further noted that these grades have not been imported into India since the demand for these products do not exist in India. Accordingly, the Authority has not excluded SABIC Grades 6821NJ and 6318BJ.
16. **Exclusion of Borstar Grades:** With respect to exclusion of Borstar Grades (FB2230, FB1200 and FB1350) manufactured through bimodal Borstar technology, ADPCL has argued that these grades have higher molecular weight and low melt flow rate (lower than or equal to 0.25 g/10 min) and that the domestic industry does not manufacture subject goods having melt flow rate lower than 1g/10 min. As stated above, it is not necessary that two products must be alike in all respects. Apart from the low melt flow index, the subject goods exported by ADPCL and the goods produced by the domestic industry have closely resembling characteristics. Accordingly, low melt flow index cannot be considered a ground for exclusion. It is further noted that each producer may have different production technology used in the production process depending upon the licensor of such technology. However, unless such production process lends an attribute leading to distinguishable physical / chemical characteristics, difference in production process itself cannot become a ground for exclusion of a product. In this regard, the Authority notes that ADPCL has not provided any evidence establishing that the LLDPE produced by ADPCL and LLDPE produced by the domestic industry are commercially or technically not substitutable.
17. The Authority further notes that the ADPCL has submitted letters from certain domestic users to substantiate its claim that Borstar Grades have a specific end use application and that domestically produced goods cannot technically substitute the same. It is noted that none of

these users have participated in the present investigation. The letters provided by them contain general information and similar sentences and phraseology. It is further noted that all these letters specifically rely on comparison with conventional C4 based LLDPE and do not address the quality or attributes of other LLDPE produced and supplied by the domestic industry. Whereas, Exhibit 3 provided by ADPCL as part of its submissions mention such characteristics for both metallocene and non-metallocene based LLDPE and not solely for conventional LLDPE. Accordingly, the Authority disagrees with ADPCL's claim and has not excluded Borstar Grades.

18. There are no known differences between the subject goods produced by the domestic industry and those imported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, classification of the goods. The domestic industry has claimed that the subject goods, being imported into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the goods manufactured by the applicants. The goods produced by the domestic industry and the imported goods are technically and commercially substitutable and accordingly, the Authority holds these products to be 'like article' under Rule 2 (d) of the AD Rules, 1995.

C. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

C.1 Views of other interested parties

19. The following submissions have been made by the other interested parties:
- i. The Petition contains insufficient evidence of injury for the purpose of initiation as required under Rule 2(b) and Art. 5.2 of AD Agreement and accordingly should not have been initiated.
 - ii. The Petitioner has not relied on actual data but on estimated figures for total domestic production. If actual data is considered, the Petitioner may not be able to satisfy the standing requirements.
 - iii. The Petitioner's standing is vitiated on account of exclusion of ONGC Petro Additions Ltd. ("OPAL") on the ground of it being a Special Economic Zone ("SEZ") unit during the POI. Rule 2(b) or Rule 5 of AD Rules, 1995 do not mandate exclusion of producer merely on account of being a SEZ unit. If OPAL is included as an eligible domestic producer, HPL and HMEL would not satisfy the requirement of Rule 5(3).
 - iv. OPAL's exclusion from total domestic production is without sufficient justification as it had exited SEZ on March 08, 2025, and was part of the domestic tariff area at the time of filing of the application by the Petitioner.
 - v. Irrespective of whether or not OPAL was operating in SEZ, its production must be included within the total domestic production as it is established in India and during the POI sold almost 85-90% of its LLDPE in Indian domestic market.
 - vi. Exclusion of OPAL artificially reduces the total eligible production and thus, inflates the share of HPL and HMEL in total domestic production.

- vii. Based on the information provided in OPAL's Annual Report, if OPAL's production is included, the share of HPL and HMEL would fall below 25% threshold prescribed under Rule 5(3) of AD Rules, 1995. Accordingly, prior to reaching any conclusion regarding the fulfilment of Rule 5(3) of AD Rules, 1995, the Authority must verify the production and sales volume of all relevant domestic producers.
- viii. By seeking to exclude OPAL on the basis of its SEZ status, the Petitioner effectively disregards the economic reality that OPAL is a producer established in India that undertakes substantial production and sales of the PUC in the domestic market.
- ix. The Authority in the previous investigations (Electrical Insulators and Solar Cells) has accepted SEZ units to be eligible to be part of the domestic industry.
- x. This approach is also consistent with international practice. USITC in Large Residential Washers in the context of injury determination treated production in Foreign Trade Zones as domestic production. Similarly, the USITC in Microwave Ovens from Japan treated goods produced in Free Trade Zone as domestically produced goods. While these findings were determined in the context of injury analysis and not standing, the underlying principles remain the same.
- xi. European Commission normally treats producers operating in free zones as domestic producers for determination of standing and for definition of domestic industry. Free zones are part of the territory of the European Union pursuant to Article 243(1) of the Union Customs Code.
- xii. The SEZ framework does not prohibit domestic tariff area sales. Units operating in SEZs are permitted to supply goods to the domestic market, subject to applicable conditions, including duties and overall Net Foreign Exchange ("NFE") requirements. Importantly, the requirement to maintain positive NFE pertains to the overall operational performance of the unit and does not negate or restrict the fact of domestic sales. Accordingly, the mere fact that a producer operates within an SEZ cannot be basis to exclude it from the domestic industry where it undertakes substantial sales in the domestic market.
- xiii. As HPL and HMEL are not representative of domestic industry and do not even account for 25% of total Indian production (if OPAL production is included), the Authority should have rejected the Petition.
- xiv. HPL and HMEL account for 26.33% of domestic sales (excluding OPAL), while OPAL itself has significant production capacity, indicating that its inclusion would materially alter the standing analysis.
- xv. Indian LLDPE industry is not fragmented and therefore, a share of 25-35% may not be accepted as constituting major proportion. Further, such a proportion does not automatically satisfy the requirement of major proportion. There is no practical difficulty in obtaining greater information, and therefore, the application must be rejected.
- xvi. The standing of HPL and HMEL falls significantly below the standard laid down by Appellate Body in *EC - Fasteners*, particularly once production of OPAL along with other domestic producers is taken into consideration. Further, if data of other Indian producers is considered, injury parameters would undergo significant change.
- xvii. If the Authority accepts the proposed definition of the domestic industry as the limited subset of producers, it would assess injury against a minor and self-selected proportion of less than 20% of the relevant Indian industry, leading to a material risk of distortion and skew the injury analysis, particularly given the much larger share of production held by the other major producers of the PUC.

- xxviii. The share of domestic industry's production must serve as a "substantial reflection of the total domestic production" such that the definition of "domestic industry" does not skew or distort the injury determination.
- xix. The object and purpose of anti-dumping duty is to protect domestic industry as a whole or those producers who are representative of the domestic industry due to their substantial/major share in Indian production. Anti-dumping duty cannot be imposed to protect interest of selected companies.
- xx. The Authority has failed to properly determine that the application has been filed "by or on behalf of the domestic industry", as required under Rule 5(3) of the AD Rules.
- xxi. The Appellate Body in *EC – Fasteners* emphasized that "a major proportion" must represent a relatively high and genuinely representative share of total domestic production, assessed in light of all producers as a whole. It rejected the EU's reliance on low shares such as 27% and even 36%, holding that such levels (particularly when derived from a self-selected or non-representative sample) do not meet the standard and distorts the injury analysis.
- xxii. The petitioners do not satisfy the separate requirement of major proportion under Rule 2(b) AD Rules, 1995. The minimum threshold for making an application under Rule 5(3) of AD Rules, 1995 cannot be extended to Rule 2(b).
- xxiii. The requirement of "major proportion" in Rule 2(b) is distinct from, and additional to, the 25% threshold under Rule 5(3). If a bare minimum share of 25–30% is accepted as sufficient in every case, the separate requirement in Rule 2(b) becomes redundant.
- xxiv. Para 4.9.11(iii) of Manual of Operating Practices does not create an absolute rule that every producer or group of producers who merely cross the bare threshold of 25% must be treated as constituting "a major proportion" of the total domestic production.
- xxv. The WTO Appellate Body in *EC – Fasteners* rejected equating the 25% threshold requirement for the purposes of ascertaining standing under Article 5.4 of the AD Agreement with the "major proportion" requirement and held it irrelevant for ascertaining "domestic industry" under Article 4.1 of the AD Agreement.
- xxvi. The Appellate Body explained that "a major proportion", should be understood as a proportion defined by reference to the total production of domestic producers as a whole. "A major proportion" of such total production will standardly serve as a substantial reflection of the total domestic production.
- xxvii. Indeed, the lower the proportion, the more sensitive an investigating authority will have to be to ensure that the proportion used substantially reflects the total production of the producers as a whole.
- xxviii. While there is no strict numerical threshold for what constitutes a "major proportion", the phrase has been understood to connote "important, serious or significant" proportion of total domestic production. Thus, the share of total production must serve as a "substantial reflection of the total domestic production" such that the definition of "domestic industry" does not skew or distort the injury determination.
- xxix. The Appellate Body in *EC – Fasteners (China)* (Article 21.5) held that even a proportion of 36% of the total domestic production remains low, even in the context of the fragmented fasteners industry.
- xxx. The Authority must call for complete and verified data from all major domestic producers for the POI before proceeding further. The Petitioner's claim is based on a limited segment of the industry, while producers accounting for a substantial share of India's total capacity have not supported any allegation of injury.
- xxxi. The information supplied by Reliance Industries Limited is deficient as it does not comply with requirements set out in Trade Notice No. 05/2021 dated July 29, 2021.

- xxxii. RIL has failed to provide documentary evidence for its installed capacity, domestic and export sales and accordingly, the same cannot be verified. Even if evidence has been provided subsequently, the information remains deficient at the stage of initiation and same must be rejected.
- xxxiii. RIL data is deficient and inconsistent with duplicate entries, making it unreliable.
- xxxiv. The subsequent filing of an updated support letter cannot cure the fundamental defect. The Petitioner did not transparently disclose the changes.
- xxxv. The Petitioner did not explicitly identify the changes made in the RIL support letter in its covering communication.
- xxxvi. The Petition claims that other Indian producers of LLDPE have supported the application, however, none of these producers have filed a support a letter in terms of Trade Notice 05/2021.
- xxxvii. The Authority must call for injury and cost data from other established Indian producers of the PUC referred to in the Petition, namely RIL, IOCL, GAIL, BCPL and OPAL to ensure that any injury assessment is representative of the domestic industry as a whole and not skewed by the inclusion of only some producers such as HMEL in this case.
- xxxviii. In absence of participation from other established players, the Authority cannot assess whether such players are earning profits or losses. The Authority should ask RIL to at least provide their figures for profitability.
- xxxix. The Authority in previous investigations such as Plain Medium Density Fibre Board (MDF) having thickness of 6mm and above has called for injury and cost related data from another producer related to the PUC.
- xl. The absence of any information from India's largest producers can only be interpreted to mean that they are not facing any injury on account of subject imports, and their non-participation implies that they are not suffering injury.
- xli. RIL and IOCL are consistent users of trade remedial measures. In the absence of cooperation from RIL, IOCL, GAIL, BCPL and OPAL, the Authority should consider that these domestic producers of LLDPE are opposed to the imposition of anti-dumping measures.

C.2 Views of the domestic industry

20. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry:
- i. The injury information for the present investigation has been provided by HPL and HMEL. As mentioned above, besides the co-applicants, there are 5 other producers of LLDPE, namely, Reliance Industries Ltd., Indian Oil Corporation, Gas Authority of India Ltd. Brahmaputra Cracker and Polymer Ltd. and ONGC-Petro Additions Limited. It may be noted that during the POI and the injury period, ONGC-Petro Additions Limited functioned as a special economic zone unit and therefore could not be considered as a domestic industry.
 - ii. Paras 4.19.21 and 4.19.23 of DGTR's Manual of Operating Practices, clearly specify that units located in SEZ "are not be treated as domestic industry" and that "production of SEZ should not be included while estimating the total production of the country".
 - iii. The Authority in several recent cases such as *Solar Cells*, *Industrial Laser Machines* has considered SEZ based units as ineligible domestic producers and has treated sales of SEZ based producers as imports into India.

- iv. HPL and HMEL account for almost 25%-35% of total LLDPE production in India. As such, HPL and HMEL's production constitutes a "major proportion" of total domestic production in India in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995. The applicants submit that it is the Authority's practice to consider production more than 25% of total eligible domestic production as "major proportion". In this regard, the applicants rely on the explanation provided in Para 4.9.11 (iii) of DGTR's Manual of Standard Operating Practices dealing with the test of major proportion.
- v. As admitted by the other interested parties, OPAL exited SEZ on March 08, 2025, 2 months after the end of the POI. Thus, OPAL's entry into domestic tariff area happened post-facto completion of POI.
- vi. It is the Authority's consistent practice of assessing the total eligible domestic production based on production carried out during the POI, just as dumping and injury is not based on post-POI fact.
- vii. In *EC – Fasteners*, the European Commission had issued questionnaires to approximately 318 known producers in the European Union, of which only 70 producers responded. Out of these 70 producers, the Commission had rejected the responses of 25 producers on the ground that they had failed to provide adequate information.
- viii. The Commission, ultimately therefore, defined on the basis of the remaining 45 producers, thereby restricting the scope of domestic industry to only those producers who were willing to be included in the sample and excluding certain producers who had otherwise provided relevant information, thus creating a risk of material distortion in injury analysis.
- ix. Moreover, the European Commission selected a sample of 6 domestic producers representing only 17.6% of the total Union production of the subject goods. This substantially narrowed the data coverage available for the injury analysis.
- x. Thus, *EC – Fasteners* decision was rendered in a situation where relevant producers were methodologically excluded and the sample represented only a limited proportion of total production.
- xi. The Appellate Body in *EC – Fasteners* refrained from providing a minimum threshold but primarily proceeded on the basis that the investigating authorities should not exclude domestic producers through self-selection process, which would lower the data coverage and thereby introduce a material risk of distortion in the injury analysis.
- xii. It is submitted that neither the WTO Anti-dumping Agreement nor the Indian municipal laws provide any threshold for determining "major proportion".
- xiii. Opposed to the facts in *EC- Fasteners*, where the sampled domestic producers constituted only 17.6% of total domestic production, in the present investigation, HPL and HMEL account for almost 25-35% of total LLDPE production in India.
- xiv. The Authority as a matter of practice as explained in Para 4.9.11 (iii) of DGTR's Manual of Standard Operating Practices has considered production exceeding 25% as "major proportion" in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995.
- xv. The 3 largest producers of LLDPE, accounting for more than 50% of Indian LLDPE production, have participated and submitted macroeconomic and price data.
- xvi. The applicants have also provided estimated sales and volumetric parameters for other Indian producers. Accordingly, the question of introducing "a material risk of distorting the injury determination" does not arise in the present investigation.

- xvii. The application has further been supported by Reliance Industries Ltd., which has provided supporter data as required under the applicable trade notices.
- xviii. The CESTAT in *Lubrizol (India) Pvt. Ltd. v. Designated Authority 2005 (7) TMI 132*, while explaining the term “major proportion” requirement held production accounting for 31% of total domestic production as major proportion. It further observed that “*major proportion of total domestic production*” cannot be viewed from the angle of solving a mathematical sum involving comparative measurements or size of different parts of a whole”.
- xix. The Authority in several of its past findings (*Hot Rolled Flat Products of Alloy or Non-Alloy Steel dated 13.08.2025*) has rejected to interpret “major proportion” as production exceeding 50% of total domestic production and construed the same as significant proportion.
- xx. The Authority in several investigations has considered domestic producers accounting for 25-35% percent of total domestic production as domestic industry in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995. In *PVC Suspension Grade Resin (Sunset Review)*, the Authority had held producers accounting for 30% of total production of subject goods in India as major proportion.
- xxi. The domestic industry submits that it has no objections or inhibitions to call data from other domestic producers. However, the non-participation of such producers in the present investigation should not constitute ground to deny relief to the domestic industry before the Authority.
- xxii. The Authority as part of the investigation procedure calls data from all producers. However, except RIL none of the other domestic producers have participated in the investigation,
- xxiii. The confidential version of RIL’s support letter was filed on record prior to the stage of initiation along with the application with all units of measurement and details of sales clearly identified in such letter as per the applicable trade notices.
- xxiv. Contrary to the facts urged by the other interested parties there has been no update in the RIL’s confidential support letter.
- xxv. The domestic industry constitutes major proportion in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995 and therefore, the non-participation of other domestic producers does not prevent the Authority from examining the injury to the domestic industry before it.
- xxvi. The application has been filed by CPMA on behalf of Indian LLDPE producers. RIL has already filed its support letter with the Authority. Further, other members of CPMA, IOCL and GAIL also supported the resolution to pursue appropriate trade remedial proceedings against the subject countries. Thus, Indian LLDPE producers have supported the allegation of injury. Moreover, subsequent to the initiation there has been no opposition from any of the domestic producers.

C.3 Examination by the Authority

21. Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 defines domestic industry as mentioned below:

‘domestic industry’ means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when

such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers'.

22. The Authority notes that the application has been filed by CPMA on behalf of the Indian LLDPE Industry. Other interested parties have raised the following concerns regarding the standing of the domestic industry:

OPAL should have been included within the scope of total eligible domestic production
Haldia Petrochemicals Ltd. and HPCL-Mittal Energy Limited do not represent major proportion of the domestic industry

a. OPAL should have been included within the scope of total eligible domestic production

23. Other interested parties have argued that OPAL, despite being a SEZ unit, is a LLDPE producer located in India and accordingly, the domestic industry in its application has incorrectly excluded OPAL from the computation of total eligible domestic production. They have also contended that other jurisdictions consider producers located in Free Trade Zone within the scope of total eligible domestic production. Further, it has been claimed that if OPAL is included within the scope of total eligible domestic production, HPL and HMEL's production would not be sufficient to qualify as applicant within Rule 5(3) of AD Rules, 1995.
24. In this regard, the Authority notes that the scheme of the SEZ Act, 2005 clearly establishes that SEZ units are treated as territories outside the customs territory of India for authorized operations and are fundamentally export-oriented entities. The Authority has already examined this issue in detail in prior proceedings and has recognized that SEZ units stand on a distinct legal and economic footing vis-à-vis producers operating in the Domestic Tariff Area ("DTA").
25. Further, the Authority recalls Section 53 of the SEZ Act which expressly provides that an SEZ shall be deemed to be a territory outside the customs territory of India for the purposes of undertaking authorized operations. Further, Section 2(i) of the SEZ Act excludes SEZ areas from the definition of "Domestic Tariff Area". The supplies from DTA units to SEZ units are treated as "exports", and supply of goods from SEZ units to DTA units attracts customs duties, including anti-dumping duties, countervailing duties, and safeguard duties under Section 30 of the SEZ Act. The legal framework therefore consciously creates an economic and customs distinction between SEZ units and DTA producers.
26. It is further noted that as per section 53 of SEZ Act, 2005, SEZ is admittedly outside the custom territory of India, however, it is within the geographical territory of India. In light of the aforesaid, assuming but not admitting that OPAL, which is a production unit falling within SEZ, whose production is required to be taken into consideration to compute the overall Indian production, yet the collective output of the domestic producers supporting the petition constitutes ***% of the total production of the PUC produced by the domestic Industry expressing support for the petition; there is no domestic producer who is opposed to the petition.

27. The Authority notes that the definition of domestic industry under Rule 2(b) of AD Rules, 1995 must be interpreted harmoniously with the SEZ Act, 2005 and the customs framework governing SEZ operations. Merely because an entity is incorporated in India or physically manufactures goods in India does not automatically render it part of the domestic industry for trade remedial purposes where the governing legal regime itself treats such entity as operating outside the customs territory of India. Further, the Authority in all its recent investigations has excluded SEZ units from the scope of the domestic industry. Accordingly, the Authority has excluded OPAL from the computation of total eligible domestic production.
28. The Authority further notes that other interested parties have also contended that as OPAL exited SEZ on March 08, 2025, that is, after the POI, and was part of the DTA at the time of filing of the application, it should have been considered as part of the total eligible domestic production. The Authority disagrees with this submission of the other interested parties. The Authority notes that the POI of the present investigation is CY 2024. All determinations pertaining to dumping and injury are to be based on the information pertaining to the POI. During the POI, OPAL continued to be a part of the SEZ and was not a DTA unit. Accordingly, for computation of total eligible domestic production under Rule 2(b) of AD Rules, 1995, the production undertaken by OPAL cannot be considered as part of total eligible domestic production.

b. Haldia Petrochemicals Ltd. and HPCL-Mittal Energy Limited do not represent major proportion of the domestic industry

29. Other interested parties have also contended that HPL and HMEL account for only 25%-30% of total production in India and as such do not account for total eligible domestic production. In this regard, other interested parties have relied on the decision of the Appellate Body in *EC – Fasteners* wherein the Appellate Body had held that domestic producers accounting for 27% of total domestic production did not constitute “major proportion” in terms of Art. 4.1 of the WTO Agreement on Anti-dumping.
30. The Authority notes that in the *Fasteners* investigation, the European Commission, while defining the domestic industry in the *Fasteners* original investigation, had limited the definition of domestic industry to only such producers which were willing to be included in the sample. Subsequent to the initiation of the investigation, the Commission received information from 70 producers out of 318 known producers. Thereafter, the Commission excluded 25 of these 70 producers from the scope of domestic industry definition, on the grounds that such producers expressed their unwillingness to be part of the sample, thereby, deliberately disregarded relevant information on record, and thus, introduced a material risk of distortion in injury examination. In this regard, the Authority recalls the observations of the Appellate Body in *EC – Fasteners*:

“429. According to the European Union's explanation, the Commission excluded 25 of these 70 producers from the domestic industry definition for various reasons, one of which was the producers' expressed unwillingness to be part of the sample.⁵⁷⁷ However, as noted above, the sample of domestic producers is a smaller universe than the domestic industry, and the unwillingness to be part of the sample should not affect whether a producer should be part of the domestic industry. This is confirmed by the relevant facts

in the fasteners investigation. Specifically, the Commission selected six producers as part of the sample, obtained relevant information from them, and verified the information on their premises. The Commission then used the information obtained from the sampled producers for its analysis of the "microeconomic" injury factors, but conducted its analysis of the "macroeconomic" injury factors on the basis of information obtained from all of the 45 producers included in the domestic industry definition. Thus, by including only those willing to be part of the sample in the domestic industry definition, the Commission's approach shrank the universe of producers whose data could have been used for part of the injury determination. Even though, due to the fragmented nature of the fasteners industry, the practical constraints on obtaining information may justify the inclusion of a smaller proportion of domestic production in the domestic industry definition, the Commission's approach in excluding those who provided relevant information but were unwilling to be part of the sample was unrelated to, and cannot be justified by, such practical constraints."

31. As can be noted from the Appellate Body's observations, the European Commission restricted the definition of domestic industry to only such producers which were willing to be included in the sample. By limiting the domestic industry coverage to only such producers the Commission "*shrank the universe of producers whose data could have been used for part of the injury determination*" as it excluded producers "*who provided relevant information but were unwilling to be part of the sample*".
32. In contrast to the above facts, the present investigation was initiated based on the injury information data provided by Haldia Petrochemicals Ltd. and HPCL-Mittal Energy Limited who account for more than ***% of total Indian production. Prior to the stage of initiation, the application was supported by Reliance Industries Limited, which provided information pertaining to installed capacity, production, value, and volume of domestic and export sales for the injury period. Subsequent to the initiation of the investigation, the Authority called for information via email dated 08.07.2025 from other domestic producers, namely Indian Oil Corporation Limited, Gas Authority of India Limited and Brahmaputra Cracker Polymer Limited and Reliance Industries Limited to provide the complete injury information. However, apart from Reliance Industries Limited, which provided information as a supporter of the investigation as per the applicable trade notices, none of the other producers responded to the same. The Authority notes that non-participation by other domestic producers does not lead to a material risk of distortion. In this regard, the Authority recalls the Panel's observation in *China – Autos (US)* wherein the following was observed:

"7.214. We find the US contention that MOFCOM's registration requirement introduced a material risk of distortion, as a process capable of leading to self-selection among domestic producers in the definition of the domestic industry, to be unconvincing. We note that there are multiple steps that must be taken in AD and CVD investigations, and IAs face logistical constraints in this regard. In previous cases, panels and the Appellate Body have concluded that an IA must be allowed some flexibility in how it ensures an orderly conduct of its investigations, for instance by establishing deadlines for interested parties to come forward to be considered for inclusion in the

*domestic industry.*³³⁶ *We consider that the same need for flexibility justifies the use of a registration process, which essentially requires interested parties to come forward by a deadline and make themselves known to the IA to be considered part of the domestic industry. The mere fact that some producers may choose not to do so, i.e., "self-select" out of coming forward, to use the US terminology, does not, in our view, introduce a material risk of distortion in the IA's process of defining the domestic industry. In our view, merely that domestic producers might choose not to participate does not mean that the registration requirement leads to a definition of domestic industry inconsistent with Articles 4.1 and 16.1. Provided a registration strikes an appropriate balance between the rights of interested parties to participate in an investigation, and administrative efficiency, we see nothing in the relevant provisions that would preclude it."*

33. In the present investigation, the Authority did call for information from all domestic producers of the PUC, however, such information was not provided. Unlike the European Commission, the Authority has not disregarded any information which is available on record. The Authority further notes that there is no legal requirement that the applicants must constitute at least 50% of the total Indian production. As noted by the Panel in *Argentina - Definitive Anti-Dumping Duties on Poultry from Brazil*, "the reference to a major proportion suggests that there may be more than one "major proportion" for the purpose of defining "domestic industry"".
34. The Authority further notes that major proportion cannot be determined on the basis of mathematical calculation. In this regard, the Authority recalls the observations of the Hon'ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in *Lubrizol (India) Pvt. Ltd. vs. Designated Authority* [2005 (187) E.L.T. 402 (Tri. - Del.)], wherein, it was held that in order to constitute major proportion, it is not necessary that production of domestic industry before the Authority should exceed more than 50% of total production in the country.

*"15.1 We may note here that the words "major proportion of the total production" in Rule 2(b) defining the 'domestic industry' are also capable of being construed so as to mean significant proportion or important part of the total production which may not necessarily exceed 50%. The word "major", as per the Oxford Dictionary, means "important, serious or significant". The word "proportion", in the context, would mean share. Therefore, the expression "major proportion" would, in the context, of total production of domestic industry, mean significant or important share. Such an interpretation is clearly permissible and going by it, **the share of the petitioner in total domestic production, being more than 31%, was undoubtedly a significant or important share i.e. a major proportion thereof.** The words "major proportion of total domestic production" cannot be viewed from the angle of solving a mathematical sum involving comparative measurements or size of different parts of a whole. The phrase is used in the context of the production output of domestic producers and admits of a broad interpretation so as to take in its sweep collective output that constitutes a significant or important share of the total domestic production of the article by the producers engaged in*

the manufacture or engaged in any activity connected with the manufacture of such article, as contemplated by Rule 2(b)...”

35. The Authority further notes that the Appellate Body’s observations in *EC – Fasteners* is limited to only such circumstances wherein the Authority by way of registration process for domestic producers introduces a risk of material distortion. In this regard, the Authority recalls the findings of the Panel in *China – Autos (US)*:

“7.220. Moreover, the Appellate Body noted that the IA had, in fact, identified and obtained information from more producers than the 45 it ultimately included in the domestic industry. The Appellate Body concluded that by including in the domestic industry only those producers willing to be included in the sample, the IA’s approach shrank the universe of producers whose data could have been used in making the injury determination.”

36. In the present case, the Authority upon initiation called for information from all domestic producers. Further, the question whether HPL and HMEL satisfy “major proportion” in terms of Rule 2(b) AD Rules, 1995 has also been assessed independently of Rule 5(3) of AD Rules, 1995. Accordingly, the Appellate Body’s observations in *EC – Fasteners* are not applicable to the present case.

37. The Authority further notes that information related to domestic producers that are outside the scope of the domestic industry is not relevant to evaluate the economic factors having a bearing on the state of the domestic industry. In this regard, the Authority recalls the observations of Panel in *EC – Bed Linen*, wherein it observed the following:

““6.182 However, our conclusion with respect to the second aspect of India’s claim is different. As we have noted, the determination of injury has to be reached for the domestic industry as defined by the investigating authorities, in this case the 35 producers comprising the “Community industry” as defined by the European Communities. In our view, information concerning companies that are not within the domestic industry is irrelevant to the evaluation of the “relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry” required under Article 3.4. This is true even though those companies may presently produce, or may have in the past produced, the like product, bed linen. Information concerning Article 3.4 factors for companies outside the domestic industry provides no basis for conclusions about the impact of dumped imports on the domestic industry itself. If other present or former bed linen producers had been considered part of the domestic industry, the fact that some of them went out of business would be relevant to the evaluation of the impact of dumped imports on the domestic industry. But given that the European Communities defined the domestic industry as 35 producers of bed linen, information concerning other companies does not inform the evaluation of “factors and indices having a bearing on the state of the industry” under Article 3.4 of the AD Agreement, and thus cannot serve as the basis of findings regarding the impact of dumped imports on the domestic industry.”

38. It has been this Authority's consistent practice to consider major proportion as significant proportion and not just producers accounting for more than 50% of total domestic production.
39. Based on the information provided in the application, the following table represents the total eligible domestic production of subject goods in India:

Indian Production (MT)				
Name of Producer	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Haldia Petrochemicals Limited (Applicant)	***	***	***	***
HPCL-Mittal Energy Limited (Applicant)	***	***	***	***
Reliance Industries Limited (Supporter)	***	***	***	***
Gas Authority of India Limited	***	***	***	***
Indian Oil Corporation Limited	***	***	***	***
Brahmaputra Cracker and Polymer Limited	***	***	***	***
Total Production	16,69,245	16,90,915	18,44,069	22,25,014
HPL and HMEL's share in total production	***	***	***	***
Range	0-10	0-10	20-30	25-35
Applicants + Supporter	***	***	***	***

40. The Authority notes that other Indian interested parties have contested the total Indian production estimation provided by the domestic industry. In this regard, the Authority has recomputed the total eligible Indian production based on the Ministry of Chemicals and Fertilizers data for the injury period including the POI¹. The Authority has considered the total production reported in Report for FY 2021-22, 2022-23 and 2023-24. Further, given that the POI is not a financial year, the Authority estimated production for Jan'24 – Mar'24 and Apr'24 – Dec'24 by apportioning data for FY 2023-24 and FY 2024-25, respectively. The Authority also referred to OPAL's Annual Reports for the aforesaid periods and applied the same methodology to compute its sales. Further, inventory to turnover ratio was applied for arriving at production figures for OPAL. The production so assessed is as below:

¹ <https://chemindia.chemicals.gov.in/Publicationspdf/Statistics-at-a-Glance-2024.pdf>

Indian Production (MT)				
Name of Producer	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Haldia Petrochemicals Limited (Applicant)	***	***	***	***
HPCL-Mittal Energy Limited (Applicant)	***	***	***	***
Reliance Industries Limited (Supporter)	***	***	***	***
Other Indian Producers	***	***	***	***
OPAL	***	***	***	***
Total Production*	29,14,100	24,24,400	27,50,000	28,42,700
Total eligible production (Total production ex. OPAL)	22,81,600	17,91,900	22,32,500	22,30,325
HPL and HMEL's share in total production	***	***	***	***
Range	0-10	0-10	20-30	25-35
Applicants + Supporter	***	***	***	***
Range	40-50%	60-70%	60-70%	70-80%

41. The Authority notes that the total production estimation provided by the domestic industry and the production estimated by the Authority based on the Report for the POI are in the same range. For the determination whether the domestic industry constitutes major proportion of the total eligible domestic production, the Authority has relied on the production figures based on the Report. Based on the same, the Authority notes that the share of HMEL and HPL's production in total eligible production is ***, which is in the same range as the share claimed by the domestic industry.
42. The Authority further notes that HMEL and HPL are the second and third eligible largest producers of LLDPE (excluding OPAL) in India and account for 25%-30% of total Indian production. Further, along with the Supporter, HPL and HMEL account for **% of total Indian production. Accordingly, the Authority considers that Haldia Petrochemicals Ltd. and HPCL-Mittal Energy Limited constitute 'major proportion' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995. Further, the Authority has considered macroeconomic data pertaining to other producers mentioned in the Report.

43. Insofar as data concerning other domestic producers is concerned, the Authority called for complete injury information from all domestic producers of the subject goods as per the prescribed format through its mail dated 08.07.2025. The information called included information pertaining to sales, cost of production and profitability of the domestic producers. However, none of the other domestic producers provided such information to the Authority. The Authority only received a support letter from Reliance Industries Limited which was already filed with the Authority prior to initiation. It is also noted that neither the Authority nor the domestic industry can compel any domestic producer to submit information pertaining to injury parameters.
44. The Authority further notes that the applicants have not imported the subject goods from the subject countries. Moreover, the applicants are not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or importer of the subject goods in India. Further, the production of the applicants' accounts represents a significant and important proportion of the total eligible domestic production and thus accounts for a major proportion of the total eligible domestic production. Thus, the applicants constitute domestic industry as defined under Rule 2(b) of the AD Rules, 1995, and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.
45. With respect to support letter filed by Reliance Industries Limited, the Authority notes that there is no difference between the letter filed at the stage of initiation and the letter circulated with the updated non-confidential version of the application. The domestic industry in the updated non-confidential version of the application only appropriately mentioned the unit of measurement therein based on the comments of the other interested parties. Accordingly, the Authority does not find any infirmity in the support letter.

D. CONFIDENTIALITY

D.1 Comments of the other interested parties

46. The other interested parties made the following submissions in this regard:
- The domestic industry has claimed excessive confidentiality.
 - The Petitioner has claimed confidentiality over details of total Indian production of the PUC.
 - The domestic industry has belatedly circulated the updated non-confidential version of the application.

D.2 Comments of the domestic industry

47. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:
- The domestic industry has provided data as per Trade Notice 10/2018.
 - The other interested parties are requesting to file certain information, which no longer form part of the application format.

D.3 Examination by Authority

48. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of AD Rules, 1995 provides as follows:

'Confidential information:

- (1) *Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
- (2) *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
- (3) *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.'*

49. Equate and RRPC have contended that the domestic industry has claimed confidentiality over total Indian production data in the application. The same has been disclosed by the Authority above.
50. With respect to disclosure of country-wise value and volume data, the Authority notes that the same has been disclosed by the domestic industry in the updated non-confidential version of the application.
51. Equate and Qatofin have contended that the domestic industry has circulated the updated non-confidential version of the application belatedly. The Authority notes that an updated non-confidential version of the application was circulated by the domestic industry on 11.04.2026 after Equate and Qatofin circulated their comments on confidentiality to the domestic industry for the first time on 09.04.2026. The updated petition mainly addresses the comments on confidentiality filed by the said exporters. It is noted that circulation of non-confidential versions of submissions is incumbent upon the interested parties themselves. Subsequent to the circulation of comments on 09.04.2026, the domestic industry circulated the updated version of the non-confidential application to the interested parties including Equate and Qatofin. Thus, since the comments on confidentiality were circulated by Equate and Qatofin belatedly, to which the domestic industry responded on 11.04.2026. Accordingly, it cannot be considered that the domestic industry has circulated a belated response.
52. Other interested parties have claimed that the domestic industry has not conformed to the Trade Notice No. 10/2018 with respect to the non-confidential version of the application. In this regard, it is noted that the comments of the other interested parties were circulated to the domestic industry, subsequent to which the domestic industry has provided the country-wise import data (volume and value), capacity utilization in required format, aggregated volume of production of other Indian producers, adjustments made to normal value, and export price. The domestic industry has further submitted that other comments by the interested parties are no longer part of the application format pertaining to confidentiality.

53. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
54. A list of all the interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E.1 Comments of the other interested parties

55. The following submissions have been made by the other interested parties:
- a. The initiation of investigation is against the spirit of India-UAE CEPA as imports from UAE have demonstrably declined during the POI.
 - b. The Petition contains inconsistent data and hence should be terminated.

E.2 Comments of the domestic industry

56. The following submissions have been made by the domestic industry:
- a. The domestic industry requests the Authority to disregard all legal and factual submissions made by All India HDPE Manufacturers Association and requests the Authority as it has neither filed any questionnaire response, nor has it filed any other submission/ document to establish its locus.
 - b. The Association has not provided its complete list of members, its by-laws, minutes of meeting to demonstrate which members have authorized it to participate in the present proceedings. In absence of the same, no weight should be lent to the submissions made by the Association.

E.3 Examination by the Authority

57. The Authority notes that trade remedial investigations are initiated based on *prima facie* evidence of dumping, injury and causal link as required under AD Rules, 1995. It is further noted that decline in imports cannot constitute a reason to not initiate an investigation if the evidence in the application contained information concerning dumping, injury and causal link. The Authority, as stipulated under India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement, carried out pre-initiation consultation with representatives from the Government of UAE and provided them the opportunity to present arguments which have been considered by the Authority in these final findings.

58. With regards to inconsistency in data contained in the application, the Authority notes that the final findings, disclosure statement and the initiation of investigation was based on data which was duly verified by the Authority from the accounting records of the domestic industry.
59. With respect to non-filing of user questionnaire by the All India HDPE/PP Woven Fabric Manufacturers Association, the Authority notes that in line with its consistent practice and keeping in view that no other Indian user has participated in the investigation, it has allowed and considered legal submissions from the association.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, AND DUMPING MARGIN

F.1 Comments of the other interested parties

60. The following submissions have been made by the other interested parties concerning the determination of normal value, export price and dumping margin:
- i. The petition did not contain sufficient evidence of dumping to justify initiation of investigation against Qatar and Kuwait.
 - ii. The petitioner has failed to demonstrate that it made any credible efforts to substantiate its claim that reliable information on prevailing prices in the State of Qatar, Kuwait and the other subject countries; or exports to third countries, were unavailable.
 - iii. LLDPE price indices and market assessments are widely published. In fact the Petitioner was aware that the Authority in previous investigation concerning LDPE from State of Qatar had found domestic sales prices to be representative.
 - iv. The Authority must find that the petition did not contain accurate and adequate evidence of dumping. Accordingly, the investigation must be terminated.
 - v. Where domestic prices are not available, the petitioner is required to rely either on export prices or cost of production in country of origin. There was no basis to estimate the normal value based on the costs of Indian producers.
 - vi. Art. 5.2 of AD Agreement requires disclosure of benchmark for normal value used for calculation of dumping margin. The Authority should have rejected the petition as normal value was not based on either of the methods.
 - vii. The applicant has not provided any basis for not considering the cost of production available in the country of origin and has also not explained why the costs of Indian domestic producers reflect the costs in the State of Saudi Arabia, Qatar, and Oman.
 - viii. The reference to related-party supply does not justify disregarding actual transfer prices without demonstrating that such transactions are not at arm's length or that they do not reasonably reflect market value.
 - ix. Separate dumping and injury margin must be computed for Rabigh Group, Kemya Group and Sadara Group from Saudi Arabia on the basis of their individual responses.
 - x. Absence of dumping from UAE on similar products (LDPE) has been established in past investigation.
 - xi. There is no particular market situation (PMS) in Saudi Arabia, Qatar, and Kuwait. No evidence has been provided to demonstrate the existence of the same apart from general assertion.

- xii. The Authority recently in *Monoethylene Glycol from Kuwait, Saudi Arabia and Singapore*, observed that there was no direct evidence of PMS in Kuwait during the POI.
- xiii. The Authority in previous investigation against Saudi Arabia has refused to consider that PMS affects price comparability.
- xiv. The Authority in *LDPE investigation* had determined that there was no raw material/utility price distortion in UAE.
- xv. The Petitioner has made a sweeping and unsubstantiated allegation that the GCC is affected by PMS due to government intervention in the pricing of certain input materials and utilities, without providing any basis.
- xvi. The Authority has rejected such misplaced assertions in the past investigations such as *Linear Alkyl Benzene (LAB) from Iran and Qatar* and *Low-Density Polyethylene (LDPE) from Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, United Arab Emirates and United States of America*. Accordingly, such general and unfounded assertions of existence of PMS must be dismissed.
- xvii. The Panel's decision in *Australia – A4 Copy Paper* requires the Petitioner to establish such a situation preventing proper comparison between domestic and export sales, in addition to PMS.
- xviii. RRPC should be awarded the weighted average rate determined for the SABIC Group.
- xix. RRPC was earlier held by Saudi Aramco and Sumitomo Chemical at 37.5% each, with the balance 25% held by public shareholders. Aramco acquired 22.5% additional stake in RRPC from Sumitomo in October 2025. RRPC and SABIC are under common control of SABIC.
- xx. The Authority had awarded RRPC duty applicable to SABIC Group in the recently concluded MEG investigation.
- xxi. The response of a cooperating producer/exporter cannot be rejected merely because another entity which exported a small portion of the producer's product has not filed a questionnaire response.
- xxii. Majority of export volume by RRPC was exported through SABIC and some quantity was exported through Sumitomo. With Aramco's announcement of acquiring 22.7% share of 37.5% Sumitomo's stake in RRPC, Sumitomo's role became limited.
- xxiii. Even if the Authority considers that RRPC's export chain is not fully on record on account of Sumitomo's non-participation, it must still use the information that has been placed on record by the cooperating producer and the cooperating related entity to the extent that such information satisfies the requirements of Annex II.
- xxiv. RRPC has also furnished resale price information and profitability statement of Sumitomo as part of verification documents. Accordingly, non-participation of Sumitomo cannot be converted into grounds for rejecting RRPC's entire questionnaire response.
- xxv. The Authority in *Polystyrene* and *Acetone* findings applied facts available only to the extent of non-cooperating sales channel.
- xxvi. The non-participation of related producer PrefChem from Malaysia is irrelevant for determination of anti-dumping duties for producers/exporters in Saudi Arabia.
- xxvii. The Authority in *PVC Suspension Resin, Halobutyl-Rubber and Isobutylene-Isoprene Rubber* granted cooperating exporters an individual duty rate even when related producers from non-subject countries did not cooperate in the investigation.
- xxviii. SHARQ is a 50-50 joint venture of SABIC and SPDC. Mitsubishi Corporation is not an affiliate of the SABIC group, rather Mitsubishi Corporation is a shareholder of

SPDC. Under Trade Notice No. 09/2018 it cannot be said that Mitsubishi is related to either Sharq or SABIC.

- xxix. Mere relationship between 2 parties is not sufficient to establish control. The Authority in Anodized aluminium frames for solar panels/modules has held that examination must focus on whether one entity is “*legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter*”.
- xxx. Mitsubishi holds only 33.34% of SPDC’s share, whereas SPDC holds 50% of share of Sharq. Neither Sharq nor Mitsubishi holds more than 5% in Sharq and therefore, it cannot be said Mitsubishi and Sharq are related entities.
- xxxi. Sharq is 50:50 joint venture between SABIC and SPDC and none of them are in a position to legally or operationally exercise restraint or direction over Sharq and thus, they cannot independently exercise control over Sharq.
- xxxii. While SABIC and SPDC together can control Sharq, Mitsubishi is only a minority shareholder in SPDC and therefore cannot legally or operationally exercise restraint over SPDC.

F.2 Views of the domestic industry

- 61. The following submissions have been made by the domestic industry concerning the determination of normal value, export price and dumping margin:
 - i. The Authority must examine whether complete domestic and export sales channel has been reported by the participating exporters from the subject countries.
 - ii. The non-confidential version of the SAPPL’s questionnaire response makes no reference to the fact that it has supplied subject goods manufactured by PRefChem to India.
 - iii. It is unclear whether PRefChem goods supplied by SAPPL to India are actually goods originating in Malaysia or goods originating in Saudi Arabia which were subsequently traded through PRefChem and SAPPL and therefore, exported to India.
 - iv. As is evident from SAPPL’s questionnaire, SAPPL has clearly stated that it has supplied goods manufactured only by producers in KSA.
 - v. SABIC’s response also does not mention that it has supplied subject goods manufactured in other subject countries to India.
 - vi. The only logical conclusion emanating from SAPPL and SABIC’s response is that goods exported from PRefChem, Malaysia are actually goods originating in Saudi Arabia which were traded and exported through PRefChem and SAPPL.
 - vii. SABIC Group’s related producer, PRefChem in Malaysia, Sharq’s related exporter, Mitsubishi Corporation and Petro Rabigh’s related exporter Sumitomo Chemical Asia Pte. Ltd. has not participated in the investigation.
 - viii. Para 12.20 of the Manual of Operating Practices clearly stipulates that responding producer has to file a complete response in respect of all related entities who are involved in exports of PUC for being considered cooperative and getting an individual dumping margin.
 - ix. In view of the incomplete sales channel, the Authority should reject entirety of response of SABIC Group, including Sadara and Kemya.

F.3 Examination by the Authority

- 62. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

'i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.'

63. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, as well as to the appropriate diplomatic representative advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority within the prescribed time limit.
64. The following producers have participated in the investigation:

Country	Name of Producer/ Exporter	Producer-Exporter / Exporter
Kuwait	Equate Petrochemical Co. ("Equate")	Producer-Exporter
Malaysia	No producer has participated from Malaysia	-
Oman	M/s OQ Polymer L.L.C. ("OQ")	Producer-Exporter
	OQ Marketing L.L.C. ("OQM")	Exporter
Qatar	Qatofin Company Limited Q.P.J.S.C ("Qatofin")	Producer-Exporter
	Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.P.J.S.C ("Muntajat")	Exporter
	QatarEnergy Marketing ("QEM")	Exporter

	TotalEnergies Petrochemicals France - Qatar Branch Office ("TotalEnergies")	Exporter
Saudi Arabia	Al-Jubail Petrochemical Company ("Kemya")	Producer-Exporter
	Arabian Petrochemical Company ("Petrokemya")	Producer-Exporter
	Eastern Petrochemical Company ("Sharq")	Producer-Exporter
	Jubail United Petrochemical Company ("United")	Producer-Exporter
	Rabigh Refinery & Petrochemical Company ("RRPC")	Producer-Exporter
	Sadara Chemical Company ("Sadara")	Producer-Exporter
	Yanbu National Petrochemical Company ("Yansab")	Producer-Exporter
	Saudi Basic Industries Corporation ("SABIC")	Exporter
	SABIC Asia Pacific Pte. Ltd. ("SAPPL")	Exporter
	SPDC	Exporter
	ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. ("EMAPPL")	Exporter
	Dow Saudi Arabia Product Marketing B.V. ("DSA")	Exporter
	Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited ("DCP (S)")	Exporter
	Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Dubai branch ("DCP (S) (D)")	Exporter
	Dow Chemical International Pvt. Ltd. Dubai Branch ("DCIPL")	Exporter
UAE	Abu Dhabi Polymers Co. Ltd ("ADPCL")	Producer-Exporter
	Borouge PTE Ltd. ("Borouge")	Exporter
	SRJ Global F.Z.E.	Exporter

65. Other interested parties have contested the allegation of particular market situation against the subject countries. The Authority notes that the domestic industry has not placed sufficient evidence on record. Accordingly, the Authority has not examined the allegation, and no adjustment on account of particular market situation has been made either to the cost of production or normal value and export price.
66. Where an exporting producer has exported through multiple sales channels (enumerated below), the Authority has determined a weighted average normal value and compared with the weighted average export price of that exporter to determine the dumping margin. Further, where an exporter has exported more than one PCN, dumping and injury margin has been determined PCN wise, and weighted average dumping and injury margin for the producer as whole has also been determined.

67. The Authority also notes that several related producers have also participated in the investigation. The Authority has determined individual dumping and injury margins for such producers and has also determined weighted average dumping and injury margin for the group. The final duty recommendation, if any, for all related producers would be based on the lower of the weighted average dumping or injury margin for the group. The following table represents the sales channel of the participating producers in the present investigation:

Sales Channel	Producer	Exporter 1*	Exporter 2*	Exporter 3*	
Domestic	Equate	-	-	-	UR customers
Export	Equate	-	-	-	UR customers
Domestic	OQ Polymers	OQ Marketing	-	-	UR customers
Export	OQ Polymers	OQ Marketing	-	-	UR customers
Domestic	Qatofin	Muntajat			UR customers
	Qatofin	QEM	-	-	UR customers
Export	Qatofin	Muntajat	-	-	UR customers
		QEM	-	-	UR customers
		Muntajat	Total Energies	-	UR customers
Domestic	Petrokemya	SABIC	-	-	UR customers
Export	Petrokemya	SABIC	SAPPL		UR customers
Domestic	Sharq	SABIC			UR customers
Export	Sharq	SABIC	SAPPL		UR customers
	Sharq	SPDC	Mitsubishi		UR customers
Domestic	United	SABIC			UR customers

Export	United	SABIC	SAPPL		UR customers
Domestic	Yansab	SABIC			UR customers
Export	Yansab	SABIC	SAPPL		UR customers
Domestic	Kemya	SABIC			
Export	Kemya	SABIC	SAPPL		UR customers
Export	Kemya	EMCAP			UR customers
Domestic	RRPC	SABIC			UR customers
	RRPC	Sumitomo			UR customers
	RRPC				UR customers
Export	RRPC	SABIC	SAPPL		UR Customer
	RRPC	Sumitomo			UR Customer
Domestic	Sadara	SABIC			UR Customer
	Sadara	DMS			UR Customer
Export	Sadara	SABIC	SAPPL		UR Customer
	Sadara	DSA	DCP (S)		UR Customer
	Sadara	DSA	DCP (S)	DCIPL	UR Customer
	Sadara	DSA	DCIPL		UR Customer
	Sadara	DSA	DCP(S) (D)	UR exporters	UR Customer
Domestic	ADPCL	Borouge			UR Customer

Export	ADPCL	Borouge			UR Customer
	ADPCL	Borouge	SRJ Exporter)	(UR	UR Customer

**All exporters are related unless specifically mentioned that they are unrelated (UR Exporter).*

68. The Authority notes that several producer-exporters, related and unrelated exporters, have participated in the present investigation. These producer-exporters have sold the subject goods both in their home market and exported to India through related party sales channels. During the course of investigation, the Authority found that in certain cases producers were selling at high prices to their related exporters and subsequently these related exporters were exporting the goods at dumped prices to India. Accordingly, as mandated under S.9(A) of the Customs Tariff Act, 1975, the Authority has determined both normal value and export prices from the point of first resale to independent customers after deducting SGA expenses and profits of related exporters and SGA expenses of producers to determine the ex-factory value at the producer level.
69. In this regard, the Authority notes that all producers from Saudi Arabia namely, Kemya, Petrokemya, Sharq, United, RRPC, Sadara, and Yansab, are either controlled directly or indirectly by SABIC or Saudi Aramco, the majority shareholder (70%) of SABIC and thus, have been considered as related parties. The shareholding patterns are as follows:

Producer	Shareholding	Direct Shareholder	Shareholding	Shareholder of Direct Shareholder
Kemya	***	SABIC	***	Saudi Aramco
	***	Exxon Chemical Arabia Inc.	***	
Petrokemya	***	SABIC	***	Saudi Aramco
RRPC	***	Saudi Aramco	***	
	***	Sumitomo Chemical Co.	***	
	***	Public Shareholding	***	
Sharq	***	SABIC	***	Saudi Aramco
	***	SPDC	***	Mitsubishi Corporation
United	***	SABIC	***	Saudi Aramco
	***	General Organization for Social Insurance	***	

Yansab	***	SABIC	***	
	***	Public	***	
SAPPL	***	Saudi Aramco	***	Saudi Aramco
Sadara	***	Excellent Performance Chemicals Company	***	Saudi Aramco
	***	Dow Saudi Arabia Holding B.V.	***	

70. Based on the above, the Authority has considered Kemya, Petrokemya, Sharq, United, RRPC, Sadara, and Yansab as related producers and form part of the same group, Saudi Aramco – SABIC Group.
71. The Authority notes that the sales channel for two producers, namely Sharq and RRPC of the SABIC Group, is incomplete on account of non-participation of related exporters. With respect to Sharq, the Authority notes that Sharq has exported the subject goods through its related entity SPDC which in turn resold them to its related entity Mitsubishi Corporation (“Mitsubishi”), which has further exported to India. Mitsubishi has not participated in the present investigation. In view of Sharq’s incomplete sales channel, the domestic industry has claimed that Sharq’s questionnaire response should be rejected.
72. The Authority notes that as part of the questionnaire response, participating exporters are required to furnish information concerning export and domestic sales channels, including the fact whether any related or unrelated exporters were part of such sales channels. Further, the questionnaire requires non-producer related entities involved in the exports of the PUC to submit Part I, Part II along with Appendix-5. Further, in Appendix 3A, the Authority specifically requires the participating exporter to identify the relationship between the exporter and customer, that is, whether they are related or not, and the nature of the relationship. This information is sought to ensure accurate determination of net export price, as there may be instances wherein the exporter’s related or unrelated exporter may be dumping. In the absence of accurate information concerning all export sales channels, the Authority would neither be able to determine the price at which the goods were finally exported to India nor the landed value of such goods in India.
73. In the present investigation, Sharq and SPDC did not provide a complete and accurate disclosure of their sales channel in their original questionnaire response filed on September 12, 2025. Specifically, SPDC omitted to even disclose in its narrative questionnaire response that it had made sales to India through its related party Mitsubishi. Furthermore, SPDC not only omitted to provide information pertaining to two columns namely, “If Related” (relationship between exporter and customer) and “what relationship” (nature of relationship”), but in fact deleted these columns altogether from Appendix 3A. Except SPDC, other entities of SABIC Group had reported these columns accurately.
74. As the questionnaire entails filing of comprehensive information, at times, inadvertent omissions can happen. To rectify such omissions, *vide* email dated October 12, 2025, the Authority provided a second opportunity to all exporters and specifically requested the exporters to clarify the names of all related producers, exporters, and exporters who were engaged in the sales or production of the subject goods in their response (Question (h) of

General Questions). Sharq and SPDC were also directed to complete their questionnaire response. However, in its response SPDC did not communicate to the Authority that its exports to India through Mitsubishi Corporation constituted related sales. Despite a specific question raised by the Authority, SPDC, in its revised appendices, once again failed to report export sales between SPDC and Mitsubishi as related party sales or to identify Mitsubishi Corporation as a related party. SPDC again in its questionnaire deleted the columns pertaining to relationship with its customer (Mitsubishi). Therefore, it follows that SPDC deliberately omitted information pertaining to its relationship with Mitsubishi.

75. The Authority further notes that Sharq has contended that Mitsubishi is not an affiliate of Sharq and that Mitsubishi does not control Sharq. In this regard, the Authority notes that prior to examining the relationship between Mitsubishi and Sharq, the Authority must examine the relationship between Mitsubishi and SPDC. Mitsubishi holds 33.34% share in SPDC, and thus directly holds more than 5% of shares in SPDC and indirectly holds more than 5% share in Sharq. The Authority further recalls its recently concluded investigation concerning imports of Mono ethylene Glycol, wherein it had held SPDC and Mitsubishi Corporation to be related, which was not contested either by Sharq or SPDC or Mitsubishi Corporation. The Authority has also perused the questionnaire response filed by Mitsubishi Corporation in that case and found that Mitsubishi Corporation had reported purchases from SPDC as related party purchases. In view of these facts, the Authority finds SPDC and Mitsubishi to be related to each other and Sharq to be indirectly related to Mitsubishi. Accordingly, the Authority has applied best information available to determine the export price and normal value of sales made by Sharq in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995.
76. The Authority notes that SABIC Group has not disclosed non-participation of another related producer, namely PRefChem from Malaysia. While export transactions in Appendix 3A/ Appendix 3B of SAPPL and SABIC listed exports by PRefChem, in response to the questions in the supplementary questionnaire response, neither of them clarified non-participation of PRefChem (50% owned by Saudi Aramco and 50% by Petronas). On account of non-participation of PRefChem, the Authority has determined the dumping and injury margin for Malaysia based on best available information in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995.
77. It is also noted that RRPC's export sales channel is incomplete on account of the non-participation of its related exporter Sumitomo. RRPC has relied on this Authority's findings in Polystyrene to claim that its response only to the extent of non-participation by its related exporter, should be rejected. The Authority notes that in Polystyrene, all related exporters of the exporter (Takht-e-Jamshid Pars Assalouyeh Petrochemical Company) had cooperated, and the Authority had determined the export price for unrelated exporters in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995. RRPC has also relied on the Authority's determination in Acetone, wherein it had applied best information for non-cooperating sales channel. The Authority notes that even in Acetone, the non-cooperating sales channel pertained only to unrelated exporters. Apposite to the facts in that case, in the present investigation, RRPC's exports to India are made through only related parties, that is, SABIC and Sumitomo. Accordingly, neither of the findings mentioned above lends any support to RRPC's argument for partial consideration of its response.
78. The Authority notes that RRPC in Section E of its questionnaire response while admitting that it had exported the PUC through both Sumitomo and SABIC, it did not file questionnaire response for Sumitomo, nor did it specify any reason for its non-participation. *Vide* email

dated October 12, 2025, the Authority enquired about RRPC's sales channels. RRPC in its response explained that in 2024 Saudi Aramco and Sumitomo had announced for acquisition of Sumitomo's 22.5% share capital in RRPC by Saudi Aramco. However, the Authority notes that the acquisition was finally completed in October 2025², that is, outside of the POI. Furthermore, even after the acquisition, Sumitomo continues to hold more than 5% share in RRPC and therefore remains related in terms of Trade Notice 9/2018 dated.

79. RRPC also explained that Sumitomo was no longer interested in business and that it was RRPC's understanding that Sumitomo intended to exit the polymer business. The Authority notes that Sumitomo held significant shareholding in RRPC during the POI and thus remained a related party. As Sumitomo has not participated in the present investigation, the Authority notes that RRPC's sales channel remains incomplete. While the Authority exercises discretion in case of non-related exporters, in case of involvement of related exporters, the same relaxation cannot be extended as it would incentivize non-participation by related exporters with low export prices and thus, prevent the Authority from accurate determination of dumping. Accordingly, the Authority has determined the export price and normal value of RRPC in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995.

F.3.1 Determination of Normal Value and Export Price

a) Normal Value for producers/exporters from Kuwait

Normal value for Equate Petrochemical Company ("Equate")

80. Equate has reported domestic sales of ***MT in the POI. The producer has claimed that all domestic sales are to unrelated parties. The producer has claimed adjustments on account of insurance, inland transportation, credit cost, and any other deduction. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence provided by Equate has accepted such adjustments in the normal value. The cost of production as claimed by Equate to the extent that same could be verified and could be legally substantiated by Equate has been considered by the Authority. It is noted that more than 80% of domestic sales were found to be profitable, accordingly, all sales have been considered for determination of normal value. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for non-cooperating producers

81. The normal value for non-cooperative producers/exporters from the Kuwait has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

b) Export price for producers / exporters from Kuwait

Export price in case of Equate

² <https://www.aramco.com/en/news-media/news/2025/aramco-completes-acquisition-of-additional-stake-in-petro-rabigh>

82. Equate has reported ***MT as exports of NMG PCN during the POI. The producer has claimed that it has made direct as well as indirect exports through an unrelated exporter of the subject goods to India. The unrelated exporter has not participated in the investigation. It is noted that export sales made through the unrelated exporter are insignificant. The producer has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost, and any other deduction. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence provided by Equate has accepted such adjustments in the export price. The Authority has taken into account the direct sales made to Indian customers on the basis of quantity and value reported in the appropriate appendices, and has also considered export price on the basis of facts available for the channels for which export price to India was not available as unrelated exporters did not cooperate in this investigation. The net export price so determined is shown in the table below.

Export price for non-co-operative exporters/producers.

83. The export price for non-cooperative producers/exporters from Kuwait has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for producers/exporters from Malaysia

Normal value for non-cooperating producers.

84. No producer-exporter from Malaysia has participated in the present investigation. Accordingly, the normal value for non-cooperative producers/exporters from Malaysia has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for non-co-operative exporters/producers.

85. The export price for non-cooperative producers/exporters from Malaysia has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for producers/exporters from Oman

Normal value for OQ Polymers LLC

86. OQ Polymers LLC has reported domestic sales of ***MT in its domestic market. These sales have been made through its related exporter OQ Marketing LLC. OQ Polymers LLC has claimed adjustments on account of inland transportation. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence provided by OQ Polymers has accepted such adjustments in the normal value. The cost of production as claimed by OQ Polymers to the extent that same could be verified and could be legally substantiated by OQ Polymers has been considered by the Authority. It is noted that only ***% of domestic sales were found to be profitable, accordingly, only profitable sales have been considered for determination of normal value. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for non-cooperating producers.

87. The normal value for non-cooperative producers/exporters from Oman has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for OQ Polymers LLC

88. OQ Polymers LLC has reported sales of ***MT of exports of NMG PCN during the POI. OQ Polymers LLC has claimed that it has made only indirect exports to India through its related exporter, OQ Marketing LLC. OQ Polymers LLC has claimed adjustments to export price on account on shipping cost. OQ Marketing LLC has claimed adjustment for credit cost. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence provided by OQ Group has accepted such adjustments in the export price. The net export price so determined is shown in the table below.

Export price for non-co-operative exporters/producers.

89. The export price for non-cooperative producers/exporters from Oman has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for producers/exporters from QatarNormal value for Qatofin Company Limited Q.P.J.S.C. (“Qatofin”)

90. Qatofin has reported domestic sales of ***MT in its domestic market. These sales have been made through its related exporter Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.P.J.S.C. (“Muntajat”). Qatofin has claimed adjustments on account of marketing fees. Further, its related exporter, Muntajat has claimed adjustments on account of insurance, inland transportation, credit cost, LC charges, bank charges, credit insurance, and documentation charges. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence provided by Qatofin and its related exporters has accepted such adjustments in the normal value. The cost of production as claimed by Qatofin to the extent that same could be verified and could be legally substantiated by Qatofin has been considered by the Authority. It is noted that more than 80% of domestic sales were found to be profitable, accordingly, all sales have been considered for determination of normal value. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for non-cooperating producers.

91. The normal value for non-cooperative producers/exporters from Qatar has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for Qatofin

92. Qatofin has reported sales of ***MT of exports of NMG PCN during the POI. Qatofin has claimed that it has made only indirect exports to India through its related exporters, Muntajat,

QatarEnergy Marketing and Total Petrochemicals France - Qatar Branch Office. Qatofin has claimed adjustments to export price on account of inland transportation. Total Petrochemicals France – Qatar Branch Office has claimed ocean freight, insurance, credit cost, bill of lading fee, lift on lift off charges, custom charges, LC charges, credit insurance and documentation charges. Qatar Energy Marketing has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, credit cost, LC charges, bank charges, credit insurance, and documentation charges. Muntajat has claimed adjustments on ocean freight, insurance, credit cost, bill of lading, lift on lift off, custom charges, LC charges, custom charges, bank charges, credit insurance, and documentation charges. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence provided by Qatofin and its related exporters has accepted such adjustments in the export price. The net export price so determined is shown in the table below.

Export price for non-co-operative exporters/producers.

93. The export price for non-cooperative producers/exporters from Qatar has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for producers/exporters from Saudi Arabia

Normal value for Kemya

94. Kemya has reported domestic sales of ***MT in the POI of NMG PCN. All domestic sales have been made through related exporter SABIC. The producer has not claimed any adjustments SABIC has claimed adjustments on account of handling& packaging, documentation, storage, land transportation and credit insurance. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence provided by Kemya has accepted such adjustments in the normal value.
95. The Authority found that except Kemya all other producers in Saudi Arabia which are related to Kemya and are using the same sales channel (through SABIC) have claimed selling and distribution expense. Kemya subsequently in its Supplementary Questionnaire Response also continued to claim no adjustments. To verify whether such costs were borne by its related exporter, the Authority checked per unit adjustments claimed by SABIC for other producers and found that per unit expenses borne by SABIC for Kemya were in the same range as other producers. The Authority also noted that sales made to SABIC were not ex-factory but rather FOB transactions. The Authority also noted that Kemya was located in the same geographic region as its related producers and therefore, there was no reason for not reporting adjustments for selling and distribution expenses. As all other producers were bearing selling and distribution expenses in addition to which SABIC was also bearing expenses in selling such goods, the Authority also adjusted Kemya's selling price by applying per unit rate reported in Appendix 4A of its related producers in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995. Further, the cost of production as claimed by Kemya to the extent that same could be verified and could be legally substantiated by Kemya has been considered by the Authority. It is noted that only *** % of domestic sales were found to be profitable, accordingly, only profitable sales have been considered for determination of normal value. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for PetroKemya

96. PetroKemya has reported domestic sales of ***MT in the POI of NMG PCN. All domestic sales have been made through related exporter SABIC. PetroKemya has claimed adjustments on account of selling and distribution expense. SABIC has claimed adjustments on account of handling& packaging, documentation, storage, land transportation and credit insurance. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence provided by PetroKemya has accepted such adjustments in the normal value. The cost of production as claimed by PetroKemya to the extent that same could be verified and could be legally substantiated by PetroKemya has been considered by the Authority. The Authority used such cost to carry out the ordinary course of trade test. It is noted that more than 80% of domestic sales were found to be profitable, accordingly, all sales have been considered for determination of normal value. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Sharq

97. Sharq has reported domestic sales of ***MT in the POI of NMG PCN. For reasons mentioned above, Sharq's normal value has been determined in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995. The Authority has considered the highest normal value of cooperating producers from Saudi Arabia as the normal value for Sharq. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for United

98. United has reported domestic sales of ***MT in the POI of NMG PCN. All domestic sales have been made through related exporter SABIC. United has claimed adjustments on account of inland transportation. SABIC has claimed adjustments on account of handling& packaging, documentation, storage, land transportation and credit insurance. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence provided by United has accepted such adjustments in the normal value. The cost of production as claimed by United to the extent that same could be verified and could be legally substantiated by United has been considered by the Authority. The Authority used such cost to carry out the ordinary course of trade test. It is noted that more than 80% of domestic sales were found to be profitable, and accordingly, all sales have been considered for determination of normal value. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Rabigh Refinery and Petrochemical Company

99. RRPC has reported domestic sales of ***MT in the POI of NMG PCN. For reasons mentioned above, RRPC's normal value has been determined in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995. The Authority has considered the highest normal value of cooperating producers from Saudi Arabia as the normal value for RRPC. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Sadara Chemical Company

100. Sadara Chemical Company has reported domestic sales of ***MT in its domestic market. These sales have been made through its related entities Dow Material Sciences Co. and SABIC. Sadara has claimed adjustments on account of inland transportation, credit cost,

packing cost and marketing fees. Dow Material Sciences Co. has claimed adjustments on account of inland transportation, credit cost, packing cost and any other deduction. SABIC has claimed adjustments on account of handling & packing, documentation, storage, land transportation, and credit insurance. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence provided by Sadara has accepted such adjustments in the normal value. The cost of production as claimed by Sadara to the extent that same could be verified and could be legally substantiated by Sadara has been considered by the Authority. The Authority used such cost to carry out the ordinary course of trade test. It is noted that all sales were found to be loss-making.

101. As Sadara's all domestic sales were found to be loss-making, and as normal value for other producers in Saudi Arabia was available, the Authority relied on data of other cooperating producers in Saudi Arabia, for determination of Sadara's normal value. The Authority has considered normal value of NMG PCNs of fully cooperating producers with highest domestic sales in volume terms in Saudi Arabia. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Yansab

102. Yansab has reported domestic sales of ***MT in its domestic market. These sales have been through its related entity SABIC. Yansab has claimed adjustments on account of storage and transportation costs. SABIC has claimed adjustments on account of handling & packaging, documentation, storage, land transportation, and credit insurance. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence provided by Yansab has accepted such adjustments in the normal value. The cost of production as claimed by Yansab to the extent that same could be verified and could be legally substantiated by Yansab has been considered by the Authority. The Authority used such cost to carry out the ordinary course of trade test. It is noted that more than 80% of domestic sales were found to be profitable, accordingly, all sales have been considered for determination of normal value. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for non-cooperating producers.

103. The normal value for non-cooperative producers/exporters from the Saudi Arabia has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for producers / exporters from Saudi Arabia

Export Price for Kemya

104. Kemya has reported ***MT as exports of NMG PCN during the POI. Kemya has claimed that it has made only indirect exports through its related exporters namely, SABIC-SAPPL and EMCAP to India. Kemya has not claimed any adjustments in its response. Similar to normal value, the Authority found that except Kemya all other producers in Saudi Arabia which are related to Kemya and are using the same sales channel (through SABIC) have claimed selling and distribution expense. Kemya subsequently in its Supplementary Questionnaire Response also stated it did not bear any expenses in relation to exports. To verify whether such costs were borne by its related exporters, the Authority checked per unit

adjustments claimed by SABIC for other producers and found that per unit expenses borne by SABIC for Kemya were in the same range as other producers. The Authority also noted that sales made to SABIC were not ex-factory but rather FOB transactions. The Authority also noted that Kemya was located in the same geographic region as its related producers and therefore, there was no reason for not reporting adjustments for selling and distribution expenses. As all other producers were bearing selling and distribution expenses in addition to which SABIC was also bearing expenses in selling such goods, the Authority also adjusted Kemya's selling price by applying per unit rate reported in Appendix 3A of its related producers.

105. SABIC has claimed adjustments on account of rebates, port charges, ocean freight, handling and packing, documentation, extra port, other expenses, storage, take-in warehouse, bank charges, custom clearance, demurrage, insurance, war risk, land transportation, on/off loading and credit insurance. SAPPL has claimed adjustments on account of LC insurance premium, credit insurance, outsourcing fee, bank charges, and commission. EMCAP has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, port and other related expenses, discount, credit cost, and canvassing commission. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence has accepted such adjustments in the export price. The net export price so determined is shown in the table below.

Export Price for PetroKemya

106. PetroKemya has reported ***MT as exports of NMG PCN during the POI. PetroKemya has claimed that it has made only indirect exports through its related exporters namely, SABIC-SAPPL to India. PetroKemya has claimed adjustments on account of selling and distribution expenses. SABIC has claimed adjustments on account of rebates, port charges, ocean freight, handling and packing, documentation, extra port, other expenses, storage, take-in warehouse, bank charges, custom clearance, demurrage, insurance, war risk, land transportation, on/off loading and credit insurance. SAPPL has claimed adjustments on account of LC insurance premium, credit insurance, outsourcing fee, bank charges, and commission. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence has accepted such adjustments in the export price. The net export price so determined is shown in the table below.

Export Price for Sharq

107. Sharq has reported ***MT as exports of NMG PCN during the POI. Sharq has claimed that it has made only indirect exports through its related exporters namely, SABIC-SAPPL and SPDC-Mitsubishi. As mentioned above, Mitsubishi Corporation, Sharq's related party has not participated in the present investigation. Accordingly, Sharq's sales channel remains incomplete and therefore, the Authority has determined export price for Sharq based on the facts available in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995 and has considered the lowest export price of cooperating producers from Saudi Arabia. The net export price so determined is shown in the table below.

Export Price for United

108. United has reported ***MT of exports of NMG PCN during the POI. United has claimed that it has made only indirect exports to India through its related exporters namely, SABIC-SAPPL. United has claimed adjustments to export price on account on inland transportation.

SABIC has claimed adjustments on account of rebates, port charges, ocean freight, handling and packing, documentation, extra port, other expenses, storage, take-in warehouse, bank charges, custom clearance, demurrage, insurance, war risk, land transportation, on/off loading and credit insurance. SAPPL has claimed adjustments on account of LC insurance premium, credit insurance, outsourcing fee, bank charges, and commission. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence has accepted such adjustments in the export price. The net export price so determined is shown in the table below.

Export Price for Rabigh Refinery and Petrochemical Company

109. RRPC has reported ***MT of exports of NMG PCN during the POI. RRPC has claimed that it has made only indirect exports to India through its related exporters namely, SABIC-SAPPL and Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd. As mentioned above, Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd, RRPC's related party, has not participated in the present investigation. Accordingly, RRPC's sales channel remains incomplete and therefore, the Authority has determined export price for RRPC based on the facts available in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995 and has considered the lowest export price of cooperating producers from Saudi Arabia. The net export price so determined is shown in the table below.

Export Price for Sadara Chemical Company

110. SCC has reported sales of ***MT of exports of NMG PCN during the POI. SCC has claimed that it has made only indirect exports to India through its related exporters namely, SABIC-SAPPL, Dow Saudi Arabia Marketing B.V., Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Dow Chemical Pacific (Singapore) Pvt. Ltd. – Dubai Branch and Dow Chemical International Pvt. Ltd. Dubai Branch. SCC has claimed adjustments on account of inland transportation, port and other related expenses, packing cost, credit cost, and marketing fees. Dow Saudi Marketing B.V. has claimed adjustments on account of Freight Sadara to Dow Warehouse, Insurance, Warehouse Cost, Dow Pacific Singapore has claimed adjustments on account of Freight Saudi Arabia to Dow Warehouse, Insurance, Port and other related expenses. Dow Chemical Pacific (Singapore) Pvt. Ltd. – Dubai Branch has claimed adjustments on account of insurance and credit cost. DCIPL has claimed adjustments on account of credit cost.
111. SABIC has claimed adjustments on account of rebates, port charges, ocean freight, handling and packing, documentation, extra port, other expenses, storage, take-in warehouse, bank charges, custom clearance, demurrage, insurance, war risk, land transportation, on/off loading and credit insurance. SAPPL has claimed adjustments on account of LC insurance premium, credit insurance, outsourcing fee, bank charges, and commission. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence has accepted such adjustments in the export price. The net export price so determined is shown in the table below.

Export Price for Yansab

112. Yansab has reported sales of ***MT of exports of NMG PCN during the POI. Yansab has claimed that it has made only indirect exports to India through its related exporters namely, SABIC-SAPPL. Yansab has claimed adjustments to export price on account on inland transportation. SABIC has claimed adjustments on account of rebates, port charges, ocean freight, handling and packing, documentation, extra port, other expenses, storage, take-in warehouse, bank charges, custom clearance, demurrage, insurance, war risk, land

transportation, on/off loading and credit insurance. SAPPL has claimed adjustments on account of LC insurance premium, credit insurance, outsourcing fee, bank charges, and commission. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence has accepted such adjustments in the export price. The net export price so determined is shown in the table below.

Export price for non-co-operative exporters/producers.

113. The export price for non-cooperative producers/exporters from Saudi Arabia has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for producers/exporters from UAE

Normal value for Abu Dhabi Polymers Company Limited (“ADPCL”)

114. ADPCL has reported domestic sales of ***MT in its domestic market. ADPCL has sold both NMG and MG PCNs in the domestic market. These sales have been through its related entity Borouge Pte Ltd. ADPCL has claimed adjustments on account of land transportation, warehouse and handling cost, credit cost, packing cost. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence has accepted such adjustments in the normal value. Additionally, its related exporter, Borouge has claimed adjustments on account of credit cost and rebates given to customers. The cost of production as claimed by the ADPCL to the extent that same could be verified and could be legally substantiated by ADPCL has been considered by the Authority. The Authority used such cost to carry out the ordinary course of trade test. It is noted that more than 80% of domestic sales were found to be profitable, accordingly, all sales have been considered for determination of normal value. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for non-cooperating producers.

115. The normal value for non-cooperative producers/exporters from UAE has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for ADPCL

116. ADPCL has reported sales of ***MT of exports of NMG and MPG PCN during the POI. ADPCL has claimed that it has made only indirect exports to India through its related exporter Borouge Pte Ltd and unrelated exporter, SRJ Global FZE. ADPCL has claimed adjustments to export price on account of ocean freight and insurance, inland transportation, port warehousing and other expenses, credit cost and packing cost. Borouge Pte Ltd. has claimed adjustments on account of credit cost, fixed cost of India office and rebates. SRJ Global FZE has not claimed any adjustments. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence has accepted such adjustments in the normal value. The net export price so determined is shown in the table below.

Export price for non-co-operative exporters/producers.

117. The export price for non-cooperative producers/exporters from UAE has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Dumping margin for related producers and Exporters

118. It is noted that in the subject investigation many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of a dumping/ injury margin and thus determine one single dumping/injury margin for them. This is in particular because calculating individual dumping/injury margins might encourage circumvention of anti-dumping measures, thus rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual dumping/ injury margin.
119. In accordance with the above, related producers and exporters have been regarded as one single entity and attributed one single dumping/ injury margin calculated on the basis of the weighted average of the dumping/ injury margins of the cooperating related producers and exporters.

F.3.2 Dumping Margin

120. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows:

Dumping Margin Table

Producer	PCN	Normal value (\$/MT)	Export Price (\$/MT)	Dumping Margin (\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
Kuwait						
Equate Petrochemical Company	NMG	***	***	***	***	10-20
Others	All	***	***	***	***	20-30
Saudi Arabia						
Al-Jubail Petrochemical Company ("Kemya")	NMG	***	***	***	***	0-10
Arabian Petrochemical Company ("Petrokemya")	NMG	***	***	***	***	0-10
Eastern Petrochemical Company ("Sharq")	NMG	***	***	***	***	20-30
Jubail United Petrochemical Company ("United")	NMG	***	***	***	***	0-10

Rabigh Refinery & Petrochemical Company	NMG	***	***	***	***	20-30
Sadara Chemical Company	NMG	***	***	***	***	0-10
Yanbu National Petrochemical Company ("Yansab")	NMG	***	***	***	***	0-10
Saudi Aramco - SABIC Group	NMG	***	***	***	***	10-20
Others	All	***	***	***	***	20-30
Qatar						
Qatofin Company Limited Q.P.J.S.C	NMG	***	***	***	***	(10)-0
Oman						
OQ Polymers L.L.C.	NMG	***	***	***	***	0-10
Others	All	***	***	***	***	10-20
UAE						
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd	NMG	***	***	***	***	0-10
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd	MG	***	***	***	***	(10)-0
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd	Wt. Avg.	***	***	***	***	0-10
Others	All	***	***	***	***	0-10
Malaysia						
Any	All	***	***	***	***	40-50

G. ASSESSMENT OF INJURY

G.1 Views of other interested parties

121. The following submissions have been made by the other interested parties with respect to injury and causal link:
- i. The existence or absence of a demand-supply gap is not determinative of injury, and the Petitioner's ability to cater to Indian demand, does not discharge the Petitioner from its obligation to demonstrate adverse volume and price effects.
 - ii. The Authority in Seamless Tubes and Pipes had terminated the investigation when major producer, Maharashtra Seamless Ltd, failed to provide information.
 - iii. Imports from State of Qatar have fallen compared to 2021-22 and have declined by almost 65%. Such a dramatic decline rules out any claim of injury from the alleged dumped imports from the State of Qatar. In fact, imports from State of Qatar have started declining even prior to commencement of HMEL's production.

- iv. While imports from State of Qatar fell steeply, domestic production increased drastically from 100 to 826 index points, whereas demand grew from 100 to 119 index points, thus clearly indicating that imports from State of Qatar did not have any adverse impact on the domestic industry.
- v. While imports from Kuwait increased in the POI by 153 index points, the domestic production and sales of the domestic industry sales and production increased by 826 and 798 index points. This demonstrates that the imports from Kuwait have not adversely affected the domestic production and sales of the Domestic Industry.
- vi. While volume of imports from Oman remained stable during the injury period, domestic industry's sales and production have increased significantly. Imports from Oman have contracted substantially while share of domestic industry has increased significantly.
- vii. UAE's share in total demand has declined in the POI and there is no effective increase in volume of imports from UAE.
- viii. The Petition contains no evidence of increase in volume of subject imports either in absolute terms or in relative to production or consumption in India.
- ix. The Petition appears to contain inflated volume of imports from Oman compared to the actual data supplied by the exporter and corresponding third-party data available in public domain. The Authority is requested to verify the same prior to undertaking injury analysis.
- x. The Petitioner has relied on end point comparisons without examining intervening trends. As recognised in *Russia – Anti- Dumping Duties on Light Commercial Vehicles*, an endpoint to end-point comparison may mask intervening developments and produce a distorted picture of trends.
- xi. Further as per *European Communities – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil*, investigation must take into account the actual intervening trends in each of the injury factors and indices rather than just a comparison of end-points.
- xii. Volume of imports from subject countries has not shown a consistent increasing trend but have declined from 528,590 MT in 2022-23 to 485,524 MT in 2023-24 and further again to 415,013 MT in the POI, a fall of over 21 percent in volume from 2022-23.
- xiii. The Petition does not explain how declining imports caused injury to the domestic industry.
- xiv. The Petitioners have been the only beneficiary of the increased Indian demand. The declining share of imports shows that such imports have not impacted the sales of the Petitioners and Indian Industry as a whole.
- xv. The decline in import volumes coinciding with increase in volume of imports clearly establishes that there is no sustained injurious import pressure.
- xvi. The growth in Petitioners' sales in more than growth in Indian demand. If imports have declined on account of HMEL's production, it shows that HMEL has been able to replace imports from the subject countries.
- xvii. Petitioners' sales have increased by 698% in the POI. Subject imports from the subject countries have adjusted to domestic supply.
- xviii. Issues relating to price effect and profitability are separate and unrelated to volume effect. Lack of volume injury is evident from the fact of substantial increase in Petitioners' sales and their market share along with the decline in market share of subject imports declined after FY 2022-23.

- xix. Imports increased only between 2021-22 and 2022-23 and have thereafter declined. Imports from the subject countries have declined significantly by 32 index points compared to previous year.
- xx. The total share of subject imports was merely 15% in the POI, whereas the market share of Petitioner has increased from 3% in the base year to 22% in the POI.
- xxi. The reliance on selective data-points to allege an increase in import volumes is misplaced and does not establish adverse volume effects.
- xxii. The Petitioner cannot rely on a general decline in the market share of other Indian producers to claim injury to themselves as other domestic producers have not provided data.
- xxiii. As per the Appellate Body's decision in *China – GOES*, the Authority must go beyond identifying relevant trends in prices and demonstrate that the subject imports have “explanatory force” for the occurrence of such trends. Application of this standard to the present investigation demonstrates a lack of correlation between the landed value of imports and the Petitioner's selling price.
- xxiv. As per the Appellate Body's decision in *EC – Bed Linens* and *Thailand H-Beams*, the investigating Authority is required to examine all relevant factors and positive developments in key parameters cannot be disregarded.
- xxv. The data contained in the Petition shows that the performance of the Domestic Industry has remained stable or improved over the injury period.
- xxvi. The attempt to disregard improvements in volumetric parameters on the ground that earlier data pertains only to HPL is misplaced.
- xxvii. The domestic industry has not provided any evidence that imports have displaced domestic production or prevented utilization of available capacity, accordingly there is no injury to the domestic industry.
- xxviii. HMEL did not exist in the base year and therefore comparing injury parameters of domestic industry in the POI with base year is economically and logically flawed.
- xxix. Installed capacity, production, capacity utilization, and sales have sharply increased over the injury period and in the POI.
- xxx. Domestic industry has expanded capacity by more than 200%, increased production by 726%, increased domestic sales by nearly 698% and massively expanded its workforce, wages and productivity.
- xxxi. Having relied on HMEL's commissioning of new capacity to explain import trends when convenient, the applicant companies cannot selectively attribute the same trend to dumped imports for the purpose of asserting financial injury.
- xxxii. The domestic industry has increased its sales by 300% over the injury period. This growth indicates that financial health of domestic producers in the PUC has been good, otherwise HMEL would not have decided to invest in the PUC market.
- xxxiii. Productivity, wages, and employment have improved steadily, indicating rapidly expanding industrial activity and improved operational efficiency.
- xxxiv. The attempt to disregard improvements in volumetric parameters on the ground that earlier data pertains only to HPL, is misplaced.
- xxxv. The Petitioner has admitted decline in import volumes in 2023–24, which coincides with the commencement of HMEL's production, demonstrating that imports have adjusted in response to increased domestic supply.
- xxxvi. the Domestic Industry has relied on aggregate country-wise data and does not rebut the Respondents' exporter-specific case that Sadara Group's exports to India declined in the POI as compared to the base year and preceding year.
- xxxvii. No adverse volume effect can be attributed to Sadara Group on the basis of country-level data.

- xxxviii. A situation where the domestic industry expands capacity, retains or improves its market share, and continues to sell significant volumes in the domestic market cannot be said to constitute volumetric injury.
- xxxix. Petition does not contain adequate and accurate evidence on the effect of prices on the domestic industry.
- xl. Petitioners have failed to furnish price undercutting data for entirety of injury period. There was marginal price undercutting in the POI.
- xli. Price undercutting has not prevented the Petitioner from increasing its market share.
- xlii. Export price of Sadara is 20-30% higher than the prices indicated in the Petition. Sadara is therefore not undercutting the prices of the domestic industry and is not causing any adverse effect on the domestic industry.
- xliii. Landed value of UAE is highest amongst the subject countries and therefore, no injury is attributable to imports from UAE. Price undercutting from UAE is extremely low and negligible.
- xliv. The landed price of subject countries has remained more or less stable during the injury period, with decline registering only in the POI, which was on account of aggressive pricing of the domestic industry.
- xlv. HPL and HMEL provide after-sales incentives to the domestic producers and such after sale discounts must be removed while computing alleged price undercutting.
- xlvi. The quantum of price undercutting can be ascertained only once complete information including after sales rebates is provided to the Authority.
- xlvii. DGTR must examine monthly price variations particularly after HMEL began production of PUC.
- xlviii. The Petitioners have been able to increase/ decrease their selling price in line with the increase/decrease in cost of sales. Subject imports from the subject countries have neither depressed nor suppressed prices of the Petitioners. Price suppression/ depression, if any, is on account of aggressive pricing by the Petitioners.
- xlix. The Petitioner reduced domestic selling prices in FY 2023-24 even when import prices remained stable, and the reduction in import prices in the POI followed the Petitioner's earlier price reduction.
- l. Petitioner's submission that it was selling at losses is not relevant for establishing price undercutting, as such losses are due to its own cost movement and commercial strategy.
- li. Domestic industry increased its prices in the POI even though landed prices of subject imports fell in the POI.
- lii. The Petitioners reduced their selling prices by 19% in FY 2023-24 from FY 2022-23 while the landed price of imports remained at the same level. Thus, the exporters were forced to reduce their prices due to predatory and aggressive pricing by the Petitioners.
- liii. Price suppression and depression movements are on account of other macroeconomic, industry-factors and commissioning of HMEL's newly commissioned plant, and not due to imports.
- liv. Petitioners' selling prices have moved in line with their own cost of sales and not in line with the landed price of imports.
- lv. The marginal decline in Petitioners' selling prices in the POI follows an exceptional price increase in 2021-22 and decline in price is a result of market correction rather than downward pressure from imports.
- lvi. While landed value declined by 1% in 2022-23, the domestic industry increased its selling price by 11%. Despite there being no change in landed value in FY 2023-24, the Petitioners reduced their selling price by 19%. Furthermore, even though the

- landed value declined in the POI, the Petitioner was able to increase its prices by 11%.
- lvii. HPL, in its Annual Report for FY 24-25 stated it has witnessed strong growth of 8% in LLDPE, thus, clearly admitting no injury.
- lviii. Imports from Qatar constitute 1% market share in the POI and therefore, it cannot influence domestic selling price and in fact, follows the prices set by the domestic industry.
- lix. If exporters sold the PUC at dumped prices into India and were undercutting the prices, import volumes would have increased, instead of declining.
- lx. The market share of imports has consistently remained within the range of 10-20% whereas the market share of domestic industry has increased from 0-10% to 20-30%. Similarly, share of Indian LLDPE industry has also recovered in the POI.
- lxi. Imports from the subject countries are maintaining a relatively small and stable share; such limited import penetration cannot be considered to have caused adverse volume effect.
- lxii. The Petitioners enjoy a market share of 22%, with domestic players having share of 83% in the POI.
- lxiii. Petitioners' market share has increased from 3% in the base year to 22% in the POI, which indicates that there is no injury to the Petitioners.
- lxiv. The Petitioner was making profits in the base year, and the loss in FY 2022-23 was on account of 25% increase in cost of sales. The Authority should investigate whether such losses were on account of intrinsic factors or internal inefficiencies.
- lxv. Any price effects claimed by the applicant cannot be attributed to imports but rather to pricing decisions, capacity adjustments, and cost dynamics acknowledged by the Applicant.
- lxvi. The applicants have admitted that the price decline commenced around the time HMEL started production. Thus, addition of new capacity coincided and likely contributed to losses to the applicants.
- lxvii. The Authority should compare HMEL's performance with its projected performance in project report and verify if HMEL's losses were truly unforeseen.
- lxviii. The Petitioner's depreciation and interest cost substantially increased by 82% and 41% respectively.
- lxix. The domestic industry has been earning negative returns since the base year when imports were at their lowest level in the base year, therefore, no injury is attributable to imports.
- lxx. The domestic industry seeks to ignore improvements in production, capacity utilisation and sales in the later years and attributes it to the entry and ramp-up of HMEL. However, deterioration in financial parameters despite the entry of new producer is relied upon to claim injury.
- lxxi. The domestic industry is relying upon favourable trends and disregarding adverse trends without context, resulting in a distorted and unreliable injury analysis.
- lxxii. The alleged deterioration in financial parameters is on account of initial pricing pressures, higher fixed costs, higher input costs and start up-operation, stabilisation challenges.
- lxxiii. Despite increase in selling price between FY 2021-22 and 2022-23, the applicants' profitability declined sharply.
- lxxiv. Despite decline in cost of sales, applicants continue to incur losses. Therefore, these alleged losses are not commensurate with movements in import prices and cannot be attributed to the alleged dumping.

- lxxv. The domestic industry's losses peaked in 2023-24 exactly when HMEL's plant was commissioned. If improvements in volume parameters are attributable to HMEL's entry, then alleged deterioration in financial parameters must also be considered on account of the same.
- lxxvi. While import prices of Qatar remained stable in 2022-23, and import prices of Kuwait increased slightly, the PBIT of domestic industry significantly declined during that period.
- lxxvii. Despite decline in prices of imports from Qatar during the POI, domestic industry's PBIT has improved. If import prices from Qatar were causing injury to the domestic industry, its PBIT should have declined.
- lxxviii. While prices for Kuwait declined marginally in the POI, the domestic industry decline in PBIT was far greater. Accordingly, injury is not due to imports from Kuwait.
- lxxix. Despite increase in prices of exports from Oman since 2022-23, domestic industry's PBIT has declined. Thus, injury is not attributable to Oman's import prices.
- lxxx. If exporters from Oman intended to dump the PUC into India, import volumes should have instead increased as prices fell.
- lxxxi. The increase in cost of sales of Petitioner's prices was on account of increase in energy and feedstock prices globally as has been accepted in HPL's Annual Report.
- lxxxii. The cost differences between HMEL and HPL are not minor but significant and inconsistent with normal industry behaviour.
- lxxxiii. The financial loss claimed by the domestic industry is self-inflicted and is on account of initial capital investments, which is evident from the sharp increase in interest cost and depreciation.
- lxxxiv. The reduction in per unit losses during the POI accompanied with increased sales and market share is inconsistent with the allegation of injury due to subject imports.
- lxxxv. Petitioners' losses increased in FY 2022-23, even though its selling price increased by 11 index points.
- lxxxvi. The fact that domestic industry remains in loss after removal of interest cost does not mean that injury is due to subject imports.
- lxxxvii. The losses can be on account of low-capacity utilization, high fixed overhead absorption, product mix issues, higher operating costs, pricing pressure arising from its own marketing strategy, and internal competition with existing domestic producers.
- lxxxviii. The inventories have increased due to commencement of production by HMEL.
- lxxxix. The increase in the average inventory is not on account of the subject import which commands only 15% share in the Indian market and has been declining throughout the injury period. The Petitioners are keeping healthy inventory ready at their disposal to cater to the increasing domestic and global demand of the PUC.
- xc. The Petition contains insufficient evidence on causation between the alleged dumping and injury to the domestic industry. No explanation has been provided on how the alleged dumped imports had "explanatory force" for any allegedly negatively trending injury factors.
- xc. Indian producers of PUC face an inherent cost disadvantage due to usage of naphtha as a raw material, whereas producers in other countries use ethane, which has a lower cost of production.
- xcii. The cash cost of producing ethylene using Ethane as a cracking route is approximately 240-250 \$/MT in Saudi Arabia. Natural advantage regarding availability of raw material and the selection feedstock efficiencies is an inherent

- advantage for the producers of PUC in Saudi Arabia when compared with Indian producers.
- xciii. The applicant companies' financial performance was influenced by internal commercial and structural factors, rather being driven by dumped imports.
- xciv. HMEL and HPL are fundamentally different in terms of operational maturity, scale, and cost behaviour, and therefore cannot be aggregated without distorting the analysis.
- xcv. HMEL was in its first year of operations during 2023-24, therefore, its cost cannot be expected to be highly efficient.
- xcvi. While cost of sales of domestic industry declined by 16% in the POI, HPL's cost of sales declined only by 5%, indicating that the cost reduction is primarily driven by HMEL, a first-year producer, rather than any genuine improvement in cost of established producer.
- xcvii. HMEL's newly commissioned plant has outperformed HPL in terms of cost efficiency, which questions the reliability and representativeness of the cost data relied upon by the Petitioner.
- xcviii. The divergent performance amongst the domestic industry indicates that the alleged injury is driven by company-specific factors unrelated to imports.
- xcix. The magnitude of losses is disproportionate to the movement in selling prices alone and persists even during periods when the cost of sales was at moderate levels.
- c. HMEL incurred losses during the first year due to initial inefficiencies linked with startup costs, which were reduced in the POI despite the allegations of dumping, price undercutting. HMEL was in operationalization stage during the injury period, therefore, injury is not due to imports from the subject countries.
- ci. The staggering increase in interest cost and depreciation fully explains the domestic industry's financial position. These are natural consequences of a large capital expansion and not effects of imports.
- cii. Publicly available credit ratings and HMEL itself confirm that the dominant cause of HMEL's financial distress is the commissioning of its US\$ 3 Billion GGSPAP petrochemical project.
- ciii. HPL continues to incur losses, despite decline in import volumes, which are attributable to its high cost of production.
- civ. Injury is not due to imports from State of Qatar but due to other subject countries.
- cv. Injury is not due to imports from Kuwait, Oman but due to other subject countries such as Saudi Arabia and UAE, whose volumes have increased substantially, both in absolute and relative terms.
- cvi. Imports from Kuwait have increased only marginally compared to significant surge from other subject countries.
- cvii. Injury is not attributable to UAE as imports from subject countries other than UAE has increased even though no comparable FTA benefit exists from these subject countries.
- cviii. Injury is due to weakened global consumption as recognized by HPL in its Annual Report. Further, HPL in its Annual Report 2023-24, has claimed that the domestic market has faced immense loss due to the inventory build-up on account of the commissioning and stabilization of one of the largest petrochemical plants in India.
- cix. HMEL, being a new entrant, has resorted to aggressive pricing to compete with established players.
- cx. HPL has suffered injury due to shutdowns undertaken during COVID-19.
- cxi. The Authority cannot simply apply Annexure III to HMEL as it started production in August 2023 and is not an established producer.

- cxii. It is the consistent practice of the Authority that in the case of a newly established domestic industry, optimization of capacity should be done on the basis of available data, read with projections in the project report.
- cxiii. For optimum utilization of raw material and utilities, only the best utilization of the established producer, HPL, ought to be considered, and HMEL's NIP should not be overstated.

G.2 Views of the domestic industry

122. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link;
- i. India currently has a dedicated capacity of around 31 lakhs MT for LLDPE against a demand of around 29 lakhs MT. Thus, there is no demand supply gap in India, and Indian manufacturers can cater to the entirety of Indian demand.
 - ii. As FY 2021-22 and 2022-23 data pertains only to HPL, volumetric data in the years FY 2023-24 and CY 2024 show an apparent improvement and may be misinterpreted to suggest that there is no injury to the domestic industry. In contrast to the volumetric parameters, financial parameters show significant price injury during the entirety of the injury period.
 - iii. The other interested parties have mostly examined individual subject countries price and volume movement against other countries and domestic industry's injury parameters to allegedly demonstrate that there has been no injury to the domestic industry on account of such exports.
 - iv. Such examination is entirely incorrect in view of the principles of cumulative assessment laid down under AD Rules, 1995.
 - v. Despite about 25% increase in Indian production capacity, the market share has declined and that of the subject imports has increased. Thus, Indian Industry is also facing volumetric injury despite having adequate capacity to cater to entirety of Indian demand.
 - vi. Imports of subject goods from the subject countries have increased significantly compared to the base year.
 - vii. The decline in import volumes from 2023-24 is on account of commencement of production by HMEL. Between the base year and the POI, while imports have increased by 48%, the demand has only increased by 19%.
 - viii. The demand for the subject goods has increased throughout the injury period. The growth rate of imports has surpassed growth rate of demand.
 - ix. Due to dumped imports from the subject countries, the domestic industry has not been able to adequately benefit from the growth in Indian demand, despite its best efforts to increase its sales, even at non-remunerative prices.
 - x. Other interested parties have failed to appreciate that whenever a new producer enters a market, after undertaking substantial investment, it cannot be expected to keep its capacities idle. Being a new entrant, it would at least attempt to partly recover its fixed cost, so as to remain viable.
 - xi. HMEL's plan to set up LLDPE production facility has been in effect since 2017. HMEL commenced commercial LLDPE production in August 2023. The data pertaining FY 2021- 22 and FY 2022-23 pertains only to HPL. Thus, once HMEL commenced production, the volumetric parameters such as production, sales etc., are bound to exhibit an upward trajectory.

- xii. Import prices are undercutting domestic prices by a very significant margin.
- xiii. The domestic industry is facing undercutting even when it is selling at losses.
- xiv. The domestic industry was indeed forced to provide post-sales discounts in face of the low-price dumped imports exported by the subject countries.
- xv. Indian users quote prices offered by the subject countries while negotiating with the domestic industry against which the domestic industry has no option but to give discounts to make sales in the domestic market.
- xvi. The evidence of post-invoicing discounts provided by the association does not in any manner weaken the case of domestic industry, but rather strengthens it, showing the economic reality and the price pressure exerted by the imports from the subject countries, forcing the domestic industry to further reduce its prices.
- xvii. Due to decline in landed value of subject imports, the domestic industry has been forced to sell below its cost, clearly evidencing price depression.
- xviii. The decline in prices commenced from the period as soon as HMEL started production.
- xix. While the domestic industry's market share has increased in the POI compared to previous years, the increase has been achieved by selling the subject goods at non-remunerative prices in India.
- xx. Compared to the base year, while the market share of Indian Industry has declined, the market share of subject countries has increased.
- xxi. The injury to the domestic industry is evident from the fact that despite significant addition in the domestic production capacity, the market share of the subject imports has increased during the POI, while that of the Indian industries has gone down.
- xxii. The domestic industry has been able to increase its market share only by making non-remunerative loss-making sales significantly below its cost. However, despite their loss-making sales, Indian Industry could not increase their share in Indian demand.
- xxiii. The domestic industry's profitability is in red and has been earning cash losses, a negative PBDIT and accumulating negative returns on capital employed during the POI.
- xxiv. The domestic industry has not only been earning losses but also has negative PBDIT and cash losses which are examined after removing interest elements. Thus, no injury cannot be attributed to HMEL's recent commencement of production.
- xxv. The increase in NFA during 2023-24 arose solely on account of capitalization of HMEL's LLDPE plant upon commencement of commercial production, pursuant to investment decisions and capital expenditure that had been planned and undertaken much earlier, in 2017.
- xxvi. Such historical capitalization cannot be construed as evidence of the domestic industry's present financial capacity to undertake fresh investments.
- xxvii. HMEL's losses have reduced in the POI on account of it becoming more efficient in terms of reducing its cost of sales. However, despite a decline in cost of sales, HMEL continued to make sales below its cost, leading to significant losses.
- xxviii. Even if the impact of depreciation and interest cost is removed, on account of its commencement of production during the injury period, HMEL was still making cash losses during the POI.
- xxix. Where the domestic industry has been unable to earn reasonable returns or even recover its costs during nearly fifteen months of production, its capacity to mobilize funds and undertake future capital investments stands materially impaired.
- xxx. The domestic industry has access to raw materials used in the production of PUC at internationally competitive prices.

- xxx. It may be noted that most of the natural gas and other feedstock prices are controlled by respective governments of the subject countries.
- xxxii. The Kingdom of Saudi Arabia compensates Aramco, the feedstock supplier to Petro Rabigh and other SABIC Group producers, to compensate the losses made by Aramco in selling feedstock at government regulated prices.
- xxxiii. Similar pricing difference was found by the Authority in case of Kuwait concerning supplies of ethane by Kuwait Petroleum Corporation to Equate and The Kuwait Olefins Company.
- xxxiv. Indian producers access raw materials at internationally competitive prices, producers in Saudi Arabia and other subject countries rely on distorted input prices by their governments. Thus, the inherent advantage is not of geographic location, rather it is of distorted input price regime.
- xxxv. Naphtha-based production process is an inherent feature of the domestic industry and that non-attribution analysis is not required to be conducted for factors which are inherent features of the domestic industry.
- xxxvi. The other interested parties are assuming, without evidence, that a first- year plant must necessarily exhibit inefficiencies.
- xxxvii. The other interested parties have failed to appreciate that while HMEL may be a new producer for LLDPE, it is an established entity in polymer business for more than a decade and has sufficient technical know-how to address any start up and stabilisation issues
- xxxviii. During the injury period, HMEL was able to quickly achieve a capacity utilization of almost 65%-75% within a span of 8 months and thus was able to stabilize its production.
- xxxix. During the POI HMEL achieved a capacity utilization of around 80-90%, which in itself is clear evidence of its technical competence, operational efficiency, and successful stabilisation of production.
- xl. The Authority in Melamine had held wherein the domestic industry has been in production for a sufficient period of time and wherein it has achieved a high-capacity utilization during the POI, the impact of startup effects is sufficiently covered.
- xli. For a product such as LLDPE, where the predominant component of cost is raw material, operational efficiency is more appropriately assessed through raw material consumption norms, which are at comparable levels for both producers.
- xlii. HMEL's lower cost of sales is primarily attributable to lower fixed cost per unit resulting from higher production volumes and higher capacity utilisation. By contrast, HPL has been incurring losses due to sustained dumped imports since 2022-23, which have adversely impacted its production levels and prevented optimal utilisation of capacity.
- xliii. The price-suppressing effect of dumped imports from the subject countries has depressed HPL's output of LLDPE, thereby increasing fixed cost absorption per unit and, consequently, its overall cost of sales.
- xliv. After undertaking substantial capital investment, it was commercially imperative for HMEL to ramp up production to stabilise operations, optimise capacity utilisation, and achieve efficient absorption of fixed costs. In capital-intensive petrochemical operations, rapid scale-up post-commissioning is both normal and necessary to attain operational equilibrium.
- xl. The present investigation is related to unfair trade practices of exporters from the subject countries. For past several years, Indian domestic LLDPE market has been

characterised with several domestic producers and internal competition amongst domestic producers is an inherent feature of the domestic market.

G.3 Examination by the Authority

123. Rule 11 of the AD Rules, 1995 read with Annexure II to the AD Rules, 1995 provides that injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the AD Rules, 1995.

G.3.1 Cumulative assessment of injury

124. Article 3.3 of the WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the AD Rules, 1995 provides that in case where imports of subject goods from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
125. Accordingly, the Authority has terminated the investigation against Qatar and Qatar has not been considered as part of the subject countries for the purpose of injury examination. Subsequent to the issuance of disclosure statement, interested parties pointed out that imports from Kuwait and Oman were less than 3% and collectively accounted for less than 7% of total imports into India. Accordingly, in terms of Rule 14 of AD Rules, 1995, they requested for termination of investigation against Kuwait and Oman on grounds of non-fulfillment of criteria laid down in Para (iii)(a) of Annexure – II to AD Rules, 1995. The Authority notes that at the stage of initiation, imports from Kuwait, Oman and Qatar were found to be dumped and together they constituted more than 7% of total quantum of imports into India. However, subsequent to negative dumping margin determination for Qatar, the collective volume for countries accounting for less than 3% of dumped imports has fallen below 7%. Accordingly, the Authority hereby terminates investigation against Kuwait, Oman and Qatar.

126. The imports of subject goods from Qatar, Kuwait and Oman have been considered as part of imports from other countries.
127. The Authority notes that:
- The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin of dumping from each of the other subject countries, is more than the *de minimis* limits prescribed under AD Rules, 1995.
 - Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
128. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess the cumulative effect of dumped imports of the subject goods from subject countries.
129. The Authority notes OQ Polymers has claimed that imports from Oman have remained stable during the injury period and accordingly, cannot be a cause of injury to the domestic industry. The Authority notes that none of the interested parties have submitted any claim for non-cumulation of imports from any of the subject countries. Further, as stated above, the conditions for cumulative assessment of imports have been fulfilled. Accordingly, the Authority considers that individual import volume and pricing trends from the individual subject countries are not required to be examined.
130. Further, in view of the peculiar facts of the present case, where the constitution of the Indian domestic producers has undergone significant change during the injury period, the Authority has considered, for the purpose of injury analysis, the verified information pertaining to the domestic industry, the supporter to the investigation, and the Indian industry as a whole, wherever such information was available and could be duly verified.

G.3.2 Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand / apparent consumption

131. The Authority for the purpose of the present investigation has estimated the demand for the subject goods in India based on the Ministry of Chemicals and Fertilisers' Report for FY 2024-25³ and FY 2023-24⁴. Upon perusing the demand provided in the Report, the Authority noted that the imports figures considered in computation of demand in the Report did not match the actual quantum of imports made during the injury period. Accordingly, the Authority adjusted imports figures considered in the Report, with the DG System import data for computing Indian demand. Further, given that the POI is a calendar year, the Authority prorated the adjusted demand based on the report for FY 2023-24 and FY 2024-25 to arrive at the demand for the POI.
132. The demand so determined is provided in the table below.

Assessment of Demand

³ https://chemicals.gov.in/sites/default/files/inline-files/Glance-2025_1.pdf

⁴ <https://chemindia.chemicals.gov.in/Publicationspdf/Statistics-at-a-Glance-2024.pdf>

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Subject countries	MT	1,60,803	2,73,231	2,83,797	2,36,986
Index	MT	100	170	176	147
Malaysia	MT	6,017	19,092	48,600	26,739
Saudi Arabia	MT	76,614	1,60,171	1,47,038	1,16,418
United Arab Emirates	MT	78,172	93,968	88,160	93,829
Other Countries	MT	3,70,200	6,07,483	5,88,368	4,79,863
Total Imports	MT	5,31,004	8,80,714	8,72,165	7,16,849
Sales of the domestic industry	MT	***	***	***	***
Index	MT	100	152	511	798
Sales of Supporter	MT	***	***	***	***
Index	MT	100	104	99	106
Sales of domestic industry + Supporter	MT	***	***	***	***
Index	MT	100	108	133	164
Sales of Other Domestic Producers	MT	***	***	***	***
Index	MT	100	72	76	72
Total Sales of Indian Industry	MT	***	***	***	***
Index	MT	100	84	95	102
Total Demand/Consumption	MT	33,78,651	32,65,325	35,74,741	36,31,353
Index	MT	100	97	106	107

133. It is seen that demand for the subject goods in India after initially declining in FY 2022-23, has consistently increased over the remaining injury period, including the POI. Compared to the base year, subject imports from the subject countries increased by 47 % in the POI. During the same period, demand for the subject goods in India increased by 7%. It is also noted that subsequent to HMEL's commencement of operations in FY 2023-24, the domestic industry's sales increased significantly in FY 2023-24 and the POI as compared to FY 2022-23 and the base year. However, despite about 25% increase in Indian capacities, there has been no commensurate increase in the sales of the Indian industry which have remained almost at the same level as the base year.

b) Import volumes from the subject countries

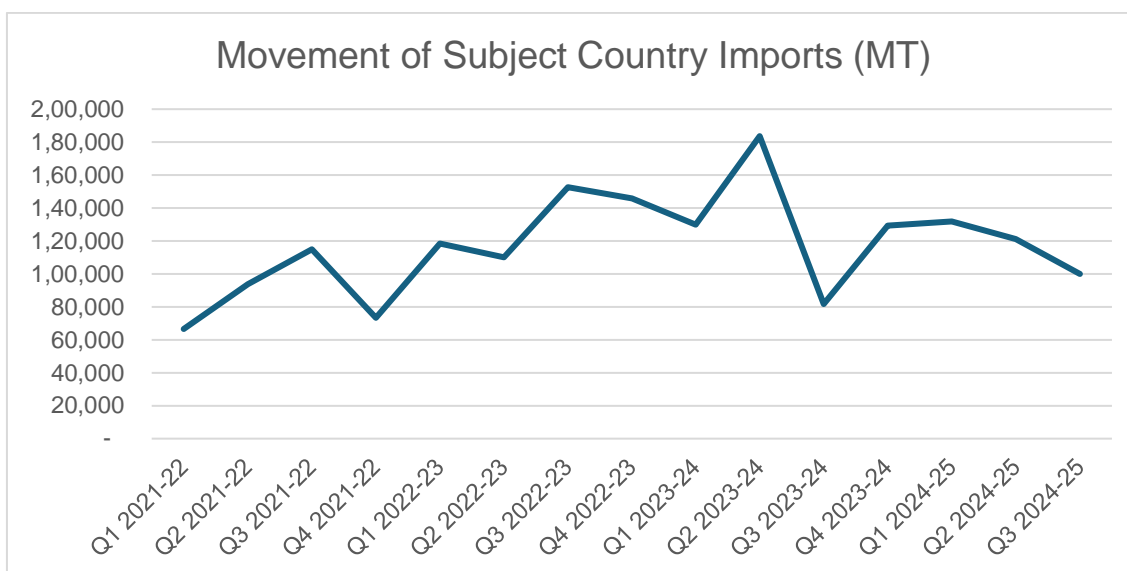
134. As regards the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the volume of dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volume of the subject

goods from the subject countries and the share of the dumped imports during the injury investigation period are as follows:

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Malaysia	MT	6,017	19,092	48,600	26,739
Saudi Arabia	MT	76,614	1,60,171	1,47,038	1,16,418
United Arab Emirates	MT	78,172	93,968	88,160	93,829
Subject Countries	MT	1,60,803	2,73,231	2,83,797	2,36,986
Non-subject Countries	MT	3,70,200	6,07,483	5,88,368	4,79,863
Total Imports	MT	5,31,004	8,80,714	8,72,165	7,16,849
Total demand	MT	33,78,651	32,65,325	35,74,741	36,31,353
Trend	Index	100	97	106	107
Imports in relation to:					
Domestic Industry production	%	***	***	***	***
Range	%	50-60%	80-90%	40-50%	20-30%
Domestic Industry +Supporter's production	%	***	***	***	***
Range	%	10-20%	20-30%	20-30%	10-20%
Total Indian Production	%	7%	15%	13%	11%
Range	%	0-10%	10-20%	10-20%	10-20%
Demand	%	5%	8%	8%	7%
Range		0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
Total Imports	%	32%	36%	36%	35%

135. From the above, the Authority notes that:
- Imports of subject goods have increased in the POI compared to the base year.
 - Imports from the subject countries accounted for 35% of total imports into India during the POI.
 - Compared to FY 2022-23, in FY 2023-24 and the POI, there has been a decline in the volume of subject imports in absolute terms as well as relative to domestic production. It is noted that the decline in volume of imports coincides with the commencement of production by HMEL in FY 2023-24. The overall quantum of subject imports from the subject countries has increased in the POI as compared to the base year.

- d. The Authority further notes that with HMEL's capacity addition in FY 2023-24, total Indian production should have increased in the POI and given the growing demand, should have surpassed the production levels of the base year. However, despite almost 25% increase in installed capacity, the Authority notes that total Indian production in the POI is below the production levels in the base year.



- e. Furthermore, despite the said capacity addition, dumped imports relative to Indian production increased by 50% in the POI.
- f. The Authority notes that imports from the subject countries have declined in the POI compared to FY 2023-24 and FY 2022-23. As can be noted from the chart below, this decline first occurred subsequent to commencement of production by HMEL in Q2 of FY 2023-24. However, thereafter, the imports increased and continued to remain at significantly high levels.
136. Qatofin and RRPC have argued that the Petition does not contain any evidence of increased volumes either in relative or absolute terms. As can be noted from the table above, imports from the subject countries have indeed declined in the POI compared to FY 22-23. This decline in imports coincides with the period of commencement of production and sales by HMEL. However, the absolute volume of such imports in the POI has increased by 47 % compared to the base year.
137. The Authority notes that during the injury period, the production capacity of Indian LLDPE producers underwent a significant change. Between the base year and the POI, Indian capacities increased by 30%, however, despite this increase, total imports of subject goods increased by 35% and imports from the subject countries increased by 47%. Further, consequent to increase in Indian production capacity in FY 2023-24, it is noted that while though the domestic industry was able to increase its domestic sales, such sales were made at prices below cost.
138. The Authority further notes that although the volume of subject imports as a percentage of Indian production and demand declined in the POI as compared to FY 2022-23 and FY 2023-

24, such decline has to be viewed in the context of the substantial increase in Indian capacity and demand. It is noted that the subject imports continued to maintain a market share higher than the base year.

139. More importantly, the subject imports continued to enter the Indian market at prices below the cost of sales of the domestic industry. The continued presence of such low-priced dumped imports has prevented the domestic industry from realising remunerative prices and forced it to sell below-cost levels. Accordingly, the Authority considers that subject imports remained significant, causing injury to the domestic industry.
140. With respect to submissions by OQ Polymers concerning conflated data for Oman contained in the Petition, the Authority clarifies that imports figures contained in the final findings are based on DG Systems data. Additionally, the same has been compared with the import volume reported by OQ Polymers and was found to be in the same range.
141. Other interested parties have claimed that imports have not exhibited a consistently increasing trend during the injury period, and therefore, there is no sustained injurious import pressure. The Authority disagrees with the claims of the other interested parties and notes that neither the Anti-dumping Agreement nor AD Rules, 1995 requires a finding of consistent increase in imports during the entirety of injury period.
142. RRPC has argued that the domestic industry has been the only beneficiary of increased Indian demand. The Authority disagrees with this claim as subject imports from the subject countries have also increased with the growth in Indian demand between the base year and the POI. The growth in the volume of subject imports is evident from the below:

	2022-23	2023-24	POI	POI compared to base year
Subject country imports	70%	4%	-16%	47%

143. As regards the submission that there is no adverse effect of the imports from subject countries as the domestic industry has been able to increase its sales during the POI, the Authority notes that in a capital-intensive industry, cost of keeping a newly operational capacity idle is significantly high. The increase in production and sales therefore does not, by itself, indicate absence of injury. The relevant question is whether such sales were made at remunerative prices. As can be seen in sections below, the domestic industry was forced to sell below cost to compete with dumped imports. Thus, the improvement in volume parameters achieved through deterioration in price and financial parameters do not indicate absence of injury.
144. In this regard, the Authority notes that RRPC has argued that issues relating to price and volume effect are separate and has requested the Authority to consider only the factum of increased sales of domestic industry and the consequent increase in market share. The Authority disagrees with such an isolated approach for assessing injury to domestic industry. Increase in sales / market share cannot be examined independently without accounting for movement in prices as such movements especially in relation to commodity products are always interlinked.

G.3.3 Price effect of the dumped imports

145. In terms of Annexure II (ii) of the AD Rules, 1995 with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) Price undercutting

146. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been worked PCN -wise by comparing the landed price of the subject imports with the selling price of comparable PCNs of the domestic industry during the POI. Price undercutting so determined is provided below:

Price undercutting based on net sales realisation of domestic industry					
PCN	Landed Price	Net Sales Realisation	Price Undercutting	Price Undercutting	Price Undercutting
	(₹ /MT)	(₹ /MT)	(₹ /MT)	(%)	Range
PUC (Wt. Avg.)	94,075	***	***	***	0-5

* Wt. Avg. price based on import volumes

147. Country wise price undercutting is as below:

	Landed Value (Wt. Avg.)	Net Sales Realisation (Wt. Avg.)	Price Undercutting	Price Undercutting	Price Undercutting
	(₹ /MT)	(₹ /MT)	(₹ /MT)	(%)	Range
Malaysia	78,860	***	***	***	20-30
Saudi Arabia	97,871	***	***	***	(10)-0
United Arab Emirates	93,659	***	***	***	0-10
Subject Countries	94,075	***	***	***	0-10

148. It is noted from the above that weighted average price undercutting from the subject countries as a whole is positive during the POI. It is further noted that out of all the subject countries the price undercutting is negative in respect of only one country, that is, Saudi Arabia.
149. Other interested parties have also contended that the Applicant has not provided price undercutting for the entirety of injury period. In this regard, the Authority recalls Para (ii) of Annexure II of AD Rules, 1995, which requires determination of “price undercutting by the

dumped imports”. The Authority further notes that as dumping is assessed in relation to the POI accordingly, price undercutting can also be determined only for the POI and not for the entirety of injury period.

150. ADPCL has argued that the landed value of UAE is highest in the POI and therefore, no injury is attributable to imports from UAE. In this regard, the Authority notes that once it decides to cumulate the volume of dumped imports from the subject countries, examination of trends of individual price undercutting becomes immaterial. The Authority notes that neither ADPCL nor the UAE Embassy have presented any arguments for decumulation of subject imports from UAE.
151. Similarly, Sadara has claimed that its exports to India are at higher prices and has not caused any injury to the domestic industry. The Authority notes that it is not required to examine exporter specific price undercutting.

b) Price suppression/depression

152. For the purpose of analyzing price suppression and depression in the domestic market, the applicants have provided information about (a) cost of sales, (b) domestic selling price as is given in the table below.

Price Suppression/ Price Depression					
Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	125	106	105
Landed Value	₹/MT	1,02,938	1,03,508	89,898	90,394
Trend	Index	100	101	87	88
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	111	90	91

153. It is noted that the cost of sales of the domestic industry increased until 2022-23, and thereafter declined, however, it has remained above the base year in the POI. Further, between the base year and the POI, selling price has declined by 12 index points, and has followed almost the same trend as the landed value of imports. Thus, while cost of sales has increased, due to decline in prices of subject imports from the subject countries, the domestic industry was not able to increase its selling prices in line with the increase in its cost of sales.
154. Based on the information available in the Petition, the Authority notes that the increase in cost of sales in 2022-23 was primarily driven by the increase in raw material costs of the domestic industry. Thereafter, with the decline in raw material prices, the domestic industry’s cost of sales has declined. At the same time, it is noted that while the landed value of imports from the subject countries was above cost of sales of the domestic industry in the base year, since 2022-23 they have been below cost of sales of the domestic industry. Thus, subject imports from the subject countries have exerted continuous price pressure on the domestic industry.

155. Other interested parties have contended that the domestic industry has been able to increase and decrease its selling price in line with its cost of sales and therefore, there is no injury to the domestic industry on account of dumped imports. It has also been argued that the domestic industry has been able to increase its price despite decline in landed value. The Authority notes that the landed value of subject countries has, since FY 2022-23, remained below the cost of sales of the domestic industry. Further, with increase in landed price of dumped imports during the POI compared to 2023-24, the domestic industry has been able to increase its prices.
156. The Authority also notes submissions of All India HDPE/PP Woven Fabric Manufacturers Association wherein it has been stated that domestic industry sets its prices at import price parity, thus indicating that domestic industry is forced to match the landed prices of the subject imports from the subject countries, and thus price movements of the domestic industry are necessarily linked to movement in landed value of the subject goods from the subject countries.

G.3.4 Economic parameters of the domestic industry

157. Annexure II to the AD Rules, 1995 provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

158. The Authority has considered the capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.

Production, Capacity, Capacity Utilisation and Sales – Domestic Industry					
Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	238	307
Production (PUC+ NPUC)	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	108	219	321
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	108	92	105
Production PUC	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	155	503	826

Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	152	511	798

159. From the above, the Authority notes that:

- i. The installed capacity and production of the domestic industry have increased over the injury period. Consequently, domestic sales have also increased over the injury period.
- ii. The domestic industry has explained that the improvement between FY 2023-24 and POI was on account of commencement of production and sales of PUC by HMEL.

160. Other interested parties have submitted that HMEL did not exist in the base year, therefore, the Authority cannot compare injury parameters of the POI with the base year. The Authority notes that the non-existence of a producer in the base year does not prevent the Authority from examining the state of the domestic industry over the injury period. It is noted that both AD Rules, 1995 and WTO Agreement on Anti-dumping require the Authority to examine the state of the domestic industry and not the state of individual domestic producers. However, for the injury examination below, appropriate weight has been given to the state of domestic industry as it existed during the injury investigation period. Thus, the Authority is required to examine all facts that may have a bearing upon the state of the domestic industry including facts related to commencement of production by a domestic producer during the injury period.

b) Market share

161. Market share of the domestic industry and of imports are shown in the table below:

Market share	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Domestic industry Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	152	511	798
Sales of Supporters	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	104	99	106
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	72	76	72
Total Indian Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	101	103	116
Imports from Subject Countries	MT	1,60,803	2,73,231	2,83,797	2,36,986
Trend	Index	100	170	176	147
Imports from Other Countries	MT	3,70,200	6,07,483	5,88,368	4,79,863
Total Imports	MT	5,31,004	8,80,714	8,72,165	7,16,849
Demand in India	MT	33,78,651	32,65,325	35,74,741	36,31,353

Trend	Index	100	97	106	107
Market Share %					
Domestic industry	%	***	***	***	***
Range	%	0-10%	0-10%	10-20%	10-20%
Domestic Industry +Supporter	%	***	***	***	***
Range	%	70-80%	60-70%	50-60%	50-60%
Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Range	%	50-60%	40-50%	30-40%	30-40%
Indian LLDPE Industry	%	***	***	***	***
Range	%	80-90%	70-80%	70-80%	70-80%
Subject Countries	%	5%	8%	8%	7%
Range	%	0-10%	10-20%	10-20%	0-10%
Other country imports	%	11%	19%	16%	13%
Range	%	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%

162. From the above, it is noted that:
- i. The market share of the domestic industry has increased over the injury period including the POI, whereas the market share of Indian Industry has declined in the POI compared to the base year.
 - ii. The market share of the domestic industry remained almost stable until FY 2022-23 but thereafter increased. Subsequently, with the commencement of production and sales by HMEL in FY 2023-24, the market share of the domestic industry and the Indian LLDPE industry increased in FY 2023-24, after first declining in FY 2022-23.
 - iii. The market share of the domestic industry and the Indian LLDPE industry increased in the POI compared to FY 2023-24. The increase in market share is primarily attributable to HMEL. However, the market share of the Indian LLDPE industry between the base year and POI, has registered a decline.
163. Other interested parties have commented that the increase in market share of the domestic industry between the base year and the POI is an indication of no injury to the domestic industry. The Authority notes that subsequent to the commencement of production by HMEL in FY 2023-24, the market share of the domestic industry has indeed increased in the POI. However, as noted above, the increase in market share was primarily on account of HMEL and such increased sales were achieved by making sales below cost. Similarly, market share of the Indian Industry as a whole has also increased in 2023-24 and the POI. However, compared to the base year, the market share of other Indian producers and the Indian LLDPE industry has declined.

164. It is further noted that while there has been a decline in the volume of imports from the subject countries between FY 2023-24 and POI, compared to the base year, the market share of subject imports from the subject countries remains above base year levels in the POI.
165. Other interested parties have submitted that imports from the subject countries enjoy a relatively stable share, and such limited share cannot be considered to adversely affect the domestic industry. The Authority notes that firstly, the share of subject imports in Indian demand is significant and has increased compared to base year. Further, while imports from the subject countries have declined since 2023-24, the landed price at which such imports have entered into India has also declined. The domestic industry has explained that it had to reduce its prices and make below-cost sales in order to compete with such imports and for its market share.

c) Inventories

166. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Inventory					
Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	1,115	1,040

167. It is noted that inventory of the domestic industry has declined in the POI compared to FY 2023-24 and has increased compared to the base year and 2022-23.

d) Profitability, cash profits, and return on capital employed

168. Profitability, return on investment, and cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Profit before Tax	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	(100)	(2509)	(5728)	(4950)
PBIT	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	(431)	(921)	(864)
PBDIT	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	(141)	(433)	(394)
Cash Profit	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	(674)	(1957)	(1645)
ROCE	%	***	***	***	***
Range	%	0-10	(10)-0	(20)-(10)	(20)-(10)

169. From the above, the Authority notes that:
- i. It is noted that the domestic industry has recorded significant losses during the POI. Further, the domestic industry incurred cash losses during the POI and has accumulated negative returns during the POI.
 - ii. The Authority further notes the fact that a new producer, HMEL, has commenced production during the injury period. To examine whether the decline in profitability parameters of the domestic industry was on account of depreciation and interest cost, the Authority compared the costs of HMEL and HPL and found depreciation and interest cost to be in the same range.
 - iii. It is further noted that despite increase in sales quantity, the domestic industry's ROCE continues to remain negative.
170. Other interested parties have argued that domestic industry earned losses during FY 2022-23 on account of increase in cost of sales and therefore injury to the domestic is on account of internal inefficiencies. The Authority notes that increase in cost of sales was on account of increase in raw material cost in FY 2022-23. It is further noted that while the domestic industry captively manufactures ethylene and propylene, it purchases feedstock for ethylene and propylene at market prices. Thus, increase in cost was on account of increase in raw material prices and were not on account of internal inefficiencies.
171. Other interested parties have also argued that despite decline in cost of sales during the POI, the domestic industry continues to incur losses and therefore, losses to domestic industry are not on account of movement in landed price of subject imports from the subject countries. In this regard, the Authority notes that while domestic industry's cost of sales declined in the POI, subject imports from the subject countries continued to enter Indian market at prices below the domestic industry's cost of sales during the POI. In order to maintain its market share, the domestic industry continued to make sales below its cost to compete with the imports from the subject countries.
172. Other interested parties have argued that there exists a significant cost and price difference between HPL and HMEL. It has been claimed that while the cost of sales for the domestic industry declined by 16% in the POI, HPL's cost of sales declined merely by 5%, indicating that cost reduction was primarily driven by HMEL, which is a new producer. The Authority notes that raw material and utilities account for 80-90% of the total cost of the sales of the domestic industry and thus, raw material prices and consumption were the primary driver of the cost. The Authority further compared the raw material consumption norms for the two entities and found them to be similar. The difference in cost of the two entities is primarily on account of differences in levels of fixed cost absorption which was higher in case of HPL, owing to its lower production and capacity utilization, due to the continuous pressure of low-priced dumped imports.
173. In contrast to HPL, HMEL commissioned its plant in 2017 and commenced production during FY 2023-24. HMEL has explained that once it commenced production in FY 2023-24, it was necessary to increase its production and capacity utilization to achieve stabilization. Further, such increase in production was in line with the increasing demand for the subject goods in India.

174. Other interested parties have also argued that domestic industry is facing injury on account of increased depreciation and interest cost in the POI. In this regard, the Authority notes that consequent to increase in the installed capacity, the interest cost and depreciation of the domestic industry have indeed increased over the injury period. It is further noted that both HMEL and HPL follow straight line method for allocation of depreciation and is thus allocated over the useful life of the assets. As regards the submission that the losses to the domestic industry are solely on account of depreciation and interest cost, the Authority notes that the domestic industry is not only in cash losses, but its PBDIT is also significantly negative, as is evident from the below table:

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cash Profit	₹/MT	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Index	100	(674)	(1,957)	(1,645)
Interest Cost	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	141	373	268
PBDIT (Cash Profit before Interest Cost)	₹/MT	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Index	100	(141)	(433)	(394)

175. In view of the above the Authority does not consider than injury to the domestic industry is on account of increased depreciation or interest costs.

e) Employment, productivity and wages

176. The position with regard to employment, wages and productivity of the domestic industry is as follows:

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	No of employees	Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	100	363	363
2	Salary & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	103	765	739
3	Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
	Trend	Index	100	155	503	552
4	Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	155	139	152

177. It is noted that the number of employees and their wages increased in the POI compared to base year.
178. Productivity per day and Productivity per employee have also consistently increased throughout the injury period as a result of increase in the production of the domestic industry.

f) Growth

Particulars	2022-23	2023-24	POI	POI in relation to base year
Production	***	***	***	***
Domestic sales	***	***	***	***
Profit Before Tax	(***)	(***)	(***)	(***)
Cash losses	***	(***)	(***)	(***)
ROCE	(***)	(***)	(***)	(***)

179. Production and sales of the domestic industry have increased in line with the increase in installed capacity and demand for the subject goods. It is noted that due to the price pressure exerted by imports from the subject countries, profitability parameters have significantly declined. Moreover, while production and sales have increased, the growth in sales was lower than growth in production.

g) Impact on the ability to raise capital investment

180. The domestic industry has submitted that it has not been able to earn adequate return on profits and therefore, its ability to raise capital investments has been impaired significantly. It is noted that HMEL commissioned its plant in 2017 and finally commenced production in FY 2023-24. However, despite achieving almost 80-90% capacity utilization, HMEL has been earning negative returns and is in cash losses. The domestic industry has also asserted that despite an increasing demand on account of dumped imports no new investments are being made as the domestic producers have not been able to earn return on the investments already made.

h) The magnitude of dumping

181. There is significant dumping of the subject goods from the subject countries, which has impacted the conditions of fair competition in the market.
182. In view of the foregoing, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

G.3.4 Overall assessment of injury

183. The examination of imports of the subject product and the performance of the domestic industry shows the following:
- Imports of subject goods from the subject countries have remained at consistently high levels throughout the injury period. While subject imports from the subject countries have declined after increasing in FY 2022-23, the volume of such imports in the POI remains above the base year level.

- ii. The landed value of subject imports from the subject countries declined in FY 2023-24. Although, there was an improvement in landed price during the POI, imports from the subject countries continued to enter into the Indian market at prices below the cost of sales of the domestic industry.
- iii. Production and domestic sales of the domestic industry have increased in POI compared to the remainder of the injury period. However, the increase in sales was achieved by making sales below cost.
- iv. Inventories of the domestic industry have increased in the POI compared to the base year.
- v. The financial performance of the domestic industry has deteriorated significantly. The domestic industry has been earning returns and has been earning cash losses during the POI.

H. Non-attribution analysis and causal link

184. The Authority examined whether other factors listed under the AD Rules, 1995, could have caused injury to the domestic industry. The Authority has examined known factors other than the dumped imports and ascertained whether such factors could have been a cause of injury to the domestic industry, so that the injury caused by other factors, if any, is not attributable to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry.

a) Volume and value of imports from third countries

185. It is noted that imports from non-subject countries constitute around 65 % of total imports in India. Such imports, except from imports from Oman, Qatar and Kuwait, are entering into India at 10-20 % higher landed value than the cost of sales and non-injurious price of the domestic industry. Further, there is no evidence that such goods are being dumped into India. Therefore, the injury caused cannot be attributed to the third countries.

186. The Authority further notes that imports from Qatar are entering into India at prices comparable to dumped imports during the POI. However, these imports are not dumped into India. Further, such imports constitute less than 3% of total imports into India and around 0.5% of the Indian demand.

187. Further, subject imports from Kuwait and Oman were found to be dumped, however, such imports account for less than 3% of total imports into India.

b) Contraction in demand

188. The Authority notes that the demand for the subject goods has, after marginally declining in FY 2022-23, consistently increased in the remainder of the injury investigation period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to a contraction in demand.

c) Pattern of consumption

189. It is noted that there has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

190. The Authority notes that there is no evidence of conditions of competition or trade restrictive practices that could have been responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e) Developments in technology

191. The Authority notes that there has been no change in technology for the production of the subject goods that could have caused injury to the domestic industry.

f) Export performance of the domestic industry

192. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

g) Performance of other products

193. The Authority has considered the data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the domestic industry.
194. Apart from the above-mentioned factors other interested parties have requested for examination of the following known factors that could have caused injury to the domestic industry:

a. Injury to the domestic industry is due to inherent cost disadvantage due to usage of naptha as raw material for ethylene

195. RRPC has claimed that the domestic industry has been facing injury on account of using Naptha for manufacturing of ethylene, whereas Saudi producers use Ethane for manufacturing of raw material. The Authority notes that under causal link analysis, the Authority is not required to address differences in the structure of the domestic industry and exporters from the subject countries. In this regard, the Authority recalls observations of the Panel in *EU – Biodiesel (Argentina)*:

“7.522. Argentina primarily takes issue with the EU authorities' conclusion that the structure of the EU industry was not a cause of injury. The two factors, namely lack of vertical integration and lack of access to raw materials, identified by Argentina, essentially are inherent features of the EU domestic industry that, according to Argentina, render it less competitive than the Argentine producers. In our view, however, this line of argument is premised on a misreading of Article 3 of the Anti-Dumping Agreement and its various paragraphs, including Article 3.5. The concept of injury envisaged by Article 3 relates to negative developments in the state of the domestic industry. Article 3 is not intended to

address differences in the structure of the domestic industry as compared to that of the exporting Member. Rather, it is clear from the text of Article 3.5 and from its indicative list of such "other factors" – which all pertain to developments in the situation of the domestic industry – that the authority is not required to conduct a non-attribution analysis with respect to features that are inherent to the domestic industry and have remained unchanged during the period considered by the investigating authority for purposes of its injury analysis."

196. The Authority notes that the fact that both constituents of the domestic industry manufacture ethylene from the same feedstock since the beginning of base year (in case of HMEL since the commencement of production). The feedstock structure of the domestic industry was constant during the injury period. A factor that is static in nature cannot explain the deterioration in profitability during the POI. Accordingly, no non-attribution analysis is required to be carried out for this factor.

b. Injury is due to weakened global demand

197. Other interested parties have contended that injury to the domestic industry is on account of weakened global demand and that this fact has been mentioned in the HPL's Annual Report itself. In this regard, the Authority notes that the demand in India has consistently increased over the injury period. Between the base year and the POI, demand has increased by 7%. Further, Indian demand has registered positive year on year growth. While none of the other interested parties have provided any data concerning global consumption, the Authority notes that it is examining domestic industry's performance in Indian market, which has witnessed a steady growth in demand. Accordingly, it cannot be considered that injury is on account of weakened global demand.

c. Injury is due to other domestic producers and on account of entry of HMEL into Indian market

198. Other interested parties have contended that injury to the domestic industry is on account inter se competition between domestic producers. It has been alleged that HMEL, being a new market entrant, has resorted to aggressive pricing to compete with the established players. In this regard, the Authority notes that competition amongst different players in a market is natural consequence of market forces and is therefore, normal market condition. The Authority further notes that from the submissions of the user industry that domestic producers follow import price parity. However, to examine whether HMEL had adversely impacted share of other Indian producers, the Authority has compared the sales of the three domestic producers:

Sales (MT)	2021-22	2022-23	2023-24	POI
RIL	***	***	***	***
Index	100	104	99	106
HPL	***	***	***	***
Index	100	152	90	97
HMEL	-	-	***	***

Index	-	-	100	167
-------	---	---	-----	-----

199. Based on the above, the Authority notes that if HMEL was resorting to aggressive pricing strategy, sales of other domestic producers would not have increased. However, as can be seen from the data above, both RIL and HPL were able to increase their domestic sales during the POI. Accordingly, it cannot be said that injury is due to pricing strategy by HMEL.

d. HMEL is a new entrant and was in the stage of operationalization during the injury period

200. Other interested parties have claimed that HMEL was in the stage of operationalization during the injury period and therefore, injury if any, is not on account of dumped imports. The Authority notes that HMEL achieved a capacity utilization of 80-90% during the POI. Further, the Authority has compared consumption norms of HMEL and HPL and found them to be comparable. As noted above, if the injury to the domestic industry was on account of new investment, such injury, contrary to the present facts, would not have resulted in cash losses and negative PBDIT. Accordingly, it cannot be considered that injury to HMEL is on account of its recent commencement of production.
201. Other interested parties have also argued that losses to HMEL in its first year of production were on account of initial inefficiencies which have reduced in the POI despite dumping. The Authority notes that HMEL commenced production of PUC in FY 2023-24. Raw material and utility norms, even for the initial year of production, have been compared with that of the other domestic producer and were found to be comparable. Further, conversion cost of HMEL was also found comparable to the participating foreign producers as well.

e. Injury is due to other subject countries

202. Participating exporters from Kuwait, Oman, Qatar, and UAE have contended that injury to the domestic industry is on account of other subject countries and not due to their respective subject countries. The Authority notes that pursuant to Para (ii) of Annexure II to AD Rules, 1995 it has cumulated imports from the subject countries. Other interested parties have not presented any arguments concerning de-cumulation of imports of individual subject countries. Accordingly, the Authority has not considered such arguments.

H.1 Factors establishing causal link

203. While other known factors listed under the AD Rules, 1995, have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by dumped imports.
- i. Subject imports from the subject countries have increased in absolute terms and have remained significant in relative terms in the POI compared to the base year. Notably, imports have continued to be at increased levels despite significant increase in Indian production capacity.
 - ii. There is dumping of the subject goods from the subject countries.
 - iii. Price undercutting from the subject countries as a whole is positive.

- iv. Landed price of the subject goods is significantly below the cost of sales of the domestic industry and thus, preventing the domestic industry from increasing its prices to recover costs and earn reasonable returns.
 - v. The market share of the Indian LLDPE industry has declined in the POI compared to the base year, whereas market share of subject countries has increased.
 - vi. Despite reduction in costs and increase in selling prices, the domestic industry continues to accumulate negative returns and has incurred cash losses during the POI.
204. The Authority, in view of the aforementioned, concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods from the subject countries and injury to the domestic industry.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

205. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the AD Rules, 1995 read with Annexure III to AD Rules, 1995, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been considered for comparing the landed price from the individual subject countries for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (that is, average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pretax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the AD Rules, 1995.
206. ADPCL and Sadara have contended that given HMEL's commencement of production in August 2023, Annexure III simpliciter cannot be applied to it for computation of its injury margin and have requested for optimization of HMEL's data with the projections in its project report. They have further requested that only best utilization of established producer, HPL, ought to be considered so that HMEL's non-injurious price is not overstated. In this regard, the Authority notes that both HMEL and HPL use same raw materials and utilities for production of the PUC. The Authority has further compared the raw material consumption norms for both the domestic producers and found such consumption to be in the same range.
207. Insofar as optimization of HMEL's data is concerned, the Authority has considered quarterly data for POI for optimization of raw material and utilities for the purpose of Annexure-III and determination of non-injurious price for HMEL. The Authority further notes that consumption norms for both HPL and HMEL are in the same range and therefore, there is no need for consideration of HPL's data for computation of HMEL's NIP. As such, there is no legal or practical basis for the Authority to accept Sadara and ADPCL's submissions.
208. In accordance with the above, related producers and exporters have been regarded as one single entity and attributed one single injury margin which was calculated on the basis of the weighted average of the injury margins of the cooperating related producers and exporters.
209. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below.

Injury Margin Table

Producer	PCN	NIP (\$/MT)	Landed Price (\$/MT)	Injury Margin (\$/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range)
Saudi Arabia						
Al-Jubail Petrochemical Company ("Kemya")	NMG	***	***	***	***	10-20
Arabian Petrochemical Company ("Petrokemya")	NMG	***	***	***	***	20-30
Eastern Petrochemical Company ("Sharq")	NMG	***	***	***	***	20-30
Jubail United Petrochemical Company ("United")	NMG	***	***	***	***	20-30
Rabigh Refinery & Petrochemical Company	NMG	***	***	***	***	20-30
Sadara Chemical Company	NMG	***	***	***	***	0-10
Yanbu National Petrochemical Company ("Yansab")	NMG	***	***	***	***	20-30
Saudi Aramco - SABIC Group	NMG	***	***	***	***	10-20
Others	All	***	***	***	***	20-30
UAE						
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd	NMG	***	***	***	***	10-20
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd	MPG	***	***	***	***	20-30
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd	Wt. Avg.	***	***	***	***	10-20
Others	All	***	***	***	***	30-40
Malaysia						
All	All	***	***	***	***	30-40

J. DUTY IMPACT ASSESSMENT**Public interest and Domestic Industry Interest****J.1 Views of other interested parties**

210. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard:

- i. The interested parties submitted that LLDPE is a critical raw material for several downstream sectors, including packaging, films, moulded articles and other plastic processing applications.
- ii. It was argued that imposition of anti-dumping duty would increase the input cost of downstream user industries and may affect the cost competitiveness of Indian users.
- iii. Certain interested parties relied on the demand-supply position in India and submitted that domestic production is insufficient to meet total consumption requirements. They contended that any duty on imports may aggravate supply constraints.
- iv. It was further submitted that the demand for LLDPE in India is expected to increase and, therefore, imports remain necessary to bridge the domestic supply gap.
- v. The interested parties also referred to the temporary exemption of basic customs duty on LLDPE imports and submitted that the Government's policy objective was to ensure continued availability of petrochemical inputs, reduce cost pressure on downstream industries and maintain supply stability.
- vi. It was argued that prevailing geopolitical developments and disruption in global supply chains should be considered while examining whether anti-dumping duty is commercially and policy-wise justified.
- vii. SRTPL submitted that it is a research and technology centre and that any imposition of anti-dumping duty may affect its research and development activities.
- viii. The interested parties also submitted that the domestic industry's claim that the duty impact would be less than 1% should be verified by the Authority, since the calculation had not been disclosed to the exporters.
- ix. Indian processors are already subjected to systematically higher input costs, with foreign suppliers offering material to India at prices that are USD 150-200 per metric ton higher than those offered to markets such as China. This differential is not market-driven but is a consequence of the perceived risk of anti-dumping actions in India.
- x. The domestic industry supplies material at import parity pricing, inclusive of customs duty (7.5%) and freight. This effectively ensures that domestic producers appropriate the entire tariff protection, while downstream users continue to procure raw materials at inflated prices relative to global benchmarks.
- xi. The imposition of duty will artificially elevate domestic prices, eliminate competitive discipline, and confer undue pricing power on the domestic industry at the cost of downstream MSMEs.
- xii. the increase in domestic input costs will render Indian processors structurally uncompetitive vis-à-vis countries such as Vietnam and other ASEAN economies, which benefit from preferential trade access under Free Trade Agreements and have access to raw materials at globally competitive prices.
- xiii. If raw material imports are restricted, finished goods imports will increase, leading to a direct displacement of domestic production. The downstream industry, which adds value and generates large-scale employment, will suffer.

J.2 Views of the domestic industry

211. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:
 - i. The domestic industry submitted that none of the interested parties had provided any quantified end-user impact assessment.

- ii. It was submitted that, in contrast, the domestic industry had placed detailed calculations on record establishing that the impact of anti-dumping duty on end users would be less than 1%.
- iii. The domestic industry further submitted that anti-dumping duty is a corrective trade remedy and does not restrict imports. It only ensures that imports enter India at fair and non-injurious prices.
- iv. The domestic industry submitted that the temporary removal of customs duty on LLDPE was only a temporary measure linked to the Middle East situation and cannot be treated as a reason to deny anti-dumping protection.
- v. It was also argued that anti-dumping duties are prospective in nature and that the geopolitical situation had substantially stabilised.
- vi. The domestic industry further submitted that removal of customs duty had reduced the limited protection available to the domestic industry against dumped imports and, therefore, strengthened the need for appropriate anti-dumping duty.
- vii. It was also submitted that exporters from the subject countries were holding high inventories due to sudden disruption in shipping routes and that, once the situation normalised, such inventories could be aggressively dumped into India, aggravating injury to domestic producers.

J.3 Examination by the Authority

212. The Authority issued initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. Further, the Authority also requested the users/ consumers to provide relevant information concerning present investigation including the likely impact of imposition of anti-dumping duties on end users, substitutability of PUC, price-sensitivity of demand, long term contracts etc.
213. The Authority notes that the objective of imposing trade remedial measures is not to restrict imports but to remove the injury caused to the domestic industry from unfair trade practices and to establish fair competition in the Indian market. The Authority is indeed aware that the impact of such duties is not limited to only the domestic producers of the PUC but also affects the users and consumers of the PUC. While the imposition of duties may introduce competition concerns domestically but it can also concurrently stimulate the emergence of new producers or further investments within the country.
214. The Authority notes that two user industries, namely SRTPL and EMC IPL, have participated in the present investigation. While SRTPL has filed an Economic Interest Questionnaire, EMC IPL has not filed the Economic Interest Questionnaire and admittedly, it is not involved in the production or use of PUC. Further, SRTPL, admittedly, a research center, has not filed any computation of impact of anti-dumping duties. Apart from the above users, All India HDPE/PP Woven Fabric Manufacturers Association, a user industry association has also participated in the present investigation. However, it has not provided any calculation concerning impact of the anti-dumping duties on the subject goods. On the other hand, the domestic industry has provided end-user impact assessment, which shows that the impact of anti-dumping duties, if recommended, would be less than 1%.
215. The Authority notes that anti-dumping duty is a remedial trade measure and not a restriction on imports. Its purpose is limited to neutralising the unfair pricing advantage arising from dumped imports and restoring fair competition in the Indian market. It does not prohibit imports from the subject countries, nor does it prevent users from sourcing LLDPE from global suppliers.
216. The Authority further notes that, even after imposition of duty, the Indian market would continue to be served by domestic producers, duty-paid imports from the subject countries and imports from non-subject countries. Therefore, the apprehension that anti-dumping duty would result in non-availability of LLDPE or supply disruption is not supported.
217. The Authority observes that the submissions regarding adverse impact on users are general in nature. No user has placed verifiable evidence showing that the determined duty would render downstream operations unviable, materially increase production cost, or significantly affect consumer prices.
218. The Authority also notes that LLDPE is only one of several inputs used in downstream products. The final price of such products depends on multiple factors, including conversion cost, labour, power, additives, freight, distribution cost, processing technology and margins. Therefore, any increase in LLDPE cannot be mechanically equated with an equivalent increase in the price of finished products.
219. The Authority has examined the calculations provided by the domestic industry. The Authority notes that the products used in packaging, moulding are generally a combination of different types of LLDPE, and other polyethylene such as LDPE. The Authority has assessed impact on different products as below. The same has been illustrated below:

Impact of Anti-Dumping Duty (ADD) on LLDPE Users & Consumers in India

Illustrative downstream impact analysis at ADD = USD 100/MT



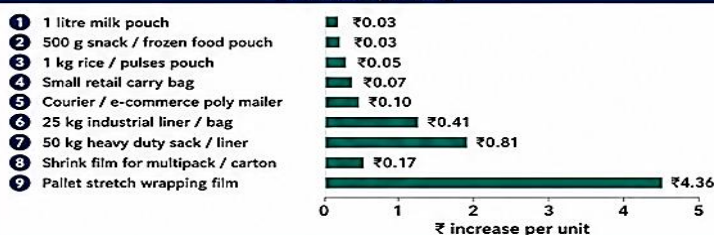
₹ USD 100/MT ADD = approx. ₹9.68 per kg of LLDPE



Assumptions: Exchange rate: ₹96.8441/USD

#	Product	₹ Indicative Product Value	Article Weight	LLDPE Content	₹ Impact at USD 100/MT ADD (₹ increase per unit & % Impact)	Impact Status
1	1 litre milk pouch	₹60	5 g	60%	₹0.03 per pouch (0.05%)	Low Impact
2	1 kg rice / pulses pouch	₹60	8 g	60%	₹0.05 per pouch (0.08%)	Low Impact
3	500 g snack / frozen food pouch	₹100	6 g	50%	₹0.03 per pouch (0.08%)	Low Impact
4	Small retail carry bag	Goods value ₹300	10 g	70%	₹0.07 per bag (0.02%)	Low Impact
5	Courier / e-commerce poly mailer	Shipment value ₹500	15 g	70%	₹0.10 per mailer (0.02%)	Low Impact
6	25 kg industrial liner / bag	Packed goods value ₹1,000	60 g	70%	₹0.41 per bag (0.04%)	Low Impact
7	50 kg heavy duty sack / liner	Packed goods value ₹1,125	120 g	70%	₹0.81 per bag (0.07%)	Low Impact
8	Shrink film for multipack / carton	Packed goods value ₹500	20 g	90%	₹0.17 per pack (0.03%)	Low Impact
9	Pallet stretch wrapping film	Goods value ₹50,000	500 g	90%	₹4.36 per pallet (0.009%)	Low Impact

Absolute impact per unit at USD 100/MT ADD (₹ increase per unit)



CONSUMER PACKAGING
mostly **0.02%** to **0.08%**
of product value



INDUSTRIAL PACKAGING
around **0.03%** to **0.07%**
of packed product value



For most consumer and industrial applications, the impact of ADD at USD 100/MT is only **below 0.1%** of product value.



220. As can be seen from the above, the impact of duties would be less than 0.5% on the end consumer product.
221. All Indian HDPE Association has submitted that exporters from subject countries charge prices USD 150-200 more than the prices at which such goods are exported to China due to perceived risk of anti-dumping actions in India. The Authority notes that prices in China could be different *vis - a - vis* Indian market on account of multitude of factors such as

volume of orders, demand, commercial terms etc. Moreover, there is no reason for such differential pricing, if exporters are undertaking fair trade in both markets.

222. With regards to increase in prices in Indian market subsequent to imposition of anti-dumping duties, the Authority notes that a significant quantity of imports will continue to come through non-subject countries. During the POI, almost 65% of subject imports were imported from non-subject countries. Further, the Indian LLDPE market is characterized by presence of several LLDPE manufacturers. Thus, internal competition amongst domestic producers as well as competition from non-subject countries would ensure that subject goods would continue to be available at competitive prices.
223. Further, as almost 62% of subject imports will continue to be imported from non-subject countries, the Authority notes that consumers will continue to have multiple sources for procuring subject goods other than domestically produced goods.
224. The Authority also takes note of the exemption from basic customs duties granted by the Central Government on the imports of the PUC, in light of the recent West Asia Crisis. It is noted that the said exemption is temporary in nature and has no bearing upon the factum of dumping and injury occurring in the POI.
225. The Authority also recognises that a viable domestic LLDPE industry is important for long-term supply security. Continued dumping may give temporary price benefits to certain users, but it would weaken domestic production, reduce investment, impair capacity utilization and increase dependence on foreign suppliers.
226. The Authority therefore considers that public interest must be assessed in a broader manner, including fair competition, domestic manufacturing capability, employment, investment, supply stability and long-term resilience of the Indian value chain.
227. Accordingly, the Authority concludes that the alleged adverse impact on users and consumers is unsubstantiated and overstated. The imposition of anti-dumping duty would not restrict imports, create scarcity or impose a disproportionate burden on users. It would only ensure that imports enter India at fair prices and do not cause injury to the domestic industry.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS

K.1 View of the other interested parties

228. The following submissions have been made by the other interested parties:

General

- i. India has initiated a large number of trade-remedy investigations against Saudi Arabian exports, particularly chemicals and petrochemicals. It stated that repeated investigations adversely affect bilateral trade and should not be used for protectionist purposes.

Standing

- ii. The Authority must independently assess whether HPL and HMEL constitute a major proportion of total domestic production after including all relevant domestic producers of the like article.
- iii. the SEZ Act does not prohibit domestic sales by SEZ units. The legal consequence of such sales is that they are subject to applicable customs duties. It does not follow that the producer becomes irrelevant for anti-dumping standing.
- iv. OPAL was producing LLDPE in India and supplying substantial quantities in the Indian market. Excluding such a producer from total domestic production gives an incomplete picture of the Indian industry.
- v. RIL's data was fully disclosed and in the absence of verifiable disclosure RRPC cannot comment on eligibility of domestic industry.

Low-volume imports, de minimis margins and termination

- vi. The volume of imports from Kuwait represents 2.44% of total imports, while imports from Oman represented 2.90%. As individual share for each of these countries is below 3% and collectively account for less than 7% of total volume of imports, the Authority must terminate investigation against Kuwait and Oman on the ground of *de minimis* import volumes.

Producer/exporter specific issues

- vii. Kemya disputed the selling and distribution expense adjustment used while determining its ex-factory normal value and export price. It submitted that the expense was not incurred by Kemya itself. It further argued that, if such an adjustment is retained, the same treatment must be followed consistently in the cost and ordinary-course-of-trade test so that normal value and export price are compared at the same level of trade.
- viii. Sadara opposed determination of a common rate for all Saudi Aramco-SABIC producers. It submitted that common shareholding does not by itself establish operational control over Sadara's pricing and commercial decisions. According to Sadara, its exports are governed by binding marketing arrangements and cannot be redirected through another producer to obtain a lower rate.
- ix. SABIC, Sharq and SPDC disputed the observations concerning the relationship between SPDC, Mitsubishi and Sharq. They submitted that Mitsubishi does not exercise the control required under the applicable legal test and that the later disclosures made by

- SPDC clarified the relationship. They further argued that any deficiency was limited to exports routed through Mitsubishi and did not affect Sharq's domestic sales or its other export channels. They therefore requested that facts available, if applied, be confined only to the specific sales channel for which information was considered incomplete.
- x. RRPC submitted that the Sumitomo sales channel had been disclosed, represented only part of its exports and was further explained during verification. It requested that any use of facts available be confined to that channel. It also sought the weighted-average rate applicable to the cooperating producers of the Saudi Aramco-SABIC Group.
 - xi. Dow and SABIC marketing entities function as Sadara's extended sales arms and perform the role of an internal sales department. Therefore, under paragraphs 12.24 and 12.32 of the DGTR Manual, the indirect selling, general and administrative expenses and profit of these related entities should not be deducted while determining the net export price.
 - xii. Alternatively the marketing fee reported by Sadara already represents the remuneration retained by the related marketing entities for performing sales and marketing functions. The deduction of both the marketing fee and the related entities' indirect expenses and profit would amount to double deduction of the same economic element and artificially lowers the net export price.
 - xiii. DCIPL has claimed only credit cost in the prescribed appendix. It therefore requested correction of the disclosure statement, which had also referred to deductions for freight, insurance, inland transportation and port-related expenses.

Determination of non-injurious price and injury margin

- xiv. The Authority should consider recoveries from by-products, scrap and joint products while determining the cost of production and non-injurious price under Annexure III.

Volume and price effects of imports

- xv. Subject imports from Saudi Arabia have not caused adverse volume effect. Subject imports from Saudi Arabia have declined by 21% compared with FY 2023-24 and by 27% compared with FY 2022-23, while the domestic industry's production and sales has increased. The increase in domestic capacity and output showed that imports had not displaced domestic production or prevented market expansion.
- xvi. As price undercutting is negative for Saudi Arabia imports from Saudi Arabia could not have caused adverse price effects from the subject countries.

Economic parameters, material injury and causal link

- xvii. The domestic industry's parameters have improved during the injury period, including capacity, production, capacity utilisation, domestic sales, market share, employment, wages and productivity. The Authority's injury findings is based mainly on profitability indicators without a sufficient explanation of why those indicators outweighed the broad improvement in output, sales and market presence.
- xviii. The alleged financial injury could have resulted from factors other than dumped imports, including HMEL's commissioning and ramp-up phase, depreciation and interest costs, feedstock and production-cost differences, competition among Indian producers, operational disruptions, global energy and feedstock prices and weakened global polymer demand.

- xix. The domestic industry has not provided details of export sales which prevents the interested parties from examining whether injury is on account of export sales.

Public interest, user impact and duration of duty

- xx. India has a demand-supply gap in LLDPE and that downstream processors depend on imports for regular and specialised grades. They referred to the temporary exemption from basic customs duty, changes in the quality-control framework and supply disruptions in West Asia. According to them, anti-dumping duty would increase raw-material costs, reduce the competitiveness of downstream processors and encourage imports of finished goods. Certain parties requested that, if duty is imposed, its duration should be limited to two years

K.2 Views of the domestic industry

229. The following submissions have been made by the domestic industry:

Scope of PUC and PCN Reporting

- i. The interested parties have not been able to substantiate their exclusion requests. Accordingly, the domestic industry requests the Authority to confirm the scope of the PUC as defined in the disclosure statement.
- ii. The Authority has not clarified whether the participating exporters have correctly identified product control number in their questionnaire response and whether the same has been verified and examined by the Authority.

Scope of domestic industry

- iii. The domestic industry requests the Authority to confirm HPL and HMEL's status as an eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995.

Dumping Margin Determination

- iv. The dumping margins for all participating exporters from the subject countries, except Qatar, is positive and significant.
- v. The Authority should verify whether Qatofin has reported all adjustments in their export price to India and selling price in their domestic market correctly. the domestic industry requests the Authority to re-examine Qatofin's dumping margin.
- vi. Sumitomo holds both Class A and Class B shares in RRPC, reflecting its strategic involvement and influence as a founding shareholder.
- vii. Sumitomo Chemical and its associated companies purchased, for the three-month period ended March 31, 2026, goods equivalent to Saudi Riyals 11,455 million, while sales of petrochemical products to them were of Saudi Riyals 2,183 million, indicating active trading relationships and export activity.
- viii. Mitsubishi Corporation's FY2025 financial results explicitly lists SPDC Ltd. (Japan) as one of its major subsidiaries and related parties. This confirms SPDC as an affiliated entity in Mitsubishi's own consolidated reporting.
- ix. The Authority has rightly rejected the questionnaire response for Sharq and RRPC. It is further submitted that the two producers are part of the Saudi Aramco-SABIC Group and

therefore, the Authority should have rejected the response of Saudi Aramco-SABIC Group in entirety.

- x. The Authority has not examined whether goods supplied by PRefChem through SAPPL to India are goods actually originating in Malaysia or goods originating in Saudi Arabia manufactured by PRefChem's related producers in Saudi Arabia which were subsequently traded through PRefChem and SAPPL.
- xi. Neither SAPPL nor SABIC mention in their questionnaire that they have supplied PUC originating in Malaysia to India. In view of the above, the domestic industry reiterates its request for rejection of the questionnaire response for Saudi Aramco-SABIC Group's entire sales channel.
- xii. Sadara manufactures and exports both NMG and MPG PCNs of LLDPE. Sadara supplies metallocene based grades under the names of Dowlex 5400 G and classifies them as high performance LLDPE. Accordingly, the Authority cannot only consider NMG selling prices of other producers in Saudi Arabia for determination of Sadara's normal value as such producers are not selling MPG PCN grades of LLDPE.
- xiii. If Sadara has not reported MPG PCNs in its questionnaire response the Authority in view of the gross misreporting of PCNs by Sadara must reject its response in entirety.

Material injury and causal link

- xiv. The Authority's conclusions clearly confirm that the Indian LLDPE industry is suffering from material injury on account of dumped imports from the subject countries.
- xv. The domestic industry submitted that dumped imports increased in absolute terms compared with the base year, entered the Indian market below its cost of sales and caused price undercutting, price suppression and price depression. It explained that the increase in production and sales resulted from capacity addition and was achieved by selling below cost. At the same time, the domestic industry continued to suffer losses, cash losses and negative returns.
- xvi. The allowed NIP of the domestic industry is significantly lower than the NIP claimed by the domestic industry.

Public interest and effect on downstream users

- xvii. The Authority has rightly confirmed that the impact of anti-dumping duties on the ultimate consumer would be less than 0.1%.
- xviii. Processors largely build packaging material prices based on conversion cost basis, where raw material price movement either side would have no impact on margin and the same is completely passed down to the ultimate consumer.

K.3 Examination by the Authority

230. The Authority has examined the post-disclosure submissions filed by the domestic industry and the other interested parties. The Authority notes that several submissions made at the post-disclosure stage are reiterations of submissions already made during the investigation and already examined in the Disclosure Statement. The Authority has nevertheless considered all relevant comments to the extent they are supported by evidence on record and are material to the final determination.

Producer/exporter-specific issues

231. Kemya has argued that adjustments have been incorrectly applied in determining its ex-factory domestic and export price. In this regard, the Authority notes that as per the methodology explained in para 68 of these final findings, expenses borne by the trader have been adjusted against the trader's export price/ normal value to arrive at the ex-factory value at the level of each trader and subsequently, expenses borne by the producer has been adjusted. Further, Kemya, in contrast to its related producers, did not report any selling or distribution or any other expense in its appendices. Kemya in its comments to disclosure statement has not explained why domestic/ export transactions were reported on FOB terms when Kemya did not bear any selling and distribution expense.
232. Kemya has also claimed that the Authority has added selling and distribution expenses to its normal value, whereas it has reduced the same from its export price. Kemya has also submitted that if the Authority considers that such adjustment by way of deduction to normal value and export price is warranted, the adjustment must be made to both export price and normal value. The Authority clarifies that it has followed the same methodology as suggested by Kemya and has subtracted the selling and distribution expense from both Kemya's normal value and export price and thus has compared both the export price and normal value at the same level of trade.
233. Kemya's related trader EMCAP has stated that Kemya's plant is located near port, therefore, it does not bear selling & distribution expenses. It is noted that the Authority had examined the geographical location of Kemya and its related producers and found them to be located in the same region. Further, the location of factory near port does not mean that goods would travel without transport charges. While EMCAP states that Kemya does not bear such charges on account of its location, it does not explain who bears such expenses. Accordingly, the Authority has not considered the submissions made by EMCAP.
234. Sharq and SPDC have argued that Mitsubishi Corporation through which they have exported the goods to India is not their related party and accordingly, the Authority should not have determined their export price and normal value in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995. It has been further stated that even though SPDC did not inform the Authority in its questionnaire appendices the nature of relationship between SPDC and Mitsubishi Corporation, the Authority had other evidence on record to determine the relationship between SPDC and Mitsubishi Corporation. In this regard, the Authority notes that if SPDC considered Mitsubishi Corporation as an unrelated party, it could have disclosed the same as an unrelated party in its questionnaire appendices. However, SPDC on two separate occasions deliberately deleted the columns pertaining to relationship between supplier (SPDC) and customer (Mitsubishi). The explanation provided by SPDC in its mail dated 06.11.2025 is only a post-facto explanation and is *prima facie* incorrect and contrary to SPDC's Annual Report which clearly identifies Mitsubishi Corporation as a related party. Moreover, the Authority in its previous investigation concerning imports of mono ethylene glycol from Saudi Arabia (final findings dated 23.09.2025) whose POI has an overlapping period with the POI of the present investigation, in which Mitsubishi Corporation had disclosed itself be a related party of SPDC in its questionnaire response. This fact was disclosed by the Authority and was not disputed either at the stage of disclosure statement or subsequent to final findings by SPDC. It is a settled position in law that admitted facts need not be proved. Further, as Mitsubishi is a related party to SPDC and holds substantial shareholding in SPDC, the

Authority considers that Mitsubishi through SPDC is in a position to exercise influence over Sharq and is accordingly, related party of Sharq.

235. RRPC has submitted that its response should not have been rejected as in its verification documents it has provided information pertaining to resale price and profitability of Sumitomo. In this regard, the Authority notes that the investigation was initiated on 30.06.2025 and all interested parties were required to file questionnaire response with the Authority by 06.09.2025. The Authority further upon request of the interested parties granted time till 12.09.2025 to file the questionnaire response. The Authority notes that Sumitomo, despite being a related exporter for the subject goods, did not file questionnaire response at this stage. After *prima facie* scrutiny of questionnaire response, the Authority issued supplementary questionnaire through mail dated 15.10.2025 to all participating exporters and requested them to complete their response. RRPC in its supplementary response dated 27.10.2025 also did not provide any data on behalf of Sumitomo nor did Sumitomo file any response on its own. Subsequently, during the desk verification of the producer-exporters data, the Authority issued verification questionnaire to RRPC requesting it to provide evidence for the claims made in its questionnaire response and appendices. As part of the verification response, RRPC submitted data allegedly pertaining to resale prices of Sumitomo and profitability of Sumitomo and also provided back up working of the same. In this regard, the Authority notes that the purpose of the verification process is to assess the accuracy and correctness of the data already submitted on record by duly verifying the same with back up documents based on the participating companies' financial records and not to collect new facts. The alleged resale and profitability information was provided by RRPC on 10.04.2026 after almost 10 months of initiation. The Authority provided both Sumitomo & RRPC several opportunities to complete their response. However, Sumitomo neither participated nor provided information as per the applicable trade notice for related exporters. The Authority could not accept such information at such a belated stage. Without prejudice to the above, the Authority notes that information provided for Sumitomo remains incomplete. While RRPC has provided a dump of Sumitomo profit & loss statement, the Authority could not verify such response from Sumitomo's financial records due to its non-participation. The profit & loss dump, sales & purchase contain no SAP or ERP based screenshots. Moreover, RRPC has not even provided Sumitomo's financial statements for the POI. In absence of these material deficiencies, the Authority could not have considered RRPC's response as complete. Accordingly, the Authority holds that it has rightly determined the export price and normal value of RRPC in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995.
236. Kemya has also claimed that the Authority should increase its cost of production by adding selling and distribution expenses to the cost of production determined by the Authority. In this regard, the Authority notes that the ordinary course of trade test is to be carried out at the ex-factory level, and thus, there is no justification for adjusting Kemya's cost of production.
237. Sadara has argued that the Authority should not have adjusted trader's profit margin and SG&A expenses while computing Sadara's net export price as sales made through Dow Group and SABIC Group function as an extended arm for undertaking sales. The Authority disagrees with Sadara's submissions. It is noted that both SABIC Group and Dow Group undertake sale for various products and for several other producers, i.e., SABIC Group and Dow Group do not exclusively trade such goods for Sadara. Further, the shareholding for SABIC Group and Dow Group is materially different than that of Sadara. Secondly, Sadara itself as a producer bears expenses (inland freight) for selling such goods and such expenses are also reflected in its financial statement. Accordingly, it cannot be considered that SABIC

Group and Dow Group are extended arms of Sadara created for undertaking sales on behalf of Sadara.

238. Sadara has also submitted that the Authority should not have deducted marketing fee expenses reported by Sadara while computing its net export price as the same reflects the profit retained by its traders. It has been further argued by removing the indirect SGA expenses and profit of Dow Group and SABIC Group, in addition to the marketing fees reported by Sadara, the Authority is carrying out double deduction for the same expense. In this regard, the Authority notes that it has determined the indirect SG&A expenses for Dow Group and SABIC Group based on the actual purchase value from Sadara (net invoice value without adjustments for marketing fee) and actual re-sale price by such traders across the sales channels. The Authority further notes that it has applied the same methodology for determination of Sadara's normal value and export price. In furtherance of application of this method, Sadara's all domestic sales were found to be loss-making, which has not been contested by Sadara.
239. It may be noted that both export price and normal value for the producer have been worked out from the first point of resale to independent customers. Moreover, all direct selling expenses reported in Sadara's and its related exporter's records were appropriately adjusted in computing indirect selling expenses as per Appendix 5 of Sadara's related exporters. Further, while determining the profit of the related exporters, the Authority has considered the purchase prices reported for suppliers and net invoice value reported in Appendix 3A/3B/4A/4B. As such sale price are included in the marketing fee, there is no question of profits being double counted.
240. Sadara has also requested that it should be assigned a separate duty and not the weighted average duty determined for Saudi Aramco-SABIC Group. Sadara has further stated it is a legally distinct entity, and Saudi Aramco is not in an operational position to control it. In this regard, the Authority notes that Saudi Aramco has 100% shareholding in Excellent Performance Chemicals Company, which in turn holds more than 50% shareholding in Sadara. Similarly, Saudi Aramco holds 70% shareholding in SABIC. In view of the same, it cannot be considered that Sadara is not a related party to other producers in Saudi Arabia. The Authority further notes that Sadara has also not contested the fact that it is related to Saudi Aramco-SABIC Group. In view of the same, the Authority has recommended a single duty margin for Saudi Aramco-SABIC Group.

Product Scope and PCN Reporting

241. The Authority has re-examined the PCNs reported by the participating producers/exporters with reference to the technical specifications and verified records. The final calculations use only the correctly reported PCNs.

Eligibility of the domestic industry and treatment of OPAL

242. The Authority notes that exclusion of OPAL for the purpose of standing does not impact the injury analysis or risk distortion as OPAL's sales and production have been assessed as part of the macroeconomic data of Indian LLDPE industry. The Authority further notes that merely because an industry becomes ineligible for the purpose of Rule 2(b) of AD Rules, 1995, it does not mean its sales or production can be excluded for the purposes of assessing demand as it would result in distortion.

243. RRPC has argued that OPAL should not have been excluded from the scope of domestic industry merely because it is a SEZ unit and that at the time of filing of the application, OPAL had exited the SEZ. In this regard, the Authority notes that OPAL's exit from the SEZ took place after the completion of the POI. It is further noted that all examination relating to injury and dumping are to be assessed in relation to the POI and not afterwards. The impact of OPAL's exit from SEZ in post-POI does not affect the determination of injury and standing in the POI. The Authority further reiterates that merely because an entity is incorporated in India or physically manufactures goods in India does not automatically render it part of the domestic industry for trade remedial purposes where the governing legal regime itself treats such entity as operating outside the customs territory of India. Accordingly, the Authority considers that it has rightly excluded OPAL from the computation of total eligible domestic production.
244. Further, RRPC has also argued that reliance on RIL's support letter cannot cure the defect of the domestic industry lacking "major proportion" in terms of Rule 2(b). In this regard, the Authority clarifies that it has not relied on RIL's support letter for determining whether HPL and HMEL satisfy the test of "major proportion" in terms of Rule 2(b) AD Rules, 1995. As noted above, HPL and HMEL constitute around 25%-30% of total eligible Indian production and constitute an important and significant share of total eligible Indian production. Accordingly, the Authority has considered HPL and HMEL as domestic industry in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995.
245. RRPC has also contended that it was not able to verify RIL's installed capacity, production and sales figures and accordingly, its right to make meaningful submissions has been prejudiced. In this regard, the Authority notes that such information is confidential in nature and all such information was circulated by RIL in indexed form. All interested parties including RRPC claim such information as confidential and is treated confidential by the Authority. Accordingly, the Authority does not consider that RRPC's right to make submissions has been prejudiced.

Volume and price effects of imports

246. Other interested parties have argued that the Authority has relied on price based factors to explain volume effect and that existence of volume effect, i.e., significant increase in volume of imports either in absolute or relative terms has to be independently established. In this regard, the Authority notes that it has found that subject imports from the subject countries have significantly increased in the POI in relation to the base year. The Authority has merely correlated the facts on record to explain the reason behind increase in volume of domestic sales.
247. Producers from Saudi Arabia have contended that prices of subject goods from Saudi Arabia are entering into India at prices higher than the selling price of the domestic industry and therefore, cannot be a cause of injury to the domestic industry. In this regard, the Authority notes that it has cumulatively assessed affect of imports from the subject countries. Producers from Saudi Arabia have not presented any argument for de-cumulation of imports from Saudi Arabia. The Authority further notes that imports from the subject countries as a whole have been found to be causing adverse price effects on the domestic industry.

Economic parameters, material injury, and causal link

248. RRPC has also contended that the absence of trend data pertaining to exports sales has prevented it from examining injury to the domestic industry. In this regard, the Authority notes that details pertaining to export sales were part of the non-confidential version of the application circulated by the domestic industry. In fact, RRPC has itself relied on export sales trends of the domestic industry in para 188 of its post-disclosure submissions.
249. Other interested parties have submitted that Indian production capacity has increased in the POI despite presence of dumped imports. In this regard, the Authority notes that HMEL commissioned its LLDPE plant in 2018 and subsequently commenced production during the injury period.
250. RRPC has argued that the domestic industry's selling price increased to 91 index points in the POI, therefore, it cannot be said that the domestic industry's prices were suppressed. In this regard, the Authority notes that increase in domestic industry's prices corresponded to the increase in landed prices of subject imports from the subject countries. Further, subject imports from the subject countries have been entering into the Indian market below the domestic industry's cost of sales.
251. Other interested parties have argued that the domestic industry is not suffering from injury as it has been able to increase its sales, production, capacity utilization, wages and productivity and that such positive factors outweigh the adversely affected profitability parameters. In this regard, the Authority notes that it has already explained that the improvement in volumetric parameters was on account of HMEL's commencement of production in FY 2023-24. The Authority notes that when a new domestic producer enters into the market after making significant capital investment it cannot be expected to keep its capacities idle. Accordingly, the Authority needs to examine both volume and financial parameters to assess injury. In the present case, while on account of commencement of production by HMEL, the domestic industry's volumetric parameters improved, the domestic industry at the same time was not able to recover its costs which adversely affected its financial parameters.
252. Other interested parties have also argued that losses to domestic industry were on account of HMEL's commencement of production in FY 2023-24, as losses to the domestic industry peaked in FY 2023-24. In this regard, the Authority notes that price of subject imports from the subject countries significantly declined in FY 2023-24 compared to FY 2022-23 and thus, the domestic was forced to reduce its prices in line with landed prices of subject imports.
253. Other interested parties have also contended that the Authority could not have relied on information pertaining to other domestic producers in its injury examination. In this regard, the Authority notes that it has carried out injury examination for the domestic industry. However, it has also examined broader macroeconomic parameters of Indian LLDPE producers as in absence of examination of volumetric data of other domestic producers, the Authority could not have examined the movements in market share and demand.
254. Other interested parties have contended that mere achievement of higher capacity utilization, comparable consumption and conversions costs with other domestic producer do not indicate HMEL's operational and financial parameters had stabilized. It has been further argued that the Authority has relied on selected financial parameters of HMEL to conclude that HMEL's performance remained unaffected from costs and inefficiencies ordinarily associated with the

initial years of operation of a newly commissioned petrochemical facility. In this regard, the Authority notes that it has examined all cost-related parameters of HMEL and compared the same with the other domestic producer. The impact of commencement of production is reflected in the form of high interest cost and elevated levels of depreciation. Accordingly, the Authority examined the PBDIT of HMEL i.e., profit after removing depreciation, interest and tax, and found it to be negative.

255. The Authority further notes that the other interested parties agree that improvement in capacity utilization, norms and conversion indicate that HMEL has achieved a degree of technical stability, but these do not establish that HMEL has achieved a mature commercial operating position. The Authority notes that HMEL has been able to sell almost 97% of its total production in domestic and export markets during the POI which indicates that it has not only achieved technical stability but also commercial operating position.
256. On an overall assessment, the Authority notes that dumped imports from the subject countries entered India in significant volumes, competed directly with the domestic like article and prevented the domestic industry from raising prices sufficiently to recover its costs and earn a reasonable return. The Authority therefore confirms that dumped imports from the subject countries have caused material injury to the domestic industry.

Non-injurious price determination

257. Other interested parties have also argued that the Authority should have made adjustments to the domestic industry's NIP for by-product credit. In this regard, the Authority notes that the domestic industry does not generate any by-product in production of the PUC, rather such by-products are generated at the stage of manufacturing of captive inputs and the same has been appropriately adjusted in computation of NIP.
258. The domestic industry has also alleged that the Authority has carried out unwarranted adjustments to its non-injurious price. In this regard, the Authority notes that the remarks of the domestic industry are in general in nature and it has not substantiated its claims. Accordingly, the Authority disagrees with the submissions of the domestic industry.

Public interest, user impact, and duration of duty

259. The Authority further notes that it has appropriately computed the impact of duties on a wide variety of products and has appropriately explained the basis of its assumptions. Further, the Authority
260. The Authority further notes that the interested parties have stated that on account of existence of demand-supply gap anti-dumping duties should not be recommended. In this regard, the Authority notes that the existence of demand-supply gap does not warrant non-recommendation of measures to counter unfair trade practices by foreign exporters.
261. The temporary exemption from basic customs duty, quality-control measures and geopolitical developments after the period of investigation serve different policy purposes and do not justify allowing injurious dumping to continue. Moreover, no exceptional circumstance has been established for justification of limiting the measure to two years.

L. CONCLUSION

262. Having examined the submissions filed by all interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes the following:
- a. The product under consideration is *Linear Low-Density Polyethylene, having density of 908.4 to 940.4 kg/m³*.
 - b. The exclusion requests made by the other interested parties have been examined and the Authority finds that the domestic industry has produced and sold the like article to the products for which exclusion has been requested. Accordingly, no exclusion requests have been considered by the Authority.
 - c. The PCN methodology adopted for the purpose of the present investigation was based on metallocene based catalysts and non-metallocene catalysts.
 - d. The application seeking imposition of anti-dumping duties was filed by Chemicals and Petrochemicals Manufacturers' Association, India, on behalf of Indian LLDPE manufacturers. Injury information has been provided by Haldia Petrochemicals Limited and HPCL-Mittal Energy Private Limited. The application has been supported by Reliance Industries Limited, which provided supporter data as per the applicable format. HPL and HMEL account for major proportion of Indian LLDPE production in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995 and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of AD Rules, 1995.
 - e. The Authority has relied upon DG Systems data for the purpose of examination of imports of the subject goods, after due examination of the transactions.
 - f. The investigation was initiated against the State of Kuwait, Malaysia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates. At the stage of initiation import volumes from the State of Kuwait, State of Qatar and the Sultanate of Oman individually accounted for less than 3% of total imports, but collectively accounted for more than 7% of total imports. During the investigation, the Authority found imports from Qatar to be non-dumped and thus, the collective share of countries (Kuwait and Oman) individually accounting for less than 3% of total imports fell below 7%. Accordingly, in terms of Rule 14 of AD Rules, 1995, the Authority has terminated investigation against Kuwait, Oman and Qatar. Accordingly, the subject countries for the present investigation are Malaysia, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates.
 - g. The dumping margin and injury margin determined for producers/exporters from the subject countries are positive and significant.
 - h. The domestic industry has suffered material injury during the period of investigation, as is evident from the following:
 - (i) The volume of dumped imports from the subject countries have increased in absolute terms compared to the base year.
 - (ii) Despite increase in domestic industry's installed capacity over the injury period and increase in demand, significant portion of domestic industry's capacity remained idle in the POI.
 - (iii) Subject goods from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry.
 - (iv) Subject goods from the subject countries are depressing the prices of the domestic industry.
 - (v) Due to commencement of production by HMEL during the injury period, the domestic industry's volume parameters have improved. However, market share

of Indian Industry as a whole has declined. It is noted that improvement in certain volume parameters does not negate material injury where price and profitability parameters show significant deterioration.

- (vi) The domestic industry has suffered financial losses, incurred cash loss and accumulated negative returns on capital employed during the period of investigation.
 - (vii) The domestic industry has not been able to earn reasonable return despite demand for the product in India.
- i. No other known factors have caused injury to the domestic industry and injury to the domestic industry is due to dumping of the subject imports into India.
 - j. The injury margin determined for producers/exporters from the subject countries is positive and significant.
 - k. Imposition of anti-dumping duty shall be in the larger public interest, as can be seen from the following:
 - (i) No interested party has demonstrated that imposition of duty would cause disproportionate adverse impact on public interest.
 - (ii) The imposition of duty shall prevent unfair advantage to foreign producers/exporters through dumping practices and would provide a level playing field to the domestic industry in the Indian market.
 - (iii) Anti-dumping duty does not prohibit imports. Imports may continue to enter the Indian market at fair and non-dumped prices.

M. RECOMMENDATIONS

263. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
264. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, for a period of 5 years, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below:

DUTY TABLE

S.No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount (US\$/MT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	3901 10 10 3901 40 10	<i>Linear Low-Density Polyethylene, having density of 908.4 to 940.4 kg/m³</i>	Kingdom of Saudi Arabia	Any Country including Kingdom of Saudi Arabia	Al-Jubail Petrochemical Company ("KEMYA")	75
2	-do-	-do-	Kingdom of Saudi Arabia	Any Country including Kingdom of Saudi Arabia	Arabian Petrochemical Company ("Petrokemya")	75
3	-do-	-do-	Kingdom of Saudi Arabia	Any Country including Kingdom of Saudi Arabia	Eastern Petrochemical Company ("Sharq")	75
4	-do-	-do-	Kingdom of Saudi Arabia	Any Country including Kingdom of Saudi Arabia	Jubail United Petrochemical Company ("United")	75
5	-do-	-do-	Kingdom of Saudi Arabia	Any Country including Kingdom of Saudi Arabia	Rabigh Refinery And Petrochemical Company	75
6	-do-	-do-	Kingdom of Saudi Arabia	Any Country including Kingdom of Saudi Arabia	Sadara Chemical Company	75
7	-do-	-do-	Kingdom of Saudi	Any Country	Yanbu National Petrochemical	75

			Arabia	including Kingdom of Saudi Arabia	Company ("Yansab")	
8	-do-	-do-	Kingdom of Saudi Arabia	Any country including Kingdom of Saudi Arabia	Any producer other than S. No. 1 to 7	225
9	-do-	-do-	Any country other than subject countries	Kingdom of Saudi Arabia	Any	225
10	-do-	-do-	United Arab Emirates	Any country including United Arab Emirates	Abu Dhabi Polymers Co. Ltd (Borouge) - Sole Proprietorship L.L.C.	41
11	-do-	-do-	United Arab Emirates	Any country including United Arab Emirates	Any producer other than S. No. 10	94
12	-do-	-do-	Any country other than subject countries	United Arab Emirates	Any	94
13	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Any	368
14	-do-	-do-	Any country other than subject countries	Malaysia	Any	368

Note - The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

“I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in the (name of country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.” If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs laws and regulations.

N. FURTHER PROCEDURE

265. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority